वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

jk'Vªh; 'kS{kd ;kstuk ,oa
iz'kklu fo'ofo|ky;

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

©jk"Vªh; 'kS{kd ;kstuk ,oa iz'kklu fo'ofo|ky; ¼200 izfr;k¡½ 2016
¼Hkkjr ljdkj }kjk fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 3 ds varxZr ?kksf"kr½

jk"Vªh; 'kS{kd ;kstuk ,oa iz'kklu fo'ofo|ky; ds fy, dqy lfpo] U;wik }kjk izdkf'kr rFkk y{; ehfM;k izk- fy-] ,&36] f}rh; eafty] lSDVj&4] uks;Mk&201301 }kjk fMtk;u ,oa foHkk iSM izk- fy-] vks[kyk esa U;wik ds izdk'ku ,dd }kjk eqfnzr A

विषय सूची

v/;k;

1.	विहंगावलोकन	1
2.	अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	23
3.	अनुसंधान	39
4.	सहचर्या और सहभागिता	75
5.	न्यूपा में नई पहल	81
6.	पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं	89
7.	कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं	95
8.	प्रकाशन	99
9.	न्यूपा में सहायता अनुदान योजना	103
10.	प्रशासन और वित्त	109

vuqyXud

I.	संकाय का अकादमिक योगदान	115

ifjf'k"V

I.	न्यूपा परिषद् के सदस्य	205
II.	प्रबंधन बोर्ड के सदस्य	207
III.	वित्त समिति के सदस्य	208
IV.	अकादमिक परिषद के सदस्य	209
V.	अध्ययन बोर्ड के सदस्य	211
VI.	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ	213
VII.	वार्षिक लेखा	217

y$kkijh{kk fjiksVZ 265

1 विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अपने महत्वपूर्ण और व्यापक शैक्षणिक कार्यकलापों के साथ देश के शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क में विशेष स्थान रखता है।

इसकी स्थापना आरंभिक रूप से फरवरी 1962 में यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र के रूप से हुई थी। इस केंद्र का मुख्य कार्य एशिया के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा विद्यालय पर्यवेक्षण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था।

1 अप्रैल 1965 से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र का नाम बदलकर एशिया शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच दस वर्ष के समझौते के समाप्त होने के बाद, एशिया संस्थान को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और तत्पश्चात 1970 में शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की गई। पुनः इस कालेज का पुनर्गठन किया गया और 31 मई 1979 को इसका विस्तार करते हुये इसको राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया।

शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीपा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुये संस्थान को वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इसे 'मानद विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत इसे डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई और पुनः नाम परिवर्तन के बाद इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) कहा जाने लगा।

U; iwkdk fe'ku vkSj fotu

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है।

इसे आगे 'राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' के नाम से संबोधित किया जायेगा। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी नीतियों, योजना तथा कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तथा संघ क्षेत्रों के स्तर पर सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण तथा स्कूल, समुदाय, जिला, राज्य/संघ प्रदेशों तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्वरित, सहभागिता और जवाबदेह शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन प्रणाली का सांस्थनीकरण;

- शैक्षिक सुधारों का अनुसमर्थन करने और शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवा पेशेवरों सहित और शिक्षाविदों सहित विशेषीकृत मानव संसाधनों के समूह का विस्तार करना;

- शैक्षिक क्षेत्र में उभरती तथा वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु तथ्य आधारित जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन एवं संबंधित विषयों के ज्ञान आधार में वृद्धि;

- शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार तथा बेहतर शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार, अनुसंधान परिणामों, नवाचारों तथा सर्वोत्तम व्यवहार समेत सूचना तथा ज्ञान की साझेदारी एवं पहुंच में सुधार;

- अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देते हुये शैक्षिक नीति निर्माण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार/तकनीक शिक्षा के सभी चरणों तथा व्यवस्था में, तथा रणनीतिक उपागम शैक्षिक योजना प्रकियाओं, अभिशासन तथा प्रबंधन में सुधार हेतु तथा अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं में नेतृत्वकारी भूमिका जो शैक्षिक नीति–निर्माण तथा देश में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन व्यवहार का निर्माण करती है।

eq[; dk;Z

अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निम्नांकित मुख्य कार्यों में संलग्न है :

- शिक्षा के सभी चरणों में शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना;
- सर्वोत्तम प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के कैडर के गठन हेतु प्री–डाक्टरल, डॉक्टरल तथा पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों सहित अध्यापन के विकसित अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों का विकास तथा आयोजन और साथ में शैक्षिक नीतियों योजना तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु सतत् सांस्थानिक क्षमता का निर्माण करना;
- शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान एजेंडा तथा वचनबद्धता को स्वरूप देना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिये आवश्यक समर्थन हेतु नये ज्ञान का सृजन तथा तथ्य आधारित नीति निर्माण और बेहतर शैक्षिक योजना और प्रबंधन व्यवहार/तकनीक का प्रयोग करना;
- केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों को उनकी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान करना और उन्हें शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में सुधार हेतु मदद करना;
- शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा निर्माण हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को परामर्श सेवायें प्रदान करना;
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान तथा नवीन ज्ञान के सृजन हेतु सूचना तथा विचारों के समाशोधन गृह के रूप में कार्य, शैक्षिक नीतियों, योजना तथा प्रशासन में विशेष रूप से, विचारों/अनुभवों के आदान–प्रदान तथा नीति–निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के बीच नीतिगत चर्चा हेतु विचार मंच प्रदान करना, प्रभावी नीतियों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन तकनीक/व्यवहार को शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को सामना करने हेतु चिह्नित करना तथा शिक्षा क्षेत्र संबंधी विकास लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में सुधार हेतु संयुक्त प्रयासों/कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों, निधि एवं एजेंसियों समेत राष्ट्रीय

तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा सहयोग;

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास में उभरती हुई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में उभरती हुई चुनौतियों की पहचान तथा शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त नीति निर्माण तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति का मूल्यांकन।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उपरोक्त कार्य राज्य तथा संघशासित प्रदेश एवं केंद्रीय स्तर पर सरकारों तथा संस्थानों के साथ निकटतम संपर्क तथा सहयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं शिक्षा व्यवस्था की योजना तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्‌दों को संबोधित करता है। विश्वविद्यालय का एक मुख्य पहलू जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संबंध द्वि–रूप कार्य प्रणाली है। विश्वविद्यालय अपने ज्ञान आधार में वृद्धि वास्तविकता क्षेत्र में अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल, कालेज, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभागों के साथ संपर्क द्वारा करता रहा है। राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्यों/संघशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण को पूर्ण करने हेतु संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण, राज्य सरकारों तथा राज्य संस्थानों के साथ निकटवर्ती संपर्क, उनकी शैक्षिक व्यवस्था का समालोचनात्मक अध्ययन, नीतियां तथा कार्यक्रम एवं उन्हें व्यावसायिक परामर्श तथा तकनीकी समर्थन हेतु प्रयासरत है। विश्वविद्यालय अपने ऐसे कार्यक्रमों की शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक थिंक टैंक (प्रसार केन्द्र) बना हुआ है। विश्वविद्यालय अपने अधिकांश क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और अन्तर्दृष्टि जमीनी स्तर के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं को हस्तान्तरित कर रहा है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय की इस दोहरी भूमिका ने अपने अध्यापन तथा अनुसंधान के अकादमिक कार्य को व्यापक प्रामाणिकता प्रदान की है।

vdknfed <kpk rFkk leFkZ lsok,a

विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे में विभाग, केंद्र, विशेष पीठ हैं जो शिक्षा के विशिष्ट पक्षों को संबोधित करते हैं तथा तकनीकी समर्थन एकक/समूह तथा अकादमिक समर्थन प्रणाली अपने संबंधित विषयगत क्षेत्रों से जुड़ी विकास तथा क्रियान्वयनकारी गविविधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। विश्वविद्यालय के संकाय में प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा राष्ट्रीय अध्येता सम्मिलित हैं जो शिक्षा नीति, योजना तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक विभाग अंतरशास्त्रीय विषयों के आधार पर संयोजित है और वे ज्ञान, विद्वता तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रमों और अनुसंधान क्षेत्रों, सामान्यतः शिक्षा, और विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में विशेष तौर पर संसाधन प्रदान करते हैं। प्रत्येक विभाग के पास अनुसंधान/परियोजना सहायकों तथा अनुसचिवीय स्टाफ के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ के रूप में संकाय सदस्य हैं। अकादमिक विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर होता है। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधन कार्यक्रमों के निष्पादन और विकास तथा उनको प्रदान किये गये क्षेत्रों में परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत, विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन आठ अकादमिक विभागों तथा विशेष पीठ विश्वविद्यालय मानक एवं मूल्यांकन एकक, परियोजना प्रबंधक एकक, भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (आई.ए.आई.ई.पी.ए.) तथा दो केंद्रों द्वारा किया गया जिन्हें अकादमिक तथा प्रशासनिक सेवा एककों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।

v d kn fe d l a Bu

fo Hkkx

- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त
- शैक्षिक नीति
- विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा
- उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
- शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

d sUnz

- राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
- उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र

, d d

- विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन एकक

v kbZ v kbZ Z h,

- भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

l e FkZ l sok, a

- पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र
- कंप्यूटर केन्द्र
- प्रकाशन एकक
- परियोजना प्रबंधन एकक
- डिजीटल अभिलेखागार

i hB r Fkk j k'Vªh; v /; s r k

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ
- अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर राजीव गांधी सथापना पीठ
- न्यूपा राष्ट्रीय अध्येता

v d kn fe d

fo Hkkx

' kS{ kd ; kt u k fo Hkkx %केंद्रीकृत नियोजन से हटकर विकेंद्रीकृत योजनाओं पर बल के साथ, न्यूपा के प्रमुख विभागों में से एक यह विभाग, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजना के आगतों, प्रक्रियाओं, और उत्पादों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पारंपरिक अर्थों में व्यापक योजना से हटकर आज, आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि में, ध्यान रणनीतिक योजना पर स्थानांतरित हो गया है। हाल के दिनों में, गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा पर दबाव के साथ न केवल शैक्षिक योजना का दायरा समष्टि स्तर पर रणनीतिक योजना के संस्थानीकरण को कवर करना है बल्कि विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म नियोजन और स्कूल सुधार योजना के रूप में स्थानीय स्तर की योजना तकनीकों का प्रयोग करना भी है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों को परामर्श उलब्ध कराने के साथ–साथ शिक्षण और प्रशिक्षण, शैक्षिक योजनाकारों के पेशेवर विकास, अनुसंधान और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। विभाग शैक्षिक विकास में पहल का निदान और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण और संकेतकों के प्रयोग हेतु शिक्षा पदाधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करने में लगा हुआ है। विभाग एम.फिल. और पी–एच.डी. के विभिन्न केंद्रिक और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के संचालन, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा) और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) शिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में योगदान देता है।

' kS{ kd i z kk u fo Hkkx %शैक्षिक प्रशासन विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और प्रबंधन के विविध आयामों अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा परामर्शकारी सेवाओं में सक्रिय रूप से बौद्धिक और अकादमिक संलग्नता है। विभाग का एक मुख्य शैक्षिक क्षेत्र सरोकार एक समृद्ध ज्ञान आधार का विकास करना और शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध आयामों पर शैक्षिक प्रशासकों तथा शोधार्थियों को एक मजबूत पेशेवर अनुसमर्थन का निर्माण करना है। अतः यह विभाग शैक्षिक प्रशासन और शासन की गतिशीलता को समझने और उसका विश्लेषण करने हेतु इसकी ठोस अवधारणा और ढांचा के विकास के लिए प्रयासरत है। यह विभाग विभिन्न स्तर के शिक्षा कर्मियों के लिये शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के विविध पक्षों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करता है।

' kS{ kd fo Ùk fo Hkkx %इस विभाग का दोहरा उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों –राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा विश्वस्तर पर आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष पर अनुसंधान करना तथा उसे प्रोत्साहित करना है तथा विकासशील देशों और भारत में शिक्षा क्षेत्र की वित्तीय योजना तथा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों के क्षमता निर्माण का सृजन करना है। विभाग के कार्यक्रम/गतिविधियां– अनुसंधान, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परामर्श हैं जो नीति, योजना तथा विकास, शिक्षा के सार्वजनिक तथा निजी वित्त पोषण, सरकारी तथा निजी संसाधनों की लामबंदी, शिक्षा के सभी स्तरों पर संसाधनों का आवंटन तथा उपयोग, प्राथमिक से उच्च, तथा संसाधन आवश्यकताओं के आकलन से

जुड़े मुद्दों के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। अधिकांशतः शोध के क्षेत्र शिक्षा के वित्त पोषण, कार्यक्रम और नीतिगत मुद्दों से संबंधित हैं। परामर्शकारी सेवाएँ नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित हैं। अध्यापन के विषय में शिक्षा का अर्थशास्त्र और शैक्षिक वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के विषय योजना तकनीक और प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हैं।

'kSf{kd uhfr foHkkx %यह विभाग नीतियों से संबंधित विभिन्न मसलों पर जिन दिशाओं की ओर शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, उन्हें ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नीति संबंधी अध्ययन करता है। यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति–निर्माताओं के बीच नीति निर्माण के प्रति मूलभूत समझ विकसित करने का प्रयास भी करता है। यह विभाग नीति निर्माताओं, कार्यकर्त्ताओं और शैक्षिक नीति तथा सार्वजनिक नीति से जुड़े अन्य लाभार्थियों/व्यक्तियों के लिए नीति संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परिसंवाद और प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है।

विभाग की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षण, अध्यापन, शोध और अकादमिक अनुसमर्थन शमिल हैं। यह विभाग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक प्रशासकों और योजनाकारों के लिये अल्पावधि और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा यह विमर्श के लिये अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है और पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी संबंधी मुद्दों पर सूचना आधार तैयार करता है। विभाग के प्रमुख शोध केन्द्र प्रायोजित शैक्षिक योजनाओं के मूल्यांकन और नीति तथा कार्य व्यवहार की समझ पर केंद्रित होता है।

यह विभाग राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये नीतिगत मुद्दों पर क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह नीति के बहुस्तरीय अभिशासन को बल देता है जिसमें आधारभूत स्तर पर सहभागिता पूर्ण ढांचे पर फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पर शिक्षा की विकेंद्रीकृत योजना और स्कूली शिक्षा में समुदाय की भूमिका इसके शोध अध्ययनों से प्रकट होता है। यह विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एम.फिल., पी–एच.डी., डेपा और आईडेपा कार्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों सहित अध्यापन संबंधी सभी कार्यक्रमों में योगदान करता है। यह (क) सांस्थानिक निर्माण और (ख) क्षमता संवर्द्धन संबंधी कार्यक्रमों में राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवा भी प्रदान करता है।

fo|ky; vkSj vukSSpkfjd f'k{kk foHkkx % विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग व्यापक रूप से अधिकार–आधारित और समेकित ढांचे के अंतर्गत पूर्व–स्कूल शिक्षा, समग्र स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल देता है। यह गुणवत्ता, समता, सामाजिक न्याय और समेकन की सैद्धांतिक समझ विकसित करने का प्रयास करता है। यह विभाग संस्थान के रूप में स्कूलों और स्कूल तथा अनौपचारिक में हो रहे बदलावों पर नीतियों तथा व्यावहारिक हस्तक्षेपों हेतु अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के उद्देश्य से शोध अध्ययन करता है। यह विभाग शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम एवं एम.फिल, पी–एच.डी. के कुछ पाठ्यक्रमों के अध्यापन सहित राज्य, जिला तथा उप–जिला स्तर के अधिकारियों के लिये कार्यशालाएं और क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करता है? यह योजनाओं तथा नीतियों के अध्ययन तथा निर्माण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यह विभाग सह–क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुभव और विशेष क्षमता साझा करता है। वर्तमान में व्यावहारिक ज्ञान के मद्देनजर यह विभाग कमोबेस सीमित चार क्षेत्रों– अधिकार आधारित ढांचे के अंदर स्कूली शिक्षा में समता गुणवत्ता और समावेशन, अध्यापक विकास और प्रबंधन, स्कूल नेतृत्व एवं स्कूली मानकों के मूल्यांकन पर विशेष बल दे रहा है। संकाय के सदस्य राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र में भी कार्य करते हैं और विद्यालय मानक और मूल्यांकन एकक में भी संबद्ध हैं।

mPp rj vkSj O;kolkf;d f'k{kk foHkkx %यह विभाग वर्षों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार अनुसंधानात्मक अनुसमर्थन और नीतिगत सुझाव प्रदान करता रहा है। विभाग के विश्व व्यापार संगठन कक्षा ने गेट्स के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों के विश्लेषण और भारत की सहमति की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभाग ने उच्चतर शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के विविध आयामों पर अध्ययन किया और उन पर विमर्श हेतु संगोष्ठियां आयोजित की तथा उनके निष्कर्षों का प्रसारण किया। यह विभाग उच्चतर शिक्षा के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहयोग करता रहा है। यह विभाग विषेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकायाध्यक्षों और कुलसचिवों के सम्मेलन और संगोझिष्ठयों के आयोजन में यू.जी.सी. का सहयोग करता रहा है।

इस विभाग ने कार्य निष्पादन आधारित उच्चतर शिक्षा पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन और भारतीय उच्चतर शिक्षा में कार्य निष्पादन आधारित वित्त पोषण पर योजना आयोग – विश्व बैंक प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन में भी सहयोग किया है। कार्य निष्पादन आधारित विभाग के नियमित वार्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणी के कालेजों के प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। वार्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत यह विभाग विभिन्न श्रेणियों के कॉलेज प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के विभिन्न आयामों तथा अकादमिक सुधार पर संगोष्ठियां आयोजित करने में अकादमिक समर्थन प्रदान करता है। विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम–एम.फिल तथा पी.एच.डी. कार्यक्रमों के केंद्रिक तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और इसके शोधार्थियों का अतिरिक्त शोधनिर्देशन कर रहा है।

'kS{kd i zf'k{k.k vkS {kerk fodkl foHkkx % यह विभाग विशेष रूप से नवनियुक्त एंव प्रोन्नत शैक्षिक प्रशासकों क्षमता में सुधार के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सहसंबंध विकसित करने पर विशेष बल देता है। शिक्षा प्रणाली और संस्थानिक स्तर के अधिकारियों के लिये विषयगत और संवर्ग आधारित पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा तथा विभागों के कार्य दल का विकास से स्थाई और समर्पित संस्थानिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से इस विभाग ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है।

इसके अलावा यह विभाग लंबी अवधि के दो डिप्लोमा कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कर्मियों के लिये आयोजित करता है। वर्ष 2013 में शैक्षिक योजना और प्रशासन में 34वां राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भारत के 12 राज्यों के 25 शिक्षा अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। शैक्षिक योजना और प्रशासन में 30वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम फरवरी 2014 से आयोजित किया गया। इसमें 17 देशों के 27 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया और भूटान के अनुरोध पर इन देशों के लिए क्षमता विकास पर दो क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

यह विभाग विशेष फोकस समूह जैसे अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षा संस्थानों (विद्यालय और उच्चतर शिक्षा) के प्रमुखों, जनजातीय क्षेत्रों के आश्रम स्कूलों के प्राचार्यों और डाइट के योजना एवं प्रबंधन विभाग के संकाय के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

'kS{kd i zca/ku lwpuk iz.kkyh foHkkx % शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग शोध और क्षमता विकास संबंधित कार्य करता है और भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा का आंकड़ा आधार और प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी परामर्श देता है। यह विभाग भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) और आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस) का प्रबंधन करता है। इसके अलावा यह विभाग शैक्षिक सांख्यिकी के मुद्दों और शिक्षा के समकालीन मुद्दों पर सम्मेलन/संगोष्ठियां और शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधियों पर कार्यशालाएं/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और सांख्यिकी तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर परामर्श प्रदान करता है। विभाग के संकाय सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली के निर्माण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। तद्नुसार स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली की दिशा में वर्ष 2012–13 से देशभर में समान आंकड़ा प्रपत्र में पहले कदम के रूप में डाइस और सेमीस का समेकित आंकड़ा संगृहित किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे 1.53 मिलियन स्कूलों से आंकड़ा एकत्र किए गए।

इस विभाग द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं के विषय निम्नलिखित हैं : शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग, एजुसेट द्वारा डाइस पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, शैक्षिक शोध में डाइस आंकड़ों का उपयोग और स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली आदि। यह विभाग तीसरी दुनिया के देशों के लिए ईएमआईएस पर सुनियोजित पाठ्यक्रम के साथ–साथ डेपा और आईडेपा में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधि पर पाठ्यक्रम का अध्यापन करता है। विभाग का संकाय ईएमआईएस और स्कूली शिक्षा से संबंधित पक्षों पर भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करता है।

fo ' kś'k i hB

e kSy kuk v Ckqy d y ke v kt kn i hB % यह पीठ स्वतंत्र भारत के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के पहले मंत्री मौलाना आज़ाद के योगदान को स्मरण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में स्थापित किया गया है। पीठ का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान मौलाना आजाद के योगदान की खोज करते हुए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास पर अध्ययन करना है। यह पीठ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। यह पीठ मौलाना आज़ाद के दर्शन और वैश्विक विचारों व अन्य संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

v /; ki d i zca/ku , oa fod kl i j jkt ho x ka/kh LFkki uk i hB % अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर राजीव गांधी स्थापना पीठ ने जून 2013 में प्रोफेसर और पीठ की नियुक्ति के साथ अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस पीठ की स्थापना अध्यापक प्रबंधन एवं विकास पर केंद्रित कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल की अवधि (2012–15) हेतु की गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन संकाय और शोध संबंध व्यय के लिए न्यूपा को निधि प्रदान करता है। राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित अध्यापक प्रबंधन और विकास पीठ ने भारत के नौ राज्यों– झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्य दशाओं पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में तकनीकी साझेदार के रूप में विश्व बैंक को भी आमंत्रित किया गया। इस अध्ययन केन्द्र में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालय अध्यापक थे। यह अध्ययन जारी है। पीठ की गतिविधियों के अनुमोदन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद् और प्रशासक शामिल हैं। इस पीठ की प्रथम मुख्य गतिविधि – भारत के नौ राज्यों में प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्य दशाओं का बहुराज्यीय अध्ययन जारी है। यह अध्ययन झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जारी है। न्यूपा नीतिगत दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा के लिए एससीईआरटी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ कार्य कर रहा है। इसके बाद मुख्य हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी और उनके साक्षात्कार लिए जाएंगे। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अध्यापकों से शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापकों के प्रबंधन और उनके स्थान के बारे में उनके विचार और राय लिए जाएं। इसके बाद अध्ययन का तीसरा चरण शुरु होगा। इसमें न्यूपा शिक्षा व्यवस्था में संभावित सुधार के लिए कार्य करेगा।

v/;kid fodkl vkSj izca/ku dks c<+kok nsus ds fy, v/;;u ihB% अध्यापक विकास और प्रबंधन पर राजीव गांधी पीठ ने जून 2013 से कार्य आरंभ कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापक विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों – देश भर में अध्यापक विकास और प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित नीति विकास और कार्य व्यवहार को उन्नत बनाने के न्यूपा के प्रयोजन को पूरा करना है।

शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करने हेतु प्रावधान, गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों का वितरण और उपयोग, मौजूदा अध्यापक संवर्ग को प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु क्षमता विकास की जरूरतों को पूरा करना और स्कूल नेतृत्व का पेशेवर विकास और क्षमता विकास इसके परस्पर संबंधित मुद्दे हैं। यद्यपि नीति और कार्य व्यवहार के बीच मज़बूत संबंध होता है जो ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर अध्यापक विकास और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पक्षों को संबोधित करता है। प्रो. विमला रामचंद्रन को इस पीठ का प्रभारी प्रोफेसर नियुक्त किया गया है।

bl ihB dh fof'k"V xfrfof/k;ka gSa%

- विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में अध्यापकों की कार्य दशाओं और संबंधित शैक्षिक प्रबंधन मुद्दों पर स्वतंत्र और साहयोगिक शोध कार्य। यह आशा है कि इससे निर्णय कार्य और प्रभावी नीतिगत ढांचे के निर्माण में अपेक्षित ज्ञान आधार और सूचनाएं संबर्धित होंगे।
- अध्यापक विकास और प्रबंधन कार्य व्यवहार में सुधार हेतु राज्य सरकारों एवं राज्य/संघ क्षेत्र स्तर के संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- राज्य स्तर के शिक्षा प्राधिकरणों और अनुमोदित कार्य व्यवहार हस्तक्षेप से जुड़े हितधारकों को साथ में लेकर अध्यापक विकास और प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नीतिगत संवाद को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हितधारकों हेतु निर्णय कार्य के सूचना आधार को सुलभ बनाने के लिए शोध कार्यों और उत्कृष्ट कार्य व्यवहारों सहित ज्ञान और सूचनाओं का प्रलेखन और प्रसारण।
- प्रभावी अध्यापक विकास और प्रबंधन कार्य व्यवहार के अंगीकरण का समर्थन।

bl dsvarxZr tkjh nks ifj;kstuk v/;;u gSa%

9 राज्यों के शोध अध्ययन में सभी वर्ग के अध्यापकों (नियमित और संविदा अध्यापक) जो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी भर्ती और विकास नीतियों तथा कार्य व्यवहारों, वेतन एवं कार्य दशाओं (स्थानांतरण, व स्थापन, व्यावसायिक संवृद्धि और विकास) संबंधी दस्तावेजों का विश्लेषण करना हैं। यह कार्य राज्य स्तरीय अध्ययनों जो राजकीय अधिसूचनाओं, आदेशों और अध्यापक प्रबंधन से जुड़े मुख्य प्रशासकों के साक्षात्कार के आधार पर किया जा रहा है।

dsUnz

jk"Vªh; fo|ky; usr`Ro dsanz¼,ulh,l,y½% राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र भारत में विद्यालयों के रूपांतरण के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये यह चार घटकों– पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, क्षमता विकास, नेटवर्क और संस्थानिक निर्माण और अंत में शोध एवं विकास पर कार्य कर रहा है। यह केंद्र व्यापक परिप्रेक्ष्य में बदलाव और विकास के लिये विद्यालय प्रमुखों के साथ–साथ प्रशासकों के नेतृत्व क्षमता विकास की परिकल्पना करता है। वर्तमान में यह केंद्र मौजूदा विद्यालयों प्रमुखों तथा नवनियुक्त विद्यालय प्रमुखों प्रारम्भिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के भावी एवं वरिष्ठ अध्यापकों जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हैं, के क्षमता विकास कार्य पर विषेष बल दे रहा है।

यह केंद्र अपने मिशन को पूरा करने के लिए विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व क्षमता निर्माण के कार्य से संलग्न है जिसमें विद्यालय रूपांतरण के रूप में विद्यालय आधारित बदलाव लाने के लिए विद्यालय प्रमुखों के साथ सतत रूप से जुड़ाव भी शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर के दो दस्तावेज़– राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यचर्या ढांचा एवं विद्यालय नेतृत्व विकास पर हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इसके साथ–साथ अनेक कार्यशालाएँ और बैठकें आयोजित की गईं। समीक्षाधीन वर्ष में 10 राज्यों–

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, राज़स्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस कार्य का शुभारंभ किया गया। राज्य विशिष्ट नेतृत्व जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिये प्रत्येक राज्य की वास्तविक स्थितियों और विद्यालयों के संदर्भों के मद्देनज़र राज्य विशिष्ट कार्यवाही योजनाएँ तैयार की गईं। इस मिशन हेतु राज्यों तथा केंद्र के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की गई। यूकेरी के अंतर्गत भारत में विद्यालय नेतृत्व पर नेशनल कालेज फार टीचिंग एंड लीडरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

mPp r j f' k{kk u hfr v uq ákku d sæz % राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति तथा योजना का अनुसमर्थन करने के लिये एक विशिष्ट संस्थान के रूप में उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई) की स्थापना की है। सीपीआरएचई शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है। यह केंद्र उच्च शिक्षा के प्रावधानों के विस्तार और सुधार के मौजूदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं समता और समावेशन की सुनिश्चितता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, प्रासंगिकता और स्नातकों के रोजगार और इसके अभिविन्यास और प्रबंधन

को अंतरराष्ट्रीयकरण तथा सुधार कार्य पर विशेष बल दे रहा है। यह केंद्र शोध को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों का नेटवर्क विकसित कर रहा है। राज्य स्तरीय निकायों जैसे– राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के साथ राज्य तथा संस्था स्तर पर उच्च शिक्षा की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न है।

, d d

fo| ky ; e kud , oa eW; kadu , d d % न्यूपा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन एकक स्थापित किया है। विद्यालय को सुधार की धूरी मानते हुए विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन एकक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय का सर्वसम्मति से एक मानक और प्रक्रिया तंत्र का विकास करना है जिसे सभी विद्यालय प्राप्त करने का प्रयास करें। यह एकक प्रत्येक विद्यालय को पूरी जवाबदेही के साथ विद्यालय सुधार हेतु स्व एवं बाह्य मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

राज्यों और विशेषज्ञ के साथ आपसी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एकक द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाएंगे :

- विविधता और बदलते संदर्भों और स्थितियों के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिये स्कूल के मानकों के सहमत ढांचे पर स्कूल मानक और मूल्यांकन (NFSSE) पर राष्ट्रीय ढांचे का विकास;
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन के लिये पुस्तिका का विकास;
- एक आपसी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से राज्य विशेष स्कूल मानकों और मूल्यांकन को संस्थागत करना;
- नियमित रूप से और स्वतंत्र स्कूल मूल्यांकन और स्कूल सुधार हेतु प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक राज्य में संस्थागत तंत्र की रूपरेखा;
- मूल्यांकनकर्त्ताओं का प्रोफाइल बनाना और राज्य स्तर पर क्षमता विकास के लिये अवसर प्रदान करना;

- आवधिक समीक्षा करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच बनाना और सभी संबंधित पक्षों के बीच अनुभवों को साझा करना।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, एक राष्ट्रीय तकनीकी समूह गठित किया गया है और स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के विकास हेतु प्रक्रिया की पहल की जा रही है।

ifj;kstuk izca/ku ,dd ¼ih-,e-;w½ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) समर्थन और प्रायोजित अनुसंधान के प्रबंधन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

यह एकक शिक्षा नीति और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (व्यक्ति शोध) के क्षेत्र में अध्ययन के लिए न्यूपा सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु न्यूपा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अध्ययन सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिये अनुदान सहायता योजना विभाग के सभी बाह्य वित्त–पोषित और आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं के उचित समन्वय के लिये प्रशासन की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

यह एकक सामान्य रूप से, परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और संबंधित समर्थन सेवाएँ प्रदान करने सहित न्यूपा में किए गए विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधन के लिये प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। यह सभी मामलों में धन और घरेलू व्यय के लेखा सहित न्यूपा – परियोजना भर्ती और नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

पीएमयू विभिन्न परियोजनाओं के लेखांकन, परियोजना स्टाफ की भर्ती, बजट के अलावा विश्वविद्यालय में चल रहे और पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्य का देखभाल करता है।

पीएमयू एकक में अध्यक्ष, कुलपति द्वारा चयनित किया जाता है। इसके अलावा पांच अन्य अकादमिक तथा समर्थन स्टाफ भी चयनित किये जाते हैं। समर्थन स्टाफ में परियोजना परामर्शदाता, परियोजना प्रबंधक तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सम्मिलित हैं। एकक के अध्यक्ष प्रो. के. बिस्वाल हैं।

Hkkjr vÝhdk
l aLFkku

Hkkjr vÝhdk 'kS{kd ;kstuk ,oa iz'kklu laLFkku ¼vkbZ,-vkbZbZih,½% भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान अप्रैल 2008 में आयोजित भारत–अफ्रीका मंच सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई कार्यवाई योजना के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अखिल अफ्रीकी संस्था है। यह संस्थान बुरूण्डी गणराज्य की राजधानी बुजुम्बुरा में स्थित है।

इसके प्रथम चरण में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी (i) अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (ii) शैक्षिक नीति शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्‌दों पर शोध और केस अध्ययन (iii) देश और क्षेत्र/महाद्वीप स्तरों पर शिक्षा के विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और आकलन (iv) अफ्रीका संघ देशों को क्षमता विकास और शोध से संबंधित विशिष्ट शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना। (v) अफ्रीकी संघ देशों में शैक्षिक योजना और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर अनुभवों और कार्य व्यवहारों को साझा करना (vi) अफ्रीका और अफ्रीका के बाहर के शिक्षा शोध से जुड़े शोधकर्त्ताओं तथा संस्थानों का नेटवर्क बनाना। (vii) सामान्यतः शैक्षिक विभाग और विशेषकर अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर नीतिगत परिसंवाद।

इसके प्रथम चरण के दौरान आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों के विस्तार के साथ दूसरे चरण के दौरान संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन पर लम्बी अवधि का उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें अफ्रीका संघ सदस्य देशों के प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों में बढ़ोतरी के लिये समिश्रित उपागम पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

v d kn fe d v u q e Fkk Z l so k , d d

i qLrd ky ; v kS i z y s[ku d sUnz% राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक अत्याधुनिक पुस्तकालय है जिसमें शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन और अन्य सहायक विषयों से संबंधित पुस्तकों और अन्य सामग्री का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र अपने पाठकों को विभिन्न सेवाएं जैसे–सीएएस, एसडीआई, संदर्भ सेवाएं वेब ओपैक, प्रसारण और फोटोकापी की सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेलनेट का सदस्य भी है। वर्तमान में पुस्तकालय में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे–यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, यूनीसेफ, विश्व बैंक, ओईसीडी आदि द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों की रिपोर्टों के अलावा 55000 से अधिक पुस्तकों/दस्तावेज़ों तथा 6,435 जर्नलों का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय में शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन तथा अन्य सहायक क्षेत्रों से संबंधित 240 जर्नल मंगाए जाते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय पाठकों के लिए ऑन लाइन जर्नल डाटाबेस, जैसे–जेएसटीओआर, एलसेवियर और सेज भी मंगाता है। न्यूपा के प्रलेखन केंद्र में अधिकारिक रिपोर्टों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रकाशनों, शैक्षिक सर्वेक्षणों, पंचवर्षीय योजनाओं और जनगणना रिपोर्टों आदि सहित लगभग 18,500 दस्तावेज हैं। प्रलेखन केंद्र के पास महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हैं जो शैक्षिक शोध और नीति निर्माण के लिए जरूरी हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक डिजीटल अभिलेखागार बनाया गया है। भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों, स्तरों और पक्षों पर शोध और संदर्भ के स्रोत के रूप में एक स्थान पर सभी दस्तावेजों की साफ्टकापी सुलभ करवाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोक्ता समुदाय का निर्माण करना है जो कि विश्वविद्यालय के कार्यों का एक विस्तार है। नवीनतम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में उच्च स्तरीय स्वचालित डिजीटल स्कैन का उपयोग डिजाइन, संग्रह और डिजीटल दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस डिजीटल अभिलेखागार में प्रयोक्ता सुलभ बहुखोजी विकल्पों के साथ अंतर्निहित उपयोगों सहित साफ्टवेयर उपलब्ध है।

वर्ष 2013 में शैक्षिक प्रलेखों का एक **fMt hVy v fHky s[kkxkj** स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी शैक्षिक प्रलेखों को एक स्थान पर डिजीटल रूप में संग्रहित करना है। डिजीटल अभिलेखागार में 8000 से अधिक अभिलेख संग्रहित हैं और सतत् इनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। प्रलेखों को मुख्यतः 18 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और इसी क्रम में आगे भी केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर उप वर्ग बनाए गये हैं। डिजीटल अभिलेखागार में आज़ादी के बाद से शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों तथा क्षेत्रों से

संबंधित नीतिगत तथा अन्य अभिलेख सुलभ करवाए जाते हैं ताकि नीति विश्लेषकों, योजनाकारों, शोधार्थियों एवं अभिरूचि रखने वाले अन्य विद्वानों को एक स्थान पर आवश्यक सामग्री सुलभ करवाई जा सके और उन्हें संदर्भ सामग्री और आंकड़ों के लिए कहीं और नही जाना पड़े। डिजीटल अभिलेखागार न्यूपा का विस्तारित कार्य है जो प्रयोक्ता समुदाय को समर्पित है।

d a; Wj d anz % कंप्यूटर केंद्र विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतें पूरा करता है। यह केंद्र विश्वविद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करता है। नेटवर्क संसाधन को पहुंचाने के लिए सभी संकाय और स्टाफ को नेटवर्क प्वांइट सुलभ किए गए हैं। न्यूपा डोमेन से सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों के व्यक्तिगत ई–मेल खाता खोले गए हैं। सभी संकाय सदस्यों को 1 जीबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्कटॉप और संकाय सदस्यों को लैपटाप आवंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय में समुचित नेटवर्क सुरक्षा का रखरखाव किया जा रहा है। केंद्र में आधुनिकतम सुविधाएं हैं, जैसे–आईबीएम–ई सिरीज सर्वर जो तीव्र अर्थनेट से जुड़ा है। वर्तमान में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं हैं–उन्नत कैट–6 केबल, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा, जिसमें उच्च कार्यनिष्पादन वाले सर्वर्स, क्लाइंट पी सी, इंटरनेट से अपलिंक और अन्य सेवाएं और अति सक्षम बहुकल्पिक यू पी एस के जरिए पर्याप्त रूप में अनवरत पावर आपूर्ति उपलब्ध है।

i zd k'ku , d d % न्यूपा में शिक्षा के शोध और विकास के प्रसार– प्रचार हेतु प्रकाशन कार्यक्रम है। न्यूपा प्रकाशन एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संबंधित सामग्रीरिपोर्टों, पुस्तकों, जर्नलों न्यूज़लेटर, अनुसंधान आलेखों, तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं : जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 'परिप्रेक्ष्य' हिन्दी जर्नल तथा एंट्रीप न्यूज़लेटर इत्यादि। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रकाशन एकक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है।

fg anh d {k % यह कक्ष शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में व्यावसायिक प्रकाशनों के अनुवाद के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी प्रशासन और संकाय को सहयोग देता है।

v fHk' kkl u v kS i zca/ku

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत घोषित एक मानद विश्वविद्यालय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शामिल हैं : अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, परिषद, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा घोषित ऐसे अन्य प्राधिकरण। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।

U; iwk i fj 'kn % न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। परिषद का मुख्य कार्य कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को कार्यान्वित करना है। न्यूपा परिषद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभी मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण का उत्तरदायी है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार न्यूपा परिषद के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति इसके उपाध्यक्ष हैं। परिषद के पदेन सदस्य हैं : सचिव, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और वित्त सलाहकार, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार। परिषद के अन्य सदस्य हैं– अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विख्यात शिक्षाविद्, अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/संघ

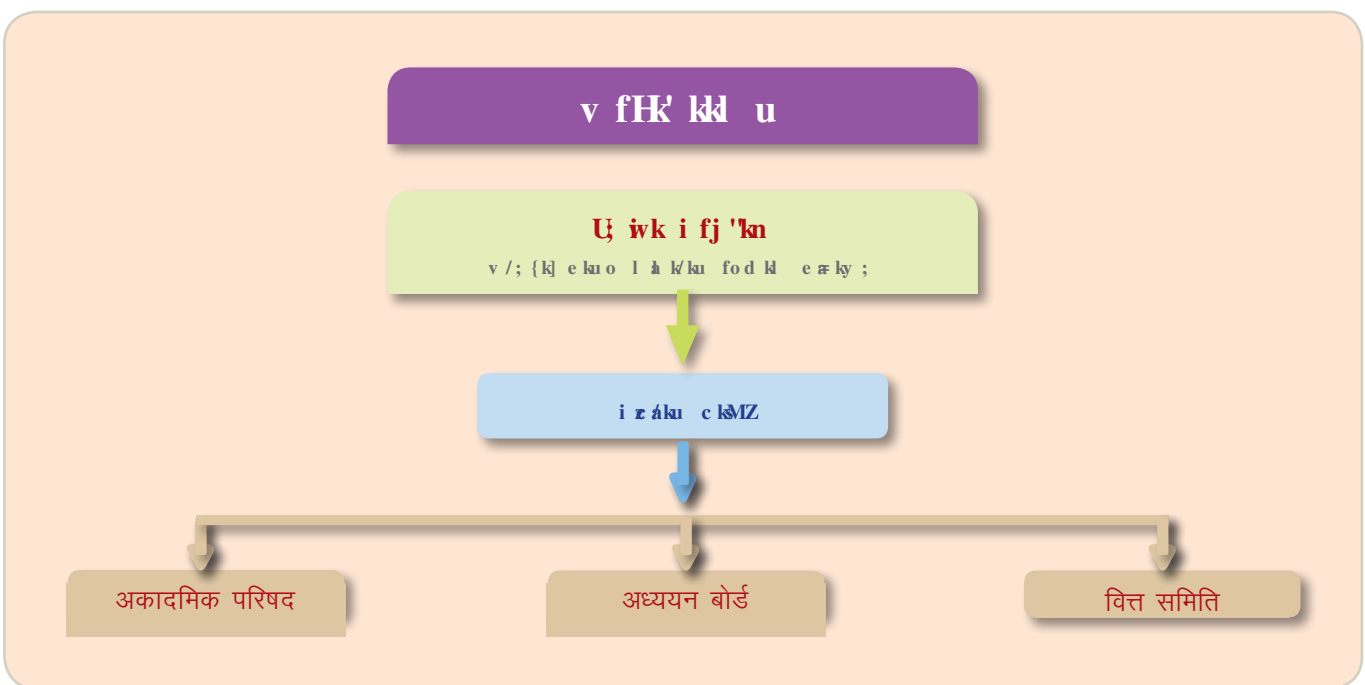

क्षेत्र प्रतिनिधि (5 प्रभागों में से प्रत्येक प्रभाग से एक–एक प्रतिनिधि) और अध्यक्ष द्वारा नामित न्यूपा संकाय का एक सदस्य। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव परिषद के सचिव हैं। दिनांक 31 मार्च 2015 के अनुसार न्यूपा परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–I में प्रस्तुत है।

izca/ku cksMZ % प्रबंधन बोर्ड राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। राष्ट्रीय विश्वद्यिालय के कुलपति प्रबंध बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य हैं : राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन सदस्य मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामिती, वि.अ.आ. के अध्यक्ष का एक नामिती, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय डीन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दो संकाय सदस्य (एक प्रोफेसर और एक सह–प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर), कुलसचिव, न्यूपा, प्रबंधन बोर्ड का सचिव होता है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

foÙk lfefr % वित्त समिति की मुख्य भूमिका विश्वविद्यालय की लेखा की जांच करना और व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा और वित्तीय आकलनों को वित्त समिति के सम्मुख रखा जाता है और समिति की टिप्पणियों के साथ इसे अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वार्षिक आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय की सीमाऐं तय करती है। विश्वविद्यालय के कुलपति वित्त समिति के पदेन अध्यक्ष हैं; इसके अतिरिक्त न्यूपा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि होता है। वित्त अधिकारी, वित्त समिति के सचिव का कार्य करता है। 31 मार्च 2015 के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–III में दी गई है।

vdknfed ifj'kn % न्यूपा अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का शीर्षस्थ अकादमिक निकाय है। अकादमिक परिषद शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श के स्तर पर सतत सुधार और अंतर–विभागीय सहयोग, परीक्षा और परीक्षण आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका पदेन अध्यक्ष कुलपति होता है। अकादमिक परिषद में शामिल हैं : विश्वविद्यालय के संकाय डीन, अकादमिक विभागों के अध्यक्ष, और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन शिक्षाशास्त्री जो विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित हों और विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा चक्रानुसार नामित एक सहायक प्रोफेसर और तीन सहयोजित सदस्य जो शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य न हों और अकादमिक परिषद द्वारा विषय विशेषज्ञ के आधार पर सहयोजित किए गए हों। न्यूपा का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है। 31 मार्च 2015 के अनुसार सदस्यों की सूची–IV में दी गई है।

v/;;u cksMZ % न्यूपा के कुलपति अध्ययन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य हैं: संकाय–डीन, विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित एक सह–प्रोफेसर, और एक सहायक प्रोफेसर और कुलपति द्वारा सहयोजित अधिकतम दो विषय विशेषज्ञ। अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की सूची 31 मार्च, 2015 के अनुसार परिशिष्ट–V में दी गई है।

dk;Zy vkSj lfefr;ka % कुलपति द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। कुलपति की अध्यक्षता में शोध अध्ययन सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इसमें अन्य विशेषज्ञों के साथ–साथ सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुलसिचव इस समिति के सदस्य सचिव हैं जो सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है।

i z'kklu vkSj

foÙk

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में तीन अनुभाग–अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन और दो कक्ष–प्रशिक्षण कक्ष और समन्वय कक्ष हैं। कुलसचिव के सभी अनुभागों के प्रभारी हैं। कुलसचिव न्यूपा परिषद, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सचिव भी हैं। कुलसचिव को प्रशासनिक कामकाज में प्रशासनिक अधिकारी और अनेक अनुभाग अधिकारी अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

कुलसचिव अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एककों, जैसे–पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, प्रकाशन एकक, मानचित्रण और हिंदी कक्ष के कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी हैं। वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग के प्रभारी है। अनुभाग अधिकारी (लेखा) वित्त अधिकारी का अनुसमर्थन करता है।

LVkQ dh la[;k ¼2014&15½

31 मार्च, 2015 के अनुसार विश्वविद्यालय की कुल स्टाफ संख्या 162 थी।

वर्ष 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय को कुल 2718.57 लाख रुपये का अनुदान मिला (गैर–योजना मद में 1511.60 लाख रुपये और योजना मद में 1206.97 लाख रु. प्राप्त हुए। वर्ष के आरंभ में विश्वविद्यालय के पास योजना और गैर–योजना, दोनों मदों में 142.50 लाख रुपये शेष थे। वर्ष के दौरान कार्यालय और छात्रावास से 71.75 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। योजना और गैर–योजना मदों में इस वर्ष का व्यय 2882.75 लाख रुपये था।

दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों की मद में इस वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के पास 268.02 लाख रुपये थे और 987.95 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्ति हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर वर्ष में कुल 579.69 लाख रुपये खर्च किए गए। (परिशिष्ट–VII)

i fj l j v k$ Hkou v kèkkj Hkw l fo èkk

विश्वविद्यालय के पास एक चार–मंजिला कार्यालय, सुसज्जित स्नानघरयुक्त 60 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास और एक आवास–क्षेत्र है। इस आवास क्षेत्र में टाइप–I के 16, टाइप–II से V तक के 8–8 क्वार्टर और एक कुलपति आवास हैं।

विश्वविद्यालय के पास बिंदापुर, द्वारका में टाइप–III के 25 क्वार्टर हैं।

विश्वविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर केंद्र, अंतरराष्ट्रीय डायनिंग हाल, जिम और क्लास रूम हैं।

विश्वविद्यालय ने परिसर में हाल ही में अर्जित 2100 वर्ग मीटर के भूखंड में नया अकादमिक भवन के निर्माण के लिये अपेक्षित कदम उठाए हैं। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लीज डीड जारी कर दिया है।

2 अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

v/;kiu vkSj Q;kolkf;d fodkl dk;Øe

,e-fQy vkSj ih&,p-Mh-

,e-fQy vkSj ih&,p-Mh- dk;Øe foftkUu i`"BHkwfe ds 'kks/kkdfe;ksa dh 'kks/k {kerk ds fuekZ.k ds fy, fMtkbu fd, x, gSa tks 'kSf{kd uhfr] ;kstuk iz'kklu rFkk foÙk ds lacaf/kr {ks=ksa esa O;kid Kku vkSj dkS'ky iznku djrs gSaA

शैक्षिक प्रशासन के लिए विद्वान तैयार करना

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक फीडर संस्थान है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जरूरत के अनुसार शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में विशेषज्ञता से युक्त मानव संसाधनों का विकास करता है। ऐसे विशेषज्ञ जो अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों/एम.फिल. और पी–एच. डी. उपाधियों के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा तैयार किये जाते हैं वे व्यापक एवं गतिशील संदर्भों में समुचित योजनाओं और कार्यनीतियों के निर्माण या सांस्थानिक प्रबंधन के सीमित भूमिकाओं से जुड़े मामलों के समाधान हेतु पूर्णतः सक्षम होते हैं। वस्तुतः विश्वविद्यालय की एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा विश्वविद्यालय युवा शोधकर्त्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है और शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उनका करियर तैयार करता है। न्यूपा यह कार्य कर रहा है और इसके माध्यम से यह शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने हेतु विशेषज्ञ और सक्षम मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रमों का महत्व इसमें अंतर्निहित गतिशील और लचीले उपागम के द्वारा है जिसमें यह शिक्षा और सामाजिक विकास की अन्य सहायक क्षेत्रों से जुड़कर नवाचारी बहुशास्त्रीय पाठ्यक्रमों का विस्तार करता है।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रम में शामिल हैं: (i) पूर्णकालिक एम.फिल. कार्यक्रम (ii) पूर्णकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम और (iii) अंशकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में आरंभ किए गए थे। एम.फिल और पी–एच.डी. कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्मियों की शोध क्षमता के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शैक्षिक नीति, योजना प्रशासन तथा वित्त के संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान

और कौशल प्रदान करते हैं। एम.फिल और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे किए गए शोध अध्ययनों से अपेक्षा की जाती है कि ये नीति निर्माण, शिक्षा सुधार कार्यक्रमों तथा क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ–साथ ज्ञान आधार को समृद्ध करने में भारी योगदान करेंगे। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत शोध के व्यापक क्षेत्रों में शामिल हैं–शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा में समता और समावेशन, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, अल्पसंख्यक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा और शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण।

एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष है। इस दो वर्षीय एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष का पाठ्यक्रम कार्य (30 क्रेडिट) है। इसके बाद एक वर्ष लघु शोध प्रबंध (30 क्रेडिट) के लिए है। दो वर्ष के एम.फिल. पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत और निर्धारित आर्हता (वर्तमान में 10 प्वाइंट स्केल पर) 6 एफ जी पी ए या इससे अधिक का ग्रेड पाने वाले शोधार्थी पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि के दो वर्ष बाद ही शोधार्थी अपने शोध प्रबंध जमा करा सकते हैं।

पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को दाखिला की पुष्टि हेतु एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। इसके बाद वे दो वर्ष के शोध कार्य के उपरांत ही वे उपाधि हेतु शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं।

अंशकालिक पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को पी–एच.डी. में दाखिला की पुष्टि से पहले एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। अंशकालिक पी–एच.डी. के शोधार्थी दाखिला की पुष्टि के कम से कम चार वर्ष बाद अपना शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं।

foojk	,e-fQy-	ih&,p-Mh- iw.kZdkfyd	ih&,p-Mh- va'kdkfyd	;ksx
वर्ष 2014–15 में नामांकन	19	11	02	32
वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की संख्या	25 (वर्ष 2013–14 में नामांकित 8 विद्यार्थियों सहित)	30 (वर्ष 2007–08 से नामांकित विद्यार्थियों सहित)	03 (वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक नामांकित विद्यार्थी)	68
वर्ष 2014–15 के दौरान उपाधि योग्य घोषित विद्यार्थियों की कुल संख्या	09	05	0	14

fMIy kek dk;Øe

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्ष 1982–83 से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में विशेष रूप से डिजाइन, डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। आरंभ में यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया था।

'kS{kd ;kstuk vkS iz'kklu esa LukrdksÙkj fMIyksek ¼ih th Mhbik½

यद्यपि वर्ष 2014–15 से इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को संवर्धित करके इसे परिवर्तन किया गया है और इसके मूलभूत डेपा से पीजीडेपा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन)– शैक्षिक योजना और प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा) में बदल दिया गया है। प्रतिभागियों के कार्य और भूमिकाओं तथा उनकी संस्थाओं जैसे एससीईआरटी/सीमेट/डाइट/डीईओ/बीईओ और राज्य सरकारों के शिक्षा निदेशालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को संबर्धित किया गया है।

पीजीडेपा कार्यक्रम को मौजूदा डेपा में व्यापक रूपांतरण के बाद निर्मित किया गया है जो एक सघन दीर्घकालिक कार्यक्रम है जो देश में पेशेवर रूप से शैक्षिक प्रशासकों का संवर्ग का विकास सुनिश्चित करेगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(i) शैक्षिक योजना और प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना।

(ii) शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर निर्णय कार्य के लिए प्रतिभागियों में योजना और प्रबंधन कौशल के विकास हेतु सक्षम बनाना।

(iii) प्रतिभागियों में योजना निर्माण, कार्यक्रम निरूपण और कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रबंधन संबंधी कौशल और योग्यता का विकास करना।

(iv) प्रतिभागियों में शैक्षिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के छ : घटक हैं: (I) पाठ्यक्रम तैयारी कार्य (II) आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य (III) परियोजना कार्य (IV) परियोजना कार्य का मूल्यांकन और अंतरिम प्रमाण पत्र विवरण और (V) उन्नत पाठ्यक्रम कार्य और (VI) अंतिम मूल्यांकन और पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र वितरण।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम का निरूपण करते समय मूलतः इस बात का ध्यान दिया गया था कि प्रतिभागी को इस पाठ्यक्रम के लिए न्यूपा में तीन माह से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े और वह अपने कार्य स्थल पर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। इसके अनुसार इसे 12 महीने के पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम में रूपातंरित किया गया है। अनेक शिक्षा विभाग इस पाठ्यक्रम हेतु अपने अधिकारियों को लंबी अवधि के लिए प्रतिनियुक्त नहीं कर सकते हैं इसलिए पीजीडेपा कार्यक्रम को इस रूप में नियोजित किया गया है कि आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य हेतु प्रतिभागियों को न्यूपा में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: कार्यस्थल पर पाठ्यक्रम तैयारी कार्य, न्यूपा में आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य, कार्यस्थल पर परियोजना कार्य, मुक्त और दूरवर्ती

r kfy d k 2.1

' kS{ kd ; kst uk v kS Á' kk u es a j k'Vªh; fMIy kse k ¼Mi s k½ d k; Øe ea j kT; @l ak {ks= o kj Hkkx hn kj h

j kT; @ l ak {ks=	34 o ka Mi s k	ÁFke i ht h Mi s k	; ksx
आंध्रप्रदेश	-	1	1
अरूणाचल प्रदेश	1	1	2
असम	-	4	4
बिहार	3	3	6
हरियाणा	-	1	1
हिमाचल प्रदेश	2	2	4
जम्मू और कश्मीर	2	1	3
कर्नाटक	1	-	1
मध्यप्रदेश	4	4	8
मणिपुर	3	3	6
मिजोरम	2	-	2
नागालैंड	1	2	3
पंजाब	-	1	1
तमिलनाडु	-	5	5
राजस्थान	1	-	1
सिक्किम	2	-	2
उत्तराखंड	3	2	5
उत्तरप्रदेश	-	1	1
पश्चिम बंगाल	-	1	1
दिल्ली	-	1	1
; ksx	**25**	**33**	**58**

अधिगम प्रणाली के द्वारा उन्नत पाठ्यक्रम और न्यूपा में संगोष्ठी सहित कार्यशाला में परियोजना कार्य प्रस्तुति।

पीजीडेपा के पाठ्यक्रम कार्य निम्नलिखित चरणों में संपादित किए जाते हैं :

चरण 1 : पाठ्यक्रम तैयारी कार्य (कार्य स्थल)

चरण 2 : आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य (न्यूपा)

चरण 3 : परियोजना कार्य (कार्य स्थल)

चरण 4 : परियोजना कार्य का मूल्यांकन और अंतरिम प्रमाण पत्र वितरण (न्यूपा)

चरण 5 : उन्नत पाठ्यक्रम कार्य (कार्य स्थल)

चरण 6 : अंतिम मूल्यांकन और पीजीडेपा प्रमाण पत्र वितरण (न्यूपा)

प्रथम पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम में 16 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 33 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका प्रथम चरण कार्य स्थल पर पाठ्यक्रम की तैयारी कार्य 1–30 सितंबर 2014 को आयोजित किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय ने 34वें डिप्लोमा कार्यक्रम के तीसरे घटक का आयोजन 5–9 मई 2014 (5 दिन) को किया जिसका पहला घटक 1 सितंबर–30 नवंबर 2014 तक (91 दिन) आयोजित किया गया था। 34वें डिप्लोमा कार्यक्रम के तीसरे घटक को 25 प्रतिभागियों ने पूरा किया।

प्रथम घटक के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 नवंबर 2014 तक (91 दिन) अध्यापन–अधिगम कार्य किया गया और दूसरा घटक 1 दिसंबर 2014 से 28 फरवरी 2015 तक किया गया।

डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग ने किया। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राज्यवार भागीदारी का विवरण तालिका 2.1 में प्रदर्शित है :

' kS{ kd ; kst uk v kS i z'kk u es a v a rjk'Vªh; fMIy kse k ¼v kbZMi s k½

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1985 से विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में 6 माह का अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के विद्यार्थी एशिया, अफ्रीका, मध्य एशियाई गण

राज्यों, दक्षिणी अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों से आते हैं। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं– (i) सघन पाठ्यचर्चा कार्यक्रम; (ii) अनुप्रयुक्त कार्य और (iii) लघु शोध प्रबंधन। आईडेपा की अवधि छः माह है और यह दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में तीन माह का सघन पाठ्यचर्या है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह चरण आवासीय है और प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस चरण के दौरान परिसर में निवास करें। दूसरे चरण में प्रतिभागी को स्वदेश में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में क्षेत्र आधारित शोध परियोजना अध्ययन करना होता है।

आईडेपा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में केंद्रिक पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक अभिविन्यास और अप्रयुक्त कार्य शामिल हैं। पाठ्यचर्या कार्य के विषय हैं : शिक्षा और विकास से संबंधित अध्ययन, विकासशील देशों में शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र, शैक्षिक योजना और प्रशासन परियोजना नियोजन, शिक्षा में व्यष्टि स्तरीय योजना शिक्षा में, वित्तीय योजना और प्रबंधन, जनशक्ति योजना, शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकें, शैक्षिक प्रबंधन, शोध प्रविधि और सांख्यिकी और शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रणाली। अनुप्रयुक्त कार्य में शामिल हैं : विषयगत संगोष्ठियां डिप्लोमा कार्यक्रम के अभिन्न घटक हैं जो प्रत्येक प्रतिभागी या प्रतिभागियों के समूह को शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित विषयों से जुड़े वस्तुगत आंकड़ा और अनुभवों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने और उनका परस्पर आदान–प्रदान करने के अवसर प्रदान करती हैं। संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में प्रतिभागियों को अपने देश की शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने और परस्पर आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को स्वदेश में उनके कार्यों की प्रासंगिकता और जरूरतों के विशिष्ट क्षेत्र में शोध परियोजना की रूपरेखा बनाने में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशलों के बीच संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में चरण–II के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी के लिए एक शोध निर्देशक नियुक्त किया जाता है जो दूसरे चरण के कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी के परियोजना कार्य का निर्देशन करता है।

कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रतिभागी के स्वदेश में आयोजित होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रथम चरण के दौरान निर्धारित क्षेत्र कार्य आधारित शोध परियोजना पर कार्य करना पड़ता है। शोध परियोजना कार्य (तीन माह की अवधि) पूरा करने के बाद प्रतिभागी को अपना लघुशोध प्रबंध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना पड़ता है। लघु शोध प्रबंध की प्राप्ति और तदुपरांत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी को डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2014–15 के दौरान विश्वविद्यालय ने 30वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का दूसरा चरण पूरा किया जिसका प्रथम चरण 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2014 को आयोजित किया गया था। उसमें 17 देशों के 27 प्रतिभागी शामिल हुए। 30वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2014 के दौरान आयोजित किया गया।

31वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रथम चरण 1 फरवरी 2015 को शुरु हुआ और इसके प्रथम घटक की अध्यापन–अधिगम गतिविधियां 30 अप्रैल 2015 तक पूरी की गईं। 31वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में 15 देशों से कुल 28 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2015 के दौरान प्रतिभागियों के स्वदेश में नियत किया गया जो परियोजना कार्य पर आधारित था।

अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग करता है।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों की देशवार भागीदारी का विवरण तालिका 2.2 में प्रदर्शित है।

rkfydk 2.2

30oas vkSj 31oas varjjk"Vªh; fMIyksek dk;Øeksa esa ns'kokj Hkkxhnkjh			
ns'k	30 okW vkbZMhih	31 okW vkbZMhih	;ksx
बांग्लादेश	3	3	6
भूटान	3	-	3
कंबोडिया	-	1	1
इथियोपिया	-	2	2
फिजी	-	2	2
घाना	1	2	3
लाइबेरिया	1	-	1
मलेशिया	1	-	1
मालदीव	1	-	1
मारीशस	-	1	1
मंगोलिया	-	1	1
म्यांमार	-	4	4
नेपाल	-	1	1
नाइजीरिया	-	1	1
नाइजर	2	2	4
फिलीस्तीन	1	-	1
पपुआ न्यू गिनी	1	-	1
फिलीपीन्स	2	-	2
रवान्डा	1	-	1
श्रीलंका	2	2	4
दक्षिण सूडान	1	-	1
तंजानिया	1	3	4
तुनिशिया	-	2	2
यूगांडा	2	-	2
उज़्बेकिस्तान	1	-	1
यमन	-	1	1
जाम्बिया	3	1	4
;ksx	27	29	56

rkfydk 2.3

lHkh dk;Øeksa esa ns'kokj Hkkxhnkjh		
Ø-la	ns'k	Hkkxhnkjksa dh la[;k
1.	आस्ट्रेलिया	1
2.	बांग्लादेश	3
3.	भूटान	3
4.	ब्राजील	1
5.	कनाडा	1
6.	चीन	1
7.	घाना	1
8.	इंडोनेशिया	11
9.	केन्या	1
10.	लाइबेरिया	1
11.	मलाया	1
12.	मालदीव	1
13.	नेपाल	1
14	नाइजीरिया	1
15.	नीदरलैंड	1
16.	नाइजर	2
17.	पाकिस्तान	2
18.	फिलीस्तीन	1
19.	पपुआ न्यू गिनी	1
20.	फिलीपीन्स	2
21.	रवान्डा	1
22.	रूस	1
23.	श्रीलंका	2
24.	दक्षिण सूडान	1
25.	तंजानिया	1
26.	यूगांडा	4
27.	संयुक्त राज्य अमेरिका	3
28.	यूनाईटेड किंगडम	12
29.	उज़्बेकिस्तान	1
30.	जाम्बिया	4
	;ksx	67

r kfy d k 2.4

Q;kol kf; d fod kl d k;Øe ka e a jkT; @ l a?k 'kkfl r {ks=ka o kj Hkkx hn kj h

Ø- l a	jkT; @l a?kh; {ks=	Hkkx hn kj ka d h l a ; k
1.	आंध्र प्रदेश	136
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	372
4.	बिहार	248
5.	छत्तीसगढ़	131
6.	गोवा	8
7.	गुजरात	140
8.	हरियाणा	285
9.	हिमाचल प्रदेश	150
10.	जम्मू और कश्मीर	74
11.	झारखण्ड	67
12.	कर्नाटक	220
13.	केरल	66
14.	मध्य प्रदेश	64
15.	महाराष्ट्र	197
16.	मणिपुर	26
17.	मेघालय	13
18.	मिजोरम	17
19.	नागालैण्ड	14
20.	ओडिशा	94
21.	पंजाब	284
22.	राजस्थान	412
23.	सिक्किम	28
24.	तेलगांना	34
25.	तमिलनाडु	48
26.	त्रिपुरा	20
27.	उत्तराखंड	32
28.	उत्तर प्रदेश	417
29.	पश्चिम बंगाल	53
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
31.	चंडीगढ़	26
32.	दादरा और नगर हवेली	5
33.	दमन और दीव	8
34.	दिल्ली	531
35.	पुडुचेरी	5
; ksx		**4,240**

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार हेतु सांस्थानिक क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों के शिक्षाकर्मियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकलाप के रूप में सतत जारी है। वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा के विभिन्न विकास क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और शिक्षा नीति योजना, प्रशासन के विविध पक्षों से जुड़े 104 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के विषय थे : स्कूलों की योजना और प्रबंधन, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन, माध्यमिक स्तर पर स्कूल प्रावधानों का आकलन, शैक्षिक वित्त की योजना और प्रबंधन, और स्कूल नेतृत्व आदि। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी थे जिला और राज्य स्तर के शिक्षाकर्मी, शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर के अन्य अधिकारी, केंद्र, राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और अन्य प्राधिकारी, कालेज प्राचार्य और कालेजों तथा उच्च शिक्षा के वरिष्ठ प्रशासक, विश्वविद्यालय तथा समाजविज्ञान शोध संस्थानों के नवनियुक्त प्राध्यापक आदि। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न

विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गईं :

'kS{kd ;kstuk fo Hkkx

- उत्तर पूर्वी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की योजना में अनुवर्ती मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यशाला, गुवाहाटी (असम), 08–12 सितम्बर, 2014
- जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, चेन्नई (तमिलनाडु), 08–13 दिसम्बर, 2014
- जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ओडिशा, भुवनेश्वर (ओडिशा) 22–27 दिसम्बर, 2014
- शिक्षा में मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 05–15 जनवरी, 2015

'kS{kd izkd u fo Hkkx

- जेपी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुरोध कार्यक्रम), 09–13 जून, 2014
- जिला और उप जिला स्तर के शैक्षणिक प्रशासकों के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 20–22 अगस्त, 2014
- जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 08–12 सितम्बर, 2014

- राज्य–स्तर शैक्षणिक प्रशासकों के लिए प्रबंधन विकास पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 22–26 सितम्बर, 2014
- जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की योजना और प्रबंधन पर कार्यशाला, 12–14 नवम्बर, 2014 साथ ही तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए अध्यक्ष का दौरा, 12–14 फरवरी, 2015
- सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार केन्द्र (सीप्स), हैदराबाद भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक योजना और प्रशासन में नवाचार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मेलन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 28–29 नवम्बर, 2014
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम, 01–05 दिसंबर, 2014
- तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासनिक सर्वेक्षण की क्षेत्रीय कार्यशाला हैदराबाद, 15–17 दिसम्बर, 2014
- तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण, 12–14 फरवरी, 2015 को क्षेत्रीय कार्यशाला
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में विविधता और समता का प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 16–20 मार्च, 2015
- सीमांत समूहों की शिक्षा की नीतियां, कार्यक्रम और चुनौतियां पर अंतराष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला शिक्षा, 25–27 मार्च, 2015

'kS{kd fo Ùk fo Hkkx

- स्कूल वित्त की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 01–05 सितंबर, 2014
- दक्षिण एशिया की उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में वैश्विक रूझान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 23–25 फरवरी, 2015

'kS{kd uhfr foHkkx

- शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी 2012 विधेयक पर अभिविन्यास कार्यशाला, 30 जून – 4 जुलाई 2014
- शिक्षा में 'गुणात्मक अनुसंधान की विधियां पर उन्मुखीकरण कार्यशाला, 21 जुलाई से 8 अगस्त 2014
- प्राथमिक स्तर वंचित बच्चों की शिक्षा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) पर नीतिगत मुद्दों और कार्यक्रम हस्तक्षेप पर अभिविन्यास कार्यक्रम 25–29 अगस्त, 2014

- शिक्षा के क्षेत्र में लोकनीति बनाने पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 17–21 नवम्बर, 2014
- शिक्षा के क्षेत्र में नीति प्रक्रियाओं के साथ रचनात्मक संलग्नता पर परामर्शदात्री बैठक, 24–25 नवम्बर, 2014
- माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर सामाजिक रूप से वंचित समूह की शिक्षाः नीतिगत मुद्दों और कार्यक्रम हस्तक्षेप पर कार्यशाला, 08–12 दिसम्बर, 2014
- उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकारी और स्वायत्त परिषद के कार्य पर अभिविन्यास कार्यक्रम, गुवाहाटी/कोहिमा, 2–6 फरवरी, 2015
- जनभागीदारी और विकेंद्रित शैक्षिक अभिशासन नीतिगत सुधार और कार्यक्रम कार्यान्वयन पर द्वितीय अनिल बोर्डिया संगोष्ठी, 16–17 फरवरी, 2015

fo|ky; vkSj vukSpkfjd f'k{kk foHkkx

- डीईओ और बीइओ के राज्य स्तरीय सम्मेलन भुवनेश्वर, ओडिशा, 08–09 मई, 2014
- राष्ट्रीय तकनीकी समूह के साथ बैठक 19 जुलाई, 2014
- समुदाय संलग्नता के द्वारा शिक्षा का रूपांतरण पर संगोष्ठी, 22 जुलाई, 2014
- उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए प्रारंभिक स्तर, पर बच्चों की स्कूल भागीदारी में सुधार पर कार्यशाला 4–8 अगस्त, 2014
- दक्षिणी राज्यों के लिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्कूल भागीदारी में सुधार पर कार्यशाला, 08–12 सितम्बर, 2014
- शिक्षा का अधिकार पर दो अभिविन्यास कार्यक्रम, 15–19 सितम्बर, 2014 और 13–17 अक्टूबर, 2014

- विद्यालय मानक और मूल्यांकन पर लघु समूह कार्यशाला, 12 सितम्बर, 2014
- विद्यालय मानक और मूल्यांकन पर तीन कार्यशाला 30–31 अक्टूबर, 2014
- प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों की भागीदारी पर कार्य परियोजना के लिए अनुवर्ती कार्यशाला, 10–14 नवंबर 2015।
- स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 27–28 नवंबर, 2014
- ईसीसीई और स्कूल शिक्षा के बीच संबंध पर कार्यशाला, 29 दिसंबर, 2014 से 2 जनवरी 2015

- एन पी एस एस ई पर राष्ट्रीय बैठक और एसएलई फ्रेमवर्क का उद्घाटन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी 2015

mPp r j , oa Q ko l kf; d f' k{kk fo Hkkx

- पूर्वोत्तर राज्यों के कालेज प्राचार्यों के लिए उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, नेहू, शिलांग, 16–20 जून 2014
- महिला कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की योजना और प्रबंधन पर ए एस सी, जबलपुर में पुनश्चर्या कार्यक्रम, 17–21 नवम्बर, 2014
- पूर्वोत्तर भारत में शिक्षण–अधिगम क्षमता विकास पर पी जी अध्यक्षों/संकायाध्यक्षों की कार्यशाला, पटना विश्वविद्यालय, 8–12 दिसंबर, 2014
- उच्च शिक्षा में 'निजीकरण पर कार्यशाला', 25 भागीदार, 15–18 दिसंबर, 2014
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और अभिशासन पर कार्यशाला, 19–21 दिसम्बर, 2014
- उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 12–14 जनवरी, 2015
- उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 12–14 मार्च, 2015

' kS{ kd i z ák u l pu k i z kky h fo Hkkx

- शैक्षिक विकास सूचकांक पर राष्ट्रीय कार्यशाला (ईडीआई)
- यूनिफाइड–डाईस पर कार्यशाला
- स्कूल के बाहर बच्चों पर तकनीकी परामर्श, 29 अगस्त 2014
- माध्यमिक शिक्षा की योजना और निगरानी में संकेतकों का प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, गांधीनगर (गुजरात), 15–19 दिसम्बर, 2014

' kS{ kd i f' k{k. k v kS {ke r k fod kl fo Hkkx

- इंडोनेशिया के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रबंधन पर लघु कोर्स, 14–25 अगस्त, 2014
- एकलव्य आदर्श आवासीय संस्थानों के प्रधानाध्यापकों (ईएमआरआईएस) और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, नासिक (महाराष्ट्र) के लिए मॉडल संस्थागत योजनाओं के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 22–27 सितम्बर, 2014
- डीईओ/बीईओ/डीआईओएस के लिए, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन, हरियाणा– 03–04 जनवरी, 2015, गुवाहाटी (असम)– 21–22 जनवरी, 2015 और मोहाली (पंजाब)– 28–29 जनवरी, 2015
- असम शिक्षा सेवाओं के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, गुवाहाटी, 06–11 जनवरी, 2015

j k'Vh; fo| ky ; us Ro d sanz

केंद्र की 2014–15 में स्तर–वार गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

Lr j &1 %i kB~; p ; kZ v kS l ke x h fod kl

- हिंदी में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के अनुवाद के लिए कार्यशाला, न्यूपा, 05–12 मई, 2014
- पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के बारे में चर्चा के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह कार्यशाला, 13 मई, 2014
- गुजराती में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, गुजरात 19–23 मई, 2014
- पश्चिम बंगाल में बांग्ला में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, 14–18 जुलाई, 2014

- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के कन्नड़ में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, कर्नाटक, (प्रथम चरण) 5–7 अगस्त, 2014
- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के तेलुगू में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (द्वितीय चरण) 12–18 अगस्त, 2014
- कर्नाटक में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका के कन्नड़ में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (द्वितीय चरण) 2–4 सितम्बर, 2014
- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक की समीक्षा और संपादन के लिए कार्यशाला, गुजरात 22–27 सितम्बर, 2014
- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका के तेलुगू में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (द्वितीय चरण) 18–22 अकटूबर, 2014
- कर्नाटक में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, (तृतीय चरण) 25–26 अक्टूबर, 2014
- कर्नाटक में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के मिजो में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, मिजोरम दिसंबर 2014 (5 प्रतिभागी) और राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के पंजाबी में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, पंजाब दिसंबर, 2014 (3 दिन)
- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और हैंडबुक के कोकबोरोक में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, त्रिपुरा, 5–12 जनवरी, 2015
- ओडिशा में राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका के ओड़िया में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, 14 जनवरी, 2015
- राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका के मणिपुरी में अनुवाद और संदर्भीकरण के लिए कार्यशाला, मणिपुर, 27–31 जनवरी, 2015

Lrj 2%{kerk fodkl

- राज्य संसाधन समूहों की क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, 14–23 जुलाई, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 04–13 अगस्त, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 08–17 सितम्बर, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, पटना, बिहार, 19–28 सितम्बर, 2014।
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, राजस्थान, अक्टूबर, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, 09–18 अक्टूबर, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, लुधियाना, पंजाब, 26 अक्टूबर – 4 नवंबर, 2014
- राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, केरल, 04–07 नवम्बर, 2014 और नवंबर 2014 के अंत में दूसरा दौर
- महाराष्ट्र में राज्य संसाधन समूहों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, 10–12 नवबर, 2014
- उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र के स्कूल प्रमुखों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, 10–19 नवम्बर, 2014

- राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, भुवनेश्वर, ओडिशा, 20–29 नवंबर, 2014
- त्रिपुरा में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, 24 नवबर – 03 दिसम्बर 2014
- एस.सी.ई.आर.टी. गुड़गांव, हरियाणा में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, 29 नवबर – 08 दिसम्बर 2014 (37 प्रतिभागी)।
- राजस्थान में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला (द्वितीय बैच), नवंबर–दिसम्बर 2014
- पुड्डुचेरी में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण के लिये कार्यशाला, (पहला दौर, नवंबर 2014) और 19–24 जनवरी 2015 (दूसरा दौर)
- गुजरात में राज्य संसाधन समूह के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का दूसरा बैच, 08–18 दिसम्बर, 2014
- कर्नाटक में राज्य संसाधन समूह के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला, (बैच–1) 15–24 दिसम्बर, 2014
- मणिपुर में राज्य संसाधन समूह के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला, 15–24 दिसम्बर, 2014।
- रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, 22–28 दिसम्बर, 2014
- कर्नाटक में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, (द्वितीय बैच) 19–28 दिसम्बर, 2014
- मिजोरम में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, 28 जनवरी–7 फरवरी, 2015
- आंध्र प्रदेश में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, 29 जनवरी–7 फरवरी, 2015
- तेलंगाना में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, 03–12 फरवरी, 2015
- शिलांग, मेघालय मर्सी 30 में राज्य संसाधन समूह की क्षमता निर्माण कार्यशाला, मार्च 30 – 9 अप्रैल, 2015

jk'Vªh; Lrj ij Ldwy izeq[kksa dk {kerk fuekZ.k

- सात हिंदी भाषी राज्यों के माध्यमिक स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर एक माह का सर्टिफिकेट कार्यक्रम, 2–27 जनवरी, 2015
- दिल्ली के माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला, 09–10 जनवरी, 2015
- विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन पर एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1 सितंबर 2014 से 30 जून, 2015
- स्कूल प्रमुखों के क्षमता विकास के लिये दो पायलट कार्यक्रम– एक इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय प्रमुखों के लिये (50 प्रतिभागी) और दूसरा दमन दीव, दादरा और नागर हवेली के माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के साथ (41 प्रतिभागी)
- एनसीटीएल, ब्रिटेन के सहयोग से राजस्थान और तमिलनाडु के माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के लिये संकुल आधारित क्षमता विकास कार्यशालाएं (1400 प्रतिभागी)

Lrj 3 %usVodZ vkSj laLFkk fodkl

- विद्यालय नेतृत्व विकास के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक, 9 अप्रैल 2014
- शिक्षा संस्थानों, एनीसईआरटी, आरआईई, न्यूपा–एनसीएसएल की विद्यालय नेतृत्व विकास पर साहयोगिक बैठक, 29 अप्रैल, 2014
- महाराष्ट्र, मुंबई, में विद्यालय नेतृत्व विकास पर बैठक 1 जुलाई, 2014
- पुड्डुचेरी, में विद्यालय नेतृत्व विकास पर परामर्शकारी बैठक 24–25 जुलाई, 2014
- उत्तराखण्ड में विद्यालय नेतृत्व विकास पर परामर्श 19 अगस्त, 2014
- ओडिशा में विद्यालय नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श 27–28 अगस्त, 2014
- बिहार में विद्यालय नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श 03–04 सितम्बर, 2014
- तृतीय चरण के लिए 14 राज्यों हेतु विद्यालय नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श 15–16 सितम्बर, 2014, आई.आई.सी., नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक, 28 फरवरी, 2015
- आईएचसी, नई दिल्ली, 16–17 मार्च, 2015 में विद्यालय नेतृत्व विकास पर दूसरा राष्ट्रीय समीक्षा और योजना कार्यशाला

- विद्यालय नेतृत्व विकास पर छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड के एंकर संस्थानों के साथ सहयोग के लिए सलाहकार बैठक, 30 मार्च 2015

Lrj 4 %vuqákku ,oa fodkl

- विद्यालय नेतृत्वः नीति, अभ्यास और अनुसंधान पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी : आईआईसी, नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014
- एनसीएसएल–न्यूपा, नई दिल्ली और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाईटेड किंगडम के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय शिक्षा में महिला नेतृत्व पर अंतरराष्ट्रीय विचार मंच, 12–13 फरवरी, 2015

mPp f'k{kk esa uhfr vuqákku dsUnz

- बड़ी शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वभौमीकरण की चुनौतियां पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, नई दिल्ली 10–11 नवंबर, 2014

vU; dk;Øe

- लिंग और शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नई दिल्ली (निरंतर, नई दिल्ली के सहयोग से) 20–30 जनवरी, 2014

- मूडल एलएमएस का उपयोग शुरु करने ऑनलाइन शिक्षण पर आईसीटी कार्यक्रम व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली, 2–4 मार्च, 2015।

वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकों सहित कुल 102 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में कुल 4305 प्रतिभागी शामिल हुए। जिनमें 4241 प्रतिभागी भारतीय थे (तालिका 2.4) और शेष 67 प्रतिभागी अन्य दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के थे।

fo'ofo|ky; LFkkiuk fnol

विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष 11 अगस्त को स्थापना दिवस मनाता है। प्रथम स्थापना व्याख्यान वर्ष 2007 में 'आलर्टनेटिव पर्सपेक्टिव्स आन हायर एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट आफ ग्लोबजाईजेशन' पर प्रो. प्रभात पटनायक, उपाध्यक्ष, केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा दिया गया। द्वितीय व्याख्यान 'डिजाईनिंग आर्किटेक्चर फार ए लर्निंग रिवाल्यूशन बेसड आन ए लाईफ साइकल एप्रोच' पर प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य, राज्य सभा, इकोटैक्नालॉजी पर यूनेस्को पीठ के अध्यक्ष, एम.एस. स्वीनाथन अनुसंधान फाउण्डेशन द्वारा दिया गया। तृतीय व्याख्यान वर्ष 2009 में 'यूनिवर्सटीज़ इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी' पर प्रो. आंद्रे बेते, राष्ट्रीय अध्येता तथा प्रोफेसर एमिरेटस, सामाजिक विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। वर्ष 2010 में चतुर्थ व्याख्यान प्रो. मृणाल गिरी, अध्यक्ष, शासी निकाय, विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र द्वारा 'एजुकेशन, ऑटोनामी एंड अकाउन्टेबिलिटी' पर दिया गया। सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान 'एजुकेशन एंड मार्डिनिटी इन मार्डन इंडिया' पर प्रो. कृष्ण कुमार, शिक्षा शास्त्र प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। समीक्षाधीन वर्ष में आठवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2014 में 'इमेजिंग नॉलेज : ड्रीमिंग डैमोक्रेसी'' विषय पर प्रो. शिव विश्वनाथन, प्रोफेसर, जननीति एवं शासकीय विद्यालय विभाग, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया।

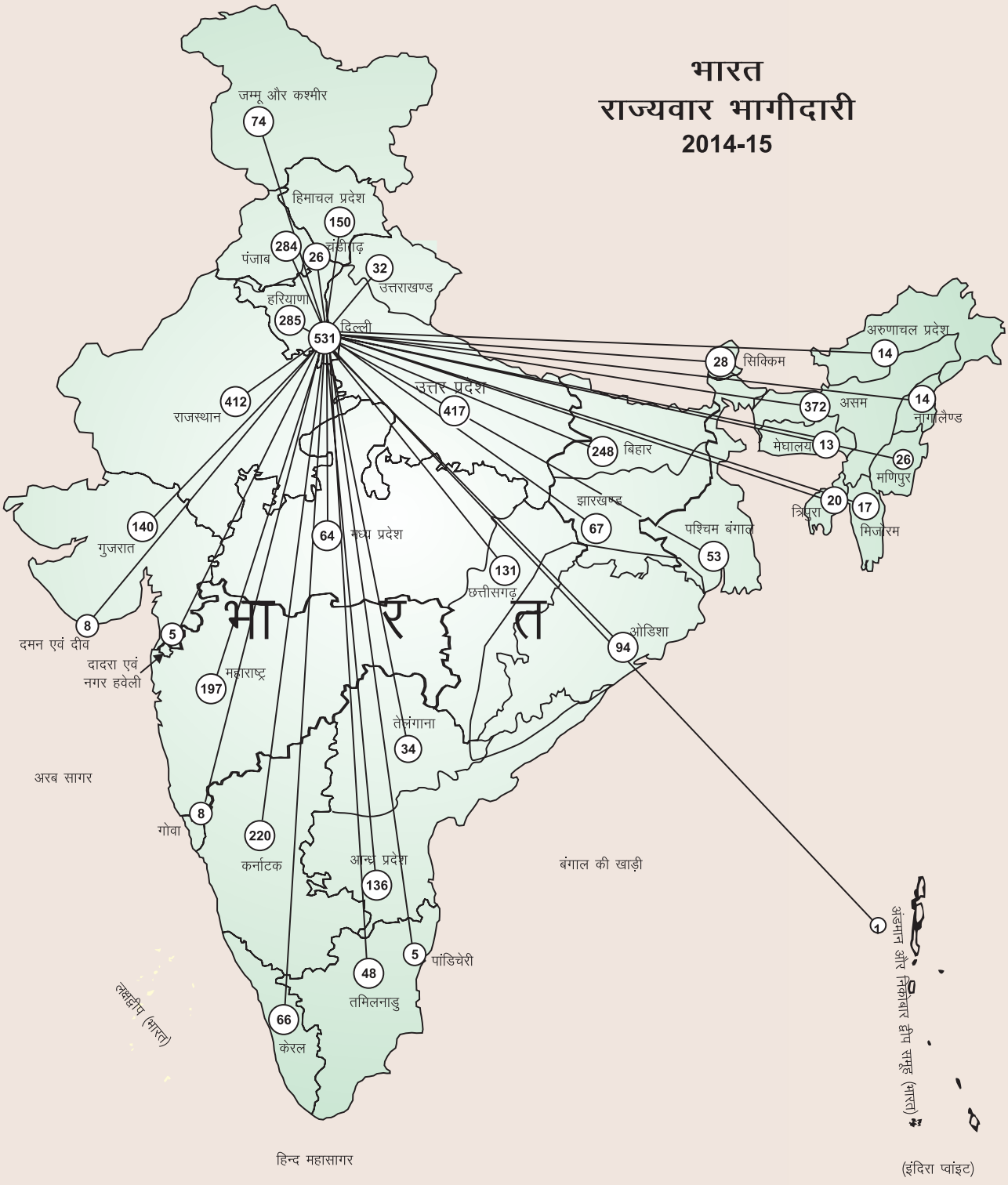
भारत
राज्यवार भागीदारी
2014-15
जम्मू और कश्मीर
74
हिमाचल प्रदेश
150
पंजाब
284
चंडीगढ़
26
उत्तराखण्ड
32
हरियाणा
285
दिल्ली
531
राजस्थान
412
उत्तर प्रदेश
417
बिहार
248
सिक्किम
28
अरुणाचल प्रदेश
14
असम
372
नागालैण्ड
14
मेघालय
13
मणिपुर
26
त्रिपुरा
20
मिजोरम
17
झारखण्ड
67
पश्चिम बंगाल
53
गुजरात
140
मध्य प्रदेश
64
छत्तीसगढ़
131
ओडिशा
94
दमन एवं दीव
8
दादरा एवं नगर हवेली
5
महाराष्ट्र
197
तेलंगाना
34
अरब सागर
गोवा
8
कर्नाटक
220
आन्ध्र प्रदेश
136
बंगाल की खाड़ी
पांडिचेरी
5
तमिलनाडु
48
केरल
66
लक्षद्वीप (भारत)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
1
हिन्द महासागर
(इंदिरा प्वांइट)
Map not to scale

3 अनुसंधान

अनुसंधान

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, शिक्षा क्षेत्र में विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु तथ्यों आधारित विकल्पों और रणनीतियों को बनाने के लिए नवीन ज्ञान जुटाने हेतु, शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन को विशेषकर ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विषयों में पारस्परिक शोध और अध्ययनों को बढ़ावा और सहायता प्रदान करता आ रहा है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में भी गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनों प्रकार के शोध, वर्तमान नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन की तकनीकों तथा प्रशासनिक ढ़ांचों एवं प्रविधियों में

तुलनात्मक अध्ययन करता है। अध्ययनों सहित ऐसे कार्य–शोध पर जोर दिया जाता है, जो शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए मुख्यं क्षेत्रों में नवीन ज्ञान को सृजित कर सकता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एम.फिल. और पी–एच. .डी. कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोध अध्ययनों, अन्य ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित शोध अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त अध्ययनों कार्यक्रम मूल्यांकन अध्ययनों और आंकड़ा प्रबंधन अध्ययनों जैसे शोध कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली में उठने वाले संभावित प्राथमिकता के मुद्दों अथवा भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तव में जिन मुद्दों से जूझ रही है, उनसे संबंधित शोध अध्ययन होते हैं। समीसाधीन वर्ष के दौरान, 10 शोध अध्ययन पूर्ण हुए थे, जबकि 38 अध्ययन प्रगति पर थे।

i wkZgkspqds s ' kksèk v è; ; u

(31 मार्च, 2015 तक)

1- Hkkjr esa fo|ky; ekufp=.k ¼foÙk i kS'k.k jfgr ' kksèk&i =½

अन्वेषक : प्रो. के. बिस्वाल

fu "d 'kkZd k l kj

जिम्मेदार विद्यालय प्रणाली बनाने का आरम्भिक बिन्दु साम्याात्मक विद्यालयी तंत्र का निर्माण करना है, जो देश की शिक्षा नीति को अनुदेशात्मक कार्यक्रम की आवश्यकताओं में परिवर्तित करने के लिए विद्यालय स्तर पर सहायक वातावरण बनाता है, जिसका अर्थ है समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने और साधनों, कार्मिकों तथा प्रक्रियाओं में न्यूनतम मानक बनाए रखने हेतु विद्यालयों के स्थान और उनकी संरचना की योजना बनाना ताकि राष्ट्र की विद्यालय प्रणाली को कुशल और प्रभावी बनाया जाए। भारत के राज्यों में भू–स्थानिक विभिन्नता तथा असमान सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास के प्रदत्त परिस्थितियों में, साम्यात्मक और कुशल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने का लक्ष्य एक बड़ा कार्य है। राज्यों में मानव–विकास के संबंध में बृहत भिन्नताएं हैं। एक असाम्य विद्यालय प्रणाली भारत में सामाजिक और आर्थिक विभेद की प्रक्रिया को और अधिक पोषित करेगी, अतएव साम्य, कुशल और प्रभावी विद्यालय प्रणाली की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, यह केस अध्ययन विद्यालय तंत्र को इष्टतम आकार और समान शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय मानचित्रण को क्रियान्वित करने में भारत के अनुभवों और परम्पराओं की जांच–पड़ताल करता है। इस रिपोर्ट को परिचय भाग सहित आठ भागों में प्रस्तुत किया गया है। भाग–2 में विद्यालय मानचित्रण के उद्भव पर स्थानीय स्तर की योजना तकनीक के रूप में चर्चा की गई है। भाग–3 में विद्यालय मानचित्रण की भारतीय व्याख्या दी गई है। भाग–4 भारत में विद्यालय मानचित्रण को निर्देषित करने वाले मानदण्डों और मानकों की जांच–पड़ताल करता है। भाग–5 भारत के विकेन्द्रित शैक्षिक ढ़ांचे में विद्यालय मानचित्रण का पड़ताल करता है। भाग–6 भारत की वर्तमान विद्यालय मानचित्रण की कार्यप्रणाली और संस्थात्मक व्यवस्थाओं की जांच–पड़ताल करता है और भाग–7 में तमिलनाडु के सलेम जिले में माध्यमिक स्तर पर आंतरिक–आव्यूह आधारित मानचित्रण के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। भाग–8 में समापन होता है।

d\$ v/;;u d s fu "d 'kZfu Eu çdkj gSa %

'यदि शिक्षा के अवसर में कोई समानता नहीं होगी तो कोई शैक्षिक विकास नहीं होगा।' हाल के वर्षों में इस कथन का महत्व भारत के कार्यक्रम योजना लेखों और शैक्षिक नीति में धीरे–धीरे बढ़ रहा है। नीति और कार्यक्रम योजना हेतु शिक्षा संबंधी स्थान–विषयक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तथा भाषाई बाधाओं से पार पाना और समान अवसरों को उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। शिक्षा को समावेशी कैसे बनाया जाए? शिक्षा प्रदान करने में प्रभावी होने हेतु विद्यालय का मानक आकार क्या होना चाहिए? शैक्षिक विकास की परिधि क्या होनी चाहिए अर्थात विस्तार बनाम समेकन पर चर्चा? शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा परिणामों के शहरी–ग्रामीण अन्तराल को कैसे पाटा जाए? वंचितों को कैसे शैक्षिक प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाया जाए? विद्यालयी शिक्षा में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षा में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता

को कैसे सुधारा जाए। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर भारत में मुख्य तौर पर चर्चा होती है। भारत में, प्राथमिक शिक्षा अधिकार बन चुकी है और राज्य तथा केन्द्र शिक्षा के अनिवार्योत्तर स्तरों के लिए समान अवसरों के सृजन के लिए एकजुट हो गए हैं। वृहद पैमाने के विकास कार्यक्रम यथा एसएसए, आरएमएसए और आरयूएसए (उच्च शिक्षा में) भारत में भाषा शिक्षा योजना को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। उप–राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने की एक संस्कृति निर्मित की जा रही है और अब सरकारी विभाग देश में शिक्षा पर सरकारी व्यय की मात्रा के बजाय गुणवत्ता को लेकर अधिक चिंतित हो गए हैं। शैक्षिक योजना और प्रबंधन में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण विकास की विचारधारा बन चुकी है। विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में देशीय स्तर के ईएमआईएस के रूप में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं तथा नीति एवं कार्यक्रम योजना निर्माण में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जिला योजना, सूक्ष्म योजना, विद्यालय मानचित्रण और विद्यालय सुधार योजना की आवश्यकता को कानून पास करके (यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उसके नियम) और कार्यक्रम योजना रूपरेखाओं द्वारा संस्थात्मक रूप दिया जा रहा है। वास्तव में गत कुछ दशकों में उभरकर आई इन बातों से शिक्षा के क्षेत्र में योजना और प्रबंधन का शैक्षिक धरातल बदल चुका है। उप–राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक कार्यकर्ताओं ने शैक्षिक योजना की भाषा को समझना और बोलना शुरू कर दिया है। यद्यपि, भारत में शैक्षिक योजना को व्यवसायीकृत और परिणामोन्मुख बनाना अभी बाकी है। देश की वर्तमान शैक्षिक योजना की परम्पराएं संपूर्ण क्षेत्र पर जोर देने वाले दृष्टिकोण वाले मॉडलों के बजाय परियोजनात्म्क योजना मॉडलों से अधिक मेल खाती हैं । इस प्रकार, योजना परंपराएं प्रायः संसाधनों तक पहुंच बनाने की स्वीकृतियों का रूप ले लेती हैं, विशेषकर संघ सरकार से मिलने वाली। इसी कारण से राज्य सरकारों ने 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से पूर्व विद्यालय मानचित्रण को एक योजना तकनीक के रूप में कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसी प्रकार, आरएमएसए की अपेक्षाओं के अनुरूप अनुपालना के रूप में विद्यालय मानचित्रण को संघ सरकार से संसाधनों का प्राप्त करने हेतु माध्यमिक स्तर के लिए किया जा रहा है जबकि अब प्राथमिक स्तर पर विद्यालय मानचित्रण को संचालित करना राज्यों के लिए सरकारी आदेशानुसार आवश्यक हो गया है, तो आरएमएसए के तहत इसे करना एक जरूरत बन चुका है। तथापि, शैक्षिक योजनाकारों और प्रबंधकों के लिए विद्यालय मानचित्रण की कार्यप्रणाली और अवधारणा के गुणागुणों को जानना और पूरी तरह से समझना अभी बाकी है। विद्यालय मानचित्रण, विशेषकर जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण ने समस्याऔ को और अधिक जटिल बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में विद्यालय मानचित्रण की अवधारणा की विभिन्न व्याख्याएं की जा रही हैं। इतना ही नहीं, जबकि विद्यालय मानचित्रण में जीआईएस एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसे समय पर अपेक्षित हल प्रस्तुत करने में विद्यालय मानचित्रण के साथ प्रौद्योगिकी को ढालने तथा प्रयुक्त करने की योग्यता की कमी लगभग सभी राज्यों में है। साथ ही साथ, डिस्टेंस मैट्रिक्स (अन्तराल आव्यूह) आधारित विद्यालय मानचित्रण यद्यपि विद्यालय मानचित्र का विश्लेषण करने और विद्यालय मानचित्रण के हलों तथा इसकी विशिष्टिताओं की दृश्यमान चित्रावली प्रस्तुत करने हेतु ईएमआईएस आंकड़ों के साथ स्थान संबंधी आंकड़ों का मिलान एवं सहक्रिया कराने में कार्यप्रणाली स्तर पर विफल प्रतीत होता है, जिसके कारण वास्तव में जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी ज्ञान, गहन कौशल आधारित और तुलनात्मक रूप से महंगी होने के कारण, जीआईएस विद्यालय मानचित्रण और शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया में केवल एक टूल के रूप में काम आई है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जीआईएस विद्यालय मानचित्रण निर्णय लेने में सहायक टूल के रूप में बहुत ही अधिक उपयोगी है बशर्ते कि यह सही कार्यविधि और ईएसआईएस तथा भूस्थानिक आंकड़ों का सही समुच्चय अपनाए। यदि जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण आधारित परतें बनाता है, युक्लेडियन दूरी के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संदर्भ में विद्यालय के अधीन आने वाले क्षेत्र को आधार बनाता है और विद्यालयों के मध्य नेटवर्क विश्लेषण करता है तथा विद्यालय के आस–पड़ोस को समुचित रूप से चिह्नित करने में सक्षम नहीं है (क्योंकि वर्तमान भारत में जीआईएस इस कार्य के लिए ऐरियल दूरी पर निर्भर करता है) और नए विद्यालयों के स्थलों अथवा विद्यालयों को अपग्रेड करने के निर्णय, पहुंच बढ़ाने से संबंधित इष्टतम निवेश के मुख्य सिद्ध ांतों को लागू करने के बजाय योजनाकार की बुद्धि के आधार पर लेता है तो जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण, चाहे जैसे भी प्रस्तुत किया गया हो, निश्चित रूप से अशुद्ध और इष्टतम से निचले स्तर का होगा, जिसके कारण पूर्व–निर्धारित स्तर के विद्यालयी नेटवर्क के विस्तार के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्ति विद्यालयों की कम अथवा अधिक इकाइयों का आकलन होगा।

राज्यों में विद्यालय मानचित्रण के किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, और वास्तविक 'वॉकिंग डिस्टेंस' आंकड़ों का प्रयुक्त करने के योग्य न होने के कारण, वर्तमान में, विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच संबंधी योजना के लिए अपेक्षित निर्णय सहायता उपलब्ध कराने में राज्यों का जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण सक्षम प्रतीत नहीं होता है। कतिपय कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान दिलाने हेतु, प्रथमतः जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण एक प्रदत्त क्षेत्र में मानचित्रण का कार्य करने के लिए 'विद्यालय' को एक इकाई के रूप में लेता है जबकि 'निवास स्थान' इसके लिए उचित इकाई होती है, यदि निवास स्थानों के लिए विद्यालयों को आवंटित किया जाना हो बजाय विद्यालयों के लिए निवास स्थानों को। द्वितीय, पहुंच के लिए योजना बनाते समय जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण विद्यालय के लिए निवास स्थान को आवंटित करता है, और तदनुसार, विद्यालय से निवास स्थानों तक की दूरी को मापता है; उचित तरीका निवास स्थानों के लिए विद्यालयों को आवंटित करना और निवास स्थान से निवास स्थान की दूरी के आंकड़े एकत्र करना है क्योंकि सामान्यतया विद्यालय एक अथवा अन्य निवास स्थान के क्षेत्र में स्थित होते हैं। तृतीय, क्योंकि नए विद्यालय की स्थापना करने अथवा वर्तमान विद्यालय का स्तर ऊंचा उठाने संबंधी निर्णय किन्हीं अन्य स्थानों पर शिक्षा संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता का कोई संदर्भ लिए बिना लिया जाता है, इसलिए भारतीय परिस्थितियों में जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण का वर्तमान रूप विद्यालय के नेटवर्कों को इष्टतम करने में पूरी तरह से विफल है। तब प्रश्न उठता है कि भारत में विद्यालयों के मानचित्रण में सुधार करने हेतु जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण में सुधार करने हेतु जीआईएस आधारित विद्यालय मानचित्रण और डिस्टेंस मैट्रिक्स आधारित विद्यालय मानचित्रण एक दूसरे के पूरक अथवा वैकल्पिक साधन हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि उचित रूप से सहयोजित किए जाते हैं तो ये विद्यालय मानचित्रण के पूरक साधन हैं। ये भारत में विद्यालय मानचित्रण को बहुत बड़े स्तर पर सुधार सकते हैं। विद्यालय मानचित्रण में जीआईएस एप्लीकेशन डिस्टेंस मैट्रिक्स आधारित एसएम प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को अपनाकर बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। विद्यालय मानचित्रण (एसएम) के वर्तमान जीआईएस समाधानों को साफ्टवेयर में डिस्टेंस मैट्रिक्स माड्यूल से सहयोजित करके आशोधित किए जाने की आवश्यकता है इसलिए भारत में डिस्टेंस मैट्रिक्स आधारित विद्यालय मानचित्रण की मुख्य विशिष्टताओं को जीआईएस आधारित एसएम को प्रायोगिक तौर पर चलाने की आवश्यकता है।

निष्कतर्षतः, संशोधित मानकों तथा मानदण्डों के आधार पर विद्यालयों के तंत्रों के पुनर्गठन से संभवतया समान अवसर उत्पन्न हों, परन्तु यह जरूरी नहीं कि इससे सभी को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। शिक्षा की सुविधाओं की आपूर्ति शायद बराबर की मांग उत्पन्न कर पाए। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों, नागरिक दबावों से प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की मांग उत्पन्न करना, और पात्र जनसंख्या के अंतिम हिस्से तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को तथा विषम परिस्थितियों में घिरे बच्चों तक विद्यालयी शिक्षा की पहुंच बनाना शिक्षा की मांग से संबंधित मुख्य चुनौतियां हैं। विद्यालयी शिक्षा को उपलब्ध कराने और इस तक पहुंच बनाने के लिए वंचितों तक जाने संबंधी नीतियों की आवश्यकता होगी। एसएम को और अधिक प्रासंगिक तथा परिणामोन्मुख बनाने के विषयों को शामिल करना पड़ेगा। जो भी हो, एसएम स्थानीय स्तर की योजना तकनीक के रूप में विकेन्द्रीकृत शैक्षिक योजना के सशक्तिकरण और शिक्षा के अवसरों के साम्यीकरण को आसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है।

2- 'kS{kd : i l sfiNM+ft ykas d ks fpfg~ur djus d s oSfYid –f"Vd ks.k ¼eksuk [kjs½

अन्वेषक : प्रो. मोना खरे

fu"d"kZ d k l kj

शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 60 वर्षों के नियोजित विकास और शिक्षा में साम्यता एवं गुणवत्ता के लक्ष्य के प्रति निष्ठा के बावजूद बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान देने और प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप की रणनीति के रूप में सरकार द्वारा इन्हें चिहि्नत किया गया। शैक्षिक विकास की विकेन्द्रित योजना के सिद्धांत के अनुरूप, इन विषमताओं को कम करने पर केन्द्रित हस्तक्षेप हेतु विभिन्न कारकों के आधार पर तुलनात्मक छोटी क्षेत्रीय इकाइयों यथा विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले जिलों (258 की संख्या में), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (3479 की संख्या में) को चिहि्नत किया गया था। तथापि, अनेक राज्यों और जिलों में अभी भी बड़े पैमाने का अन्तर है। जैसाकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि अंतिम ऐसे 6–7 प्रतिशत बच्चों 'जिन तक पहुंचना कठिन है' को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना एक चुनौती है।

11वीं पंचवर्षीय योजना पर वर्किंग समूह की रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया कि अन्तर्राज्य, अन्तर–जिला और अन्तर–ब्लॉक विषमताओं को कम करना आगामी वर्षों की चुनौती होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन चिंताओं को दोहराया गया। इसलिए वर्तमान पिछड़े/विकसित क्षेत्रों की पहचान ध्यानपूर्वक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए करनी पड़ेगी। शैक्षिक विकास/पिछड़ेपन को बहुआयामी अवधारणा होने के कारण शिक्षा के सभी स्तरों के स्तर पर अनेक मानदण्डों को सम्मिलित करते हुए शैक्षिक विकास को बहुचलकारकीय सूचकांकों को एक अलग नजरिये से देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार का बहुआयामी सूचकांक शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने में सबसे अधिक न्यायोचित संकेतक हो सकता है। एक संयुक्त संकेतक अथवा संश्लिष्ट सूचकांक सभी आयामों, उद्देश्यों, व्यैक्तिक संकेतकों तथा प्रयुक्त चलकारकों का एक समुच्चय होता है। इसका अर्थ यह है कि संयुक्त संकेतक की औपचारिक परिभाषा इसके सामुहिक समुच्चय के अंतर्गत विशेषताओं के एक समूह के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार के सूचकांकों को विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान ऐसे प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिहि्नत करना संभव है जो इन विषमताओं की व्याख्या करने में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हैं।

संयुक्त सूचकांक संस्थानों/क्षेत्रों के निष्पादन की कसौटी के लिए उत्तरोत्तर अधिक उपयोग किए जा रहे हैं। संगठन यथा संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, यूनेस्को, भारत सरकार तथा अन्य संस्थानों और देशों को श्रेणीक्रम प्रदान करने हेतु संयुक्त सूचकांकों का प्रयोग कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन के विभिन्न साधनों में श्रेणीक्रम संभवतया जनता का सबसे अधिक ध्यान खींचता है। इसी प्रकार, यूनएनडीपी देशों को एचडीआई के आधार पर श्रेणी प्रदान करता है और इएफए जीएमआर इडीआई का प्रयोग करता है। विभिन्न प्रसिद्ध वैश्विक संगठनों द्वारा विकसित किए गए ऐसे अनेक सूचकांक यथा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, नवोन्मेष सूचकांक, संधारणीयता सूचकांक आदि चलन में हैं। यह सूची लम्बी है परन्तु एक चीज साझी है कि ये सभी विविध उप–संकेतकों/चलकारकों के माध्यम से अनेक आयामों के आधार पर मापे जाने वाले संयुक्त सूचकांक हैं।

उद्देश्य : यह एकल विषयक लेख शैक्षिक विकास/पिछड़ेपन के सूचकांक को विकसित करने की विभिन्न तकनीकों को समझने के लिए एक कार्यप्रणाली के प्रदर्शक के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया गया है। यद्यपि ये तकनीकें गणितीय और सांख्यिकीय प्रकृति की हैं, यह एकल विषयक लेख गणितज्ञ–इतरों तथा सांख्यिकीविद–इतरों के लिए एक साधन–प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के प्राथमिक दृष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुत करेगा।

मूल उद्देश्य पाठक में निम्नलिखित के बारे में समझ विकसित कराना है :

1. शैक्षिक विकास के विविध संकेतकों की समझ और पहचान करना;
2. विविध संकेतकों के समूहन से संबंधित समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना;
3. बहुचलकारकीय सूचकांक को विकसित करने की वैकल्पिक तकनीकों को सीखना;
4. शैक्षिक विकास के एक बहुचलकारकीय सूचकांक को बनाने की विभिन्न कार्य प्रणालियों को अनुप्रयुक्त करना और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को चिह्नित करना;
5. इस प्रकार का सूचकांक विकसित करने में सजीवन व्यवहारिक आंकड़ों के समूहों का प्रयोग करना।

y{kdksrhu HkkxksaesackaVkx;kgS%

भाग–1 में शैक्षिक विकास की बहुआयामी प्रकृति की चर्चा है इस भाग में मुख्य रूप से ध्यान शैक्षिक विकास को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने पर केन्द्रित किया गया है ताकि आंतरिक कुशलता के संकेतकों के साथ–साथ क्षेत्र विशेष में शैक्षिक विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य वातावरण की पहचान उनको समावेशित करने के औचित्य सहित की जा सके।

भाग–2 में बहुचलकारकीय सूचकांक तैयार करने की विधियों से संबंधित अवधारणाओं तथा प्रेमेयों पर चर्चा है। इस भाग का ध्यान विविध चलकारकों को प्रयुक्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने पर और विविध आंकड़ों के समूहों से संबंधित साधनों पर केन्द्रित है ताकि समूहन तकनीकी रूप से संभव हो सके। यह उपलब्ध साहित्य में इसी प्रकार के किए गए कार्यों का उदाहरण देकर विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करता है।

भाग–3 भाग–2 में विकसित की गई पूर्वापेक्षाओं का प्रयोग बहुचलकारकीय सूचकांक तैयार करने की तकनीकों की और अधिक गहन व्याख्या करने में करता है। यह भाग व्यवहारिक अभिवृति वाला और भाग–2 में

चर्चित वैकल्पिक दृष्टिकोणों को एक ईडीआई विकसित करने हेतु शैक्षिक आंकड़ा समूह पर अनुप्रयुक्त करने और ईडीआई का प्रयोग शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को चिह्नित करने पर केन्द्रित है। यह भाग बहुचलकारकीय सूचकांक तैयार करने की विभिन्न कार्यविधियों के ऐतिहासिक विकास क्रम की तह में जाने का प्रयास करता है।

3- tut kr h; {ks=ka esa çkFkfed vkSj mPp çkFkfed f'k{kk d s fy , mi y Cèk l fo èkkv ka d k e Y; kad u

अन्वेषक : प्रो. के. सुजाता

fu "d "kZ d k l kj

इसमें नौ राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के 25 विशिष्ट ध्यायनाकर्षित जिलों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है : (i) प्रधानतः जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों की भागीदारी तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच की जांच करना (ii) यह जांच करना कि क्या उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं जनजातीय बच्चों की लैंगिक भिन्नता संबंधी, भाषाई और सामाजिक–सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और (iii) जनजातीय बच्चों के संबंध में अध्यापकों के परिप्रेक्ष्य के अतिरिक्त, अभिभावकों के अपने बच्चों की शिक्षा और उपलब्ध शिक्षा की सुविधाओं के बारे में दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

मुख्य् संस्तुतियां

1. प्राथमिक स्तर की आरम्भिक कक्षाओं में जनजातीयों के लिए अनुदेशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा के संबंध में एक राष्ट्रीय और राज्य नीति अपनाये जाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात, अगले स्तर पर क्षेत्रीय भाषा की ओर अविरत संक्रमण की संस्तुति की जाती है।
2. आंध्र प्रदेश के समान मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों से अध्यापकों की भर्ती की नीति की आवश्यकता है। परन्तु विविधता सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के हित में एक चौथाई अध्यापक गैर–जनजातीय श्रेणी से लेने की आवश्यकता है।
3. विद्यालयों की अच्छी स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की संरचना की गुणवत्ता में सुधार करना और सुविधाओं विशेषकर चहारदीवार, प्रयोग करने योग्य शौचालयों, लड़कियों के लिए अलग शौचालयों, पेयजल, कक्षाओं में फर्नीचर तथा उपकरणों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। विद्यालय के भवनों के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना और स्थानीय मौसम की स्थितियों के लायक बनाया जाना आवश्यक है।
4. बाधाएं उत्पन्न करके अभिभावकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले विभेद (जनजातीय परिवारों में लड़कियों को घरेलू कार्य, भाई–बहनों की देखभाल में लगाने की उच्च प्रवृत्ति है) और विद्यालय में अदृश्य भेदभाव (उपयोग योग्य शौचालयों की कमी, महिला अध्यापकों की अनुपस्थिति, अध्यापकों का अनुपस्थित रहना आदि) से पार पाने हेतु विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं, प्रभावी प्रोत्साहन और लड़कियों के लिए और अधिक आश्रम विद्यालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
5. महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और असम की तरह शिक्षा विभाग को सभी जनजातीय केन्द्रित/अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना, अनुवीक्षण और प्रशासन/प्रबंधन का कार्य करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि जनजातीय कल्याण और शिक्षा विभागों के दोहरे प्रशासन की समस्या से बचा जा सके।
6. विद्यालय अनुवीक्षण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग अध्यापकों की अनुपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए।
7. जनजातीय क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों का आकार छोटा होने के कारण, संरचना की गुणवत्ता और मात्रा तथा अध्यापकों की संख्या एक मुद्दा बना रहता है। अतः आवासीय आश्रम स्कूल और स्कूल काम्प्लेक्स प्रणाली बनाने संबंधी एक वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाने की आवश्यकता है।
8. वार्षिक विद्यालय समय–सारणी, विद्यालय का समय, अवकाश और छुट्टियों को स्थानीय भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए और स्थानीय जनजातीय त्यौहारों एवं मेलों का भी ध्यान रखना चाहिए।
9. अधिकतम ग्रामीण जनजातीय विद्यालय आकार में छोटे होते हैं और सुसज्जित नहीं होते हैं, अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे विद्यालयों के बजट में उच्चतर प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर वृद्धि

कर देनी चाहिए। कठिन भूभाग और खराब सड़कों के कारण सामान्यतया विद्यालयों तक भौतिक पहुंच समस्याओं से भरी होती है, अतः जहां अपेक्षित हो वहां विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों तक परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. दूरस्थ निवास स्थानों के मामले में जहां विद्यालय प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते हैं और लाभप्रद नहीं हैं, आश्रम विद्यालयों की सुविधा का प्रसार और निर्माण किया जाना चाहिए तथा अधिक केजीबीवीज लड़कियों की शैक्षिक आवश्याकताओं का ध्यान रखने हेतु खोले जाने चाहिए।

12. अवसर लागत से पार पाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि करनी चाहिए। विद्यार्थियों को लेखन–सामग्री भी दी जानी चाहिए और उनके लिए और अधिक छात्रवृत्तियां होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षाओं की लड़कियों को साईकिलें दी जानी चाहिए।

13. अध्यापकों को दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कुछ मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि उनके पास गांव अथवा इसके निकट क्षेत्र में मकान नहीं है तो उन्हें मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अध्यापकों को गांव में रहने की सुविधा मिलने से, अध्यापकों की अनुपस्थिति प्रवृत्ति घटेगी और अधिक समय पढ़ने–पढ़ाने को दिया जा सकेगा।

14. लघु अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से अध्यापकों को जनजातीय क्षेत्र के विद्यालयों में नियुक्त करने से पूर्व जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से परिचित कराया जाना चाहिए।

15. अध्यापकों की सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और यदि विद्यालय में केवल संविदा अध्यापक हैं तो कम से कम एक नियमित अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए।

16. जनजातीय बच्चों की शिक्षा की नीति का पुनरीक्षण राष्ट्रीय स्तर और जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में राज्य–स्तर पर भी किया जाना चाहिए।

पुनरीक्षण में सभी पहलूओं को शामिल करना चाहिए यथा विभिन्न विभागों की भूमिका, विशेषकर जनजातीय कल्याण विभाग, वित्त, प्रोत्साहन, भाषा–संबंधी मुद्दे, केजीबीवीएस और आश्रम स्कूलों की भूमिका, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता और विद्यालयों का अनुवीक्षण तंत्र।

4- dsjy ds'kS{kd ç'kklu dsrhu jsl o"kZ.k dsfy, çkjfEHkd vè;;u

अन्वेषक : डॉ. आर.एस. त्यागी

fu"d'kZ dk lkj

गत दो दशकों के दौरान केरल में विद्यालयी शिक्षा के प्रशासनिक ढ़ांचे और कार्यों में आए परिवर्तन को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह अध्ययन किया गया। पूर्वनिर्मित प्रश्नावली के आधार पर आंकड़े और सूचना राज्य स्तर पर शिक्षा सचिवालय तथा सभी निदेशालयों सहित, क्षेत्रीय, जिला, ब्लॉक और संस्थात्मक स्तरों पर एकत्र की गई। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि गत दो दशकों के दौरान केरल ने संस्थानों के स्तर से लेकर सचिवालय के स्तर तक प्रशासन के सभी स्तरों पर एक बहुत बड़े प्रशासनिक ढ़ांचे और कार्यों की स्थापना की है। इसमें प्रशासन को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने हेतु प्रशासन के सभी स्तरों पर ई–गर्वर्नेन्स की प्रणाली को भी शुरू किया है। यह ज्ञात हुआ कि न केवल विभिन्न शैक्षिक प्रशासन के स्तरों तथा प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सहित विभिन्न स्तरों के भीतर बल्कि शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने वाले अन्य विभागों यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के साथ आपसी सहयोग और एकात्मकता की कमी रही है और आगे देश के अधिकतर राज्यों की तरह, उसने भी विकास कार्यक्रमों के लिए समान्तर परियोजना प्रबंधन संरचानाएं यथा एसएसए, आरएमएसए बनाई हैं। आरटीई की व्यवस्था अभी भी एसएसए द्वारा देखी जा रही है। शिक्षा विभाग के इस कार्य के कारण आपसी असहयोग की कमी से और अधिक देरी तथा शैक्षिक प्रशासकों में जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना की कमी हो गई है। राज्य को हजारों अनार्थिक विद्यालयों, सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के हजारों निकाले हुए तथा अधिक अध्यापकों, अध्यापकों के स्थानान्तरण की मुख्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और अध्यापकों के लगभग 7000 मुकदमों के केस जो शैक्षिक प्रशासकों के बहुत बड़े समय के भाग को खा जाते हैं, वह शिक्षा अधिकारियों के सहज कार्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। हालांकि केरल को बहुत पहले देश में शैक्षिक रूप से अग्रणी राज्य का दर्जा प्राप्त है परन्तु यह अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे का सामना कर रहा है क्योंकि ऐसा कोई विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण नहीं

है जिससे शिक्षा अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापन– शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता प्रदान कर सकते। अध्ययन सुझाता है कि प्रशासन के युक्ति युक्त मूल्यांकन के आधार पर दोनों निदेशालयों अर्थात विद्यालयी शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के निदेशालयों का एकीकरण अवश्य होना चाहिए। राज्य को राज्य स्तरीय शिक्षा सेवा की स्थापना करनी चाहिए जिससे शैक्षिक रूप से कुशल शैक्षिक अधिकारियों की समय पर उपलब्धता में मदद मिलेगी। यह सुझाव भी दिया गया कि अधि–अध्यापकों की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यापक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक द्वारा अध्यापकों की भर्ती के बजाए निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती कर सके क्योंकि राज्य सरकार इन विद्यालयों में अध्यापकों के वेतन के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के लिए कष्ट निवारण प्रकोष्ठ बनाने के साथ–साथ, राज्य को शिक्षा राष्ट्रीय नीति द्वारा सुझाए गए अनुसार शून्य स्थानान्तरण की ओर भी अग्रसर होना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, देश के अन्य राज्यों और संघ राज्यों में तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े एकत्र करने हेतु शोध में प्रयुक्त सामग्री का परिष्कार किया गया।

5- fcgkj esa 'kSf{kd ç'kklu dk vè;;u&lajpuk] dk;Zvkj çfØ;k

अन्वेषक : डॉ. मंजू नरूला

fu"d'kZ dk lkj

1990–91 में जब दूसरा अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन का सर्वेक्षण किया गया था तब से गत दो दशकों के दौरान बिहार में स्कूली शिक्षा के शासन में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान रिपोर्ट में बिहार राज्य में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक रूप से हुए विभिन्न परिवर्तनों को शामिल किया गया है। यह शैक्षिक प्रशासन में संरचना, कार्यों, प्रक्रिया एवं कार्यविधियों सहित नीतिगत पहलों की जांच करती है और विभिन्न स्तरों यथा सचिवालय, निदेशालय, क्षेत्रीय, जिला, ब्लॉक और संस्थागत स्तरों पर प्रशासन और प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तनों का सीमांकन भी करती है। सर्वेक्षण रिपोर्ट शिक्षा के विधिक आधार, शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों, शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन, स्थानीय निकायों की भूमिका, कार्मिक प्रबंधन, शैक्षिक योजना की प्रक्रिया, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा शिक्षा सहायक निकाय के बारे में सूचित करते हुए राज्य के बारे में सामान्य जानकारियों का विवरण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में संस्थान के मुखिया के कार्यों का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में भावी विकास की संभावनाओं और शिक्षा के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं की भी चर्चा की गई है।

6- ekè;fed f'k{kk esa yMfd;ksa ds fy, d stUæ }kjk çk;ksftr jk"Vªh; çksRlkgu ;kstuk dk ewY;kadu

अन्वेषक : डॉ. वी.पी.एस. राजू

fu"d'kZ dk lkj

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ‘माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना’ का मूल्यांकन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मानदण्डों और सिद्धांतों के अनुसार जनवरी, 2014 में आरम्भ किया गया था। जब से द्वितीय स्रोत प्राप्त हुए हैं, देश के सभी क्षेत्रों–उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, केन्द्रीय तथा उत्तर–पूर्व को सम्मिलित करने हेतु अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, पंजाब, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आठ सैम्पल राज्यों का चुनाव किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि मूल्यांकन द्वितीय और प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करके किया जाएगा। कुल 16 जिलों के कम से कम 219 विद्यालयों और 2008–09 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान कक्षा 9 में नामांकित 1889 चयनित छात्राओं को सैम्पल के रूप में लिया गया है। इसी बीच, लड़कियों, प्रधान अध्यापकों और कार्मिकों के लिए अलग–अलग प्रश्नावलियों/अनुसूचियों का प्रयोग करके क्षेत्र–सर्वेक्षण किया गया, जिसमें संख्यांकन, अनुक्रमण, कोड प्रदान करने, सारणीयन, व्याख्या करने और विश्लेषण के भागों को सफलतापूर्वक सम्पन्न, किया गया। एक सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात, मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि साधनहीन परिवारों की बहुत सी लड़कियां जो आर्थिक एवं अन्य सामाजिक विवशताओं के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही त्याग देती थीं, उन्हें ये योजना बेहतर लगी। यह मूल्यांकन संपूर्ण भारत में इस योजना के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय को सुझावों और संस्तुतियों के एक नोट के साथ पूरा हुआ।

,u,lvkbZth,lbZ;kstuk dk çHkko

एनएसआईजीएसई योजना से निर्धन परिवारों को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा जारी रखने की प्रक्रिया में अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए भेजने में सहायता मिली। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों की संभावनाओं और प्रतिभा को भी अभिभावकों और अध्यापकों की ओर से पहचान मिली।

यह योजना प्रोत्साहन प्राप्तकर्ता को अपनी शिक्षा जारी रखने और अपने शैक्षिक लक्ष्यों के बारे में बहुत ही स्पष्ट होने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। यह योजना निर्धन लड़कियों को स्कूली वर्षों के दौरान उनकी शैक्षिक मैरिट को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि उनमें से बहुतों को बेहतर करियर को पाने के लिए उच्च शिक्षा की आकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी उनमें भर देती है। इसका उनके छोटे भाई–बहनों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर भी शिक्षा के संबंध में प्रेरणादायक प्रभाव पड़ता है। उनकी प्रेरणात्मक भूमिका के अतिरिक्त, लाभार्थी अन्यों का आवेदन करने के संबंध में ठोस मार्गदर्शन भी करते हैं।

इस योजना के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता अभिभावकों को अपने बच्चों को उच्च कक्षाओं, विशेषकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भेजने, पुस्तकें और लेखन–सामग्री खरीदने के योग्य बनाती है। कुछ बच्चे तो कम्प्यूटरों में कौशल विकास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण और अन्य कार्यों के लिए चयनित होने पर अच्छे निष्पादन की आवश्यकता और अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत ही विवेकशील हो जाते हैं। साथ ही, बहुत थोड़ी राशि होने, और अपने खुद के खाते में इसके जमा होने में लगने वाली अत्यधिक देरी के कारण भी लाभार्थी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करके नाखुश रहते हैं।

सभी संस्थानों के प्रधानों ने बताया कि एनएसआईजीएसई योजना से माध्यमिक कक्षाओं, विशेषकर कक्षा 8 से 9 तक की लड़कियों को अभिप्रेरणा प्राप्त हुई। ऐसे लाभार्थियों में, जो नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित हो रहे थे और इस दृढ़ विश्वास के साथ कि भविष्य में उन्हें लाभ होगा अपने शैक्षिक निष्पादन में अच्छा कर रहे थे, एक शानदार बदलाव दिख रहा था।

उदाहरणार्थ, पंजाब में विद्यालयों में लड़कियों का प्रवेश बढ़ गया है जबकि दूसरी ओर बच्चियों को मिलने वाले मौद्रिक प्रोत्साहन के रूप में आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए मिलने वाली जरूरी प्रेरणा के कारण स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है।

7- v Ur jkZVªh; ckMkZl s la) fo| ky; ksa dk v è; ; u

अन्वेषक : प्रणति पांडा

fu "d 'kkZd k l kj

"भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय" के विषय पर इस अध्ययन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। भारतीय विद्यालयों को विदेशी बोर्डों से संबद्ध करने से संबंधित नीति बनाने का शुरूआती प्रयास एमएचआरडी द्वारा किया गया था। वर्तमान अध्ययन में, परिभाषित टीओआर के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों के साथ संबद्धता/प्राधिकृत करने और पंजीकरण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की मांग, विदेशी अध्यापकों को रोजगार, वृद्धि की प्रवृत्ति आदि को समझने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में, अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों, उनकी विविध बोर्डों से संबद्धता, अन्तर्राष्ट्रीय अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या, शुल्क संरचना इत्यादि के संबंध में कोई डाटाबेस उपलब्ध नहीं है।

गत दो दशकों के दौरान, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की कई गुणा वृद्धि हुई है। इन्टरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, ग्लोबल स्कूल आदि के रूप में पहचाने जाने वाले ये विद्यालय मुख्य रूप से तीन विदेशी बोर्डों – इन्टरनेशनल बैककॉलॉरेट (आईबी) जिसका मूल जेनेवा में है कैम्ब्रिज इन्टरनेशनल एक्जामिनेशन (सीआईई), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक भाग और ऐडेक्सल, पीयर्सन कम्पनी का एक भाग, से संबद्ध हैं। इन तीन अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों से संबद्ध लगभग 478 अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय हैं। गत पांच वर्षों के दौरान, भारत के बहुत सारे निजी विद्यालयों ने स्वेच्छा से अन्तरर्राष्ट्रीय बोर्डों से संबद्धता मांगी थी। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की कवरेज केवल 19 राज्यों तक सीमित है। सी आई और आई बी दोनों द्वारा भारत में प्राधिकृत विद्यालयों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है। अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों ने दो एकदम भिन्न मार्ग अपनाए हैं। आई बी प्राधिकृत 102 विद्यालयों (चार दूतावासीय विद्यालय को छोड़कर) में से 67 विद्यालयों ने सीधा रास्ता अपनाया अर्थात विद्यालय स्थापित करने की आज्ञा राज्य से लेने के पश्चात उन्होंने आई बी से सीधे प्राधिकृत करा लिया। कुल सीआईई प्राधिकृत 139 विद्यालयों ने यही रूट अपनाया दूसरा मार्ग यह है कि सीबीएसई, सीआईएससीई और राज्य बोर्डों से पहले से संबद्ध विद्यालयों ने स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों से संबद्ध करा लिया। 95 प्रतिशत से अधिक अन्तरर्राष्ट्रीय विद्यालय दोहरा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं (अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यथा सीबीएसई, आईसीएसई अथवा राज्य बोर्ड अथवा आईबी, सीआईई और राष्ट्रीय बोर्डों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त कार्यक्रम)। अध्ययन के मुख्य, निष्कर्ष और सुझाव, प्रश्नावलियों, साक्षात्कारों और विद्यालयों के दौरों आदि के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित हैं।

हाल ही के वर्षों में जो ध्यानाकर्षी वृद्धि हुई है वह वृद्धि तुलनात्मक रूप से अस्थायी, अनियोजित और बेढ़ंग रही है।

गत पांच वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की संघटना विविधतापूर्ण और जटिल होती है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय सभी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषताओं यथा प्रवासी विद्यार्थियों और अध्यापकों की बहुलता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों से लेकर घरेलू विद्यार्थी और अध्यापकों वाले अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड की संबद्धता/असंबद्धता वाले विद्यालय होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय विभिन्न श्रेणियों के यथा इन्टरनेशनल डे स्कूल/इन्टरनेशनल डे–कम–बोर्डिंग स्कूल/इन्टरनेशनल बोर्डिंग स्कूल होते हैं। इनमें "ऐतिहासिक स्वतंत्रता पूर्व के विद्यालयों" को भी शामिल किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड अपने लोगों का प्रयोग करने की आज्ञा विद्यालय को उचित पंजीकरण और प्राधिकृत किए जाने के बाद देता है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों को अपने विद्यालयों के नाम में कोई भी शब्द यथा इन्टरनेशनल, ग्लोबल/वर्ल्ड का प्रयोग करने में उनकी स्वयं की पसंद और स्वततंत्रता होती है। भारतीय विद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों द्वारा संबद्धता प्रदान करने/प्राधिकृत करने/पंजीकृत करने की नीति और रीति अन्य देशों के समान होती है। अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड विद्यालयों के विभिन्न आकार (छोटे, बड़े), संदर्भ (ग्रामीण, शहरी) अथवा इस उद्देश्य के, किसी धार्मिक प्रबंधन वाले विद्यालयों को प्राधिकृत करने के संबंध में कोई विशिष्ट अधिमान नहीं देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड से प्राधिकृत किए जाने की इच्छा रखने वाले निजी विद्यालयों की विधिक स्थिति के बारे में दोनों बोर्डों (आईबी और सीआईई) की अपेक्षाएं भिन्न हैं। सीआईई पंजीकरण के मामले में विधिक मुद्दों को विद्यालयों की जिम्मेदारी माना जाता है जबकि आईबी अथॉराईजेशन के लिए, विद्यालय को स्थानीय/प्रान्तीय/राज्य प्राधिकारी से विद्यालय के शैक्षिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त होने की पुष्टि संबंधी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है। आईबी और सीआईई दोनों गैर–लाभ अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड हैं। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों से संबद्धता/प्राधिकार/पंजीकरण लेने, विद्यालयों को प्राधिकृत किए जाने, परीक्षाओं, स्टाफ के व्यावसायिक विकास और निरीक्षण से संबंधित अनेक शुल्कों का भुगतान करना होता है। दोनों अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड जोर देकर कहते हैं कि निर्धारित पाठ्यक्रम, अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं जांचने की प्रक्रियाएं उनके कार्यक्रमों की मुख्य शक्ति है तथा अन्य राष्ट्रीय एवं संवैधानिक मूल्यों तथा अन्य भारतीय संदर्भों को संयोजित करने की जिम्मेदारी विद्यालयों की है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की तेजी से हुई वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मांग के स्थान पर उनके घरेलू कारणों से प्रभावित है। भारत में सामान्यतया प्रवासी परिवार, व्यापारी वर्ग और बहुराष्ट्रीय व्यवसायी अपने बच्चों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों को बहुत अधिक पसंद करते हैं। हाल ही के वर्षों में, भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों ने अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों को सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले के तौर पर, अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की शिक्षा की आकांक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विदेश में पढ़ने के लिए मार्ग खुलने के तौर पर मानते हुए अपनाते हैं।

माध्यमिक शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य प्रमाणपत्र (आईजीसीएसई, सीआई) और डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी, आईबी) भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हैं। दोनों बोर्डों के संबद्ध विद्यालयों की प्रवेश नीति और शुल्क–संरचना एक जैसी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की शुल्क संरचना में व्यापक भिन्नताएं हैं।

विश्व के विभिन्न देशों की अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के संबंध में नीतियां अलग–अलग हैं। कुछ देशों ने "अहस्तक्षेप की अभिवृत्ति" को अपनाया है तो अनेक दूसरे देशों ने विनियमीकरण के मानदण्ड बनाएं हैं। बहुत अधिक विभिन्नताओं के साथ, जिस तरह से इस प्रकार के विद्यालयों की अनियोजित तथा असंरचनात्मक ढ़ंग से स्थापना में वृद्धि हुई है, उससे नीति–निर्माताओं और योजनाकारों को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में चल रहे इन अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों का किसी प्रकार का कोई "डाटाबेस" उपलब्ध नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की विविधता के कारण उन विद्यालयों की गुणवत्ता और मानदण्डों से संबंधित सार्थक मुद्दे उठे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के इस प्रसार से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। दूसरी ओर, इस वैश्वीकृत युग में शायद ही कोई अन्तरर्राष्ट्रीय विद्यालयों की आवश्यकता को चुनौती दे सकता है परन्तु इसके लिए सरकार द्वारा योजनाबद्ध पहल तथा एक बहुत ही पारदर्शी नीति विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

यह सिफारिश की जाती है कि भारत सरकार को विद्यालयी शिक्षा के भाग के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और विनियमीकरण से संबंधित नीतिगत ढ़ांचा तैयार करने के संबंध में उचित कदम उठाने की पहल करनी चाहिए। परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए एक विनियामक तंत्र तुरंत विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए एक विनियामक प्राधिकरण – भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय विनियामक प्राधिकरण (आई एस आर ए) की स्थापना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत की जाए। प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों से पंजीकृत/प्राधिकृत किए जाने की मांग करने वाले विद्यालयों द्वारा पूरे किए जाने वाले मानदण्डों को और केन्द्र और राज्य सरकारों की परिभाषित भूमिका को निर्धारित करेगा। विद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डों/प्रदाताओं को आवेदन नियामक प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण के उद्देश्यों, संघटन और कार्यों को प्राधिकरण को स्थापित करने संबंधी तैयार किए गए नीति–लेख में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय को विद्यालय से संबंधित सभी अपेक्षित विवरणों से युक्त अद्यतन केवल एक वेबसाइट रखना आवश्यक होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों को विनियमित करने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक तात्कालिक उपाय के रूप में एक 'प्रकोष्ठ' की स्थापना विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के प्रसार और कामकाज का अनुवीक्षण करने हेतु की जाए। भारतीय संदर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय की विशेषताओं को स्पष्ट करना किसी सरकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय क्या है? एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय को यह नाम देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए? यह सिफारिश की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय संबंधी नीतिगत ढ़ांचे में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय के आवश्यक घटकों – किसी विदेशी बोर्ड से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के संघटन में एक सार्थक (>20%) अन्तर्राष्ट्रीय मिश्रण और शिक्षक वर्ग में (>20%) सार्थक अन्तर्राष्ट्रीय मिश्रण (सार्थक >20% एक मनमानी आंकड़ा है जिसे तर्कसंगत रूप से बढ़ाया जा सकता है, परन्तु कम नहीं किया जा सकता) को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

विद्यालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों और इनके अभ्यास में भारतीय विशिष्ट तत्वों यथा भारत का इतिहास और संस्कृति, कला, संगीत, भारतीय भाषाओं और भारतीय राष्ट्रीय दिवसों, उत्सवों आदि को सम्मिलित करना चाहिए। एनसीईआरटी को विभिन्न स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय पाठयक्रमों का पुनरीक्षण करने और भारतीय विशिष्ट तत्वों एवं संवैधानिक मूल्यों को एकीकृत करने का सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपा जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी अध्यापकों की भर्ती के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों में भारतीय और विदेशी अध्यापकों के अनुपात को विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले अन्तर्राष्ट्रीय अध्यापकों के वेतन तथा कार्य–अनुज्ञापत्र एवं वीजा संबंधी नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय विदेश मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले अन्तर्राष्ट्रीय अध्यापकों की वेतन–संरचना तथा कार्य अनुज्ञापत्र एवं वीजा से संबंधित नीति तैयार करे।

प्रस्तावित प्राधिकरण को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का अनुवेक्षण करते समय, शिक्षा शुल्कों और विद्यालय के खर्चों के अनुरूप अन्य प्रभारों को भी विनियमित करना पड़ेगा। प्राधिकरण को शुल्कों और अन्य प्रभारों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना होगा। यह भी संस्तुति की जाती है कि प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों के कामकाज विशेषकर भारतीय विशिष्ट तत्वों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रमों में शामिल करने, विद्यार्थियों के प्रवेश की नीति, शुल्क संरचना, संरचनात्मक सुविधाओं इत्यादि से संबंधित, का अनुवीक्षण करने हेतु एक स्थाई तन्त्र बनाना चाहिए।

8- gfj;k.kk vk§ jkt LFkku esa iwZ&çkFkfed f'k{kk dh ekax ds lkekftd igywa dk vè;;u

अन्वेषक : डॉ. मधुमिता बंद्योपाध्याय

fu"d"kZd kl kj

यह शोध अध्ययन विद्यालय–पूर्व शिक्षा के निर्बाध कार्य के संबंध में आपूर्ति पहलों का अध्ययन करने और क्या वे मांग की संगति में है, इसका अध्ययन करने के लिए किया गया। इसमें विभिन्न प्रबंधन संघों द्वारा संचालित प्री–स्कूलों द्वारा प्रदत्त भौतिक और शैक्षिक सुविधाओं, विद्यालय–पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, बच्चों के प्री–स्कूल से प्राथमिक विद्यालय तक के संक्रमण की स्थिति विद्यालय–पूर्व शिक्षा और आस–पड़ोस के क्षेत्रों में विद्यालय–पूर्व शिक्षा हेतु उपलब्ध केन्द्रों और विद्यालयों के कामकाज के बारे में अभिभावकों की राय का अध्ययन शामिल है। अध्ययन प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों पर आधारित था। प्राथमिक आंकड़े 3280 प्री–स्कूल विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए 84 विद्यालयों और 72 आंगनवाड़ियों से पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। ये आंकड़े 84 विद्यालयों के प्रधानों, 67 विद्यालय–पूर्व विद्यालयों के अध्यापकों, 72 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकाओं, 1132 सैम्पल अभिभावकों का साक्षात्कार लेकर भी एकत्रित किए गए हैं। प्री–स्कूल से प्राथमिक विद्यालय तक संक्रमण की स्थित और आरम्भिक ग्रेड में बच्चों की शैक्षिक स्थिति का मूल्याकन करने हेतु कक्षा 1 और कक्षा 2 में नामांकित लगभग 3500 (अनुमानित) बच्चों से संबंधित स्कूल रोस्टर डाटा एकत्रित किया गया

है। आंगनवाड़ी और विद्यालय सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि प्री–स्कूल शिक्षा तक पहुंच के संबंध में हरियाणा, राजस्थान की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

हरियाणा में जबकि सभी सरकारी विद्यालयों में कम से कम एक नर्सरी ग्रेड था, राजस्थान के किसी भी सरकारी विद्यालय में प्री–प्राईमरी अनुभाग नहीं है तथा निजी विद्यालयों के अलावा, केवल एडब्ल्यूडब्ल्यू ही विद्यालय–पूर्व शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि दोनों राज्यों के सैम्पल निजी विद्यालय विद्यालय–पूर्व शिक्षा प्रदान करने से संबंधित सुविधाओं से युक्त हैं। हालांकि आंगनवाड़ियों और कुछ सरकारी विद्यालयों में भी कार्य की गुणवत्ता संतुष्टि कारक नहीं है। यह ज्ञात हुआ कि अनेक विद्यालयों के अध्यापक इन बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित नहीं हैं और आंगनवाड़ी और सरकारी विद्यालयों में अध्यापन एवं शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया की घटिया गुणवत्ता के कारण बहुत सारे बच्चों में अभी आधारभूत लिखने, पढ़ने और उच्चारित करने का कौशल्य विकसित किया जाना शेष है।

9- i at kc esa v è; ki d ka d h d k; Z r fLFkfr ; ka d k v è; ; u % u hfr v k\$ j hfr ; ka d k j \$ kkad u

अन्वेषक : डॉ. अनुपम पचौरी और प्रो.विमला रामचन्द्रन

fu "d 'kkZd k l kj

पंजाब के अध्यापकों की कार्यगत स्थितियों का अध्ययन एक गुणात्मक शोध अध्ययन था। इस अध्ययन में पंजाब के नियमित और संविदा अध्यापकों के संबंध में भर्ती तैनाती नीतियों एवं परम्पराओं, वेतन सेवा लाभ तथा कार्यगत स्थितियों के साथ–साथ अध्यापकों की तैनाती, स्थानान्तरण, पहली और बाद की तैनातियां, व्यावसायिक वृद्धि, विकास और मूल्यांकन को दर्ज एवं विश्लेषित किया गया है। प्रथम चरण में दस्तावेजों को एकत्रित करना और डेस्क रिव्यू शामिल था दूसरे चरण में चिह्नित मुद्दों और आगे खोज करने हेतु एक जिला (मोहाली) और राज्य के स्तर के मुख्य कार्मिकों के साथ मुद्दों और विषयवस्तु (थीम) आधारित साक्षात्कार शामिल थे। तीसरे चरण में दूसरे चरण के अनुक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पंजाब में अध्यापन करने वाले नियमित और संविदा अध्यापकों की अनेक श्रेणियों के साथ केन्द्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से मुद्दों का और आगे समन्वेषण किया।

अध्ययन के निष्कर्षों से निर्देशित होता है कि पंजाब में शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसार अध्यापकों को श्रेणियों में बांटने से, समुचित संसाधनों रहित प्रबंधन और प्रशासनिक ढ़ांचों के दोहराव के कारण बरबादी की गुंजाइश उत्पन्न हो गई है।

इसके कारण अध्यापकों की कुछ श्रेणियों के लिए करियर विकास के मार्ग की स्पष्ट कमी हो गई है। इस प्रकार, जबकि तंत्र में कुल मिलाकर खर्च वृद्धमान है और आरटीई अधिनियम, 2009 का बेहतर अनुपालन है, इसमें असंतुष्ट अध्यापकों का जमावड़ा भी है। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी योजनाओं और निधियों को पंजाब राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के एक छत्र के तहत मिलाकर एकस्थ कर दिया जाए और अध्यापकों का एक एकीकृत कैडर बना दिया जाए। इस एकीकरण से असमानताएं कम हो जाएंगी।

10- u k\$&j kT; ka d s ç kFkfe d v k\$ e kè; fe d fo | ky ; h v è; ki d ka d h d k; Z fLFkfr ; ka d s fo"k; i j v è; ; u

अन्वेषक : प्रो. विमला रामचन्द्रन, डॉ. प्रेरणा गोयल चटर्जी, श्री निखिल माथुर और सुश्री अपर्णा रवि

fu "d 'kkZd k l kj

इस अध्ययन को भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक प्रासंगिक समय पर संकल्पित और क्रियान्वित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 ने अध्यापक विद्यार्थी अनुपात और अध्यापकों की योग्यताओं को अधिदिष्ट कर दिया है और अध्यापन तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण के बारे में कुछ संकेत भी दिए हैं। आरटीई अधिनियम और जस्टिस वर्मा समिति द्वारा सभी अध्यापकों, चाहे संविदा अथवा ग्रेड में हों, के लिए भर्ती में प्रथम चरण के रूप में अध्यापक पात्रता परीक्षा को अधिदिष्ट करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, अनेक राज्य सरकारों ने संविदा अध्यापकों से संबंधित अपनी नीतियों का पुनरीक्षण किया है और कुछ अन्य ने यह विचार किए बिना कि दीर्घावधि में उनका क्या होगा संविदा अध्यापकों को काम पर रखा है। ये वो समय है जब हमारे विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करने और हमारे बच्चों की शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित करने का बहुत अधिक दबाव भी है।

उपर्युक्त को ध्याान में रखते हुए न्यूपा (अध्यापक प्रबंधन एवं विकास से संबंधित चेयर के तत्वधान के तहत) ने भारत के नौ राज्यों यथा झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्य स्थितियों को समझने हेतु एक अध्ययन की पहल की थी। विश्व बैंक को तकनीकी साझेदार के रूप में इस अध्ययन से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया।

यह अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के सरकारी विद्यालयी अध्यापकों पर केन्द्रित है। माध्यमिक स्तर पर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को इसलिए सम्मिलत किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के इस भाग में उनका दखल अधिक है। इस शोध में अध्यापकों की सभी श्रेणियां– नियमित, संविदा और पार्ट–टाईम अध्यापक शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया है कि 'अध्यापक प्रबंधन' की हमारी समझ बनाने के लिए निम्नलिखित मुद्दों की खोजबीन करनी होगी : भर्ती संबंधी नीतियां और रीतियां तैनाती और पुनः तैनाती (स्थानान्तरण/तैनाती) नीतियां और रीतियां वेतन, गैर–वेतन लाभ और सेवा की शर्तें (पेन्शन, अन्य/दीर्घावधि के लाभ) अध्यापकों की भौतिक कार्य–स्थितियां अध्यापकों की भूमिकाएं, कार्य, जिम्मेदारियां व्यावसायिक विकास के मार्ग और अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंधन स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली और अध्यापकों के अधिकार, शिकायत निवारण तंत्र (गत 2 वर्षों में दायर किए गए विधिक केसों के डेस्क रिव्यू, के माध्यम से) और अध्यापकों की यूनियनों के अधिदेश।

यह अध्ययन भर्ती किए गए अध्यापकों की गुणवत्ता और क्षमता के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वे हमारे विद्यालय में कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बजाए यह अध्ययन यह जानने के लिए है कि क्या सरकार जहां आवश्यक हो अध्यापकों की भर्ती और तैनाती करने में सक्षम है, क्या कार्य रीतियां नीतियों के अनुरूप हैं और क्या ये कार्य पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

v è; ; u rhu Lrjksa i j l pkfy r fd ; k x ; k %

(i) अध्यापक प्रबंधन और विकास के विषय पर उपलब्ध सामग्री का डेस्क रिव्यू;

(ii) चिह्नित मुद्दों की गहन खोजबीन और

(iii) राज्य और जिला स्तरों पर हितधारकों के साथ वार्तालाप

नीतिगत तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन और हितधारकों के साथ साक्षात्कारों के माध्यम से अपनायी गई कार्य प्रणाली प्राथमिक तौर पर गुणात्मक प्रकृति की थी। तथापि, जिस संदर्भ में अध्ययन को करना था उसके परिग्रहण हेतु आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया।

l aLrqfr ; ka

इस अध्ययन ने दर्शाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए विस्तृत मार्गनिर्देशों (यथा एनसीटीई द्वारा अध्यापकों के लिए अर्हताएं निर्धारित करना और यूडीआईएसई डाटाबेस को तैयार करना) ने अध्यापक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा।

ये सब कहने के पश्चात, अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या राज्यों के कर्मचारी के रूप में है, और अंत में राज्यों को ही अध्यापकों की भर्ती और तैनाती की नीतियों का निर्धारण, वेतन की वित्त व्यवस्था करना, पदोन्नति के मानदडों का निर्णय करना होता है और इन अध्यापकों को व्यावसायिक विकास तथा शिकायत निवारण संरचनाओं के रूप में सहायता उपलब्ध कराना है।

इस अध्ययन से जो एक अभिभूतकारी संदेश उभरकर आया है, वह है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गहन अध्यापक प्रबंधन नीति को विकसित करना अत्यावश्यक है – जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित भर्ती प्रोटोकॉल, स्थानान्तरण शासन–पद्धति और अध्यापकों की शिक्षेत्तर कार्यों (यथा ब्लॉक अथवा कलस्टर स्तर के प्रशासनिक कार्मिक) पर प्रतिनियुक्ति जैसे मामलों के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश, शिक्षा संबंधी कार्यों (डीआईईटी, सीआरसी और बीआरसी में मुख्य संसाधक के रूप में) और पदोन्नति (प्रधानाध्यापक के रूप में) शामिल हों। परन्तु एक विस्तृत नीति ही काफी नहीं है बल्कि एक ऐसे ढ़ांचे की आवश्यकता होती है जिस में कार्य पारदर्शी तरीके से होते हों, अपारदर्शी प्रक्रियाओं से जुड़े तनाव, देरी और उलझन कम हों।

इस अध्ययन में पांच मुख्य अध्यापक प्रबंधन मुद्दों को चिह्नित किया गया है, जिन पर राज्य सरकारों को अपने विद्यालय शिक्षा तंत्रों में सुधार करने हेतु ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पांचों मुद्दे सह–संबंधित हैं एक में परिवर्तन दूसरों को प्रभावित करेगा।

¼d½ l qO; oLFkr vkSj ikjn'khZ HkrhZ vkSj rSukrh

कर्नाटक और तमिलनाडु ने अन्य राज्यों के सामने यह उदाहरण पेश किया है कि अध्यापकों की भर्ती, तैनाती और स्थानान्तरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी कैसे बनाया जाए। उनकी प्रणाली में कुछ साझी विशेषताएं हैं : (1) प्रत्येक के लिए स्पष्ट नीतियां हैं (2) आधुनिक सॉफ्टवेयर और सूचना प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करते हुए अधिकतर प्रक्रियाएं ऑनलाईन और पारदर्शी हैं। (3) भर्ती और स्थानान्तरण की प्रक्रिया में स्पष्ट) रूप से परिभाषित सीमारेखा दी गई है, जो वर्षों से स्थिर है और (4) प्राथमिक स्तर के अध्यापक (इसी स्तर पर अन्य राज्यों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना है) ब्लॉक स्तर के कैडर के होते हैं, जिससे उनको प्रथम तैनाती में काफी विकल्प मिलते हैं।

इसके आगे, भर्ती नीतियां और कार्य रीतियों को उन दो मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके कारण अध्यापक प्रबंधन बहुत अधिक जटिल हो जाता है । पहला अध्यापकों के अनेक कैडर होने से संबंधित है। इससे कई स्थितियां जटिल बन जाती हैं। इसी समान स्तर पर जिला परिषद अथवा पीआरआई अध्यापक और कुछ परियोजना– विशिष्ट अध्यापक (आरएमएसए अथवा एसएसए की निधि से पोषित) होते हैं अथवा एक विद्यालय में, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों को संभवत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कैडर के प्राध्यापकों, दोनों से संबंधित जिम्मेदारी लेनी पड़ती है।

दूसरा मुद्दा राज्यों के भीतर, बल्कि वास्तव में जिलों और ब्लॉकों में पीटीआरएस के वितरण से संबंधित है। सभी राज्यों में दोनों बहुत कम पीटीआरएस (1:10 से नीचे) और बहुत ऊंची पीटीआरएस (1:100 से ऊपर) वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए राज्यों द्वारा विद्यालय स्तर पर अध्यापकों के वितरण की जांच किया जाना और तदनुसार इसे तर्कसंगत बनाया जाना अत्यावश्यक है। अध्यापकों की माध्यमिक स्तर पर जरूरत का मूल्यांकन करने हेतु राज्यों को एक माप विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाने वाला मानक पीटीआर काम नहीं आता है (संभवतया इस प्रकार के माप की आवश्यकता उच्च प्राथमिक अध्यापकों के लिए भी है)।

¼[k½ vè;kidksa dks l akfèkr l gk;rk&l ajpuk rd l gt igq¡p

बीआरसी और सीआरसी की संरचनाओं को अध्यापकों के लिए एक सहकर्मी सहायता तंत्र के रूप में संकल्पित किया गया था। अध्यापकों को सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित तीन चीजों को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। प्रथम, प्रधान अध्यापक/विद्यालय प्रिंसिपल की संरचनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सरकारें इस भूमिका के महत्व का मान करके और सभी विद्यालयों में एक प्रधान अध्यापक की उपस्थिति सुनिश्चित करके (रिक्ति पदों की संख्या निन्दास्पद है) तथा ऐसे व्यक्ति को रखकर जो सक्षम और अभिप्रेरित हो (केवल सबसे अधिक वरिष्ठ अध्यापक को नियुक्त कर देना कोई बहुत अच्छी नीति नहीं है) शुरूआत कर सकती हैं।

सरकारों द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के रूप में कार्यरत सभी में सामर्थ्य निर्माण किए जाने की भी आवश्यकता है।

दूसरे, अध्यापकों के लिए एक व्यवस्थित समावेशन कार्यक्रम होना चाहिए। वर्तमान में, नए अध्यापकों से केवल अपनी कार्यगत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को, बहुत कम औपचारिक मार्ग निर्देशन एवं सहायता के साथ, सीखने की अपेक्षा की जाती है। आरम्भ में, राज्यों को एक ऐसी पुस्तिका तैयार करनी चाहिए, जिसमें नए अध्यापकों को अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकारों से संबंधित जरूरी सारी सूचना उपलब्ध हो। तत्पश्चात, नए अध्यापकों के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक को – नए अध्यापक को मदद देने एवं प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी के साथ, ज्ञान गुरू नियत किया जाना चाहिए। और अंत में, राज्यों को नए अध्यापकों के लिए सामर्थ्य निर्माण की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

तीसरा, और अधिक स्पष्टता से, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सरकारों को विद्यालयों के आकार तथा विद्यार्थियों की संख्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए। बहुत से ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों तक विद्यालयों का फैलाव होने से बेशक बच्चों की स्कूल तक पहुंच बढ़ी है। तथापि, इससे अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालयों को बनाने में आवश्यक उचित संख्या में अध्यापकों की कमी (और उचित सहायता के बिना और प्राय: बिना उचित भौतिक ढ़ांचे वाले) छोटे विद्यालय पनप गए।

संख्या में कम तथा बड़े विद्यालयों में अध्यापक प्रबंधन ही सहज नहीं होगा बल्कि ऐसी पूरी संभावना है कि ऐसे विद्यालय हमारे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेंगे। अध्यापक प्रभावशालीपूर्ण तरीके से निष्पादन कर पाएं इसके लिए उन्हें यह जानना आवश्यक है कि उनके व्यावसायिक हितों और महत्वकाक्षांओं की रक्षा हेतु तंत्र उपलब्ध है। भारत सरकार को विभिन्य राज्यों की अच्छी परम्पराओं को आहरित करके शिकायत निवारण तंत्र पर एक राष्ट्रीय स्तर की चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। भारत सरकार ने सभी विद्यालयों और शिक्षा संबंधी संस्थानों यथा सीआरसी, बीआरसी, डीआईईटी, एससीईआरटी आदि को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2073 के अंतर्गत लाने के लिए राज्यों को उत्साहित करना चाहिए।"

¼x½ ç;kl vkSj fu'iknu dsfy, çkRlkgu

वर्तमान में पदोन्नतियां पूरी तरह से वरिष्ठता और अर्हताएं एकत्रित करने पर निर्भर करती हैं, न कि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्ति में मदद करने के वास्तविक कार्य के आधार पर। जिन राज्यों में निष्पादन को पुरस्कृत किए जाने संबंधी घोषणा की गई है (जैसेकि मध्य प्रदेश में संविदा अध्यापकों को पक्का करने के लिए), वहां पर भी हमें इस नीति को वास्तविकता में लागू किए जाने के सबूत शायद ही मिले हो।

यह महत्वपूर्ण है कि करियर प्रगति ढ़ांचों में अनुभव और अर्हताओं पर निर्भर न रहकर इसके बजाय प्रभावी निष्पादन को पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अध्यापक प्रभावी बनें।

वास्तव में, कर्नाटक को छोड़कर जहां दूरस्थ क्षेत्र में सेवा के वर्षों की गणना अध्यापक के स्थानान्तरण के अवसरों के संबंध में की जाती है, अध्यापकों को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई सकारात्मक प्रोत्साहन नहीं मिलता। अतिरिक्त भत्तों, उसी गांव अथवा विद्यालय के परिसर में मकान, निश्चित वर्षों के पश्चात, शहरी क्षेत्र में तैनाती में प्राथमिकता इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन बनाए जाने का विचार अच्छा हो सकता है। राज्य नीति को ग्रामीण अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यापन को एक सकारात्मक विकल्प के रूप में देखना चाहिए, जिसे अच्छे अध्यापक चुनना चाहे, ना कि 'अच्छी' तैनाती की प्रतीक्षा में एक सही जाने वाली लाचारी के रूप में।

करियर प्रगति के विषय पर एक अंतिम बिन्दू : विविध कैडरों के होने से भी अध्यापकों के लिए अपनी व्यावसायिक प्रगति करने में अधिक कठिनाई आती है, क्योंकि प्रायः पदोन्न्ति के लिए उन्हें अपने वर्तमान कैडर को छोड़ना पड़ता है और वापसी नहीं कर सकते – इस प्रकार, एक अध्यापक और अधिक प्रभावी प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए (प्राथमिक अध्यापक, उच्च प्राथमिक अध्यापक तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्र दल के सदस्य के रूप में) विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

¼?k½ mÙkjnkf;Ro vkSj fu"iknu ijçfrfØ;k

अध्यापक मूल्यांकन संभवतया राज्य के अध्यापक प्रबंधन तंत्रों का अत्यल्प–विकसित ही नहीं बल्कि सबसे अधिक विस्मृत भाग भी है। प्रभावी मूल्यांकन तंत्र की कमी का अर्थ है कि अध्यापकों को अपने निष्पादन के संबंध में कोई फीडबैक प्राप्त नहीं होगा और न ही उनके व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं के संबंध में कोई मार्ग निर्देशन प्राप्त होगा और न तंत्र प्रशासक आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाईन अथवा इसके लिए अनुबन्ध कर सकते हैं। एक मूल्यांकन तंत्र होने से पदोन्नति को भी केवल सेवा की अवधि के बजाय अच्छे निष्पादन के पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इससे आगे एक लाभ यह होगा कि घटिया निष्पादन के बाद भी बने रहने वाले गिनती के कुछ अध्यापकों को अध्यापन के व्यवसाय से हटाया जा सकेगा। इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए जाने की अपेक्षा है।

¼M-½ mUur vkadM+k ç.kkyh

एक पारदर्शी और योग्यता/अनुभव आधारित अध्यापक कैडर का प्रबंधन एक एकीकृत अध्यापक–एमआईएस द्वारा, जिसमें कार्मिक और तैनाती इतिहास उपलब्ध हो, प्रशिक्षण इतिहास दर्ज हो तथा अन्य अध्यापक–विशिष्ट सूचना उपलब्ध हो, बहुत ही उत्कृष्ट होगा। हालांकि बिहार इस अध्ययन में शामिल राज्यों में नहीं था, परन्तु बिहार में हाल ही में ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिसमें तकनीकी हल पहले से उपलब्ध हैं। एक मजबूत अध्यापक सूचना प्रणाली (क) पदोन्नति/वेतनवृद्धि/स्थाानान्तरण में प्रशासनिक अकुशलताओं यथा सेवा पुस्तिका/अध्यापक का अभिलेख के रखरखाव के कारण होने वाले विलम्ब को कम करेगी और (ख) अध्यापकों को उनकी आवश्यकताओं/पूर्व प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त करने में सक्षम बनाती है। यदि डीआईएसई और यूडीआईएसई अध्यापक विशिष्ट सूचना इस प्रणाली से एकत्रित करता है तो प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए भी समान रूप से अत्यधिक लाभदायक होगा। राज्य और जिला के कार्मिकों को इस प्रकार की प्रणाली का प्रभावी प्रयोग अपने निर्णय लेने में करने हेतु उच्च स्तर की क्षमता की आवश्यकता होगी।

यदि एकीकृत अध्यापक–एमआईएस में अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं को कैप्चर किया जा सकता तो अध्यापकों के किसे और किसके लिए वाले उत्तरदायित्व से संबंधित बहुत से मुद्दों का निवारण हो सकता। इसे दूसरी प्रकार से कहा जाए तो – इस प्रकार के एकीकृत अध्यापक एमआईएस को विकसित किया जाना अध्यापकों और राज्य सरकार की इस आपसी समझ पर निर्भर करता है कि अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी है और अतएव एमआईएस के माध्यम से किस प्रकार की सूचना एकत्रित की जानी चाहिए।

अंत में, जैसाकि रिपोर्ट दर्शाती है, विभिन्न राज्यों में बहुत सी प्रशासनिक समस्याएं येन–केन–प्रकारेण तैयार की गई नीतियों अथवा रीतियों (उदाहरणार्थ, सेवा नियमों में स्पष्टता की कमी के चलते अध्यापक लाभों के भुगतान में विलम्ब होना और कोर्ट केसों का उत्पन्न होना) के कारण उत्पन्न हुई थी। इस मुद्दे को हल करने का एक तरीका राज्य सरकार के लिए ये होगा कि नई नीतियों और क्रियाविधियों पर परामर्श लेने हेतु मसौदा–प्रलेख को प्रकाशित करके निश्चित अवधि के भीतर टिप्पणी आमंत्रित की जाए। इस तरीके से प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि होने के साथ–साथ, पारदर्शिता के प्रसार का अतिरिक्त लाभ भी होगा।

tkjh vuqla/kku
v/;;u
(31 मार्च, 2015 तक)

1- rfeyukMq vkSj vksfM'kk esa vkj-,e-,l-,- ds varxZr ftyk lSdsaMjh f'k{kk ;kstukvksa ds fodkl ij fØ;k&fu"B vuqla/kku ;kstuk

अन्वेषक : प्रो. एस. एम. आई. ए. ज़ैदी, प्रो. के बिस्वाल और डॉ. एन.के. मोहंती

यह अध्ययन आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत क्रिया–निष्ठ अनुसंधान के माध्यम से राज्यों द्वारा अपनी जिला सैकेंडरी शिक्षा योजनाएँ (परिप्रेक्ष्य और वार्षिक योजनाएँ) तैयार करने के लिए अनुसरण की जाने वाली योजना प्रक्रिया, कार्य–पद्धति और तकनीकों की आलोचनात्मक समीक्षा करने का एक प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य योजना निर्माण के लिए वर्तमान संदर्भ स्थितियों और संस्थागत, तकनीकी और अन्य बाधाओं को समझना और यह जानना है कि आर.एम.एस.ए. संरचना को किस हद तक कार्यान्वयन के लिए समझा गया है और सैकंडरी शिक्षा की योजना और प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर कितना लागू किया गया है।

इसके अध्ययन के अलावा जिला–स्तर पर योजना प्रक्रिया का अन्वेषण करने और डी.एस.ई.पी. के निर्माण में संस्थागत, तकनीकी और व्यावसायिक बाधाओं का आकलन करने संबंधी कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए, अध्ययन का लक्ष्य शैक्षणिक योजना में प्रभावी डिज़ाइन और क्षमता–निर्माण गतिविधियाँ प्रदान करने हेतु प्रशिक्षकों के रूप में न्यूपा संकाय की व्यावसायिक क्षमताओं को सवंर्धित करने के लिए क्रिया–निष्ठ अनुसंधान के माध्यम में अतिरिक्त ज्ञान सृजित करना है। इस संदर्भ में, तमिलनाडु और ओडिशा में क्रिया–निष्ठ अनुसंधान कार्यान्वित किया जा रहा है। तमिलनाडू में चार जिलों (सेलम, थेनी, कुड्डुलोर, मदुरै) और ओडिशा के दो जिलों (क्योनझार और गंजाम) को अनुसंधान कार्यान्वित करने के लिए चुना गया।

अब तक, संबद्ध साहित्य की समीक्षा की जा चुकी है। अनुसंधान दल के प्रतिदर्श राज्यों में राज्य और जिला योजना दलों के साथ अंतःक्रिया के कई दौर हुए। सामान्य रूप में विद्यालय शिक्षा में, जिला योजना के और विशेष रूप में, आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत योजना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए दो कार्यशालाएँ और चार परामर्शी बैठके आयोजित की गईं। संरचित डी.सी.एफ.एस. तैयार किए गए और प्रयोग से पहले संगत मात्रात्मक और गुणात्मक आँकड़े एकत्रित करने के लिए उनका परीक्षण किया गया। सामूहिक कार्य, फोकस, समूह चर्चाएं, क्षेत्र अवलोकन, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार के साथ जिला और उप–जिला स्तरीय प्रशासनिक इकाइयों और विद्यालयों के क्षेत्र के दौरे किए गए। आँकड़ों का कूट–लेखन, उनको फीड करने (feeding) और डाटा परिमार्जन (cleaning) का कार्य किया जा चुका है। टी.एस.जी., आर.एम.एस.ए., भारतीय जनगणना, एन.एस.एस.ओ. और यू.डी.आई.एस.ई. जैसे स्रोतों से एकत्रित किए गए उन आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है। प्रतिदर्श राज्यों के आर.एम.एस.ए. योजना दस्तावेजों की समीक्षा की गई। क्रिया–निष्ठ अनुसंधान की प्रथम अवस्था की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया। क्रिया–निष्ठ अनुसंधान की दूसरी अवस्था में अंतःक्षेप जारी हैं। इसके निष्कर्षों को साझा करने के लिए राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के साथ मार्च 2016 में अनुसंधान संपन्न हो जाएगा।

2- Hkkjr esa ek/;fed f'k{kk ds izlkj dh laHkkO; %izkjfHkd f'k{kk ds fo|kFkhZ&izokg iSVuZ vkSj lao/kZu {kerk dk fo'ys"k.k

अन्वेषक : प्रो. के. बिसवाल

यह अध्ययन 2009 में प्रो. कीथ लूइस (सुजैक विश्वविद्यालय, यू.के.) द्वारा और न्यूपा दल द्वारा आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत भारत में सैकेंडरी शिक्षा के प्रसार के लिए नीति–मार्गदर्शक नोट तैयार करते समय किए गए पिछले कार्य का विस्तार है। इस अनुसंधान का लक्ष्य प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से सैकेंडरी स्तरों में संक्रमण दरों के सम्भावित विकास को ध्यान में रख कर सैकेंडरी विद्यालय में प्रारंभिक स्तर के माध्यम से राज्यवार प्रवाह दरों का आंकलन करना है। यह लक्ष्य यू.डी.आई.एस.ई. आंकडे और अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (ए.आई.एस.ई.एस.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रकाशनों, भारतीय जनगणना इत्यादि जैसे अन्य स्रोतों के आंकडों का प्रयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन में विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी प्रवाह का आकलन करने के

लिए ओडिसा और तमिलनाडू को दो प्रतिदर्श राज्यों के रूप में लिया गया है।

bl v è; ; u d s mn n ś; fu Eu fy f[kr gS %

(i) ग्रेड 10 को आधार बनाकर ग्रेड 1 से विद्यार्थी प्रवाह के गतिकी को समझना चूँकि ये सैकेंडरी विद्यालय के प्रसार की गतिकी और लागतों को प्रभावित करते हैं।

(ii) विद्यार्थी प्रवाह प्रतिमानों पर आधारित राज्यों और जनसंख्या उप–समूहों के समूहों की पहचान करना/पता लगाना जिन्हें नियत लक्ष्यों को प्रप्ति की संभावना के विभिन्न स्तरों को दर्शाने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

(iii) आर.एम.एस.ए. और प्रेरित विद्यार्थी प्रवाह द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बीच अंतराल का पता लगाना और पता लगाई गई वृद्धि पर इन्हें मुख्य बाधाओं से संबद्ध करना।

(iv) सैकेंडरी विद्यालय के प्रसार की विभेदक दरों की लागतों और निहितार्थों (आशयो) का आकलन करना और सैकेंडरी शिक्षा की क्षमता में विस्तार के लिए निवेश के वर्तमान स्तरों के साथ इनकी तुलना करना।

(v) विभिन्न समुदायों में सैकेंडरी विद्यालय की पहुँच को विस्तृत करने के लिए आपूर्ति और मांग को आकार देने वाले तथा प्रभावित करने वाले घटकों को समझने के लिए केस अध्ययनों और लक्ष्यानुसरण अध्ययनों (अवस्था 2 में) की योजना बनाना व उन्हें प्रारंभ करना।

अभी, संगत आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, और संबद्ध साहित्य की समीक्षा की जा रही है। गौण आंकड़ों के आधार पर, मुख्यतः यू.डी.आई.एस.ई. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रकाशनों और भारतीय जनगणना, के आंकड़ो से तमिलनाडू के लिए प्रक्षेपण मॉडल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

3- mPp ' k$kf. kd i zo`t u d s d kj. kksa v k$ i fj. kke ksa d s LFkkfu d i fji {; % fgekpy ; i zn's k d k d s$ v è; ; u

अन्वेषक : डॉ. सुमन नेगी

संबद्ध साहित्य की समीक्षा और आंकड़े एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। गौण आंकडों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक और शिक्षा प्रोफाईल के दो अध्ययनों की रूपरेखा का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रव्रजन से संबंधित आंकडे (जनसंख्या 2011 की तालिका डी2 और डी3) पूरी हो चुकी हैं। डी 4 की प्रव्रजन तालिकाओं की छंटाई का कार्य चल रहा है। सभी राज्यों के लिए अंतिम तालिकाएं बनाई जा चुकी हैं। प्रश्नावलियाँ तैयार हो चुकी हैं और कुल्लू जिले के दो गाँवों में स्वचालित है। क्षेत्र कार्य नवम्बर 2014 को पूरा हो गया था। पहले पाँच अध्यनों के प्रारूप की रूपरेखा का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यतः प्राथमिक आंकडे का विश्लेषण चल रहा है। दो जिलों से एकत्रित किए गए आंकड़ों से एम.एस.एक्सेल में डाल दिया गया है। एस.पी.एस.एस. में आंकड़ा परिमार्जन, छंटाई और कोडिंग का कार्य प्रगति पर है।

4- t sMj i j , d f' k{kk&, Vy l % , d ft y k&Lr j h; i zLr qfr

अन्वेषक : डॉ. सुमन नेगी और प्रो. मोना खरे

मानचित्र उपयोगी सूचना का दृश्य रूप प्रस्तुतिकरण हैं, जो विचारों और डिज़ाइनों को अभिव्यक्त करते हैं। आकड़ों की श्रृंखला (सीरिज़) के रूप में स्थानिक सूचना के प्रतिरूप और उन्हें संगठित करने के लिए ये एक प्रभावी रूपक प्रदान करते हैं। आज शिक्षा और शिक्षण संसाधनों में/के रूप में इन भौगोलिक या बिम्ब निरूपणों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। 'मानचित्र' साधन के महत्व के मद्देनज़र 'मानचित्र' के माध्यम से विभिन्न चीज़ों के लिए सूचना की प्रस्तुति की जा सकती है, इनमें एक शिक्षा और उससे संबद्ध घटक भी है जिन्हें इस माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है।

इस शैक्षणिक आंकडे के प्रसार को आगे बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रसार के अन्य पूरक तरीकों का भी अन्वेषण किया जा सकता है। इनमें एक है जी.आई.एस. और एटलस के रूप में मानचित्र आधारित सूचना–प्रसार, जो विश्व भर में एक प्रभावी माध्यम है।

भारत जैसे विविधता वाले देश में असंख्य विषमताओं और भेदभाव के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जेंडर असमानता प्रमुख क्षेत्रों में से एक हैं, जहाँ समूचे सामाजिक–आर्थिक पहलुओं में विषमता दृष्टिगत होती है और इस प्रक्रिया में शिक्षा भी पीछे नहीं है। शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं में संबंधित आंकड़े

पहुँच (सुलभता) और सामाजिक के संदर्भ में जेंडर में व्याप्त भिन्नताओं को दर्शाते हैं, और यह पहलू ग्रामीण जनसमूह, उपेक्षित जातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में ज्यादा दृष्टिगत होता है।

इस संबंध में, इस अध्ययन में उन शिक्षा आंकड़ों को उपयोग करने का प्रयास किया गया है जिन्हें न्यूपा एकत्रित व समेकित करता है और पूरे भारत के विभिन्न जिलों में इन जेंडर–अंतरालों को सुव्यवथित करता है। प्रदर्शित सूचकों की पुष्टि के लिए आंकड़ा निरूपणों के अन्य रूपों के साथ एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक नोट भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल शैक्षणिक योजना, नीति–निर्माण, शिक्षकों और अनुसंधान में जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अनुसंधान प्रक्रिया में योगदान और इसके परिणाम मुख्यतः आँकड़ा समुच्चयों, के माध्यम में निरूपित किए गए। यहाँ हमारा उद्देश्य शैक्षणिक विकास के इन सूक्ष्म भेदों को दर्शाना और मानचित्र साधनों का प्रयोग करके इसे मानचित्रों द्वारा निरूपित करना है।

míś; vkSj visf{kr ifj.kke

अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) जेंडर से जुड़े चयनित सूचकों को निरूपित करने के लिए डी.आई.एस.आर. और यू.डी.आई.एस.ई. आंकड़ों का प्रयोग करना।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कालसापेक्ष (कालिक) प्रवृत्तियाँ को निरूपित करना।

(iii) सांख्यिकीय रूप में परिकलित आंकड़ा प्रवृत्यिों को भी निरूपित करना।

fØ;k&fofèk

यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई डी.ई.वी.इन्फो. (DevInfo) प्रणाली का प्रयोग करके मानचित्र बनाए जाएँगे। जिला इस साफ्टवेयर में उपलब्ध सीमाओं का तीसरा और निम्नतम स्तर है और इस विशिष्ट अध्ययन में आंकड़े इस और इससे ऊपर के स्तर को निरूपित कर रहे हैं। न्यूपा के ई.एम.आई.एस. विभाग को यह सॉफ्टवेयर यूनिसेफ द्वारा प्रदान किया गया है और इस परियोजना के लिए इसे साझा करने के लिए तैयार है। डी.आई.एस.ई. और यू.डी.आई.एस.ई. आंकड़ों का प्रयोग उन विभिन्न चुने गए सूचकों को निरूपित करने के लिए किया जाएगा जो शैक्षणिक पहुँच और सहभागिता में जेंडर अंतराल को व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सूचकों और संबद्ध सूचकों से संबंधित कालिक प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विश्लेषण का प्रयोग निरूपण के लिए भी किया जाएगा।

fu:fir fd, x, dqN lwpd fuEufyf[kr gSa%

- विद्यालय शिक्षा में उत्तरजीविता दरें
- विशिष्ट आय समूहों में जनसंख्या वृद्धि
- प्रक्षेपित जनसंख्या और उसकी वृद्धि
- कुल नामांकन अनुपात
- निविल (नेट) नामांकन अनुपात
- विद्यार्थी उपलब्धि और पुनरावृत्ति
- जेंडर समता (समानता) सूचकांक

वर्तमान में आँकड़ा–संग्रहण के लिए अनिवार्य साधन विकसित किए गए हैं, और संगत आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

5- Hkkjr esa lSdsaMjh f'k{kk esa lkoZfud vkSj futh feJ.k %vkdkj] fo|ky; esa mifLFkfr lqfoèkk,a vkSj izos'k izksQkbZ

अन्वेषक : डॉ एन.के. मोहंती और प्रो. एस.एम. आई.ए. ज़ैदी

सामान्यतः शिक्षा में निजी क्षेत्र और शिक्षा सेवा प्रदान करने में सार्वजनिक–निजी सम्मिश्रण की भूमिका पर विचार–विमर्श (चर्चा) को ध्यान में रखते हुए इस बृहद स्तर के अध्ययन का लक्ष्य प्रबंधन और क्षेत्र द्वारा सैकेंडरी विद्यालय नेटवर्क के आकार और संरचना, सुविधाओं के संदर्भ में उनकी विशेषताओं कर्मचारी अभिविन्यास और देश भर के राज्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थी प्रोफाइल पर विचार करना है। आय–वर्ग के आधार पर राज्य में जनसंख्या वितरण के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों में सहभागिता दरों को संबद्ध करने का प्रयास भी किया जाएगा। यह प्रबंधन द्वारा सैकेंडरी शिक्षा में सहभागिता दरों में प्रतिमान और समानता के लिए उनके निहितार्थ ज्ञात करने में सहायक हो सकता है, विशेष रूप से सैकेंडरी विद्यालयी प्रावधानों

में क्षेत्रीय असंतुलनों पर विचार करने के लिए आर.एम.एस.ए. कार्यनीतियों और राज्य भूमिका की छानबीन करने के लिए।

उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों (पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) में सैकंडरी विद्यालय नेटवर्कों के बाजार प्रेरित निर्माणों के बजाय सांस्थनिक रूप से प्रेरित निहितार्थों में जाँचने में सहायक होगा। यह अध्ययन विभिन्न राज्यों में जिस तरह से सैकेंडरी शिक्षा को व्यवस्थित और प्रदान किया जाता है, उससे संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

विशिष्ट रूप से अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) प्रांरभिक और सैकेंडरी स्तरों पर संस्थागत मिश्रण (निजी और सार्वजनिक) के पैटर्न को स्थापित करना;

(ii) विद्यालय में उपलब्ध प्रावधानों, कर्मचारी अभिविन्यास और प्रवेश विशेषताओं द्वारा निजी और सार्वजनिक संस्थानों को रूपरेखा बनना;

(iii) विद्यालयों के मिश्रण के संदर्भ में व्यापक पहुँच के लिए आर.एम.एस.ए. हेतु निहितार्थ और समता के संभावित प्रभावो का पता लगाना; और

(iv) आर.एम.एस.ए. के तहत योजना के लिए निहितार्थ निकालना और संसाधनों का आबंटन।

अध्ययन में प्रमुख राज्यों में सैकेंडरी विद्यालय नेटवर्क की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया जाएगा और राज्यों में सैकेंडरी शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों के प्रति संस्थागत और उत्तरदायी कारको का पता लगाने का प्रयास करेगा (उदाहरण के लिए, सरकारी असहायता प्राप्त संस्थानों या सहायता प्राप्त संस्थानों या सरकार द्वारा प्रबंधित संस्थानों का बड़ा हिस्सा)। यह सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों की रूपरेखा भी तैयार करेगा। (सैकेंडरी स्तर पर प्रवेश आकार, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और सहभागिता दरों और समूह की सामाजिक–आर्थिक विशेषताएँ के संदर्भ में)। राज्यों में सैकेंडरी शिक्षा वितरण प्रणालियों और समता व गुणवता को बेहतर बनाने के लिए उनके निहितार्थों के संबंध में अंतर्दृष्टि (जानकारी) प्रदान करेगा।

सैकेंडरी आंकड़ा विश्लेषण के आधार पर राज्यों के चयन का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। संबद्ध साहित्य की समीक्षा की जा रही है। यू.डी.आई.एस.ई., एन.एस.एस.ई. और भारतीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

6- 'kSf.kd iz'kklu dk rr̀h; vf[ky Hkkjrh; losZ{k.k

अन्वेषक : डॉ. आर.एस. त्यागी

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) दो शैक्षणिक प्रशासन सर्वेक्षण कर चुका है (पहला, 1973 में और दूसरा 1990 में), जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण का मूल प्रयोजन शैक्षणिक प्रशासन की प्रतिस्थिति और प्रणाली की परिवर्तनशील मांगों के प्रति अनुक्रियाशीलता की छानबीन करना था। पिछले दो दशकों के दौरान कई नीति पहलों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरूआत की गई जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप–जिला और संस्थागत स्तरों, पर प्रशासनिक संरचनाओं और कार्य प्रणाली में सुधार एवं बदलाव हुए हैं। इन पहलों और अंतःक्षेपों से शैक्षणिक शासन में नए आयाम जुड़े हैं। विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक प्रशासन की स्थिति की छानबीन करने के लिए और शैक्षणिक शासन में परिवर्तनों की योजना बनाने के लिए तथा शैक्षणिक प्रशासन और शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए कई विषय संबंधी अध्ययनों के लिए न्यूपा ने 2013 में तीसरा अखिल भारतीय शैक्षणिक प्रशासन सर्वेक्षण प्रारंभ किया।

losZ{k.k ds fof'k"V mís'; bl izdkj gS%

- सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की संरचनाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में शैक्षणिक प्रशासन की वर्तमान प्रतिस्थिति का निरीक्षण करना;
- शैक्षणिक प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए लिए पद्धति–निर्मित करने हेतु कार्यनीतियाँ तैयार करने के लिए प्रमुख मुद्‌दों और अंतक्षेप क्षेत्रों की पहचान करना; और
- राष्ट्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर विद्यालय–शिक्षा के शासन में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

,d cM+s ¼c`gÙkj½ losZ{k.k ds :Ik esa fuEufyf[kr vè;;u vkSj xfrfofèk;k¡ dh xbZ%

- डॉ. आर.एस. त्यागी द्वारा केरल शैक्षणिक प्रशासन पर प्रायोगिक/अग्रगामी अध्ययन;
- डॉ. मंजू नरुला द्वारा बिहार में शैक्षणिक प्रशासन पर प्रायोगिक अध्ययन; अंतिम रूप दिए जाने की अवस्था में।
- इन प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर तीसरे सर्वेक्षण के लिए साधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है; और
- प्रो. कुमार सुरेश द्वारा मध्य प्रदेश और बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों के दायित्वों और क्षमता पर अध्ययन।

अब तक, राज्यों के साथ संस्थागत व्यवस्थाएँ की गई हैं और सर्वेक्षण करने के लिए आंकड़ा संग्रहण साधन विकसित कर लिए गए हैं। केरल और बिहार में अध्ययन की रिपोर्टों को बनाने का काम प्रगति पर है। बिहार और केरल में प्रारंभिक अध्ययन किए गए। आजकल राज्यों में सर्वेक्षण चल रहा है।

7- eè; izns'k vkSj fcgkj esa izkjafHkd f'k{kk ds izca/ku esa LFkkuh; fudk;ksa ds lkS>s nkf;Roksa vkSj {kerk ij vè;;uA

अन्वेषक : प्रो. कुमार सुरेश

इस अध्ययन में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन में राज्य और स्थानीय निकायो के बीच संबंध के स्वरूप की योजना बनाने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास किया गया है। संबंध की योजना बनाने के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर पर, इसका लक्ष्य राज्य अधिनियमों, सरकारी आदेशों और परिपत्रों के माध्यम से उन्हें प्रदत शक्ति (अधिकार) और दायित्वों के आधार पर स्थानीय निकायों की सक्षमता की जाँच करना है। जाँच के दूसरे स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि आनुभविक रूप से बुनियादी स्थिति में स्थानीय निकायों के बीच शक्ति और दायित्वों को कितना साझा किया गया है।

चूँकि संगत अधिनियम, परिपत्र, सरकारी आदेश अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटकों में से है, अधिकांश संबद्ध दस्तावेज़ बिहार से एकत्रित करके और समीक्षा कर ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और स्थानीय निकायों के बीच संबंध से संबंधित संगत आकड़े एकत्रित करने के प्रयोजन से प्रतिदर्श राज्यों में क्षेत्र दौरे किए गए। संगत आंकड़ें और सूचना को संसाधित किया जा चुका है। मसौदा रिपोर्ट लिखने का कार्य चल रहा है।

8- vkaèkz izns'k vkSj mÙkj izns'k esa izkjafHkd voLFkk esa eqfLye cPpksa ds xSj&ukekadu vkSj i<+kbZ@Ldwy chp esa gh NksM+us (Drop-out) ds dkj.k %,d rqyukRed vè;;u

अन्वेषक : डॉ. वी.पी.एस. राजू

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य भारत के दो राज्यों में प्रारंभिक अवस्था में मुस्लिम बच्चों के गैर–नामांकन और पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के कारणों का पता लगाना है। तदनुसार प्रारंभिक अवस्था में मुसलमानों में गैर–नामांकन और स्कूल बीच में ही छोड़ने के कारणों के मुद्दे पर विचार करके शोध/शैक्षिक कार्य के स्वरूप का प्रारंभिक आकलन करने के लिए उपलब्ध साहित्य की समीक्षा का कार्य पूरा हो गया है। साहित्य समीक्षा दर्शाती है कि कोई भी ऐसा सारगर्भित अनुसंधान या शैक्षिक साहित्य नहीं मिला जिसमें प्रारंभिक स्तर पर मुसलमानों में ग़ैर–नामांकन और स्कूल बीच में ही छोड़ने के विषय में काम किया हो। इसके अलावा, एन.एस.एस.ओ., डी.आई.एस.ई. और जनगणना रिपोर्टों से संगत गौण आंकड़े भी एकत्रित किए जा चुके हैं। आजकल, अनुसंधान रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य चल रहा है।

9- Hkkjr esa bathfu;fjax f'k{kk dh o`f)

अन्वेषक : प्रो. जे.बी.जी. तिलक

बी.आर.आई.सी. देशों में उच्च शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन के एक हिस्से के रूप में 2009.2010 में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडू में भारत के लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों के बड़ी मात्रा में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। यह सर्वेक्षण छात्र इन संस्थानों के विद्यार्थियों की विशेषताओं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा पर व्यय और इंजीनियरिंग शिक्षा पर गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी आंकडे प्रदान करता है।

विगत में भारत में ऐसे बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। निर्धारित अध्ययनों में शामिल हैं 1962 में दिल्ली

विश्वविद्यालय पर वी.के.आर.वी. राव द्वारा किया गया अध्ययन, 1970 के दशको में पश्चिम बंगाल में विकास सन्याल द्वारा आई.आई.ई.पी. अध्ययन।

वित्तीयन, शुल्क, लोन और अन्य पहलुओं से संबंधित नीति–निर्माण के लिए विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का विस्तृत विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण होगा। अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन पूरा हो चुका है और अंतिम परिणाम पुस्तक के रूप में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किए गए। भारत पर इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित किए गए आंकड़ो का प्रयोग करके भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की वृद्धि पर अध्ययन तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर फोकस किया गया है:

- इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए वृद्धि : सार्वजनिक और निजी
- इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में कौन से विद्यार्थी जाते हैं
- इंजीनियरिंग शिक्षा की माँग के निर्धारकों की छानबीन करना
- प्राइवेट शिक्षा की वृद्धि को स्पष्ट करने वाले कारक
- इंजीनियरिंग शिक्षा की लागतें (घरेलू और निजी)

अध्ययन की रिपोर्ट लिखने का कार्य प्रगति पर है; कुछ अध्यायों के प्रारूप पूरे हो चुके है और शेष पर कार्य चल रहा है।

10- ,l-,l-,- ds varxZr fo|ky; vuqnkuksa dk mi;ksx vkSj mudsmi;ksx iSVuksZ ij vè;;u %es?kky; dk ds vè;;u ¼U;wk lsfcuk fdlh vkfFkZd lgk;rk ds½

अन्वेषक : प्रो. वाई जोसेफीन

सर्वशिक्षा अभियान इस आधार–वाक्य पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा अंतःक्षेपों को वित्तीय सहायता जारी रखी जानी चाहिए। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य होना आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत सहायता का अनुपात पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90:10 और शेष भारत के लिए 65:35 होगा।

केन्द्र से मेघालय और उसके जिलों को दिए गए फंडो और एस.एस.ए. के अंतर्गत विद्यालय अनुदानों के उपयोग का विश्लेषण किया गया। यह कार्य मुख्यतः राज्य से एकत्रित किए गए प्राथमिक आंकड़ो और डाईस/यू. डाईस और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के गौण आंकड़ों के आधार पर किया गया।

आंकड़ों और संबद्ध सूचना का प्रारंभिक विश्लेषण दर्शाता है कि एस.एस.ए. के अंतर्गत बजट प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना और बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी.) के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें एस.एस.ए. मानदंडो में विर्निदिष्ट सभी अंतःक्षेपों को शामिल किया गया है। एक वर्ष के लिए मद–वार बजट मांगें वार्षिक कार्य–योजना और बजट में शामिल हैं। ए.डब्ल्यू.पी. एंड. बी. प्रस्तावों पर दो भागों में विचार किया गया – चालू वर्ष के लिए योजना और पिछले वर्ष की प्रगति का सिंहावलोकन जिसमें चालू वर्ष की पिछली (शेष/बची) `चपससवअमत गतिविधियों को चालू वर्ष में ले जाने का प्रस्ताव शामिल है।

वित आयोग भी राज्य सरकार के जरिए समाज के कुल बजट परिव्यय के लिए सहायता अनुदान के रूप में फंड प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, बारहवें वित आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य प्रत्येक राज्य के एस.एस.ए. के लिए अनुमानित व्यय के 15% अनुदान की सिफारिश की थी। पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में, 12वें वित आयोग ने वर्ष 2007–08 और वर्ष 2008–09 में प्रत्येक राज्य द्वारा दी गई औसत राशि और 10% शेयर के आधार पर जितनी राशि की उन्हें जरूरत है, के बीच अंतर की सिफारिश की, बशर्ते जो कि प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 करोड़ रूपए हो।

अनुमोदित परिव्यय के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10 का साझा पैटर्न वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान की कटौती के बाद है। पी.ए.बी. की दिनांकों के आधार पर, भारत सरकार एस.एस.ए. राज्य सोसायटी की पहली किस्त जारी करती है और आगे की किश्तें केवल तभी जारी की जाती हैं जब राज्य सरकार को उसको अनुरूपयोगी (अनुरूप) हिस्सा हस्तांतरिक कर देता है और हस्तांतरित फंडों (केन्द्र और राज्य) का कम से कम 50: व्यय कार्य योग्य हो।

चालू वर्ष में अनुमोदित बजट परिव्यय के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना कार्यालयों को इसे जारी करता है। राज्य परियोजना कार्यालय भारत सरकार और राज्य सरकार से इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जिलों को उनका फंड जारी करता है। जिला स्तर पर भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। जिला परियोजना कार्यालय इसे उप–जिला और खंड संसाधन केंद्र और समूह संसाधन केंद्र को जारी करता है ताकि कार्यान्वयन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रत्येक जिला कार्यालय को चालू वर्ष का जिला बजट प्रदान किया जा रहा था जिसमें फंड बजट के अनुसार खर्च किए गए थे। सिविल कार्यों, अध्ययन–अध्यापन उपकरण, विद्यालय

अनुदानों, वार्षिक अनुदानों के लिए प्रयुक्त सभी फंड सोसायटी में अपनाई गई विकेन्द्रीकरण विधि के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति स्तर को हस्तांतरित कर दिए गए।अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

11- f'k{kk _.kksa ij C;kt &vkfFkZd lgk;rk dh dsUnzh; &lsDVj ;kstuk dk ewY;kadu % ykHkkfFkZ;ksa ds lkekftd &vkfFkZd izksQkbZy dk ,d fo'ys"k.k

अन्वेषक : डॉ. गीता रानी

भारत सरकार ने अपने वर्ष 2009–10 के संघ बजट में भारतीय बैंक एसोसिएशन की शिक्षा लोन योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में लिए गए लोनों को कवर (cover) (वसूली) करने के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पूरक योजना प्रारंभ की। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने ब्याज आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करना है। योजना के पूरक उद्देश्य है समानता सार्वजनिक जवाबदेही और नवप्रर्वतन को संवंर्धित करना। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं (जिनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष 4–5 लाख से कम है) और उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखते हैं।

इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि शिक्षा लोन पर केन्द्रीय सेक्टर की ब्याज आर्थिक सहायता योजना से कौन लाभान्वित होते हैं। तदनुसार इस मूल्यांकन से निम्नलिखित शोध प्रश्न उठते हैं:

- सामाजिक समूहों को प्रदान की गई (द्वारा ली गई) ब्याज आर्थिक सहायता में क्या कोई विसंगमित है?
- आर्थिक समूहों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता में क्या कोई विसंगति है?
- राज्यों को प्रदान की गई ब्याज आर्थिक सहायता में क्या कोई विसंगति है?
- बैंकों को प्रदान की गई ब्याज आर्थिक सहायता में क्या कोई विसंगति है?

इस मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- समूह द्वारा प्राप्त की गई ब्याज आर्थिक सहायता में असमानता की छानबीन करना।
- समूह द्वारा प्राप्त की गई ब्याज आर्थिक सहायता के वितरण की छानबीन करना।
- समूह द्वारा प्राप्त की गई ब्याज आर्थिक सहायता में विसंगति का आकलन करना।
- समूह द्वारा प्राप्त की गई ब्याज आर्थिक सहायता में भिन्नताओं का विश्लेषण करना।

बैंकों से प्राप्त किए गए आंकडें इसमें प्रस्तावित अनुसंधान प्रश्नों और उद्देश्यों की छानबीन करने में प्रयुक्त होंगे। अब तक संगत आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं। आंकड़ा–परिमार्जन और एकरूपता की जाँच का कार्य प्रगति पर है।

12- pqus x, jkT;ksa esa eqDr vkSj vfuok;Z f'k{kk ds vf/kdkj ds varxZr fut h fo|ky;ksa esa det+ksj oxksZa vkSj lqfo/kkoafpr lewgksa ds cPpksa ds fy, 15% lhVksa ds lao/kkfud izko/kku dk v/;;u

अन्वेषक : प्रो. अविनाश कुमार सिंह

मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के कार्यान्वयन के साथ अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत राज्यों में निजी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कमजोर वर्गों और सुविधावंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें प्रदान करनी प्रारंभ कर दी हैं। यद्यपि अधिनियम के कार्यान्वयन का यह चौथा वर्ष है फिर भी प्रावधानों से संबंधित नियमों और विनियमों को कार्यान्वित करने के संबंध में कार्याकर्ताओं को ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, बच्चों की पहचान करने और चयन के लिए पात्रता मानदंड का अनुसरण कैसे किया जा रहा है? विभिन्न राज्यों में निजी विद्यालय संविधानिक प्रतिबद्धताओं और प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियमों और विनियमों का अनुसरण किस प्रकार कर रहे हैं? इन अधिकारो को प्राप्त करने के लिए बच्चों और अभिभावकों को किन समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? आर.टी.ई. प्रावधान के कार्यान्वयन में अंतर और अंतरा राज्य दोनों में भिन्नताओं की सूचना है। इस संदर्भ में, देश के पाँच अलग–अलग जोनों में व्याप्त 10 चुने गए राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुविधावंचित बच्चों की शिक्षा की नीति और पद्धति (प्रचलन) की समझ को विकसित करने के लिए अन्वेषी अध्ययन का आयोजन किया जा

रहा है। इस अध्ययन के मुख्य उद्‌देश्य हैं (क) नीति और पद्धति के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में आर.टी.ई. अधिनियम के तहत आरक्षण प्रावधान के कार्यान्वयन का स्वरूप और सीमा का निर्धारण करना; (ख) सुविधावंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणियों के बच्चों और माता–पिता में आरक्षण प्रावधानों संबंधी जागरूकता के स्तर का पता लगाना; (ग) विद्याालय और कक्षा में विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के समायोजन से संबंधित मुद्‌दों की जाँच करना; (घ) विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वियन के संबंध में नवीन प्रचलनों का पता लगाना; (ड.) विभिन्न सहयोगियों (स्टैकहोल्डरो), माता–पिता, बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा कार्यकर्ताओं को आर.टी.ई. प्रावधानों के कार्यान्वयन में जो समस्याएँ और बाधाएँ आती है उनका पता लगाना; और (च) निजी विद्यालयों में आरक्षण संबंधी आर.टी.ई. प्रावधान की योजना और कार्यान्वयन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उपुयक्त उपाय सुझाना।

उपर्युक्त अनुसंधान परियोजना कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था है जिसके अंतर्गत अनुसंधान साधनों के वर्ण्य–विषय और विकास से संबंधित साहित्य का संकलन और समीक्षा शामिल हैं।

इसके अलावा, आंकड़ें एकत्रित करने के साधनों के फॉर्मेट तैयार हो रहे हैं, निम्नलिखित साधन डिज़ाइन किए गए:

- घरेलू/पारिवारिक सूचना अनुसूचियाँ
- विद्यालय सूचना अनुसूची
- मुख्याध्यापक और अन्य अध्यापकों के लिए अनुसूची
- सुविधावंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अनुसूची
- इन बच्चों और अन्य समुदाय सदस्यों के माता–पिता के लिए अनुसूचियाँ
- विद्यालय संचालन समितियों के सदस्यों के लिए अनुसूचियाँ
- विभिन्न स्तरों (समूह, खंड, जिला, राज्य) पर शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए जाँच सूचियाँ

13- fo|ky;ksa esa *fof'k"V lh[kus dh v{kerk okys ¼vfèkxe v'kDrrk½* cPpksa ds lekos'ku ds fy, uhfr vkSj i)fr;ksa ¼iz;ksx½ dk ,d vè;;u

अन्वेषक : डॉ. वीरा गुप्ता

विद्यालय शिक्षा में बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली अक्षमताओं के विभिन्न स्वरूप के प्रति बढ़ती जागरूकता से अधिगम अक्षमता शिक्षा और नीति सरोकार के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरी है। आर.टी.ई. अधिनियम 2009 और पी.डब्ल्यू.डी. विधेयक–2012, दोनों ने समस्या से निपटने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में अधिगम अशक्तता को शामिल किया है। यद्यपि नीति प्रयास किए जा रहे हैं तथापि निर्धारण (आकलन) और कार्यक्रम संबंधी अंतःक्षेपों के संबंध में संस्थागत और विद्यालयी स्तरी पर ज्यादा स्पष्टता नहीं है। अधिगम अक्षमता के स्वरूप और सीमा के संबंध में राज्यों में अत्यधिक भिन्नता है। अड़मान निकोबार में 0: एस.एल.डी. है जबकि गोवा में 45: एस.एल.डी है (डी.आई.एस.ई., 2011–12)। यह समझने की जरूरत है कि नीति और प्रचलनों के संदर्भ में अधिगम–विशिष्ट अशक्तता से संबद्ध वर्तमान और उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विद्यालय और संस्थागत स्तरो पर अधिगम अशक्तता की संकल्पना किस प्रकार संचालित है। प्रस्तावित अनुसंधान इस दिशा में एक वास्तविक कदम है। तथापि भारत में एस.एल.डी. पर नीति नवजात अवस्था में है, क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रचलनों के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए समन्वेषी अध्ययनों की आवश्यकता है।

प्रस्तावित अध्ययन का लक्ष्य नीति और नीति–क्रिया–विधियों के निर्माण के लिए साक्ष्य फीड करने के उद्‌देश्य से आधारभूत स्तर पर यथार्थता का पता लगाना है। इसलिए, अध्ययन में प्रस्तावित है कि डिसलेक्सिया के विशेष संदर्भ में स्कूली शिक्षा में अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को समावेशित करने की नीति और अभ्यास की छानबीन की जाए।

bl vè;;u ds eq[; y{; gSa%

क) अधिगम विशिष्ट अक्षमता की समस्या का स्वरूप और सीमा तथा नीतियों और पद्धतियों के संदर्भ में अनुसरणशील कार्यक्रम अंतःक्षेपों को सुनिश्चित करना।

ख) भारत के विशिष्ट राज्यों में एस.एल.डी. की पहचान, परामर्श और शैक्षिक अंतःक्षेप के लिए राज्य व जिला स्तरीय नीतियों और व्यवहारों का अध्ययन करना।

ग) एस.एल.डी. से अधिगगम परिणामों पर कार्यक्रम अंतःक्षेपों के प्रभाव और क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रचलनों संबंधी दस्तावेज का अध्ययन करना।

घ) आकलन, निदान, शिक्षण नीतियों और कार्यक्रम प्रावधानों के लिए एस.एल.डी. पर नीति–निर्धारण के लिए योगदान (आगत) प्रदान करना।

यह अध्ययन बी.आर.सी. और विद्यालय स्तर पर गौण दस्तावेजों के विश्लेषण और क्षेत्र आधारित अनुभवजन्य (आनुभविक) आंकड़े दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। इसमें एस.एल.डी. की पहचान, आकलन और अंतःक्षेपों के लिए जिलों, बी.आर.सी. और विद्यालयों की संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों, परिपत्रों और आदेशों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा प्रचालन संबंधी वास्तविकताओं को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र आधारित अनुभवजन्य आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। विद्यालय आधारित अनुसंधान आंकड़े चुने गए विद्यालयों से एकत्रित किए जाएंगे। आंकड़े अवलोकन और साक्षात्कार अनुसूचियों की सहायता से एकत्रित किए जाएंगे। ये अध्यापकों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जाएंगे। क्षेत्र आधारित आंकडे 30 विद्यालयों से एकत्रित किए जाएंगे।

आजकल संगत साहित्य कि समीक्षा की जा रही है और आंकड़ा–संग्रहण के लिए अपेक्षित साधनों को तैयार किया जा रहा है।

14- v kj-Vh-bZd sv ar xZ l erkd ki qe Z; kd u %u hfr i fj i z{; v kS y kd fi z

अन्वेषक : डॉ. नरेश कुमार

इस अध्ययन का आशय क्षेत्र के सामाजिक प्रत्यक्ष को ध्यान में रखकर समता के विचार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टियों को जोड़ना है। इस प्रयोजन के लिए आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रदत्त समता प्रावधान मुख्य केन्द्र बिंदु होंगे। इस मुद्दे पर अत्यधिक अस्पष्टता होने के बावजूद समता पर 'सामाजिक प्रत्यक्ष' की प्रासंगिकता का महत्व बढ़ा है। इस प्रवृति में विभिन्न प्रावधानों वाला आर.टी.ई. अधिनियम 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए साम्यिक शिक्षा निष्पादित करने के लिए अत्यंत समग्र संरचना प्रदान करता है। विभिन्न समावेशी प्रावधानों वाला आर. टी.ई. अधिनियम शिक्षा में समानता की प्राप्ति के लिए पिछले सभी प्रयासों से सार्थक गुणात्मक रूप में हटने को प्रतिबिंबित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आर. टी.ई. अधिनियम से पहले कोई ऐसी नीति/कार्यक्रम नहीं है जो समता के विचार को इतने मूलरूप में प्रस्तुत करता है।

इस अध्ययन का लक्ष्य एक व्यापक संरचना तैयार करना और शिक्षा में समता के विषय में उत्तर देने वालों (प्रत्यर्थियों) के शैक्षिक अनुभवों और संबद्ध सामाजिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना है। 'शिक्षा में समता' को सम्मिलित करने के लिए विभिन्न सहयोगियों के दृष्टिकोण (प्रत्यक्ष ज्ञान) को समझना भी शामिल है। इस तरह, इस शोध में इन प्रत्यक्ष ज्ञानों के लिए आधार बनाने वाले मानदंड का पता चल सकेगा।

सामान्यतः अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य नीति परिप्रेक्ष्यों और सामाजिक प्रत्यक्ष ज्ञान के अध्ययन में शिक्षा में समता की तुलनात्मक जानकारी तक पहुँचना और विशिष्ट संदर्भों में आर.टी.ई. के अंतर्गत समता प्रावधानों पर सामाजिक प्रत्यक्ष को समझना है। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक प्रत्यक्ष ज्ञान से आर.टी.ई. के अंतर्गत 'साम्यिक शिक्षा' के विचार को समझना
- आर.टी.ई. प्रावधानों (सम्मिश्र कक्षा, समीपस्थ शिक्षा/स्कूल) और शिक्षा में समता के बीच संबंध को समझना
- 'आर.टी.ई. अधिनियम' द्वारा दिए गए और 'लोगों द्वारा अपेक्षित' के रूप में समता के अर्थ में अंतर को समझना
- साम्यिक शिक्षा नीति से लोगों की मुख्य अपेक्षाओं का पता लगाना।

अब तक संबद्ध साहित्य की समीक्षा की जा चुकी है। परियोजना वर्ण्य–विषय से संबद्ध दस्तावेज की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। मार्गदर्शी अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार हो चुकी है।

15- v PNs fo| ky ; ksa d h r y k'k esa % 1000 fo| ky ; ksa d h v u qla èkku i fj ; kst u k

अन्वेषक : डॉ. नरेश कुमार

औपचारिक संगठन और वह स्थान जो विद्यार्थियों को सबसे अच्छी संभावित शिक्षा प्रदान करेगा, इस रूप में विद्यालय के अध्ययन पर एक अच्छा अनुसंधान भारत में नहीं हुआ है। विद्यालय संबंधी कुछ निर्णायक मुद्दों, चुनौतियाँ और विविध गुणवत्ता सूचकों पर टुकड़ों (खंडशः) ढंग में अध्ययन किया गया है। सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट (मान्यता प्राप्त और अ–मान्यता प्राप्त) विद्यालयों की विद्यालय शिक्षा को प्रबंधन का आकलन (निर्धारण) विभिन्न सहयोगियों द्वारा अलग–अलग नज़रियों से किया गया है। फिर भी, विद्यालयों में कार्यान्वित सभी चुनौतियाँ यह बताने में असफल रही कि ''विद्यालय बच्चों के लिए सही/अच्छा कर रहा है या नहीं''। विद्यालय को इस नज़रिए से देखने के व्यापक निहितार्थ हैं। अक्सर नीति–निर्माता शोधकर्ता, जनता और माता–पिता के लिए एक ही स्थान पर स्थित समान विद्यार्थी–समूह

और अध्यापक वाले विद्यालयों में निष्पादन, संस्कृति और बच्चों के अधिकार में अंतर एक कूट पहेली है।

पिछले दो दशकों में विद्यालयी प्रक्रिया में 'विद्यालय विकल्प (पसंद)' और 'परिवर्तनशील अपेक्षाओं' के कारण प्राइवेट विद्यालय की ओर लोगों का झुकाव काफी बढ़ा है। हालांकि प्राइवेट विद्यालय 20: विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जबकि सरकारी विद्यालय में 80: से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी सरकारी स्कूलों को 'गुणवत्ता के अभाव वाले विद्यालय' की संज्ञा दी जाती है। सरकारी स्कूल जनता के विश्वास और माता–पिता की पसंद के प्रति अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने में पीछे ही रहे हैं।

प्रारंभिक स्तर पर 1412178 स्कूलों और सैकेंडरी स्तर पर 128370 स्कूलों में पर्याप्तता और सुविधाओं में विविधीकृत संदर्भ और अंतर गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों के कई परिदृश्यों और प्रतिपादनों को प्रस्तुत करते है। विद्यालयों की प्रभाविता संबंधी साहित्य में इस धारणा को चुनौती दी गई है कि विद्यालयों के बीच भिन्नताओं का विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अंतर्राष्ट्रीय रूप में, विद्यालयों को सूचकों और विद्यार्थियों के परिणामों के आधार पर सफल और उच्च निष्पादन वाले विद्यालयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अनेक ऐसे सरकारी स्कूल है जिसे विभिन्न सहयोगियों द्वारा 'अच्छे विद्यालयों' के रूप में स्वीकृत किया व मान्यता दी गई है। अतः बहुपरिप्रेक्ष्य से विविध संदर्भ में स्थित अच्छे विद्यालयों का केस विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। इस तरह, परियोजना का लक्ष्य राज्य भर के विभिन्न विद्यालयों की संदर्भीकृत कार्य–पद्ध तिष्को समझने के लिए सहयोगियों की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का पता लगाना है और शिक्षा क्षेत्र के कार्मिकों तथा ज्यादा से ज्यादा जनता को इसके बारे में बताना है ताकि सरकार द्वारा प्रबंधित विद्यालय शिक्षा के पक्ष में जनता का विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सके।

bl ifj;kstuk ds eq[; mn~ns'; g S%

- बहु परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से 'अच्छे/श्रेष्ठ विद्यालयों', की पहचान करना;
- संदर्भ विनिर्दिष्ता से संबद्ध करके 'समग्र (संपूर्ण) विद्यालय का दस्तावेज तैयार करना;
- जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए विभिन्न सहयोगियों और सार्वजनिक मीडिया से अच्छे विद्यालयों के विवरण का आदन–प्रदान; और
- 'अच्छा स्कूल कौन से हैं' की मुख्य विशेषता और समझ को प्राप्त करना।

अब तक, विभिन्न स्रोतों (अभिभावकों, अध्यापकों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि) से सुझाए गए अच्छे विद्यालयों की व्यापक सूची तैयार की जा चुकी है। आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य चल रहा है।

16- Hkkjr ds 'kgjh Lyeksa ds cPpksa dh f'k{kk esa lgHkkfxrk dk leh{kkRed vkdyu ¼eSfVªd½

अन्वेषक : डॉ. सुनीता चुघ

इस अध्ययन में भारत के चुने गए दस शहरो के स्लमों में जीवन यापन कर रहे बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का आंकलन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में विशेष रूप से यह छानबीन करने का प्रयास किया गया है कि क्या राज्य चुने गए स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है या नहीं, विशेषतौर पर आर.टी.ई. 2009 अधिनियम के संदर्भ में। इस अध्ययन से अपेक्षा है कि इसमें उन मुद्दों/व्यवधानों का पता लगाया जाए जो आर.टी.ई. 2009 अधिनियम के अधिदेश को पूरा करने में बाधक हैं।

- शहरी क्षेत्रों और स्लम क्षेत्रों दोनों में सुलभता (पहुँच) और गुणवत्ता प्रावधान पर केन्द्रित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल करना;
- चुने गए स्लम क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के लिए समीपस्थ (नजदीकी) विद्यालयी में कितनी सुविधाएं उपलब्ध है छानबीन करना;
- प्रावधान और विद्यालयों में बच्चों की सहभागिता में विविधता का अन्वेषण करना;
- विविधीकृत प्रावधान में बच्चों की सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना;
- शिक्षा के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के प्रति अभिभावकों की मनोवृत्ति का पता लगाना;
- विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रावधान का पता लगाना;
- प्रारंभिक शिक्षा चक्र (सत्र) में नामांकन, प्रतिधारण और समापन को सुनिश्चित करने में एस.एम.सी. की भूमिका की छानबीन करना।

चूँकि यह अध्ययन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, अतः जनगणना, एन.एस.एस.ओ. जैसे गौण स्रोतों से एकत्रित

किए गए आंकड़े और गौण स्रोतों पर आधारित चुने गए शहरों का शैक्षिक प्रोफाईल तैयार किया गया है। संगत अध्ययनों की समीक्षा की जा रही है और काफी अध्ययनों की समीक्षा की जा चुकी है।

आंकड़े एकत्रित करने में सहायता के लिए शहर के स्तर पर कुछ नोडल संस्थान और मुख्य व्यक्तियों की पहचान की गई है। आंकड़ा–संग्रहण के साधन तैयार किए जा रहे हैं। आंकड़ा–संग्रहण के लिए प्रतिदर्श डिज़ाइन और साधनों को अंतिम रूप देने के लिए सारे नगर समन्वयकों के साथ परामर्शी बैठक आयोजित की जा रही है।

अब तब, संबद्ध साहित्य की समीक्षा पूरी हो चुकी है। आंकड़ा–संग्रहण के लिए साधन विकसित किए जा चुके हैं। क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।

17- mPp f' k{kk e safo Ùkh; u v k\$ l ke F; Z¼ vt h- l h- l s Q aM i kIr ½

अन्वेषक : प्रो. सुधांशु भूषण

विस्तार और गुणवत्ता सुधार के परिणामस्वरूप, जब सामर्थ्य का मुद्दा आता है तब उच्च शिक्षा में नीति एक कठिन कार्य हो जाता है। एक ओर सार्वजनिक व्यय निर्णायक है और निर्धनों के लिए संसाधन जुटाने और लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के तरीकों का पता लगाना होगा, यहाँ उच्च शिक्षा के प्राइवेट वित्तीय का प्रश्न उठता है। उच्च शिक्षा के पारिवारिक वित्तीयन को निजीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्तियों के मद्दे नज़र महत्व प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा के निजीकरण के कारण शुल्क बढ़ने की प्रवृत्तियों से उच्च शिक्षा में पैसा लगाने के कारण पारिवारिक बोझ बढ़ा है।

इसी से सामर्थ्यता का मुद्दा उठता है। इसके बदले सामर्थ्यता से पहुँच तथा विषयों की पसंद और पर इसका प्रभाव पड़ा है। भिन्न–भिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों में सामर्थ्य के संबंध में भी अलग–अलग प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। शहरी और ग्रामीण संदर्भों व विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों में अंतर हो सकता है। उपर्युक्त को देखते हुए, अनुसंधान परियोजना का मुख्य लक्ष्य निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में सामर्थ्य का अध्ययन करना है।

आजकल, अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

18- Hkkjr h; mPp f' k{kk l aLFkku ksa e sa Lo k; Ùkr k

अन्वेषक : डॉ नीरू स्नेही

उच्च शिक्षा संसधानों की स्वायत्तता का मुद्दा भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति में सुधारों को प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। स्वायत्तता प्रदान करना ऐसा सूचित करता प्रतीत होता है कि स्वायत्तता असंख्य समस्याओं का सामना करने वालों के लिए रामबाण है। इस परियोजना का लक्ष्य इस बात का अन्वेषण करना है कि सामान्य रूप में स्वायत्तता किस हद तक भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रचलित है अर्थात विशेष रूप से स्नातकपूर्व कॉलेजों। कितनी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए; क्या कॉलेजों के लिए स्वायत्तता होनी चाहिए; किस वर्ग–प्रबंधन, अध्यापक, विद्यार्थी को स्वायत्ता को दी जानी चाहिए और केन्द्र, राज्य, विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. किससे स्वायत्तता?

इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन अध्ययन को मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्य–पद्धति में स्वायत्तता की भूमिका को जानना है। विशिष्ट रूप में स्नातकपूर्व संस्थानों में, स्नातकपूर्व संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने में स्टैकहोल्डरो की भूमिका की छानबीन करना, संबद्ध कॉलेजों व स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों की कार्यपद्धति का विश्लेषण व तुलना करना, और स्वायत्त और गैर–स्वायत्त संबद्ध कॉलेजों की कार्य–पद्धति के अनुभवों के प्रलेख देना।

इस परियोजना की कार्य–पद्धति उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता की संकल्पना, स्वायत्तता प्रदान करने में स्टैकहोल्डरो की भूमिका, विभिन्न संस्थानों की कार्य–पद्धति में विद्यमान स्वायत्तता के प्रभाव को समझने के लक्ष्य पर आधारित है। अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन का मिश्रण है। इस संबंध में विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के साथ–साथ विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों के अधिनियमों और संविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा पद्धति में स्वायत्तता की संकल्पना के विकास का विश्लेषण किया जा रहा है।

इस संबधं में गौण आंकड़ों की समीक्षा जारी है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों, शोध–लेखनों और विभिन्न पुस्तकों की विषयवस्तुओं का विश्लेषण करना भी शामिल है। इसके अलावा, क्षेत्र कार्य भी इस परियोजना की अनिवार्यता है जिसके लिए प्रश्नावलियों का पहला

सैट तैयार किया जा रहा है। गौण आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

19- Mh-vkbZ-,l-bZ- vkadMksa dk iz;ksx djrs gq, izkjafHkd f'k{kk ij vuqla/kku dk;ZØe

अन्वेषक : प्रो. अरुण सी. मेहता

यह शोध ई.एम.आई. के विभाग द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान कार्यक्रम डी.आई.एस.ई. आंकड़ों का प्रयोग करते हुए केवल प्रारंभिक शिक्षा पर लघु अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय, आई.सी.एस.एस.आर. अनुसंधान संस्थाओं इत्यादि में काम करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अवसर प्रदान करना है। लगभग 40 अनुसंधान प्रस्ताव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। विभागीय समिति द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा करके 10 प्रस्तावों की सूची तैयार की गयी। न्यूपा ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और सुझावों के आधार पर सभी शोधकर्ताओं ने अपने.अपने प्रस्तावों को संशोधित किया। अनुसंधान कार्यक्रम के लिए फंड एन.यू.पी.ए. द्वारा दिया जाता है। पहली किश्त जारी कर दी गई है।

20- fo|ky; f'k{kk dh Hkw&LFkkfud lwpuk iz.kkyh ij ,d iz;ksxkRed v/;;u

अन्वेषक : अनुगुला एन.रेड्डी

विद्यालय शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली विकसित करने की इस प्रायोगिक परियोजना के दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य विद्यालयों को भू–स्थानिक आंकड़ों को एकत्रित करने और शैक्षणिक योजना और मॉनीटरिंग में उनका प्रयोग करने हेतु विद्यालय शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणालियाँ विकसित करने में विभिन्न राज्य सरकारों के अनुभवों की समीक्षा करना। दूसरा उद्देश्य खंडों में विद्यालय शिक्षा के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली का आदि रूप विकसित करना और स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक योजना में भू–स्थानिक आंकड़ों की पद्धति और अनुप्रयोग दर्शाना। जी.आई.एस. वेबसाइटों पर जाकर और वेबसाइटों की विषयवस्तुओं की छानबीन करके और विद्यालय के स्थान की योजना बनाने और मानीटरिंग के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले विभिन्न साधनो ंकी वेबसाइटों पर उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है।

इसके बाद विद्यालय शिक्षा के लिए जी.आई.एस. विकसित करने के लिए अपनायी गई पद्धतियों और योजना व मॉनिटरिंग में इनका प्रयोग करने पर गहन विचार–विमर्श करने हेतु राज्यों के दौरे किए जाएंगे। आद्य रूप भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा से एकत्रित किए गए विद्यालयों के भू–स्थानिक आँकड़ें पहले से ही सुलभ हैं। इन आंकड़ों की सहायता से आद्य रूप जी.आई.एस. विकसित करने और उसे आरंभ करने की योजना बनायी गई है। अब तक, क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है, और आँकड़ा–विश्लेषण का कार्य चल रहा है।

21- vuqlwfpr tkfr ds cPpksa esa f'k{kk % jktLFkku ds nks xkaoksa dk xgu v/;;u

अन्वेषक : प्रो. बी.के. पांडा

स्वतंत्रता के बाद, संविधानिक लोकतंत्र ने सामाजिक–आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त किए है, क्योंकि अवसर की समता और सामाजिक न्याय को स्वतंत्र भारत की विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधानिक संरक्षण और बेहतर शैक्षणिक आर्थिक सुविधाओं के कारण है यह आशा की जाती है कि यह ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता के लिए प्रेरक कारक का कार्य करेगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की गैर अनुसूचित आबादी के बराबर लाएगा।

अतः प्रश्न उठता है कि विद्यालय किस हद तक इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में समर्थ रहे हैं और यदि विद्यालय इन समुदाय के बच्चों को आकृष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं तो कौन से कारक हैं जो इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा अर्जित करने में बाधक हैं। ऐसी मान्यताओं के आधार पर अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की पहचान की गई:

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों को जानना;

- अनुसूचित जाति परिवारों की तुलना में समुदायों और शिक्षा के लिए उनकी वरीयता/आकांक्षा को विस्तार से समझना;
- अनुसूचित जाति के परिवारों के बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने में आने वाले विभिन्न सामाजिक–आर्थिक व्यवधानों का पता लगाना; और
- राज्य नीतियों के उन प्रावधानों को जानना जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं।

अब तब, समीक्षा और साधनों को विकसित करने का मूलभूत कार्य किया गया है और साधनों को आज़माने और आधारभूत आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जा चुका है। अध्ययन रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है।

22- fnYyh 'kSy&iwoZ f'k{kk iznku djus esa fut h erkf/kdkfj;ksa (Franchises) dk v/;;u

अन्वेषक : डॉ. सविता कौशल

इस अध्ययन का उद्देश्य चुने गए निजी मताधिकारियों (विशेषाधिकारियों) की शैक्षिक और प्रशासनिक संरचना व शासन का विश्लेषण करना है। इसके अलावा, चयनित निजी फ्रैंचाइज शालापूर्व विद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाओं और प्रदान की गई आधारभूत सुविधाओं की छानबीन भी की जाएगी।

इन विद्यालयों में आने वाले बच्चों की पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया जाएगा। इसमें प्रतिदर्श विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा अपनाई गई पाठ्यचर्या तकनीकों का अन्वेषण किया जाएगा और प्राइवेट फ्रेंचाइज शालापूर्व विद्यालयों की कार्य पद्धति से संबंधित उपलब्धियों या कमियों, यदि कोई हों तो, का पता लगाया जाएगा।

अब तब, शालापूर्व विद्यालयों के आंकड़ें एकत्रित किए जा चुके हैं। आंकड़ों का विश्लेषण हो चुका है; और अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।

23- vkfMlk esa lSdsaMjh Lrj ij vuqlwfpr tkfr ds cPpksa esa Nk=ofÙk ;kstuk vkSj 'kSf.kd xfr'khyrk dk v/;;u

अन्वेषक : डॉ. एस.के. मलिक

संविधान को अपनाने के बाद में, हम उच्च प्राथमिक शिक्षा की सर्व–व्यापकता का प्रयास कर रहे हैं। हमने नब्बे के प्रारंभिक दशक में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम प्रारंभ किया और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ मं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की ताकि देश में प्रारंभिक शिक्षा का सर्व–व्यापकीकरण किया जा सके। स्कूल बीच में छोड़ने की दर अत्यधिक है, शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं हैं, विद्यालय–बाह्य (Out-of-School) बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सभी सुधारों के बावजूद दर अभी भी पीछे है। जहाँ तक शैक्षणिक सूचकों का संबंध है सुविधावंचित वर्गों के बच्चे अन्य समूहों से पीछे हैं। आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एस.एम.सी. निर्धारित करना अनिवार्य है। इसी तरह आर.एम.एस.ए. ने योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समितियों और अभिभावक–अध्यापक संघ जैसे निकायों के माध्यम से सैकेंडरी शिक्षा के प्रबंधन के लिए पंचायतीराज संस्थानों और निकायों, समुदाय, अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य सहयोगियों को शामिल किया। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत यह सुझाव है कि राज्य लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों को मुफ्त (निशुल्क) वास और आवास सुविधाएँ, छात्रवृत्ति और नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों और राज्य स्कीमों का लाभ उठाया जाना चाहिए। अब यह अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि सैकेंडरी स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति कितनी सहयोगी (मददगार) है।

v/;;u ds fof'k"V mn~ns'; fuEufyf[kr gS%

(क) सैकेंडरी स्तर की शिक्षा समाप्त हो जाने पर छात्रवृत्ति की प्रभाविता और उच्च ग्रेडों के लिए अनुसूचित जाति के बच्चों की शैक्षणिक गतिशीलता का अध्ययन करना;

(ख) समापन दर और संक्रमण दर के संदर्भ में, योगदान और परिणामों के संबंध में स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यकर्ता जिन समस्याओं व व्यवधानों का सामना करते हैं, उनका पता लगाना

(घ) अनुसूचित जाति के बच्चों द्वारा सैकेंडरी शिक्षा पूरा न कर पाने के कारणों का पता लगाना;

(ड.) छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों की छानबीन करना।

यह अध्ययन ओड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। इसमें 30 जिले हैं। इन 30 जिलों में से अनुसूचित जाति की ज्यादा आबादी वाले दो जिलों को चुनकर अध्ययन किया गया। दो जिलों में से छह खंडो का चयन किया गया। गहन अध्ययन के लिए प्रत्येक खंड में से 10 सरकारी सैकेंडरी विद्यालयों को चुना गया। इस अध्ययन के

प्रत्यर्थियों में अध्यापक, मुख्यध्यापक, विद्यार्थी, प्रशासक और अभिभावक हैं।

इस अध्ययन के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक संबंधित साहित्य का अध्ययन पूरा कर लिया गया, आंकड़ा संग्रह के लिए आवश्यक उपकरण तैयार किए गए और अध्ययन क्षेत्र का दौरा किया गया।

24- fofoèkrk vkSj HksnHkko %ukxfjd vfèkxe vkSj yksdrkaf=d dk;Zdsfy, mPp f'k{kk

जाँचकर्त्ता : डॉ. निधि एस. सब्बरवाल और डॉ. मलिश सी.एम.

यह अनुसंधान परियोजना छह राज्यों के 11 उच्च शिक्षा संस्थानों का केस अध्ययन है। इस अनुसंधान का लक्ष्य कॉलेज परिसरों में विविधता और भेदभाव के मुद्दे की जानकारी हासिल करना है ताकि युवाओं में लोकतांत्रिक कार्य और नागरिकता का सवंर्धित करने के लिए नीति और पद्धतियाँ विकसित की जा सके।

अनुसंधान परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करके चुने गए 11 उच्च शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों में विविधता की छानबीन की गई है।

इन केस अध्ययनों में बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध सरकारी कॉलेजों दोनों के केस अध्ययन शामिल हैं।

यह परियोजना कार्यान्वयन अधीन है और अब तक इस अनुसंधान परियोजना की संपन्न हो चुकी गतिविधियाँ हैः

(i) अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किया गया;

(ii) अनुसंधान प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक का अयोजन;

(iii) छह अनुसंधान टीमें गठित की गई;

(iv) अनुसंधान दस्तावेज विकसित किए गए;

(v) अग्रगामी अध्ययन आयोजित किया गया;

(vi) अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला के लिए सामग्री तैयार की गई;

(vii) छह अनुसंधान टीमों के साथ अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला आयोजित की गई; और

(viii) अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई।

यह परियोजना छह राज्यों – बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित है।

25- Hkkjr esa lkoZtfud mPp f'k{kk laLFkkuksa dk foÙkh;u %QaMksa ds izokg vkSj muds mi;ksx dk ,d dsl vè;;u

अन्वेषक : डॉ. जीनुशा पाणिग्रही

इस अनुसंधान का उद्देश्य संसाधन आबंटन; भारतीय संदर्भ में आय सृजन गतिविधियों के जरिए और अनुदानों के रूप में प्राप्त संसाधनों की उपयोगिता के पैटर्नों का अध्ययन करना है। अध्ययन के लक्ष्य हैं; नव उदारवादी विपणन सिद्धांत की पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा संस्थानों के विविधीकृत फंडो के स्रोतों का अध्ययन करना; संसाधनों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का विश्लेषण करना; विविध उच्च शिक्षा संसथानों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में आने वाले सापेक्षिक चुनौतियों को जानना, उन गतिविधियों का पता लगाना जो निधि की कमी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संसाधनों के व्यय और उपयोग करने के पैटर्न का विश्लेषण करना।

यह परियोजना पाँच राज्यों – बिहार, ओड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तरांचल, के 10 उच्च शिक्षा संस्थानो का केस अध्ययन है।

यह परियोजना कार्यन्वित है और इस अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी गतिविधियाँ निम्नलिखित हैंः

(i) अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किया गया

(ii) जनवरी 2015 में परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ – जो शिक्षक और नीति–निर्माता हैं, विशेषज्ञ समिति के हिस्से थे।

(iii) परियोजना के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक प्रपत्र विकसित किए गए

(iv) मार्च 2015 में आयोजित प्रपत्रों की बैठक में प्रपत्रों पर चर्चा की गई

(v) परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व अग्रगामी अध्ययन आयोजित किया गया। यह अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों (सरकारी मान्यता प्राप्त) में से एक कॉलेज में किया गया

(vi) अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई।

अब, आंकड़ा–संग्रहण के साधनों के विकास का कार्य प्रगति पर है।

26- Hkkjr esa mPp f'k{kk dk 'kklu vkSj izca/ku

अन्वेषक : डॉ. गरिमा मलिक

इस अनुसंधान का लक्ष्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा कार्यों का शासन और प्रबंधन कैसे किया जाता है तथा उच्च शिक्षा संस्थान के शासन व प्रबंधन को जानना है।

vuqla/kku ifj;kstuk ds fof'k"V mís'; gSa%

(i) राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत स्तर पर शासन संरचना और प्रक्रियाओं के विकास पर विचार–विमर्श करना;

(ii) राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करना और शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा राज्य परिषदें और उच्च शिक्षा संस्थान परस्पर मिलकर कैसे कार्य करते हैं, इसका अध्ययन करना; और

(iii) विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शासी निकायो की भूमिका और कार्य–शैली का अध्ययन करना।

संस्थागत स्तर पर उच्च शिक्षा के प्रबंधन का अध्ययन करना है।

ifj;kstuk dk;kZRed gSa vkSj vuqla/kku ifj;kstuk ds varxZr iwjh dh xbZ xfrfof/k;k¡ fuEufyf[kr gSa%

(i) अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किया गया

(ii) 4 दिसंबर, 2014 को आयोजित विशेषज्ञ समिति बैठक में प्रस्ताव की समीक्षा की गई

(iii) गुणात्मक और मात्रात्मक प्रपत्र तैयार किए गए

(iv) अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला की सामग्री तैयार की गई

(v) अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला आयोजित की गई

यह परियोजना पाँच राज्यों – हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित है।

27- Hkkjr esa mPp f'k{kk dh xq.koÙkk % laLFkkxr Lrj ij 'kgjh vkSj vkarfjd xq.koÙkk vk'oklu dk v/;;u

अन्वेषक : डॉ. अनुपम पचौरी

यह अनुसंधान अध्ययन एक बहु–राज्य, बहु–संस्थागत अध्ययन है और इसका लक्ष्य बाह्य गुणवत्ता आश्वासन (ई.क्यू.ए.) और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन (आई. क्यू.ए.) की संरचना और कार्य, उनके परस्पर संबंध और मिश्रित–विधियों की उपागम के जरिए पाँच राज्यों – कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और तैलांगना के 10 उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन के सहभागियों की सहभागिता को जानना है।

परियोजना कार्यान्वित है और अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत पूरी की गई गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) अध्ययन के लिए अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किया गया और 24 सिंतबर, 2014 को आयोजित आंतरिक (पी.आर.एम.ई.) (विभागीय) संकाय की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(ii) प्रतिपुष्टि और साहित्य समीक्षा के बाद प्रस्ताव को संशोधित करके 8 जनवरी, 2015 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(iii) पाँच राज्यों के पाँच विश्वविद्यालयों और चुने गए विश्वविद्यालयों से एक–एक संबद्ध कॉलेज से पाँच संस्थागत टीमें गठित की गई।

(iv) गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान प्रपत्र तैयार किए गए जिनमें विद्यार्थी और संकाय सर्वेक्षण प्रश्नावलियाँ, संकाय और विद्यार्थियों के साथ एफ.जी.डी. के लिए फोकस समूह विचार–विमर्श वर्ण्य विषय, चुने गए विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के संस्थागत नेताओं के लिए इंटरव्यू अनुसूचियाँ शामिल हैं।

(v) अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा में बाहरी विशेषज्ञों के विशेषज्ञ समूह/उच्च शिक्षा में अनुसंधानकर्ताओं से परामर्श करके अनुसंधान प्रपत्रों का पुनरीक्षण किया गया।

(vi) अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला आयोजित की गई।

(vii) परियोजना प्रारंभ की गई।

(viii) प्रश्नावलियों को कूटबद्ध किया जा रहा है और

अनुसंधान टीमों की सुगमता के लिए कोड–पुस्तिका तैयार की जा रही है।

परियोजना पाँच राज्यों – कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और तेलगांना में कार्यान्वित है।

28- mPp f'k{kk esa v/;;u v/;kiu ¼f'k{k.k&f'k{kk½

अन्वेषक : डॉ. सयांतन मंडल

परियोजना का लक्ष्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन–अध्यापन के पहलुओं का विश्लेषण करना है। यह अनुसंधान परियोजना बहु–राज्य, बहु–संस्थागत अध्ययन है और इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल प्रत्येक राज्यों से (एक विश्वविद्यालय और एक इसके संबद्ध कॉलेज) चुने उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों अध्ययन–अध्यापन की छानबीन करने के लिए मिश्रित विधियों की उपागम का प्रयोग किया गया।

परियोजना कार्यान्वित है और अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत पूरी की गई गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) प्रारंभिक कार्यों में अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना सम्मिलित है

(ii) अनुसंधान प्रपत्रों का विकास

(iii) अनुसंधान दलो ंका चयन

(iv) प्रपत्र बैठक में विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करना

(v) परियोजना की योजना बनाना

(vi) भारतीय उच्च शिक्षा में अध्ययन–अध्यापन पर कार्यशाला के लिए दस्तावेज तैयार किए गए

(vii) अनुसंधान क्रिया–विधि कार्यशाला आयोजित की गई।

यह परियोजना पाँच राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित है।

29- l-f'k-v- esa y{sxd lerk dsifj.kke % iwohZ fnYyh vkSj vtesj ftysdk {ks=h; dk;Z

अन्वेषक : प्रो. रत्ना सुदर्शन

प्रस्तुत क्षेत्रीय अध्ययन में यह पता करना है कि चुनिंदा जिलों में सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और लैंगिक समता पर कितना और किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तलाशने के प्रयास हैं:

- विभिन्न हितधारकों के बीच शिक्षा में लैंगिक समता के बारे में क्या समझ है।
- स.शि.अ. के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री अध्ययन के संदर्भ और इसके लक्ष्य के प्रति कितना प्रासंगिक है।
- इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में हस्तक्षेप का समग्र प्रभाव कितना कारगर है और अधिकतम सकारात्मक प्रभाव बनाने हेतु किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन को परिवर्तन विधि के सिद्धांत का प्रयोग करके निरूपित किया गया है। स.शि.अ. टो.ओ.सी. नहीं बन सकता है फिर यह टी.ओ.सी. देखा जा सकता है। जो कार्यक्रम दस्तावेज पर आधारित है। विशिष्ट संदर्भों के विश्लेषण से अनुभवाश्रित पर्यवेक्षण पर आधारित परिवर्तन माडल विकसित होता है। अभिष्ट और अनाभिष्ट निष्कर्षों की पहचान कर ली गई है। साक्षात्कार और समूह चर्चा के माध्यम से आंकड़ा संग्रहित किया गया है।

क्षेत्र कार्य के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया जिससे प्रतिदर्श में सभी प्रकार की विविधताएं हो। अजमेर, राजस्थान जिले का पिसांगन अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड जिले का धौलादेवी ब्लाक, पूर्वी दिल्ली से कल्याणपुरी प्रतिदर्श के क्षेत्र थे। प्रत्येक स्थान पर एक या दो माध्यमिक विद्यालयों, और केजीबीवी (पिसांगन और धौलादेवी) कक्षा 6–12 को नोडल बिंदु बनाया गया जिसके चारों ओर प्रतिदर्श चुने गए। प्रतिदर्श में स्कूल के अध्यापक 12/13 वर्ष और अधिक आयु के लड़के–लड़कियां थे। अभिभावक, भाई–बहन, और शिक्षा अधिकारी थे। पिसांगन और धौलादेवी, प्रत्येक ब्लाक में लगभग 100 प्रतिदर्श लिए गए और दिल्ली से 45 प्रतिदर्श थे।

,e-fQy- fMxzh ikBîØe djus okys fo|kfFkZ;ksa dh lwph ¼o'kZ 2014&15½

Ø-la	fo|kFkhZ dk uke	'kks/k i zca/k	i ;Zos{kd
1.	अंशुल सलूजा	नो डिटेंशन पॉलिसी एंड इट्स इंम्प्लीकेशन फार रिड्यूशिंग वेस्टेज एंड इन्हांसिंग अचीवमेंट लेवल आफ स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल : ए केस स्टडी आफ गर्वनमेंट प्राइमरी स्कूल इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आफ हरियाणा	डॉ. एन. के मोहन्ती
2.	अमरदीप कुमार	पार्टीसिपेशन आफ महादलित स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन	डॉ. वाई जोसेफिन
3.	मृदुस्मिता सिंह	द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड इट्स इंप्लीकेशन फार द चिल्ड्रेन आफ डिसएडवेंटज सैक्शन आफ सोसायटी इन दिल्ली स्कूल्स	डॉ. मंजू नरूला
4.	पामेला दासगुप्ता	ए स्ट्डी आन एकेडमिक सुपरविज़न इन केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्कूल्स आफ दिल्ली एंड एनसीआर–यूपी	डॉ. आर. एस. त्यागी
5.	खुशबू रानी गुप्ता	एजूकेशन आफ द डिस्एडवेंटेज (25% रिर्जवेशन) अन्डर द राईट आफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009: ए केस आफ स्लेक्टेड प्राइवेट अनेडेड स्कूल्स इन दिल्ली	डॉ. वीरा गुप्ता
6.	संगीता डे	प्राब्लम्स एंड कन्सट्रेंट इन अटेंडिंग अपर प्राइमरी एजुकेशन: ए केस स्टडी आफ मैंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेज अमंग रूरल एडोलेसेंट्स इन रिवारी डिस्ट्रिक्ट आफ हरियाणा	डॉ. विनीता सिरोही
7.	सुमित कुमार	इंटर–स्टेट माईग्रेशन फार हायर एजुकेशन: ए केस स्टडी आफ स्टूडेंट्स फ्राम बिहार इन्रोल्ड इन यूनिर्वसिटी आफ दिल्ली	डॉ. नीरू स्नेह
8.	दिपेन्द्र कुमार पाठक	फंशनिंग आफ स्कूल मेनेजमेंट कमिटी (एसएमसी) इन एलीमेंट्री स्कूल्स	डॉ. वी.पी.एस. राजू
9.	ज्योत्सना सोनल	इंटर–ट्राइबल वेरीयेशन इन स्कूलिंग : ए कम्पेरेटिव स्टडी आफ भूटिया एंड थारू इन उत्तराखण्ड	प्रो. के सुजाथा
10.	अपराजिता गंतायत	इंडस्ट्री–एकेडमिक लिंकेज इन आईटी सैक्टर : ए केस स्टडी आफ स्लैक्ट इंस्टीट्यूशन एंड आर्गेनाईजेशन इन दिल्ली एंड एनसीआर	डॉ. आरती श्रीवास्तवा

ih&,p-Mh fMxzh ls lEekfur Nk=ksa dh lwph ¼o'kZ 2014&15½

Ø-la	fo|kFkhZ dk uke	'kks/k i zca/k	i ;Zos{kd
1.	श्री भरत चन्द्र रौत	अफरमेटिव एक्शन फार वीकर सैक्शन आफ द सोसायटी इन इंस्टीट्यूशन आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया	प्रो. के सुजाता
2.	श्री सुधांशु शेखर पात्रा (पार्ट टाइम)	ए स्टडी इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज रिलेटेड टू टीचर मैंनेजमेंट इन ओडिशा	प्रो. अरुण मेहता
3.	सुश्री चारू स्मिता मलिक	ए स्टडी आफ इक्विटी इन एक्सेस एंड पार्टीसिपेशन इन सेकेण्डरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश	प्रो. एस. एम. आई. ए. जैदी

fnukad	oDrk	'kh"kZd
20.05.2014	प्रो. हैन्ज मेयर	मेजर ट्रैण्ड्स इन गर्वनेंस आफ हायर एजुकेशन इंटरप्रेन्यूरलिज्म, ऑटोनामी एंड डिसरपटिव इनोवेशन
27.05.2014	——	इवाल्यूशन स्टडीज इन एजुकेशन
17.07.2014	डा. अमिता गुप्ता	डिवर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेजः वॉयस एंड इमेज फ्राम फाइव कन्ट्रीज इन एशिया
01.09.2014	प्रो. एम.एन. पनिनि	इनइक्वालिटीज, अफ्टर इकोनोमिक रिफार्मः स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस
15.09.2014	प्रो. वाणी के. बरूआ	इनइक्वालिटी, सेग्रेगेशन एंड लर्नर अचीवमेंट एट पोस्ट–प्राइमरी स्कूल लेवलः ए कम्पेरेटिव अनालिसिस
24.09.2014	प्रो. उषा नायर	गर्ल चाइल्ड एट रिस्क इन इंडियाः बिफोर एंड अफ्टर बर्थ
05.11.2014	प्रो. रश्मि सोमनाथन	स्कूल मील्स एंड स्टूडेंट आउटकम इन दिल्ली
13.11.2014	प्रो. रत्ना सुदर्शन	जेंडर इक्वालिटी आउटकम आफ एसएसए
11.12.2014	डा. राधिका अयंगर	एजुकेशन, ससटेनेबिलिटी एंड द पोस्ट–2015 डवलपमेंट एजेंडा
12.01.2015	डा. लुईस कब्रेरा	अम्बेडकरः ए ग्लोबल सिटीजन?
14.01.2015	प्रो. जेम्स अर्वानिटाकिस	ए स्टूडेंट इंटरएक्शन आन रिसर्च स्टडीज
15.01.2015	प्रो. आरोन बेनावोट	ग्लोबल एजुकेशन टारगेट्स पोस्ट 2015ः प्रिओरिटीज, पॉलिसीज एंड पालिटिक्स
09.02.2015	प्रोफेसर अंजेला डब्ल्यू लिटल	स्कूल क्वालिटी काउंट्सः एवीडेंस फ्राम डवलपिंग कन्ट्रीज
12.02.2015	डा. सोमेन चट्टोपाध्याय एंड दिपेन्द्र नाथ दास	एकेडमिक परफारमेंस इंडिकेटर (एपीआई)ः स्ट्रेट जैकेटिंग हायर एजुकेशन रिफार्म
18.03.2015	डा. राहुल चौधा	इंटरनेशनलाजेशन आफ अमेरिकन हायर एजुकेशन एंड इट्स इंप्लीकेशन फार इंडिया
19.03.2015	प्रो. सेल्वा रत्नम	मलेशिया पब्लिक–प्राइवेट हायर एजुकेशन सिस्टमः कैन इट अन्डरपिन इन इन्कूलसिव हायर–क्वालिटी टेलेंट टू अचीव हाई इन्कम नेशन स्टेटस बॉय 2020?

4 सहचर्या और सहभागिता

सहचर्या और सहभागिता

l gHkkfxrk i zkkyh

d nz vkSj jkT; ljdkjksa dks

sa l kf; d @ rduhd h

FkkZ vkSj ijke'kZ kjh

lsok,a

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014–15 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के मानव संसाधन विकास मंत्रालयों/शिक्षा विभागों और केंद्र तथा राज्य स्तर के संस्थानों को व्यावसायिक/तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया ताकि वे अपनी विशिष्ट क्षमता विकास की जरूरतों को पूरा कर सकें और शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण में सुधार हेतु उन्हें मदद मिल सके। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में व्यावसायिक/तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में प्रगति आकलन हेतु राज्य/संघीय सरकारों को व्यावसायिक सहयोग प्रदान किए गए। राज्यों/संघीय सरकारों तथा केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों/संस्थानों को तकनीकी/व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान करने के साथ–साथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों

जैसे– यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों को भी परामर्शकारी और व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान किया। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय की विशेषज्ञता को मान्यता देते हुए, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों/संगोष्ठियों में संकाय को आमंत्रित किया गया।

v aj kZVªh; fudk;ksa ds lkFk lnL;rk vkSj le>kSrs

mPprj f'k{kk uhfr vkSj vuqla/kku dsUnz

lhihvkj,pbZ&U;wk & fcfzV'k dkmafly %,d igy

दुनिया की उच्च शिक्षा की बड़ी व्यवस्था वाले देशों के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने

के उद्देश्य से सीपीआरएचई और ब्रिटिश काउंसिल ने संवाद की श्रृंखला का आयोजन किया। इस दिशा में पहला संवाद मई 2014 में मियामी में आयोजित ब्रिटिश काउंसिल के विश्व सम्मेलन में किया गया। इसी क्रम में नई दिल्ली में 10–11 नवंबर 2014 को इन दो संस्थानों के तत्वाधान में वृहद शिक्षा व्यवस्थाओं में उच्च शिक्षा में जन भागीदारी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया के वृहद शिक्षा व्यवस्था वाले देशों– भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रूस, अमरीका और इंगलैंड जहां उच्च शिक्षा में दुनिया का आधा नामांकन शामिल है, ने भाग लिया। इस संगोष्ठी के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- वृहद शैक्षणिक व्यवस्था के संचालन और प्रबंधन के अनुभवों को साझा करना।
- अपवंचित विद्यार्थी आबादी के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच का दायरा बढ़ाते हुए गुणवत्ता सुधार की रणनीतियाँ पर चर्चा करना।
- उच्च शिक्षा की प्रभावशीलता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वृहद शिक्षा व्यवस्थाओं के अभिशासन और प्रबंधन पर विचार–विमर्श करना।
- उच्च शिक्षा में जन भागीदारी के वित्त–पोषण की रणनीतियों पर चर्चा करना।

U;wk & ,fMucxZ fo'ofo|ky;]le>kSrk Kkiu

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के. ने नई दिल्ली

में दिनांक 20 फरवरी 2015 को दोनों संस्थानों के बीच आपसी शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

न्यूपा की ओर से प्रो. आर. गोविंदा, कुलपति, न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राचार्य सर टिमोथी ओ 'शिया' द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में दोनों संस्थानों के बीच संतुलित विद्यार्थियों/संकाय/स्टाफ के आदान–प्रदान के अलावा साहयोगिक अनुसंधान, प्रकाशन, संयुक्त प्रकाशन और साझा पाठ्यक्रम संचालन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। इस ज्ञापन में परस्पर लाभ हेतु अनुभवों, कौशलों और उत्कृष्ट कार्य व्यवहारों को साझा करने के प्रावधान हैं।

भारत और इंग्लैंड दो महत्वपूर्ण संस्थानों के बीच ऐसे समय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जब सार्वजनिक शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता का सरोकार विशेषकर भारतीय संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

v kbZ,-v kbZbZ h-, - i fjl j fod kl e sa i xfr

वर्ष 2014–15 में बुरुण्डी में पंजीकृत भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की स्थापना हेतु परिसर विकास और निर्माण/पुर्नस्थापन एवं अन्य भौतिक सुविधाओं में व्यापक प्रगति हुई।

संस्थान की स्थापना हेतु एवं परिसर के विकास के लिए तथा अकादमिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु बुरुण्डी सरकार ने 36,972 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित किया। यह भूखण्ड बुरुण्डी विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान एवं शैक्षिक विज्ञान संकाय, कैम्पस कैमन्गो के परिसर में स्थित हैं बुरुण्डी सरकार द्वारा आवंटित भूखण्ड में दो पुरानी इमारतें हैं। इसमें से एक इमारत में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है जबकि दूसरी इमारत में व्यापक नवीकरण की आवश्यकता है जिससे कि संस्थान के अकादमिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके। भवन के नवीकरण और पुर्निनिर्माण एवं अन्य भौतिक सुविधाओं हेतु लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से एक भवन का प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जायेगा। इस भवन में चार कक्ष हैं– एक व्याख्यान कक्ष, एक बैठक कक्ष, पुस्तकालय हेतु बड़ा कमरा, और कंप्यूटर लैब केंद्र हेतु एक कक्ष। दूसरे भवन में निदेशक कार्यालय समेत 6–8 संकाय सदस्यों के बैठने के लिए जगह है। इसके अतिरिक्त 8–10 प्रशासनिक स्टाफ के कार्य हेतु जगह तथा संकाय की बैठकों के लिए कक्ष है। अन्य परिसर विकास गतिविधियों में संस्थान के परिसर और मनोविज्ञान तथा शैक्षिक विज्ञान संकाय के बीच दीवार का निर्माण आधा पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त संस्थान के लिए पृथक प्रवेश द्वार का निर्माण और दोनों भवनों को बिजली तथा पानी की आपूर्ति सम्मिलित है।

संस्थान का मुख्य कार्य क्षमता निर्माण/विकास है। संस्थान की स्थापना और संचालन से संबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाएगी। अकादमिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का प्रथम चरण 2016 के दूसरे भाग में प्रारंभ किया जायेगा। इसके अंतर्गत सम्मिलित होगाः

1. अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों का प्रशिक्षण

2. अफ्रीका संघ सदस्य देशों की आवश्यकताओं/परिस्थितियों के अनुसार अनुसंधान तथा केस अध्ययन

3. देश तथा क्षेत्रीय/महाद्वीपीय स्तर पर शैक्षिक विकास में प्रवृत्ति का मूल्यांकन तथा विश्लेषण

4. अफ्रीकी संघ सदस्य देशों की विशिष्ट शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तकनीकी सहायता

5. प्रभावी शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन व्यवहारों तथा शैक्षिक विकास से जुड़े केस अध्ययनों एवं नवाचार तथा अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों का प्रचार एवं प्रलेखन

6. अफ्रीका संघ सदस्य देशों में शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन से जुड़ी मुख्य शैक्षिक चुनौतियों के निष्पादन हेतु अफ्रीकी देशों तथा अन्य देशों के अनुभवों और ज्ञान को साझा करना

7. अफ्रीका सदस्य देशों द्वारा निर्धारित शैक्षिक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नीति प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के सृजन हेतु नीतिगत चर्चा को व्यवहार में लाना।

सस्थान के अकादमिक कार्यक्रम/गतिविधियों के द्वितीय चरण में, प्रथम चरण के कार्यक्रमों/गतिविधियों के विस्तार के अलावा संस्थान अफ्रीकी संघ सदस्य देशों में प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के समूह में वृद्धि करने हेतु मिश्रिम उपागम के प्रयोग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों समेत शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में उन्नत स्तर के डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

ofapr lewgksa dh f'k{kk ij varjhi {ks=h; dk;Zkkyk ¼25&27 ekpZ 2015] ubZfnYyh] Hkkjr½

विषय की आवर्ती प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए और सभी के लिए शिक्षा, पोस्ट 2015 शिक्षा एजेंडा एवं सतत् विकास के मद्देनजर, जो शिक्षा में समता की सिफारिश करता है, न्यूपा ने शैक्षिक योजना में प्रशिक्षण और अनुसंधान के एशिया नेटवर्क (अंतरीप) के सहयोग से वंचित समूहों की शिक्षाः नीतयां, कार्यक्रम तथा चुनौतियां पर दिनांक 25–27 मार्च, 2015 के दौरान, नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, नेपाल, भारत, शिक्षा विभाग के प्रमुख, भूटान, मालद्वीप, म्यांमार तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं

राष्ट्रीय संगठन, विषय विशेषज्ञ समेत 25 वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों ने भागीदारी करी।

भागीदारों ने अपने देशों के संदर्भ में वचित समूहों की शिक्षा पर अपने अनुभवों को प्रस्तुत किया। कार्यशाला में वंचित समूहों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में समता, क्रियान्वयन में मुद्दे तथा चुनौतियां पर वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु चर्चा की गई।

कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन प्रो. कविता शर्मा, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को किया गया। प्रो. कविता शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। क्षेत्रीय कार्यशाला की समाप्ति दिनांक 27 मार्च 2015 को की गई। अंतरीप सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा हुई और अंतरीप के अंतर्गत भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की गई।

5 U; iwk esa ubZ igy

R L YANTHAN

न्यूपा में नई पहल

, e-fQy- ikB~;Øe dk iqxBZ

न्यूपा के एम.फिल. पाठ्यक्रम में आतंरिक कार्य समूह और बाह्य विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। ये बदलाव निम्नलिखित हैं:

- ट्रिमेस्टर से सेमेस्टर प्रणाली लागू करना

- पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का संशोधन और अद्यतन
- शोधार्थियों के लिए कौशल निर्माण के अवसरों का प्रावधान और वृद्धि
- विषय सूची, क्रेडिट (भार मान) और समयावधि के सापेक्ष पाठ्यक्रम में संशोधन

वस्तुतः न्यूपा पिछले छः वर्षों से अधिक समय से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एम.फिल. और पी–एच. डी. कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

Mis k d k i ht h Mis k e smUu ; u

विश्वविद्यालय में 1982 से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संचालित 6 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उन्नयन करके इसे पूर्णकालिक 9 माह का पीजीडिप्लोमा कार्यक्रम बना दिया गया है। इसका पहला बैच सितंबर 2014 में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के मानद विश्वविद्यालय के रूप में

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय बनाए जाने के बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई और डेपा का पीजीडेपा के रूप में उन्नयन किया गया।

नई पीजीडेपा कार्यक्रम को छः चरणों में पूरा किया जाएगा जिसमें– कक्षा शिक्षण–अधिगम, मूलभूत पाठ्यचर्या शिक्षण, परियोजना कार्य, परियोजना कार्य प्रस्तुति और दूरवर्ती ऑनलाइन तरीके से उन्नयन पाठ्यक्रम शामिल हैं।

u okp kj d sfy , jk'Vh; i qjLd kj

न्यूपा देश के विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह 29 नवंबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रमुख गणमान्य अतिथि श्री राजर्षि भट्टाचार्य, सचिव, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, सुश्री वृंदा सरूप, विशेष सचिव उपस्थित थे। इस राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह के बाद शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग जिला और ब्लॉक स्तर के 200 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

इस पुरस्कार समारोह का मुख्य उद्देश्य जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन हेतु जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपनाये जा रहे नवाचारी विचारों तथा कार्य व्यवहारों को प्रतिष्ठित और प्रोत्साहित करना है और विद्यालय स्तर पर सांस्थानिक विकास और कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करना है। जमीनी स्तर पर नीतिगत

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार की मान्यता अधिकारियों को प्रोत्साहित करती है और पुरस्कार वितरण समारोह तथा सम्मेलन न्यूपा के शैक्षिक प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित किया गया तथा प्रो. के. सुजाता तथा प्रो. कुमार सुरेश द्वारा अपने विभाग के सचिवों के सहयोग से समन्वयन किया गया।

fo| ky ; us`Ro fodkl esa iht hMh, l , y , e &ehy dk i RFkj

विद्यालय प्राचार्यों के साथ–साथ प्रशासकों के क्षमता निर्माण के द्वारा विद्यालय नेतृत्व विकास की गति को बढ़ाने की दिशा में एक नए कदम के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व विकास केन्द्र ने विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन में 9 माह का कार्यक्रम (पीजीडीएसएलएम) का शुभारम्भ किया। प्रथम पीजीडीएसएलएम में 10 पाठ्यक्रम हैं जो तीन चरणों में पूरे किए जाएंगे: तैयारी कार्य, कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य जो 34 क्रेडिट (भारमान), 510 घंटे और 340 सत्रों में समाप्त किया जाएगा। यह न्यूपा में सितंबर 2014 में आरंभ हुआ।

इस कार्यक्रम के विज़न को विद्यालयों में कार्यव्यवहार में लागू करने के उद्देश्य से इसमें प्रयोगकर्त्ता शिक्षाशास्त्रीय विधियों को अपनाया गया है ताकि सैद्धान्तिक विवेचनों के साथ–साथ विद्यालय नेतृत्व के वास्तविक कार्यव्यवहारों से प्रतिभागियों को अवगत करवाया जा सके। इस कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल हैं: विद्यालय रूपान्तरण के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत और व्यावसायिक सक्षमताओं का आत्मसमीक्षा के लिए समर्थ बनाना, विद्यालय रूपांतरण हेतु अपेक्षित विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण विकसित करना, टीमवर्क, साझेदारी और विद्यार्थी अधिगम के लिए शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं के लिए कौशल, मनोवृत्ति और सम्यक ज्ञान का विकास करना। पीजीडीएसएलएम में नवाचारों के द्वारा डिजाइन, योजना अेर प्रक्रियाओं में बदलाव को लागू करने पर विशेष बल दिया गया है।

U; iwk }kjk d\`Uh z; ; kst uk d k ' kqHkkj aHk

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुमोदन से विश्वविद्यालय ने विद्यालय आंकलन, नेतृत्व और विद्यालय शिक्षा सांख्यिकी के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 2014–15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों

के लिए रु. 70.82 करोड़ की लागत से केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का शुभारम्भ किया। न्यूपा और संघ/राज्य क्षेत्र, इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रम पीएबी प्रक्रिया के भाग होंगे। इसमें विद्यालय आंकलन नेतृत्व और विद्यालय शिक्षा सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना का संवर्धन और समन्वयन समाहित होगा।

fo|ky; usr`Ro ij varjjk'Vªh; laxks'Bh

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में नवंबर 2014 में विद्यालय नेतृत्व, नीति, कार्य व्यवहार और शोध पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह एनसीएसएल–न्यूपा का पहला प्रयास था। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विश्वभर में विद्यालय नेतृत्व के मुद्दों को प्रकाश में लाना और विद्यालय नेतृत्व पर कार्यरत भारत, इंगलैंड, कनाडा और अन्य देशों के शोधार्थियों को एक मंच प्रदान करना था। इसके प्रमुख ददेश्य थे– भारत में और अन्य देशों में विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्रों में मौजूदा जारी शोध अध्ययनों और कार्य व्यवहारों को साझा करना, भारत में गुणवत्ता, समता, विविधता के मुद्दों पर विचार विमर्श करना तथा नेतृत्व विकास एवं विद्यालय सुधार पर अनुभवों को साझा करना। इन सभी मुद्दों पर आम समझ स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि स्थानीय विद्यालय ढांचे और विद्यालय नेतृत्व में नवाचारी कार्यकर्त्ता केंद्रित प्रक्रियाओं के विकास के अवसर सुलभ किया जा सके। इन उद्देश्यों को छः व्यापक क्षेत्रों में समाहित किया गया– चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विद्यालय सुधार, विद्यालयों में विविधता और समानता, प्रधानाध्यापक की भूमिका, प्रधानाध्यापकों की व्यावसायिक तैयारी, अध्यापक नेतृत्व, नेतृत्व और अध्यापक शिक्षा एवं विद्यालय नेतृत्व पद स्थापन में महिलाएँ।

efgyk usr`Ro ij varjjk'Vªh; fodkl eap

भूमंडलीकरण और निजीकरण के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक एवं निजी शिक्षा प्रणाली में महिला नेतृत्व और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन लैंगिक तथा स्त्रीवादी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसे विद्यालय शिक्षा में भी देखा जा सकता है जिसमें महिलाओं की भागीदारी के प्रयास किए परन्तु वे निजी और व्यावसायिक स्तरों पर विभिन्न कार्यों और उम्मीदों के बीच उलझ गया। अभी तक भारत में यहाँ तक कि स्काटलैंड में

भी महिला नेतृत्व के बारे में बहुत कम शोधकार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में न्यूपा और एडिनबर्ग, स्काटलैंड में फरवरी 2015 में एक संयुक्त विचार मंच का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के संदर्भ में शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सहयोगिक अध्ययन करने हेतु चर्चा करना और शोध के तरीके निर्धारित करना था।

अंतरराष्ट्रीय विचार मंच के उद्देश्य थे– नीतिगत ढांचे और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक मानक और शर्तों के अन्तर्गत भारत और स्काटलैंड में विद्यालय नेतृत्व के संकल्पनात्मक अवधारणाओं पर चर्चा करना, भारत और स्काटलैंड में विद्यालय नेतृत्व के पदों पर पद स्थापित महिलाओं पर चर्चा करना। भारत तथा स्काटलैंड के संदर्भ में अग्रणी विद्यालयों में महिलाओं के नेतृत्व के तरीकों के अनुभवों को साझा करना। नीतिगत ढांचे और विद्यालय नेतृत्व कार्य व्यवहारों के बीच बढ़ती खाई की समीक्षा को भी मुख्य चर्चा में शामिल किया गया।

इस विचारमंच में एडिनबर्ग विश्वविद्याल, ब्रिटिश उच्चायोग, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, मुंबई केन्द्र तथा राज्य स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य पेशेवरों में आमंत्रित किया गया था।

6 पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

NIEPA-VI-C-18

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

Kku vkSj lwpuk dh lk>snkjh

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित मौजूदा और नवीनतम ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्य आरंभ किए हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान और सूचना प्रलेखन और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र द्वारा वर्ष 2014–15 में की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

विश्वविद्यालय का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र विश्वविद्यालय के संकाय और स्टाफ सदस्यों, देश–विदेश के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालय के एम.फिल. तथा पी.एच.डी. के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अतिथि संकाय सदस्यों तथा पाठकों की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है। पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अधिगम और शोध में सहयोग के लिए आधुनिक अध्यापन– अधिगम सामग्री, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे– वाई–फाई से सुसज्जित है।

समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत पुस्तकालय ने अपनी संग्रह नीति में व्यापक परिवर्तन किया है। पुस्तकालय लगभग 80 प्रतिशत जर्नल मुद्रित और ऑनलाईन स्वरूप में मंगाता है। हालांकि, पुस्तकों को मुद्रित रूप में ही प्राथमिकता दी जाती है।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकों तथा अन्य सामग्री के संपूर्ण संग्रह को चार प्रमुख अनुभागों– सामान्य, संदर्भ, श्रृंखला, और क्षेत्र अध्ययन संग्रह में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षित काल में पुस्तकालय में 897 नए पुस्तकों/दस्तावेजों का संग्रह किया गया। वर्तमान वर्ष में पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास संयुक्त राष्ट्र, युनेस्को, ओ.ई.सी.डी, आई.एल.ओ., यूनिसेफ, विश्व बैक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों इत्यादि के अलावा 58,283 पुस्तकों और दस्तावेजों का संग्रह है। समीक्षाधीन वर्ष में पुस्तकालय ने शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंधन तथा इससे संबंधित विषयों पर 250 राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय जर्नल एवम् पत्रिकाएं मंगाईं। इन पत्र–पत्रिकाओं से 1346 प्रमुख आलेखों का सूचीकरण किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष में पुस्तकालय ने 7,167 जर्नलों को उपयोगकर्त्ताओं को सूचना प्रदान करने के लिए जिल्द में तैयार किए। न्यूपा ने चार आनलाईन डाटाबेस एलसेवियर सेज, एमेराल्ड, डाटाबेस तथा जे.स्टोर जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों से खरीदे। पुस्तकालय के पास 523 ई–बुक का संग्रह है। न्यूपा पुस्तकालय में मल्टीमीडिया केंद्र है। वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, फिल्म, माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप्स और सी.डी. के रूप में गैर–मुद्रित सामग्री उपलब्ध है।

न्यूपा पुस्तकालय ने वर्ष 2014–15 के दौरान नई आनलाईन सूचना सेवाएँ जैसे कि– ''न्यूज फ्लैश'', 'न्यूपा इन द प्रेस', एस.डी.आई. (न्यूपा संकाय के अकादमिक कार्य का प्रसार) तथा 'न्यू अराईवल' प्रारम्भ किया है। पुस्तकालय ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की ग्रन्थ सूची तैयार की है। उपभोक्ताओं को संदर्भ सामग्री, आलेखों, रिपोर्टों इत्यादि के लिये फोटोग्राफी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

न्यूपा पुस्तकालय में सभी गतिविधियाँ, जैसे कि सूची बनाना, प्राप्तियाँ, प्रसार तथा श्रेणी नियंत्रण पूर्ण रूप से

कम्प्यूटरीकृत है। इसके लिये लिबसिस 7 साफ्टवेयर पैकेज का नवीनतम वर्ज़न का प्रयोग किया जा रहा है। न्यूपा में लैन से इंटरनेट या फिर इंटरानेट के माध्यम से सीधे या यू.आर.एल. के माध्यम से न्यूपा की वेबसाईट पर वेब ओपेक का प्रयोग करके ओपेक का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से न्यूपा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटाबेस देख सकते हैं।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु न्यूपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र डेलनेट का सदस्य हैं, इससे न्यूपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र में उपलब्ध शैक्षिक योजना और प्रशासन पर वृहद रूप से उपलब्ध अमूल्य अधिकारिक दस्तावेज़ों के पहचान की सुविधा उपलब्ध हुई है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुये सभी दस्तावेज़ों तथा रिकार्ड का डिजीटलीकरण हेतु परियोजना चलाई जा रही है। यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे देश में शिक्षा पर वृहद ऑनलाईन अभिलेखीय सूचना उपलब्ध हो पाएगी

fMt hVy l a k/ku ksa d h i gp

इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संकाय तथा अनुसंधानविदों के बीच विभिन्न प्रकार की सूचना की साझेदारी, संपर्कता, सहभाजन के लिए इंटरनेट गतिविधियों को सुदृढ़ तथा विकसित किया गया है। यह सूचना तथा ज्ञान का संग्रह, सृजन, हस्तांतरण तथा एकीकरण करता है। इसके डिज़ीटल संसाधन जैसे पुस्तकें, आलेख, अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, सम्मेलन संगोष्ठी के कार्यकलाप, विख्यात शिक्षाविद् व्याख्यान श्रृंखला, दृश्य–श्रव्य व्याख्यान, समिति तथा समिति रिपोर्टें, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह सभी संसाधन पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र के वेब पृष्ठ (http://www.nuepa.org/libdoc/index.html, पर भी उपलब्ध हैं। प्रलेखन केन्द्र शिक्षा तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के 5,000 दस्तावेज़ों के डिजीटल अभिलेख उपलब्ध कराता है। यह दस्तावेज़ इंटरनेट या इंटरानेट के माध्यम से http://www.nuepa.org.archives/index.html, पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त नई प्राप्तियों की सूची, नए जर्नलों तथा बंद किऐ जाने वाले जर्नलों की सूची, पाक्षिकों के वर्तमान घटक; जे. स्टोर तथा ऑनलाईन जर्नल डाटाबेस का सम्पूर्ण टेक्स्ट एक्सेस; संदर्भ ग्रंथ सूची – मांग पर प्रेस कतरनें, साहित्य की खोज तथा इलैक्ट्रानिक दस्तावेज़ वितरण प्रणाली (ई.डी.डी.एस.) के लिये इंटरनेट के माध्यम से चौबीस घंटे की पहुंच पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र को विस्तारित की गई हैं। इससे अंतः पुस्तकालय ऋण तथा डेलनेट के माध्यम से पुस्तकों, दस्तावेज़ों, आलेखों, इत्यादि के लिये प्रयोगकर्त्ता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सुदृढ़ीकरण हुआ है।

7 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर केंद्र विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैम्पस नेटवर्क आधार तथा इसके सक्रिय संघटकों को कंप्यूटर केंद्र द्वारा संचालित, रखरखाव तथा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर केंद्र एन.एम. ई.आई.सी.टी परियोजना के अंतर्गत एन.के.एन./एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की गई 1 जी.बी.पी.एस ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट संपर्कतता से सुसज्जित है। विश्वविद्यालय में सतत रूप से हर समय इंटरनेट की संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए अर्नेट से 10 एम.बी.पी.एस. के बैकअप की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर केंद्र सभी स्टाफ सदस्यों, प्रशिक्षुओं, परियोजना स्टाफ, कार्यक्रम भागीदारों, अनुसंधानविदों को कंप्यूटर सुविधा तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेटवर्क संसाधानों का प्रयोग करने हेतु सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय सदस्यों को उच्च गति वाली इंटरनेट संपर्कतता तथा नेटवर्क प्वाइंट प्रदान किये गये हैं। न्यूपा डोमेन पर सभी स्टाफ तथा संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत ई–मेल खाता की सुविधा दी गई है। कुलपति तथा अन्य सभी संकाय सदस्यों के निवास पर ब्राड–बैन्ड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय को डैस्कटाप/लैपटाप कंप्यूटर सुविधा दी गई है। कंप्यूटर केंद्र की सुविधाएं बिना किसी व्यावधान के लगातार 12 घंटे उपलब्ध रहती हैं। कंप्यूटर केन्द्र पर विश्वविद्यालय के अपने कंप्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है।

कंप्यूटर केन्द्र विश्वविद्यालय की दैनिक अकादमिक तथा गैर अकादमिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रकार के नवीनतम कंप्यूटर और प्रिंटरों तथा मल्टी–फंक्शन डिवाईज़ेज से सुसज्जित है। विश्वविद्यालय के सभी तलों पर सभी कमरे नेटवर्क (विंडोज़ 2008 आपरेटिंग सिस्टम सर्वर सहित) से जुड़े हुए हैं।

न्यूपा भवन से न्यूपा हास्टल को उच्च गति इंटरनेट संपर्कतता उपलब्ध कराई गई है। न्यूपा छात्रावास के सभी तलों के कमरों में अतिथियों के लिये प्रमाणित तथा सुरक्षित वाई–फाई संपकर्तता उपलब्ध–कराई गई है।

यह केंद्र अकादमिक एककों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण और प्रणाली स्तर के प्रबंधन संबंधी मुद्दे तथा दूसरे कार्यकलापों में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गैर–अकादमिक एककों जैसे – पुस्तकालय, प्रशासन तथा वित्त विभागों को भी सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान की डाटा प्रोसेसिंग, घरेलू साफ्टवेयर विकास, तथा वर्ड प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अन्य विशिष्ट कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है।

लेखा अनुभाग को भी कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए समर्थन दिया जाता है। इसमें शामिल है, वेतन पर्ची, आयकर गणना, पेंशन, भविष्य निधि गणना आदि। इसके लिए एस.पी.एस.एस. सांख्यिकी पैकेज नेटवर्क वर्जन सर्वर के साथ स्थापित किया गया है ताकि प्रयोगकर्त्ता नेटवर्क पर गणना कर सकें। कंप्यूटर केंद्र दैनिक गतिविधियों के लिये ओपन स्रोत साफ्टवेयरों को प्रोत्साहन देता है।

विश्वविद्यालय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक डाटा केन्द्र स्थापित किया गया है। डाटा केन्द्र उच्च गुणवत्तायुक्त डाटा सर्वर तथा वेब सर्वर से जुड़ा है जोकि चौबीसों घंटे उपभोक्ताओं के लिये ऑन–लाईन उपलब्ध है। डाटा सेंटर समर्पित समानांतर यू.पी.एस. सिस्टम से समर्थ है जो सर्वर को पावर बैक–अप प्रदान करता हैं। घरेलू डाटा सेंटर को सुदृढ़ बनाने हेतु एस.ए. एन. स्टोरेज़ के साथ ब्लेड सर्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इंटरनेट संलग्नता में वृद्धि तथा समर्थतता हेतु एवं डाटा केन्द्र का इंटरनेट लिंक हेतु बैक–अप कनेक्टिविटी के लिये 10 एम.बी.पी.एस. रेडियो फ्रीक्वेन्सी लिंग (आर.एफ. लिंक) प्रारम्भ हो चुका है।

भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जाने–माने कार्यक्रम एकीकृत शैक्षिक जिला प्रणाली सूचना (यू–डाईस) के लिये सर्वर का रखरखाव संगणक केन्द्र करता है।

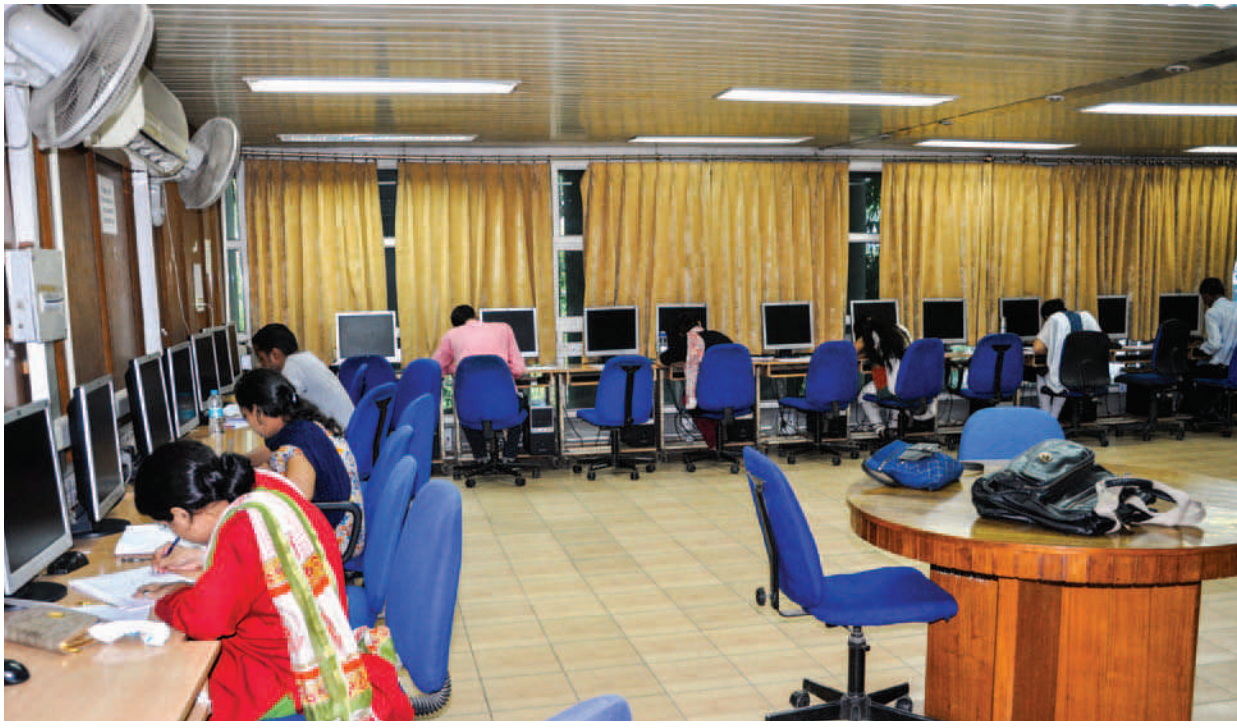

8 प्रकाशन

NUEPA PUBLICATIONS
EDUCATION, SOCIETY and DEVELOPMENT
SINGLE TEACHER SCHOOLS IN TRIBAL AREAS
Teacher Education in Haryana
EDUCATIONAL DEVELOPMENT AMONG TRIBES
A Study of Sub-Plan Areas in Andhra Pradesh
K. SUJATHA
Financing Education in India
Jandhyala BG Tilak
Edited by
Community Participation and Empowerment in Primary Education
DEVELOPMENT OF SECONDARY EDUCATION IN INDIA

Who Goes to School?
Exploring Exclusion in Indian Education
MODULES
MAKING SCHOOL SUCCESSFUL
NUEPA
Annual Report
2010-2011
DEVELOPMENT OF SECONDARY EDUCATION IN INDIA
NEWSLETTER
ANTRIEP
Occasional Papers

NUEPA PUBLICATIONS
(for Display Only)
JOURNAL OF EDUCATIONAL
PLANNING AND ADMINISTRATION
(Subscriptions details available)

प्रकाशन

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रकाशन एकक विश्वविद्यालय द्वारा की गई शोध और विकास गतिविधियों के निष्कर्षों के प्रकाशन और प्रसारण द्वारा ज्ञान की साझेदारी संबंधी कार्यकलापों का अनुसमर्थन व्यापक स्तर पर करता रहा है। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुक्रम में प्रकाशन एकक समसामयिक आलेख/जर्नल/पाक्षिक न्यूजलेटर, पुस्तकें, एम.फिल. और पी–एच.डी. की विवरणिका और प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेण्डर प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों की श्रृंखला भी प्रकाशित करता है। प्रकाशन एकक कंप्यूटरों तथा प्रिंटरों से सुसज्जित है और विश्वविद्यालय के डीटीपी कार्य भी करता है।

वर्ष 2014–15 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले गए – जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी), परिप्रेक्ष्य (हिंदी) शिक्षा का सामाजिक–आर्थिक संदर्भ पर जर्नल और एंट्रीप न्यूज लेटर, एम.फिल तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों की विवरणिका तथा पाठ्यचर्या गाईड। विश्वविद्यालय ने अनेक शोध और संगोष्ठियों/सम्मेलनों की रिपोर्टें पुस्तक और मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने निम्नांकित प्रमुख प्रकाशन निकाले :

tuZy

- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVIII अंक 1, 2014
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVIII अंक 2, 2014
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVIII अंक 3, 2014
- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXVIII अंक 4, 2014
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XX अंक 1, 2013
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XX अक 2, 2013
- परिप्रेक्ष्य, जिल्द XX अंक 3, 2013

, afVªi U;wy sVj %

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एंट्रिप (एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन एजुकेशनल प्लानिंग) न्यूजलेटर (अर्धवार्षिक) – वर्ष 19, अंक 1, जनवरी–जून 2013 प्रकाशित किया गया।

l el ke f; d v ky s[k %

वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित समसामयिक आलेख प्रकाशित किए गए:

- न्यूपा समसामयिक आलेख सं. 45: एजुकेशन, पावर्टी एंड एक्सक्लूजन, मधुमिता बंद्योपाध्याय, नई दिल्ली: न्यूपा, पृष्ठ 55

fu %'kqYd i zd k' ku %

समीक्षाधीन वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित निःशुल्क प्रकाशन निकाले गये :

1. एजुकेशन फॉर ऑल : टुवार्ड्स क्वालिटी विद इक्विटी (इंडिया)
2. डाईस फ्लैश स्टैटिस्टिक्स 2013–14 : प्रोग्रेस टूवर्डस

यू.ई.ई. : एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया

3. एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया : व्हेयर डू वी स्टेंड? डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स 2011–12 (जिल्द I तथा II)

i kB ;Øe l af/kr l kexzh

1. स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट : पाठ्यचर्या रूपरेखा (बंगाली, गुजराती संस्करण)
2. स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट : हस्तपुस्तिका (गुजराती, हिन्दी संस्करण)
3. एम.फिल.–पी–एच.डी. पाठ्यचर्या मार्गदर्शिका 2014–15
4. एम.फिल.–पी–एच.डी. पाठ्यचर्या मार्गदर्शिका 2014–15 फॉर ऑपशनल कोर्सेज़
5. शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर प्रो. कुलदीप माथुर का मुख्य संभाषण (28–29 नवंबर, 2014)

v U;

1. न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेण्डर, (अंग्रेजी) 2014–15
2. न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेण्डर, (हिन्दी) 2014–15
3. न्यूपा वार्षिक रिपोर्ट, (अंग्रेजी) 2013–14
4. न्यूपा वार्षिक रिपोर्ट, (हिन्दी) 2013–14
5. प्रास्पैक्ट्स (एम.फिल. तथा पी–एच.डी. कार्यक्रम) 2015–16

fe fe ;ksxzkQ i zdk'ku

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों, समसामयिक आलेखों, न्यूपा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों की रिपोर्टें/प्रशिक्षण सामग्री/मिमियोग्राफ प्रकाशित किए।

न्यूपा वेबसाइट को योगदान :

न्यूपा ने ज्ञान और सूचना के वृहद प्रचार–प्रसार के लिए वेबसाइट का निर्माण किया है। प्रकाशन विभाग ने अपने प्रकाशनों से संबंधित निम्नांकित सूचनाएं अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराई है : न्यूपा के समूल्य तथा निःशुल्क प्रकाशनों की वृहद सूची तथा न्यूपा के लिए निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची; जेपा के वर्तमान तथा भविष्य के अंकों के बारे में सूचना; न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर; न्यूपा एट ए ग्लान्स, प्रेस विज्ञापन तथा एम.फिल और पी–एच.डी. प्रोग्राम; निगम ज्ञापन और नियम (न्यूपा); हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य; न्यूपा समसामयिक आलेख को अपलोड करना; एंट्रीप न्यूजलेटर को अपलोड करना; न्यूपा वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण) 2013–14।

9 न्यूपा में सहायता अनुदान योजना

न्यूपा में सहायता अनुदान योजना

कार्य योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही योजना में उनकी पुनः व्याख्या के विभिन्न मानकों का क्रियान्वयन हेतु उद्देश्यों का वृहद प्रचार आवश्यक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ निकटतम सहयोग आवश्यक है। नीति के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वयन हेतु, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर समर्थन व्यवस्था समेत अंतःशास्त्रीय उपागम आवश्यक है।

इस संदर्भ में ये आवश्यक हैं: (अ) देश में शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वृहद जागरूकता पैदा करना, (ब) नीति उन्मुख अध्ययनों तथा संगोष्ठियों को आरंभ करना ताकि मध्य–पाठ्यक्रम सुधार, संशोधन तथा नीति हस्तक्षेपों के साथ समायोजन किया जा सके (स) अध्यापकों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं और संचार माध्यमों को प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके साझा मंच प्रदान करना। (द) शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी तथा अच्छे व्यवहार एवं सफल प्रयोग को बढ़ावा देना (य) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना की समीक्षा को सुविधाजनक बनाना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायता अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत योग्य संस्थानों तथा संगठनों को वित्तीय सहायता शिक्षा नीति के प्रबंधन तथा क्रियान्वयन पक्ष पर सीधे प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के आधार पर प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत सम्मेलनों का आयोजन, प्रभावी तथा मूल्यांकन अध्ययन, सर्वोत्तम विकल्पों पर परामर्शकारी अध्ययन, भारत सरकार को सलाह देने हेतु तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मॉडल, विडियो फिल्म इत्यादि का निर्माण सम्मिलित हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय के माध्यम से यह योजना संचालित की है जो सहायता अनुदान समिति के द्वारा इसे संचालित करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2015 के अनुसार इस समिति के निम्नांकित सदस्य हैं:

प्रोफेसर नीलम सूद	–	अध्यक्ष
प्रोफेसर ए.के. शर्मा	–	सदस्य
प्रोफेसर कुमार सुरेश	–	सदस्य
प्रोफेसर वाई. जोसेफिन	–	सदस्य
प्रोफेसर प्रमिला मेनन	–	सदस्य
प्रोफेसर के. बिस्वाल	–	सदस्य
श्री बसवराज स्वामी	–	सदस्य सचिव

सहायता अनुदान समिति ने इस योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार डाटाबेस तैयार किया गया और सहायता अनुदान समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष 2014–15 के दौरान समिति ने निम्नांकित सहायता अनुदान की संस्तुति प्रदान की। जिसका विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है :

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान संस्तुत प्रस्तावों की सूची

Ø- la	laLFkk dk uke	ifj;kstuk dk 'kh"kZd	LohÑr lgk;rk vuqnku jkf'k
1.	साई एजुकेशन रूरल एंड अर्बन डवलपमेंट सोसायटी कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश	दो दिवसीय संगोष्ठी: शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ते अपराध के संदर्भ में नैतिक शिक्षा के सरोकार और चुनौतियां	रु. 3,00,000/–
2.	ग्लोरियस वूमन इम्पावरमेंट, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश	संगोष्ठी: शिक्षा का मौलिक अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर और अपवंचित बच्चों के 25 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन की नीतियां	रु. 3,00,000/–
3.	नव ज्योति यूथ एसोसिएशन, कुरुनूल, आन्ध्र प्रदेश	संगोष्ठी: माध्यमिक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में परीक्षा सुधार की आवश्यकता	रु. 3,00,000/–
4.	नव जीवन ग्रामोद्योग समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश	संगोष्ठी: शिक्षा के मौलिक अधिकार के संदर्भ में बाल श्रमिकों के पुनर्वास की चुनौतियां	रु. 3,00,000/–
5.	फतिमा मुस्लिम महिला मंडली (एफएमएमएम), कुरुनूल, आन्ध्र प्रदेश	संगोष्ठी: समकालीन शिक्षा प्रणाली में मदरसा शिक्षा और इसके विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने की चुनौतियां	रु. 3,00,000/–
6.	अलीगढ़ हिस्टोरियन समिति, अलीगढ़	संगोष्ठी: भारत में असमानता के रूप: अतीत और वर्तमान	रु. 3,00,000/–
7.	सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड इकोनोमिक डवलपमेंट (सीड), नई दिल्ली	सम्मेलन: शोध और नवाचार के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उच्च शिक्षा	रु. 3,00,000/–
8.	एसोसिएशन फॉर वूमन एंड रूरल इनरिचमेंट (एडब्ल्यूएआरई), ओडिशा	संगोष्ठी: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति: शिक्षा का अधिकार"	रु. 3,00,000/–
9.	समाधान, बिहार	संगोष्ठी: बिहार के विशेष संदर्भ में किशोर विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण और परिणाम	रु. 3,00,000/–
10.	संघर्षोत्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश	कार्यशाला: शिक्षा में सफाई और मोबाइल फोन की भूमिका।	रु. 3,00,000/–
11.	इंडियन एकेडमी ऑफ सोशियल साईंसेज, इलाहाबाद	प्रस्ताव: 37वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस: मुख्य विषय: टिकाऊ पर्यावरणीय समाज का निमार्ण	रु. 3,00,000/–
12.	चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लेंड्रान, मोहाली	संगोष्ठी: "भारत में शैक्षिक नीतियां और कार्यक्रम"	रु. 2,45,000/–

13.	भारती महिला संगम, तेलंगांना राज्य	संगोष्ठीः सीमांत वर्ग की प्रारम्भिक शिक्षा के सरोकार और चुनौतियां	रु. 3,00,000/–
14.	गार्गी कॉलेज (युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली) एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स (डीयू)	सम्मेलनः ''शिक्षा, रणनीति और सामाजिक परिवर्तन''	रु. 3,00,000/–
15.	श्री स्वरूप निष्ठा आश्रम फिलासॉफिकल वैलफेयर सोसायटी (एसएनएपीएस), जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	संगोष्ठीः अनंतपुर जिले में मूल्य आधारित नैतिक शिक्षा'' आंध्र प्रदेश	रु. 3,00,000/–
16.	बस्ती एरिया डवलपमेंट परिषद, (बीएडीसी) ओडिशा	संगोष्ठीः शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका।	रु. 3,00,000/–
17.	पीपुल्स काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इलाहाबाद	प्रथम अखिल भारतीय जन चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान शिखर सम्मेलन	रु. 3,00,000/–
18.	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, दिल्ली	''भारतीय इतिहास कांग्रेस का 75वां सत्र'', 28–30 दिसंबर, 2014	रु. 3,00,000/–
19.	प्रगति रूरल एंड एजुकेशनल डवलपमेंट सोसायटी (पीआरईडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश	कार्यशालाः ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रभाव	रु. 3,00,000/–
20.	एजुकेशनल टैक्नोलॉजी एंड मेंनेजमेंट एकेडेमी, गुड़गांव	सम्मेलनः ''मानव शिक्षा विज्ञान के उभरते प्रभाव और अधिगम क्षमता में सुधार''	रु. 3,00,000/–
21.	इंडियन एकेडेमी ऑफ सोशियल साइंसेज, इलाहाबाद	प्रस्तावः ''ज्ञान प्रणाली, वैज्ञानिक सोच और भारतीय जन''	रु. 3,00,000/–
22.	ह्यूमन एंड रूरल इंटेग्रेशन फॉर टैक्निकल एक्शन, आंध्र प्रदेश	संगोष्ठीः ''चयन आधारित क्रेडिट प्रणालीः चुनौतियां और सुझाव''	रु. 3,00,000/–
23.	आनंद मैमोरियल फाउण्डेशन, पटना	शोध अध्ययनः बिहार के ग्रामीण महिलाओं पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत सरकार के त्वरित महिला साक्षरता में मुख्य सत्र, अक्षर आंचल योजना और बिहार राज्य द्वारा संचालित साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महादलित साक्षरता कार्य का प्रभाव।	रु. 5,00,000/–
24.	केरल डवलपमेंट सोसायटी, नई दिल्ली	शोध अध्ययनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 और विस्थापित कामगारों के बच्चों की शिक्षाः चुनिंदा राज्यों का अध्ययन	रु. 5,00,000/–
25.	सेंटर फॉर बजट एंड पालिसी स्टडी, बंगलुरु	शोध अध्ययनः कर्नाटक में निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत लागू आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया का प्रलेखन	रु. 5,00,000/–

10 प्रशासन और वित्त

प्रशासन और वित्त

i z'kkl u

विश्वविद्यालय के पास हाउसकीपींग तथा सुरक्षा सेवाओं के लिये बाहय सेवा–स्रोतों के अतिरिक्त निम्नांकित स्वीकृत पद हैं।

प्रशासन तथा अकादमिक एंव तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रशासन के कार्य के अनुसार स्थापित अनुभागों द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित की जाती हैं।

इसके अनुभाग कार्यकलापों के अनुसार स्थापित किये गए हैं जिन्हें संगठनात्मक आरेख में प्रदर्शित किया गया है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अलावा विभिन्न अकादमिक और अनुसचिवीय पदों पर 70 परियोजना कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।

c kä l ax Zi n	l a[; k
कुलपति	01
कुलसचिव	01
संवर्ग पद	
संकाय (कुलपति, प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर)	42
अकादमिक समर्थन स्टाफ़	11
प्रशासन, वित्त, सचिवीय तथा अन्य तकनीकी स्टाफ	70
सहायक स्टाफ (एम.टी.एस.)	37
; kx	162

fu;qfDr;k¡

lewg ^;*

Ø-la	uke	in	fu;qfDr dh frfFk
1.	प्रो. के. श्रीनिवास	प्रोफेसर	14.08.2014
2.	डा. सुनीता चुग	सह–प्रोफेसर	26.05.2014
3.	डा. मनीषा प्रियम	सह–प्रोफेसर	19.06.2014

R;kxi=

Ø-la	uke	in	R;kx dh frfFk
1.	प्रो. के. श्रीनिवास	सिस्टम एनालिस्ट	14.08.2014

lsokfuo`fÙk

lewg ^ch*

Ø-la	uke	in	lsokfuo`fÙk dh frfFk
1.	श्री पी.एन. त्यागी	प्रशिक्षण अधिकारी	31.01.2015

lewg ^lh*

Ø-la	uke	in	lsokfuo`fÙk dh frfFk
1.	श्री श्याम लाल	सहायक	31.05.2014
2.	श्री जे.डी. भाटिया	इलेक्ट्रिशियन	31.07.2014
3.	श्री के.के. मोहनन	एमटीएस	30.09.2014
4.	श्री राज कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	03.11.2014
5.	श्री जय भगवान	एम.टी.एस.	31.01.2015

LoSfPNd lsokfuo`fÙk

Ø-la	uke	in	lsokfuo`fÙk dh frfFk
1.	श्री बालक राम	एमटीएस (माली)	28.02.2015

fo Ùk r Fkk y s[kk fo Hkkx

न्यूपा में वित्त तथा लेखा सेवाएं लेखा अनुभाग द्वारा संचालित की जाती हैं जिसका अध्यक्ष वित्त अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखाकार और कार्यालय के आठ सदस्य तथा अनुसचीवीय स्टाफ होता है। यह अनुभाग बजट की तैयारी, मासिक वेतन तथा पेंशन बिल, अन्य व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति जैसे चिकित्सा, एल.टी.सी. बिल, अग्रिम इत्यादि, वस्तुओं की खरीद के लिये बिल भुगतान प्रक्रिया, कार्य, संविदा इत्यादि, पूर्व लेखा परीक्षा, बाह्य परीक्षा के साथ समन्वयन तथा वित्त तथा लेखा से जुड़े अन्य मसलों के लिये उत्तरदायी होता है। यह सभी वित्तीय मसलों पर समयबद्ध परामर्श देता है तथा वित्तीय भागीदारी, लेखा बयान, उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि हेतु सभी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु प्रभावी सहायता प्रदान करता है। वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य सचिव होता है जो विश्वविद्यालय के वित्त, निर्देशन तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये व्यय की सीमा तय करता है। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय से प्राप्त अनुदान निम्नांकित है :

i kIr vuqnku dk O;kSjk ¼2010&2015½ ¼#- yk[k esa½

Ø-la	' kh'kZ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सहायता अनुदान (योजना)	1013.59	1197.60	1129.80	1185.00	1206.97
	सहायता अनुदान (योजनेतर)	1092.00	1033.55	1070.44	1415.00	1511.60
	आंतरिक प्राप्तियां	117.13	110.11	101.87	102.81	71.75
	; ksx	**2222.72**	**2341.26**	**2302.11**	**2702.81**	**2790.32**
2.	व्यय (योजना)	980.33	1106.38	1325.69	1,272.97	1239.00
	व्यय (योजनेतर)	1123.05	1059.36	1307.54	1441.86	1643.35
	; ksx	**2103.38**	**2165.74**	**2633.23**	**2714.83**	**2882.35**
3.	आंतरिक प्राप्तियां व्यय के प्रतिशत के रूप में	1%	1%	1%	1%	1%
4.	सहायता अनुदान व्यय का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान सहायता अनुदान में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और इसी अनुपात में इसका व्यय भी बढ़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यूपा अपनी मुख्य गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दे रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन/ हिन्दी कक्ष

fganh d {k

हिंदी कक्ष अनुवाद की सुविधा के माध्यम से अनुसंधान प्रशिक्षण और प्रशासन में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकाशनों के हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के साथ साथ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान रोजमर्रा के कार्यों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:

अ) हिंदी में प्रगामी प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

ब) हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य के तीन अंक प्रकाशित किए गये। यह जर्नल शिक्षा के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है।

स) विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों को तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषण

द) हिंदी में निम्नलिखित सामग्री का अनुवाद करके उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार किया गया:

(i) वार्षिक रिपोर्ट : 2013–14

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2014–15

(iii) हस्तपुस्तिका, पाठ्यचर्या तथा विविध अनुसंधान उपकरण

यह कक्ष परिपत्र, पत्रों, नोटिस, कार्यालय ज्ञापन इत्यादि का हिंदी अनुवाद भी प्रदान करता है।

य) हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए:

(i) एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के 4 अधिकारियों और 15 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नमंच और विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के लिये हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इन प्रतियोगिताओं में कुल 30 कर्मचारियों ने भागीदारी की।

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

v u g Xu d

संकाय का अकादमिक योगदान

शैक्षिक योजना विभाग

, l -, e -v kbZ, - t Sh ¼fo Hkkx kè; {k½

l a ks'B h@ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीयः

गीतम यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम में केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित राजभाषा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, 22–23 मई, 2014।

गुवाहाटी, 10–11 सितम्बर, 2014, आरएमएसए–तकनीकी सहयोग एजेंसी (टीसीए) द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए असम में आयोजित दूरदर्शी कार्यशाला में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

राज्य परियोजना निदेशालय, तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित 'आरएमएसए के तहत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2015–16) तैयार करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला' में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया। यरकौड सलेम जिला, तमिलनाडु, 22–26 सितम्बर, 2014।

शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में अभिनव के लिए पुरस्कार की राष्ट्रीय योजना के तहत न्यूपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता की, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 26–27 नवंबर, 2014 ।

गुवाहाटी, 21–22 जनवरी, 2015 के दौरान डीईओ और असम के बीईओएस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2015 के दौरान न्यूपा द्वारा आयोजित ''स्कूल के मानकों और मूल्यांकन'' पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में एक सत्र, की अध्यक्षता की तथा भाग लिया।

डाइट, रायपुर, 09–12 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित, छत्तीसगढ़ के संकाय के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की योजना और डिजाइन पर उन्मुखीकरण कार्यशाला में संसाधान व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

एससीईआरटी, दिल्ली द्वारा आयोजित, 17 मार्च 2015 'बदलते माध्यमिक शिक्षा की आकृतिः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर राज्य स्तर संगोष्ठी में भाग लिया और एक सत्र की अध्यक्षता की।

व्याख्यान (न्यूपा से बाहर)

एप्लाइड मैनपावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएएमआर),

आईएएमआर, नरेला, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए मानव संसाधन योजना और विकास में मास्टर डिग्री कोर्स में शैक्षिक योजना पर व्याख्यान दिया।

मानव संसाधन योजना और विकास में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कोर्स के प्रतिभागियों के लिए शैक्षिक योजना पर व्याख्यान दिया। एप्लाइड मैनपावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएएमआर), नरेला, नई दिल्ली, 20 मार्च 2015

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षिक सहायता

एक सदस्य के रूप में, डाईट, कड़कड़डूमा, दिल्ली, 19 दिसंबर, 2014 के मध्य अवधि कार्यक्रम सलाहकार समिति (पीएसी) की बैठक में भाग लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 5 वीं संयुक्त समीक्षा मिशन, आरएमएसए, 9 फरवरी 2015 की अंतिम दौर की बैठकों में भाग लिया।

टीसीए द्वारा आयोजित आरएमएसए–टीसीए की चौथी बैठक में भाग लिया, कार्यकारी समिति, सीआईईटी, एनसीईआरटी, 13 फरवरी, 2015।

एक सदस्य के रूप में, एससीईआरटी, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, 4 मार्च 2015 को एससीईआरटी, दिल्ली की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, एससीईआरटी, दिल्ली, 18 मार्च, 2015 को डाइट, केशवपुर की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, एससीईआरटी, दिल्ली, 19 मार्च, 2015 को डाइट, आरके पुरम की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, एससीईआरटी, 25 मार्च, 2015 को डाइट, कड़कड़डूमा की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, एससीईआरटी, 25 मार्च, 2015 को डाइट, दरियागंज की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

एक सदस्य के रूप में, 30 मार्च, 2015 को एससीईआरटी, डाईट, मोती बाग की वार्षिक पीएसी की बैठक में भाग लिया।

e ksu k [kjs

i zd k' ku

पुस्तकें/अध्याय:

एजुकेशन ऐड एंड इन्टरनेशनल कोपरेशन इन इंडिया: शिफ्टिंग डायनामिक्स, इंक्रींजिंग कोलाबोरेशन. चैप्टर इन 1–ह्वेन चेंग, शेंग–जू चान (एडीटर) 'इन्टरनेशनल एजुकेशन ऐड इन डवलपिंग एशिया–पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज'' स्प्रिंग साइंस बिजनेस मीडिया शिंगापुर प्रा. लि. (प्रकाशनाधीन)

''संचार कौशल – एक कला, एक विधा'', व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम – दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी'' मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल. (प्रकाशनाधीन)

शोध पत्र/लेख/नोट्स:

''आइडियोलॉजीकल शिफ्ट इन इंडिया हायर एजुकेशन इंटरनेशनलाइजेशन,'' इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, नं. 78 (स्पेशल इष्यू), द बोस्टन कॉलेज सेंटर फार इंटरनेशनल हायर एजुकेशन (सीआईएचई)

''इंप्लायमेंट, इंप्लायबिलिटी एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया: द मिसिंग लिंक्स'', हायर एजुकेशन फार द फ्यूचर, 1(1), 39–62 अगस्त 2014, द केरल स्टेट हायर एजूकेशन काउंसिल, सेज पब्लिकेशन (लॉस एन्जेल्स, लन्दन, नई दिल्ली, सिंगापुर, वाशिंगटन डीसी)

v uq ä akku v è; ; u

जारी:

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए वैकल्पिक तरीके (अनुसंधान मोनोग्राफ – पहला मसौदा तैयार)

शैक्षिक अनुसंधान के लिए सांख्यिकीय तरीके पर तीन मॉड्यूल का पहला मसौदा तैयार (प्रो. सुधांशु भूषण, डॉ. सुमन नेगी और श्री शषिरंजन झा, पीएच–डी. विद्वान के साथ)

''भारत में तुलनात्मक शैक्षिक लाभ की स्थानिक गतिशीलता'' पर चल रही एक अनुसंधान परियोजना शुरू

l a k'B h@ l Ee y u@ d k; Zkky kv ka e a Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय:

''उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता की और भाग लिया, एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 23–24 जुलाई, 2014।

सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, 12 जनवरी, 2015 को आयोजित, विविधता और भेदभाव पर अनुसंधान परियोजना के बारे में जानकारी के संग्रह के लिए अनुसंधान उपकरणों पर चर्चा हेतु कार्यशाला में भाग लिया।

विविधता और भेदभाव पर अनुसंधान परियोजना पर अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला में भाग लिया। सी.पी. आर.एच.ई., न्यूपा 9–10 फरवरी, 2015।

ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, नई दिल्ली, 11–12 फरवरी, 2015 को आयोजित ''उच्च शिक्षा में महिला एवं नेतृत्व'' पर संगोष्ठी में भाग लिया।

भारत में उच्च शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन पर परियोजना के लिए शोध के साधन पर चर्चा के लिए कार्यशाला में भाग लिया। सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, 18 मार्च, 2015।

''मानव संसाधन विकास में चुनौतियां'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और ''मानव संसाधन विकास ज्ञान के लिए उच्च शिक्षा का पुनर्निर्माण।'' पर एक सत्र की अध्यक्षता की, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 28 मार्च 2015।

ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आईआईसी, नई दिल्ली, 31 मार्च – 1 अप्रैल, 2015 को भारत में प्रबंधन शिक्षा के भविष्य पर विशेषज्ञ, के रूप में 9वें राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन (एनआरसी) के समवर्ती सत्र में भाग लिया और अध्यक्षता की।

अंतर्राष्ट्रीय:

ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, नई दिल्ली, फरवरी 10–11, 2015 के दौरान आयोजित ''उच्च शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व'', पर ग्लोबल शिक्षा संवाद–दक्षिण एशिया सीरीज 2015 में भाग लिया।

çf' k{k.k k d k; Øe @ l Ee y u @ d k; Zkky kv ka d k v k; kt u

शिक्षा में मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके, 16 राज्यों से 18 विश्वविद्यालयों के 10 संकाय सदस्यों और 18 शोधार्थियों, जिसमें 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 05–15 जनवरी, 2015 को संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम। रिपोर्ट और संबंधित सामग्री वेब पोर्टल पर अपलोड।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और इक्विटी के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला कार्यक्रम में चर्चाकार, 'उच्च शिक्षा के संस्थानों में पहुंच और भागीदारी में क्षमता: आर्थिक – और क्षेत्रीय असमानताओं के परिप्रेक्ष्य' न्यूपा, 16–20 मार्च, 2015।

çf' k{k.k k l ke x h v k\$ i kBî Øe fod fl r v k\$ fu 'i fkn r

1–5 सितंबर, 2014: (अंतर–राज्यीय बदलाव: भारत में स्कूल शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के वित्त पोषण में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना और स्कूल वित्त के प्रबंधन और योजना में अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति।

v U; ' kS{ kd v k\$ O; kol kf; d ; ksx n ku

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन:

Mh k ' kks k ç c a k d k i ; Z s{ k.k kA

, e -fQ y -@ i h, p &Mh d k; Zd k Ik; Z s{ k.k k%

- पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा पर छाया शिक्षा: एक बहुस्तरीय विश्लेषण, शोध छात्र (शोविक मुखर्जी)
- भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्थानिक ज्ञान आधारित उद्योगों का वितरण और प्रवासन के बीच अंतर–संबंध, शोध–छात्र (सुमित कुमार)

fofHkUu Hkkjrh; fo'ofo|ky;ksa ls ih,p&Mh- 'kks/k dk ewY;kadu A

शिक्षण:

निम्नलिखित पाठ्यक्रम में शिक्षण में शामिल:

- एम.फिल. पीएच–डी–सीसी3, सीसी5 और ओसी 11।
- शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)
- शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा)

अन्य गतिविधियां:

सी.पी.एच.आर.ई.–न्यूपा, 25 जुलाई, 2014 को आयोजित आई.एच.ई.आर. 2014 की समीक्षा पर सहकर्मी लेखक बैठक में भाग लिया।

न्यूपा वेब पोर्टल, समन्वयक, रखरखाव और प्रबंधन

सदस्य, पर्यवेक्षकों के आवंटन के लिए समिति

सदस्य, एम.फिल. और पी.एच–डी. प्रवेश समिति

सदस्य, एम.फिल./पी.एच–डी. के प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न की स्थापना हेतु समिति।

उच्च शिक्षा विभाग, डी.ए.सी.

शैक्षिक वित्त विभाग, डी.ए.सी.

शैक्षिक योजना विभाग, डी.ए.सी.

सदस्य – एम.फिल पाठ्यचर्या संशोधन और पुनर्गठन समिति।

lkoZ fud fudk;ksa dks ijke'kZ vkS 'kS{kd lgk;rk

एनसीईआरटी में संसाधन व्यक्ति आर.आई.ई., भोपाल, 26–27 फरवरी, 2015 को आयोजित मूल्यांकन की निगरानी करना और परियोजना योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

'उच्च शिक्षा में महिला नेताओं' पर अपने अध्ययन के लिए ब्रिटिश काउंसिल आर्थिक खुफिया इकाई को दिया साक्षात्कार – के रूप में प्रकाशित ''कहाँ महिलाएं हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में उच्च शिक्षा प्रबंधन में – प्रवृत्तियाँ, (एक कस्टम शोध रिपोर्ट), ब्रिटिश काउंसिल मार्च 2014।

U;wik ds ckgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

सदस्य, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा उत्पादन सूचकांक पर उप–समिति, सांख्यिकी और पीआई; मंत्रालय, सीएसओ।

अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नोएडा) की उप –समिति स्थायी सदस्य।

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड (डी.ए.बी.), योजना एवं निगरानी विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो – यूजीसी पर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर डे कार्यक्रम के लिए एस.एल.एम. के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ।

सह–संपादक, भारतीय आर्थिक जर्नल, भारतीय आर्थिक संघ

पुस्तक प्रस्ताव के समीक्षक: स्प्रिंगर, सिंगापुर के लिए।

संपादकीय सलाहकार बोर्ड हिमगिरी शिक्षा समीक्षा आईएसएसएन 2321–6336

ds fcLoky

çdk'ku

शोध पत्र/लेख/टिप्पणियां

स्कूल मैपिंग प्रोसेस इन इंडिया. रिसर्च पेपर, न्यूपा, नई दिल्ली, नवंबर 2014, मिमियो,

थीम पेपर (विद प्रो. जे.बी.जी. तिलक एवं पी.आर. पंचमुखी) टाइटल्ड, ''स्टेटिक्स ऑन एजुकेशन'', मिनिस्ट्री आफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अप्रैल 2014, असेसिबल एट http:\\mospi.nic.in\Mospi_New/upload/Them_Paper_Education.pdf

आर्टिकल (विद प्रो. तिलक) टाइटल्ड ''ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन इन इंडिया'' इन आईएएसएसआई क्वालिटी, वाल्यूम 32, सं. 4, आनलाइन पब्लिस्ड इन दिसंबर 2014. अवेलेबल एट http:\\www.indianjournals.com\ijor.x?target=ijor:iassi&volume=32&issue=4&type=toc

v uql aèkku vè;;u

जारी:

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर कार्रवाई अनुसंधान परियोजना। (एस.एम.आई.ए. जैदी और एन.के. मोहंती के साथ) यह परियोजना तमिलनाडु (थेनी और सलेम जिले) और ओडिशा (गंजाम और क्योंझर जिले) में चार जिलों में लागू की जा रही है। परियोजना के पहले चरण में, अनुसंधान टीम राज्य और जिला योजना टीमों के साथ बातचीत के कई सत्र आयोजित किए गए । दो कार्यशालाओं और दो परामर्शदात्री बैठकों का आयोजन किया गया। नमूना राज्यों और संबंधित साहित्य की योजना दस्तावेजों की समीक्षा की गई और प्राथमिक और माध्यमिक आंकड़ा एकत्र किए गए थे। नमूना राज्यों और जिलों से एकत्र किए गए आंकड़ों और जानकारी और फील्ड नोट्स के आधार पर, पहले चरण की मसौदा रिपोर्ट जो स्कूल शिक्षा और उनके सामाजिक–आर्थिक और संस्थागत संदर्भ में योजना प्रथाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित थी जो तैयार की गई।

la'kks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk vksa esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय:

आईएचसी, नई दिल्ली, में न्यूपा द्वारा आयोजित स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन में भाग लिया, फरवरी 10–11, 2015।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vksa dk vk;kstu

गंजाम ओडिशा में तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर ओडिशा में परामर्शदात्री बैठक का निरूपण और आयोजन, ओडिशा, 6–9 अगस्त, 2014 (प्रो. एस.एम. आई.ए. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) का आयोजन किया।

गुवाहाटी, असम, पूर्वोत्तर राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्यशाला का (डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) आयोजन और निरूपण, 08–11 सितम्बर, 2014।

यरकाड, सेलम, तमिलनाडु में आरएमएसए के तहत ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी 2015/126 के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला, का निरूपण और आयोजन, 21–26 सितम्बर, 2014 (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और डॉ. एन. के. मोहंती के साथ)।

चेन्नई, तमिलनाडु में जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरूपण और आयोजन, 08–13 दिसम्बर, 2014 (डॉ. एन.के. मोहंती के साथ)।

भुवनेश्वर, ओडिशा में जिला माध्यमिक शिक्षा की योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरूपण और आयोजन ओडिशा, 22–27 दिसम्बर, 2014 (डॉ. एन.के. मोहंती के साथ)।

चंडीगढ़ में न्यूपा द्वारा आयोजित पंजाब डीईओ सम्मेलन में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में काम किया 28–29 जनवरी, 2015।

भुवनेश्वर, ओडिशा में माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए, ओडिशा की ओर से आयोजित एडब्ल्युपी का निरूपण एवं आरएमएसए के तहत 2015–16 के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी के साथ) एक संसाधन व्यक्ति के रूप में काम, 2–3 मार्च, 2015।

ikBîØe çf'k{k.k lkexh dk fodkl vkS f'k{k.k

आरएमएसए पर केंद्रित माध्यमिक शिक्षा में जिला योजना पर अभिप्रेरणात्मक अभ्यास का संशोधन (डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) अगस्त 2014 ।

ऑनलाइन पीजीडेपा पाठ्यक्रम का निरूपण और विकास (प्रो. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ), मूडल के प्रयोग से ''शैक्षिक योजना पर उन्नत पाठ्यक्रम'' विकसित।

सेक्टर निदानः पहुंच और भागीदारी के संकेतकः पर अभिप्रेरणा अभ्यास (प्रो एस.एम.आई.ए. जैदी और डॉ. एन. के. मोहंती के साथ) विकसित किया, अगस्त 2014

आंतरिक क्षमता के संकेतकः सेक्टर निदान पर अभिप्रेरणा अभ्यास (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और डॉ. एन.के. मोहंती के साथ) विकसित किया, अगस्त 2014।

vU; 'kS{kd vkS O;kolkf;d ;kxnku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकनः

पीएच–डी. के बाहरी परीक्षक शोध प्रबंध ''स्कूल में उपस्थिति के निर्धारण में सामाजिक–आर्थिक कारकः पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद जिलों का एक अध्ययन'' श्री देबदुलाल ठाकुर, जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान संस्थान, जेएनयू, नई दिल्ली, अप्रैल 2014।

पी.एच–डी. पर्यवेक्षण सुश्री निधि रावत 'भारत में प्राथमिक शिक्षा में जीआईएस आधारित स्कूल मैपिंग का एक अध्ययन''

पी.एच–डी. पर्यवेक्षण, 'पश्चिम बंगाल में स्कूल आधारित प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारीः बर्दवान और पुरुलिया जिलों में चयन माध्यमिक स्कूलों का एक अध्ययन''। श्री दीपेंद्र कुमार पाठक द्वारा।

पीजीडेपा परियोजना शोध अध्ययन पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, श्री दलीप कुमार वर्मा द्वारा ''हिमाचल प्रदेश में आरएमएसए के तहत निधि प्रवाह और उपयोग प्रतिमान का एक अध्ययन''।

शोध प्रबंध पर्यवेक्षण, श्री एम. अदामूः मेराडी/नाइजर के क्षेत्र में शिक्षकों के विकास के मॉडल और नीतियां का एक अध्ययन''।

शिक्षणः

सम्पादित एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम नं ओसी–1 (शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत योजना तकनीक) (डॉ एनके मोहंती के साथ), 2014–16।

पाठ्यक्रम समन्वयक, पीजीडेपा पाठ्यक्रम सं. 903ः शैक्षिक योजना, नवंबर 2014।

शैक्षिक योजना के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और न्यूपा के पाठ्यक्रमों के संचालन से संबद्ध।

शैक्षिक योजना से जुड़े न्यूपा के अन्य पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से संबद्ध।

पाठ्यक्रम समन्वयक, (डॉ सुमन नेगी के साथ) आईडेपा पाठ्यक्रम सं. एनओ 205ः कार्यप्रणाली और शैक्षिक योजना की तकनीक, मार्च 2015।

पाठ्यक्रम समन्वयक, (डॉ सुमन नेगी के साथ) आईडेपा पाठ्यक्रम सं. एनओ 207ः शिक्षा विकास परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन, मार्च 2015।

अन्य गतिविधियांः

प्रमुख, परियोजना प्रबंधन एकक, न्यूपा में अनुसंधान की निगरानी के लिए फरवरी 2015 में दस्तावेज (1 और 2) तैयार किया।

न्यूपा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप की सिफारिश के लिए न्यूपा शोध समूह का संयोजक।

न्यूपा अनुसंधान शुरू करने के लिए कार्य समूह का संयोजक, रिपोर्ट श्रृंखला 2015 प्रकाशन।

न्यूपा कार्य समीक्षा एवं सलाहकार समिति का सदस्य।

न्यूपा की प्रकाशन सलाहकार समिति का सदस्य।

सदस्य, न्यूपा नीति संक्षिप्त श्रृंखला संपादक मंडल।

सदस्य, एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा की डिजाइन के लिए समिति।

एम.फिल./पी–एच.डी. की लिखित परीक्षा लिपियों के मूल्यांकन के लिए सदस्य, समिति।

भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देने के लिए आरएमएसए–टीसीए और न्यूपा सहयोगी कार्यक्रमों में भाग लिया।

एम.फिल./पी–एच.डी. में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन में सहायता प्रदान की। 2015/16।

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkS 'kS{kd lgk;rk

भुवनेश्वर, आरएमएसए–टीसीए द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तर की योजना के परिप्रेक्ष्य पर एक कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, 21–22 मई, 2014।

आरएमएसए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की परिणाम ढांचे और निगरानी के दस्तावेज के विकास में (डॉ एनके मोहंती के साथ) योगदान दिया। पिछले वर्षों के रुझान और माध्यमिक शिक्षा के उप–क्षेत्र में आरएमएसए के कार्यान्वयन और अन्य संबंधित हस्तक्षेप के कारण भविष्य में परिवर्तन के विश्लेषण पर आधारित

आरएफडी में मात्रात्मक संकेतक से प्रत्येक के लिए लक्ष्यों को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा जनवरी 2015 में आरएमएसए जे.आर.एम. में नवीनतम संशोधित राष्ट्रीय स्तर की आरएफडी प्रस्तुत की गई।

प्रो जे.बी.जी. तिलक, न्यूपा की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित स्कूल शिक्षा पर वित्तीय आंकड़ों के विशेषज्ञ समूह के सदस्य।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएमएसए के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आरएमएसए के तहत राज्य और जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (परिप्रेक्ष्य और एडब्ल्यूपी एंड बी) की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आरएमएसए के विभिन्न परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठक में भाग लिया, फरवरी 2015 से मई 2014 तक।

M, , u-d s ekg a h

çdk'ku

शोध पत्र/लेख/नोट्सः

(न्यूपा, समसामयिक पत्र, 2014 में प्रकाशन के लिए स्वीकार) भारत में माध्यमिक स्तर पर प्रावधान और स्कूल प्रदर्शन।

vuqla/kku v/;;u

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर कार्य अनुसंधान परियोजना (प्रो. एस.एम.आई.ए. ज़ैदी और प्रो. के. बिस्वाल) के साथ।

भारत में माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक–निजी मिश्रण पर एक अनुसंधान परियोजना स्कूल सुविधाएं और आंतरिक प्रोफाइल शुरू की (जारी)।

laxks"Bh@lEesyu@dk;Zkkyk vk;ksftr@lEesyu@dk;Zkkyk esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीयः

न्यूपा, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 28–29 नवम्बर, 2014 को आयोजित शैक्षिक प्रशासन में अभिनव पर राष्ट्रीय सम्मेलन में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में काम किया।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Zkkyk vk;ksftr dk vk;kstu

गंजम, ओडिशा, 06–09 अगस्त, 2014 ''तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर परामर्शदात्री बैठक'' (प्रो. एस.एम. आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ) का आयोजन किया।

तमिलनाडु में आरएमएसए के तहत ए.डब्ल्यू.पी. तथा बी 2015–16 के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला (प्रो एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो के. बिस्वाल के साथ) का आयोजन किया। यरकौड, सेलम, तमिलनाडु, 21–26 सितम्बर, 2014।

çf'k{k.k lkexh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu"ikfnr

आरएमएसए पर बल के साथ माध्यमिक शिक्षा में जिला योजना पर सतत अभ्यास (प्रो. के. बिस्वाल के साथ) संशोधित अगस्त 2014।

पहुंच और भागीदारी के संकेतक क्षेत्र निदान पर सतत अभ्यास व्यायाम (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ) विकसित, अगस्त 2014।

आंतरिक क्षमता, के संकेतकः क्षेत्र निदान पर सतत् अभ्यास व्यायाम (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ) विकसित अगस्त 2014।

यू.पी.ई. के लिए परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी हेतु क्षेत्र निदान पर अनुरूपण अभ्यास, प्रो. के. बिस्वाल के साथ, सितंबर 2014।

गुवाहाटी, असम, 08–11 सितम्बर, 2014 'माध्यमिक पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा के लिए योजना हेतु मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्यशाला' (डॉ. के. बिस्वाल के साथ) आयोजन किया।

डॉ. के. बिस्वाल के साथ आयोजित 'तमिलनाडु में जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम'। चेन्नई, तमिलनाडु, 08–13 दिसम्बर, 2014।

डॉ के. बिस्वाल के साथ आयोजित 'ओडिशा में जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम',

भुवनेश्वर, ओडिशा, 22–27 दिसम्बर, 2014।

v U; 'kS{kd vkS O;kolkf;d ;ksxnku

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन:

श्री राकेश कुमार, व्याख्याता, आहार, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा 'प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की भागीदारी पर एक अध्ययन' शीर्षक डेपा 2014 शोध प्रबंध का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण किया।

इथियोपिया के श्री मेसफिन हेली द्वारा आईडेपा 2014 शोध प्रबंध शीर्षक ''इथियोपिया में एस.एन.एन.पी. क्षेत्रीय राज्य में प्राथमिक स्तर पर बाहर के स्कूल बच्चों को प्रभावित करने वाले कारक''।

पाठ्यक्रम समन्वयन:

आईडेपा पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में, आयोजित पाठ्यक्रम सं. 204 शैक्षिक योजना, फरवरी 2015।

शिक्षण:

एम.फिल./पीएच–डी. के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम नं ओसी–1 (शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत योजना तकनीक) (प्रो. के. बिस्वाल के साथ) कार्यक्रम, 2014–16।

आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 205 कार्यप्रणाली और शैक्षिक योजना की तकनीक, मार्च 2015

शिक्षा विकास परियोजनाओं की योजना तथा निगरानी आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 207, मार्च 2015

पाठ्यक्रम समन्वय के रूप में, पीजीडेपा पाठ्यक्रम सं. 903: शैक्षिक योजना : संकल्पना, प्रकार तथा उपागम का संचालन, नवंबर 2013

शैक्षिक योजना के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और न्यूपा के पाठ्यक्रम से संबद्ध।

अन्य गतिविधियां:

एम.फिल./पीएच–डी. प्रवेश समिति के एक सदस्य के रूप में एम.फिल./पीएच–डी. में प्रवेश कार्यक्रम 2014–16, के लिए संसाधन अनुप्रयोगों और अन्य संबंधित गतिविधियों में सहायता प्रदान की।

l koZ fud fud k; ksa d ks i j ke' kZ v kS ' kS{kd l gk; r k

आरएमएसए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संरचना और निगरानी के दस्तावेज की तैयारी और रूपरेखा को अंतिम रूप देने में (प्रो. के. बिस्वाल के साथ) योगदान दिया और सेमीस 2009/10 और 2012–13 के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आरएफडी में सभी मात्रात्मक संकेतकों के लिए वर्ष 2013–14 के लिए आंकड़ा प्रदान किया। इसके अलावा, पिछले वर्षों के रुझान और आरएमएसए और माध्यमिक शिक्षा के उप–क्षेत्र में अन्य संबंधित हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के कारण संभावित परिवर्तन के विश्लेषण पर आधारित आरएफडी में मात्रात्मक संकेतक से प्रत्येक के लिए लक्ष्यों को प्रदान किया। यह दाताओं के साथ बातचीत और आरएमएसए में प्रगति की निगरानी के लिए आरएफडी को अंतिम रूप देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सक्षम किया। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्य विशिष्ट आरएफडी को विकसित करने और लागू करने के लिए कहा गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएमएसए के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत राज्य और जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (परिप्रेक्ष्य और ए.डब्ल्यु.पी. एंड बी.) आरएमएसए के तहत की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, में आरएमएसए के विभिन्न परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठक में भाग लिया, मई 2014 से फरवरी 2015।

ओडिशा माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए, ओडिशा, भुवनेश्वर, ओडिशा की ओर से आयोजित ए.डब्ल्यू.पी. का निरूपण एवं आरएमएसए के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला में (प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी और प्रो. के. बिस्वाल के साथ) संसाधन व्यक्ति के रूप में, 02–03 मार्च, 2015।

l qu usxh

l ak's'Bh@lEesyu@dk;Zkyk,a esa Hkkx hnkjh

राष्ट्रीय:

न्यूपा, द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 28–29 नवम्बर, 2014।

कुरुक्षेत्र, हरियाणा में, डीईओ और बी.ई.ओ के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन, 03–04 जनवरी, 2015।

न्यूपा द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक, 10–11 फरवरी, 2015।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Zkyk,a

'शिक्षा में मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय।

शैक्षिक अनुसंधान में सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के उपयोग पर कार्यशाला के लिए (प्रो. ए.सी. मेहता) के साथ समन्वयक।

i kBî Øe çf'k{k.k lkexh dk fodkl vkS v è;ki u

आंकड़ा विशेषताओं की समझ पर मॉड्यूल।

शैक्षिक विकास के संकेतकों पर मॉड्यूल।

vU; 'kS{kd vkS O;kolkf;d ;kxnku

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन:

पर्यवेक्षण, आईडेपा के श्री जीसेन त्रूपका द्वारा ल्हुंसे जिला, भूटान में शिक्षकों के प्रोत्साहन के स्तर पर एक अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध 2014।

यंगरजुंगला द्वार पीजीडेपा परियोजना शोध प्रबंध: नगालैंड के 'जूनियर शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व क्षमता निर्माण का पर्यवेक्षण

पाठ्यक्रम समन्वय :

परियोजना योजना और लेखन: पीजीडेपा पाठ्यक्रम नं. 905 के लिए पाठ्यक्रम संयोजक।

कोर्स के प्रभारी' आईडेपा कोर्स पाठ्यक्रम: नं. 205 कार्यप्रणाली और शैक्षिक योजना की तकनीक (प्रो. बिस्वाल के साथ)

प्रभारी आईडेपा पाठ्यक्रम नं. 207 परियोजना योजना और प्रबंधन: (प्रो. बिस्वाल के साथ)।

अन्य गतिविधियां:

एम.फिल. में (सीसी 03) अनुसंधान क्रियाविधि के शिक्षण में शामिल।

l koZ fud fud k;ksa d ks i j ke'kZ v kS 'kS{kd l gk;rk

हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के राज्यों के लिए आरएमएसए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का मूल्यांकन (2014–15)

शैक्षिक प्रशासन विभाग

d s l q kr k ¼fo Hkkx kè;{k½

çdk'ku

पुस्तकें/दस्तावेज/रिपोर्ट:

- इनोवेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन: अब्स्ट्रैक्ट्स (ज्वाइंटली प्रीपेयर्ड, न्यूपा, 2014)
- इनोवेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन: स्लैक्ट केसेज (एडीटेड ज्वाइंटली विद कुमार सुरेश, न्यूपा 2014)

शोध पत्र/लेख/टिप्पणियां :

प्राइवेट ट्यूशन इन इंडिया : ट्रेंड्स एंड इश्यूज, पेडोगॉस इंटरनेशनल जर्नल, सीआइईपीएस, पेरिस, एटलियर 5: कोले एट सोसाइटी, ला कान्फीएन्स इन जेयू

इनोवेशंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन : स्लैक्टेड केसेज (2014) न्यूपा नई दिल्ली (एडीटेड ज्वाइंटली)।

व्हाट मेक्स स्कूल्स सक्सैसफुलः केस स्टडीज आफ सेकेण्डरी स्कूल्स, शिप्रा पब्लिशर्स एंड न्यूपा (फोर्थकमिंग)

v uq akku v è; ; u

पूरे किएः

नौ राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)।

आंध्र प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्याप्त सुविधाओं का आकलन (मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

शिक्षा के अधिकार के तहत समेकन और बहिष्करणः दिल्ली, के दिल्ली पब्लिक स्कूलों का केस अध्ययन (संयुक्त) 2014।

जारीः

तृतीय, अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण 2012–2015 (संयुक्त अध्ययन)।

l a ks'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीयः

यूनिसेफ द्वारा भुवनेश्वर, भारत में आदिवासी बच्चों का पोषण : सीमांतकों की आवाजें, अच्छे कार्य व्यवहार और नीति निहितार्थ राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया 15–16 जनवरी, 2015।

अंतर्राष्ट्रीयः

पेरिस, फ्रांस में आईडीपी केन्द्र द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिक्षा विचार मंच में भारत में निजी ट्यूशनः प्रवृत्तियां और मुद्देः आलेख प्रस्तुत, 11–13 जून, 2014।

तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली, भारत के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा' पर एक सत्र की अध्यक्षता की 16–18 नवम्बर, 2014

çf'k{k.k kd k; Ø e@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

भुवनेश्वर, ओडिशा, 08–09 मई, 2014 के राज्य स्तरीय डीईओ और बीईओ, सम्मेलन में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

जिला और उप जिला स्तर पर प्रशासन का सुदृढ़ीकरणः जिला शिक्षा अधिकारियों की बदलती भूमिकाएं पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 22 अगस्त, 2014 (संयुक्त कार्यक्रम)

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार और पुरस्कार प्रस्तुति, 27–28 नवंबर 2014.

तीसरी अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला, हैदराबाद, 15–17 दिसम्बर, 2014 (संयुक्त कार्यक्रम)।

कुरुक्षेत्र, हरियाणा में डीईओ और बीईओ सम्मेलन – संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, 03–04 जनवरी, 2015।

उपेक्षित समूहों की शिक्षा नीतियाँ, कार्यक्रम और मुद्दे और चुनौतियां, पर एंट्रीप के तहत क्षेत्रीय कार्यशाला, 25–27 मार्च, 2015ः गुवाहाटी, असम में क्षेत्रीय कार्यशाला डीईओ और बीईओ सम्मेलन – राज्य में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, जनवरी 20–21, 2015।

v U; 'kS{kd v kS O; kol kf; d ; kxn ku

पर्यवेक्षण और मूल्यांकनः

दो पी–एच.डी. और एक एम.फिल. विद्यार्थी का पर्यवेक्षण।

शिक्षणः आईडेपा के 10 सत्र डेपा (10 सत्र) शैक्षिक प्रशासन का शिक्षण, फरवरी–अप्रैल 2015।

एम.फिल/पी–एच.डी. के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर कोर पाठ्यक्रम शिक्षण (10 सत्र)।

अन्य गतिविधियांः

एन.सी.एस.एल. द्वारा संचालित स्कूलों के प्रिंसिपलों के पीजी डिप्लोमा के लिए अतिथि व्याख्यान दिया।

एन्ट्रीप न्यूजलेटर (द्वि–वार्षिक) और न्यूपा समसामयिक पेपर सीरीज के संपादक

U; wk d s ckgj ç[; kr fud k; ksa d h l nL; r k

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल स्टडीज

सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, सीमैट, तिरुवनंतपुरम, केरल

सदस्य, ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के शिक्षा'' पर अखिल भारतीय अध्ययन के लिए समन्वय समिति, आईसीएसएसआर, नई दिल्ली

वीपीजीएस, शिक्षा शिक्षा संस्थान, बीबीए विश्वविद्यालय, लखनऊ

सदस्य, कार्यकारी निकाय, एनईजीएफआईआरई, नई दिल्ली

d q kj l gjs'k

çdk'ku

पुस्तकें/अध्याय:

अब्स्ट्रैक्ट्स आफ इनोवेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशनः (ज्वाइंटली प्रीपेयर्ड, न्यूपा, 2014)

इनोवेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशनः स्लैक्ट केसेज (एडीटेड ज्वाइंटली विद प्रो. के. सुजाता, न्यूपा, 2014

चैप्टर ऑन 'अफरमेटिव एक्शन एंड 'पैरिटी आफ पार्टीसिपेशन', इन हायर एजुकेशनः पालिसी पर्सपैक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिसपॉन्स (इन प्रैस इन एन एडीटेड वाल्यूम पब्लिशरुड बाइ रूटलेज)

vuql a/kku v/;;u

जारी अध्ययन:

तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण 2012–2015 (संयुक्त अध्ययन)।

मध्य प्रदेश और बिहार में 'प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की साझी जिम्मेदारियां और क्षमता' पर अध्ययन।

l a ks'Bh@lEesyu@dk;Zkkyk vkSa esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय:

शैक्षिक नीति विभाग, न्यूपा द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक अभिशासन और जनभागीदारी : नीतिगत सुधार और कार्यक्रम और कार्यक्रम कार्यव्यवहार पर आयोजित द्वितीय अनिल बोर्डिया स्मारक संगोष्ठी में भाग लिया और विकेंद्रीकृत और सहभागितापूर्ण विद्यालय अभिशासन : नीति और कार्यव्यवहार का अंतःसंबंध पर आलेख प्रस्तुत किया, फरवरी 16–17, 2015

प्रो. नंदू राम के सम्मान में 'सीमाओं के पार और अन्यता : अस्मिता और अंतर सांस्कृतिक अंतराल का प्रतिबिंब पर सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित डॉ अंबेडकर चेयर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुति, नई दिल्ली।

शिक्षण अधिगम और क्षमता विकास में स्नातकोत्तर प्रमुखों/डीन के कार्यशाला में भाग लिया और डॉक्टरल शोध रुझान और तुलनात्मक प्रथा पर प्रस्तुति दी।

हैदराबाद में शैक्षिक प्रशासन पर दक्षिण भारतीय राज्यों, के क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

दिल्ली में उत्तर भारतीय राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय:

भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संघवाद और वैश्विक दुनिया में अभिशासन : मुद्दे और चुनौतियां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और वैश्वीकरण अभिशासन पर विमर्श के बदलते मुद्दे और शैक्षिक संघवाद की खिसकती जमीन पर आलेख प्रस्तुत किया 4–5 फरवरी, 2015।

çf'k{k.k dk;ZØe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिला और उप–जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन के मजबूतीकरण पर कार्यशाला, न्यूपा, नई दिल्ली, 20–22 अगस्त, 2014 (प्रो के. सुजाता के साथ)

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन (प्रो के. सुजाता के साथ) नई दिल्ली, 28–29 नवम्बर, 2014

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और समता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम। न्यूपा, नई दिल्ली, 17–20 मार्च, 2015

नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियां : हाशिए पर समूह की शिक्षा पर (प्रो. के. सुजाता के साथ) एंट्रीप क्षेत्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015

i kB~; Øe v kS ç f' k{k.k l kex h d k fo d kl v kS f' k{k.k

, e-fQ y -@ i h&, p -Mh- i kB~; Øe

समन्वयक, पाठ्यक्रम विकास दल (एम.फिल. / पी–एच. डी.)

सीसीः 7ः शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन

सीसीः 1ः शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

ओसीः 07ः समता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा

y \$ ku d kS ky

सदस्य, पाठ्यक्रम विकास टीमः

शिक्षा नीति

शिक्षा और मानवाधिकार

स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी

i ht hMh k i kB~; Øe d sfy , %

शैक्षिक प्रबंधन (आमने–सामने शिक्षण)

उन्नत पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम समन्वयक)

v U; ' kS{kd v kS O; kol kf; d ; kxnku

i ; Z\${k.k@ e kxZn'kZu %

एक एम.फिल. विद्यार्थी के शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण।

दो पी–एच.डी. विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण

डेपा और आईडेपा में प्रत्येक के एक–एक परियोजना अध्ययन का पर्यवेक्षण

i kB~; Øe l eUo; ¼, e-fQ y -@ i h&, p -Mh-½%

पाठ्यक्रम के लिए समन्वयकः सीसी–07ः शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन

पाठ्यक्रम के लिए समन्वयक ओसी–07ः समता और बहु सांस्कृतिक शिक्षा

शिक्षणः

सीसी–01ः राजनीतिक परिप्रेक्ष्य (एम.फिल. / पी–एच.डी.)

v U; x fr fo f/k; k %

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के शुभारंभ कार्यक्रम के विस्तार चयन / मूल्यांकन और वैधता के ढाँचे का विकास, चयन / मूल्यांकन / वीडियो सम्मेलन आदि, क्षेत्र दौरे, परामर्श और जन निकायों के शैक्षणिक अनुसमर्थन के द्वारा चुनिंदा नवाचारों की प्रमाणिकता की प्रक्रिया से संम्बद्ध (प्रो. के. सुजाता के साथ)।

l ko Z fud fud k; ksa d ks i j ke ' kZ r Fkk v d kn fe d l eFkZu

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए स्वायत्त स्थिति और मान्यता देने और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन और तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

दिल्ली विश्वविद्यालय (1), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (5), जामिया मिलिया इस्लामिया (3), इग्नू (2), पटना विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय आदि की डॉक्टरेट थीसिस के लिए बाह्य परीक्षक

U; wk d s c kg j ç[; kr fu d k; ksa d h l nL; r k

आजीवन सदस्य, भारतीय सामाजिक सोसायटी

आजीवन सदस्य, आईआईपीए

सदस्य, विशेषज्ञ समिति, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, सदस्य संपादकीय बोर्ड, जर्नल आफ गांधीयन स्टडीज

अनुसंधान अध्ययन बोर्ड, इग्नू

सदस्य, शैक्षणिक सलाहकार समिति, रायपुर विश्वविद्यालय

सदस्य, शासी निकाय, सेंट जेवियर्स शिक्षा कॉलेज, (ऑटोनोमस) पलयामकोट्टि, तमिलनाडु

fo u hr k fl j kg h

ç d k' ku

शोध पत्र / लेख / नोट्सः

पेपर "स्किल्स इन्फॉरमेशन बेस फार टैक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसी", इंडियन एजुकेशनल रिव्यू जर्नल (एनसीईआरटी, दिल्ली), जुलाई 2014 इश्यू।

आर्टिकल ''एजुकेशन–इंडस्ट्री इंटरफेस की टू स्किल प्रोजैक्ट'', द हिन्दुस्तान टाइम्स (फरवरी 25, 2015)।

पेपर ''वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया: पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेज'' (अंडर रिविजन) फॉर पब्लिकेशन इन एशिया–पैसिफिक जर्नल आफ कोआपरेटिव एजुकेशन।

l a ks'Bh@l Ee s yu@d k; Zkky kv ksa e s a Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय:

'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ शिक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, 1 सितम्बर, 2014।

यूनिसेफ, बेंगलुरू, द्वारा आयोजित 'किशोरावस्था प्रोग्रामिंग' पर कार्यशाला में भाग लिया 30–31 अक्टूबर, 2014।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली, में आयोजित 'शैक्षिक प्रशासन में नवाचार' हेतु पुरस्कार वितरण समारोह और दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, 28–29 नवम्बर, 2014

अंतर्राष्ट्रीय:

सीबीएसई और वाणिज्य एवं उद्योग पीएचडी चैंबर, ''स्कूलों में कौशल'' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, 11 अप्रैल, 2014 को आयोजित

शैक्षिक योजना, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के एशियन नेटवर्क (एंट्रीप) के 'सीमांतकों की शिक्षा: नीतियों कार्यक्रमों और चुनौतियां' पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया, 25–27 मार्च, 2015

v k; k\$t r çf' k{k. k d k; Øe @ d k; Zkky k@ l Ee s y u

'व्यावसायिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन' पर अभिविन्यास कार्यक्रम, न्यूपा, 1–05 दिसम्बर, 2014।

न्यूपा के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्ति

çf' k{k. k l kexzh v k\$ i kBî Øe d kfod kl v k\$ f' k{k. k

समन्वयक, एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम

वैकल्पिक पाठ्यक्रम संगठनात्मक में संशोधन योगदान विकास और नेतृत्व और शैक्षिक प्रशासन के कोर पाठ्यक्रम।

पीजीडेपा कार्यक्रम में संगठनात्मक व्यवहार पर एडवांस कोर्स के लिए सामग्री की पहचान

शिक्षा की योजना और प्रबंधन और प्रशिक्षण पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए पठन सामग्री की पहचान

v U; ' k\$kf. kd v k\$ O; kol kf; d ; kx n ku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकन:

एम.फिल. व पी–एच.डी. विद्यार्थियों का शोध मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण

डेपा और आईडेपा के शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण

शिक्षण:

मूल पाठ्यक्रम सीसीआई– शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में एसोसिएट संकाय और शिक्षण (12 सत्र)

पीजीडेपा में शैक्षिक प्रशासन पर पाठ्यक्रम में एसोसिएट संकाय और शिक्षण

अन्य गतिविधियां:

न्यूपा अनुसंधान के कार्य समूह के सदस्य के रूप में योगदान, प्रकाशन श्रृंखला रिपोर्ट

न्यूपा – अनुसंधान पर कार्य समूह के सदस्य एक के रूप में योगदान

l koZ fud fud k; ksa d ks i j ke' kZ v k\$ ' k\${kd l gk; rk

स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर एप्टीट्यूड मूल्यांकन (एमएचआरडी) के लिए विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में योगदान।

सर्व शिक्षा अभियान, की 21वीं संयुक्त समीक्षा मिशन में मिशन के सदस्य के रूप में योगदान (भारत सरकार

नामित) 2–12 फरवरी, 2015. उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर जिलों का दौरा करने और राज्य की रिपोर्ट तैयार किया।

इंडियन जर्नल वोकेशनल एजुकेशन के लिए आलेख की समीक्षा, पीएसएससीआईवीई

U;wk d sckgj ç[;kr fudk;ksad hl nL;rk

सदस्य, इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल एजुकेशन के लिए संपादक मंडल

सदस्य, टीवीईटी के उभरते – विजन 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शैक्षणिक समिति, पीएसएससीआईवीई, भोपाल

आजीवन सदस्य, भारतीय प्रयुक्त मनोविज्ञान एकेडमी

आजीवन सदस्य, भारतीय नैदानिक मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन

v kj-,l - R;kxh

çdk'ku

शोध पत्र/लेख/नोट्सः

''एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स इन मैंनेजमेंट आफ एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया–इम्पैक्ट आफ ग्लोबलाइजेशन'', इंडियन जर्नल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम 9, सं. 4, अक्टूबर–दिसंबर 2014'', पीपी. 776–791 (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली)।

''गर्वनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया'', झारखण्ड जर्नल आफ डवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज वाल्यूम 13, नं. 1, (जनवरी–मार्च 2015). पीपी. 6346–6361 (जेवियर इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस) डा. कमिल बकर पथ, रांची–834001, झारखण्ड

vuqla/kku v/;;u

पूर्णः

केरल में शैक्षिक प्रशासनः संरचनाएं, कार्य और प्रक्रियाएं।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए समन्वयक। न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 सितम्बर, 2014।

एससीईआरटी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा, सहित दक्षिणी राज्यों के लिए शैक्षिक प्रशासन की तीसरी अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए समन्वयक, 15 से 17 दिसंबर 2014।

उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर के लिए शैक्षिक प्रशासन की तीसरी अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए समन्वयक। न्यूपा, नई दिल्ली, 12–14 फरवरी, 2015।

शैक्षिक प्रशासन की तीसरी अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए समन्वयक के रूप में, डिजाइन और सर्वेक्षण के चार प्रकार के उपकरणों के लिए शोधनः (विभाग के प्रमुख के मार्गदर्शन में) के निम्न प्रमुख गतिविधियों में शामिल किया गया।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय के लिहाज से सामग्री और प्रारूप तैयार करना।

राज्यों और संघ राज्यों में सर्वेक्षण के लिए राज्यवार नोडल अधिकारियों का नामांकन।

सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली और तौर तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय और राज्य स्तर के संगठन की कार्यशालाओं का आयोजन।

çf'k{k.k lkexzh vk\$ ikBîØe fodflr vk\$ fu'ikfnr

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सामग्री/पाठ्यक्रम विकसित, न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 सितम्बर, 2014

पीजीडेपा पाठ्यक्रम 904 यूनिट 1 के लिए विकसित कोर्स शैक्षिक प्रशासन।

vU; 'kS{kd vkS O;kolkf;d ;ksxnku

i;Zo{k.k@eY;kadu %

एक पीजीडेपा और एक आईडेपा में भागीदार के परियोजना अध्ययन का मार्गदर्शन।

ikB~;Øe leUo; %

संयोजक शैक्षिक प्रशासनः पीजीडेपा पाठ्यक्रम 904 यूनिट 1

अन्य गतिविधियां:

सदस्य सचिव, मॉडल शिक्षा संहिता की तैयारी पर समिति के रूप में, न्यूपा में परियोजना मोड में कोड की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए समिति, उप–समिति और विशेषज्ञ समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित) के समन्वित कई बैठकों का आयोजन ।

lkoZ fud fudk;ksa dks ijke'kZ vkS 'kS{kd lgk;rk

तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर राज्य स्तर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, अमृतसर, 30–31 मार्च 2015।

U;wik ds ckgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

सदस्य, स्कूली शिक्षा बोर्ड में नियमन और समतुल्यता पर समिति।

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ।

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी शिक्षा समितियों के वर्ल्ड कांग्रेस का –एक सहबद्ध संगठन।

eaFku : yk

çdk'ku

शोध पत्र/लेख/नोट्स:

''एजुकेशनल डवलपमेंट आफ मुस्लिम मिनियोरिटीः विद स्पेशल रिफ्रेंस टू मुस्लिम कन्स्ट्रेटेड स्टेट्स आफ इंडिया, जर्नल आफ एजुकेशन एंड रिसर्च, काठमाण्डू युनिवर्सिटी, स्कूल आफ एजुकेशन, वाल्यूम 4, नं. 1, 2014.

''वूमन एजुकेशन इन पोस्ट इनडिपेंडेंस इंडिया'', (को–ऑथर गौरी श्रीवास्तव) इन मर्मर मुखोपाध्याय एंड मधु परहार (एडीटर) इंडियन एजुकेशन, ए डवलपमेंटल डिस्कोरेज, नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन (2015)

vuqlaèkku vè;;u

पूरे किएः

बिहार में शैक्षिक प्रशासनः संरचना, प्रक्रिया और भावी संभावनाएं

laxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय:

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शैक्षिक प्रशासन में नवाचार और पुरस्कार वितरण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, 28–29 नवम्बर, 2014

अंतर्राष्ट्रीय:

शैक्षिक योजना, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के एशियन नेटवर्क (एंट्रिप) द्वारा सीमांतकों की शिक्षाः नीतियां कार्यक्रम और चुनौतियां 'विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया, 25–27 मार्च, 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

जेपी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए 'शैक्षिक प्रशासन' पर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला। न्यूपा, नई दिल्ली, 09–13 जून, 2014

राज्य स्तरीय शैक्षणिक प्रशासकों के लिए 'प्रबंधन विकास' पर अभिविन्यास कार्यक्रम। न्यूपा, नई दिल्ली, 22–26 सितंबर, 2014।

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodkl rFkk f'k{k.k

पीजीडेपा में शैक्षिक प्रशासन पर उन्नत पाठ्यक्रम के लिए सामग्री की तैयारी में एसोसिएट संकाय के रूप में कार्य (चरण 5), और शिक्षण

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकनः

डेपा 2013–14 शोध प्रबंध शीर्षक ''उत्तराखंड के नौगांव ब्लॉक उत्तरकाशी जिले में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों, क्लस्टर स्तर के पदाधिकारियों और स्कूल प्रमुखों की भूमिका का अध्ययन''।

एम.फिल. शोध प्रबंध (2013) शिक्षा का अधिकार और समाज के वंचित धारा के बच्चे : दिल्ली में मलिन बस्तियों का एक अध्ययन मार्गदर्शन और मूल्यांकन।

मार्गदर्शन और मूल्यांकन : आईडेपा शोध प्रबंध ''काजोकेजी काउंटी, दक्षिण सूडान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की पहुंच, भागीदारी और मदद (2013–14)

पाठ्यक्रम समन्वयः

डेपा पाठ्यक्रम सं. 108 : भारत में शैक्षिक योजना का समन्वय, नवंबर 2013

शैक्षिक योजना प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में शैक्षिक प्रबंधन पाठ्यक्रम के समन्वयक।

शिक्षणः

शैक्षिक प्रबंधन पर पाठ्यक्रम का शिक्षण और संकाय सहयोगी

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kS{kd lgk;rk

सदस्य, 07–17 अक्टूबर, 2014 के दौरान मानव संसाधन विकास (एमएचआरडी) मंत्रालय द्वारा आयोजित, संयुक्त समीक्षा मिशन

U;wjk dscksgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

आजीवन – सदस्य, अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ।

आजीवन – सदस्य, भारत का तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी।

सदस्य, शिक्षा और आर्थिक विकास सोसायटी।

oh- lq/kkfjrk (अवकाश पर)

शैक्षिक वित्त विभाग

tàa;kyk chthfryd ¼foHkkxkè;{k½

çdk'ku

पुस्तकें/अध्यायः

लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लैक्ट रीडिंग्स (एडीटर, ए. मैथ्यू एंड जंध्याला बी.जी. तिलक), नई दिल्लीः शिप्रा प्रकाशन/नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2014।

शोध पत्र/लेख/नोट्सः

''ट्रांजिसन टू हायर एजूकेशन इन इंडिया'', इन ट्रांजिसन फ्रॉम सेकेण्डरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशनः केस स्टडीज फ्रॉम एशिया एंड द पैसिफिक पेरिसः यूनेस्को एंड बैंकॉक; यूनेस्को (2015), पीपी 47–66।

हायर एजुकेशन इन साउथ एशियाः क्राइसिस एंड चैलेजेज, सोशियल साइंटिस्ट, 43 (1–2), सं। 500–501 (जनवरी–फरवरी 2015)ः पृ. 43–59।

मिस्प्लेस्ड रिफ्रॉम्स (इन हायर एजुकेशन इन साउथ एशिया), सेमीनार नं. 665 (जनवरी 2015)ः पृ. 68–74।

ग्लोबल रैंकिंग्स वर्ल्ड क्लास यूनिर्वसिटीज एंड डिलेमा इन

हायर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया कृष्णा यूनिवर्सिटी पब्लिक लैक्चर 2014, मैकिलीपटनमः कृष्णा युनिवर्सिटी (18 अगस्त 2014)

प्राइवेट हायर एजुकेशन इन इंडिया, इकानमिक एंड पालिटिकल वीकली, 49 (40) (4 अक्टूबर 2014) पृ. 32–38 http://www.epw.in/system/files/pdf/2014_49/40/Private_Higher_Education_in_India.pdf

फैक्टर्स अफैक्टिंग द क्वालिटी आफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द फोर लार्जेस्ट इमरजिंग इकॉनमिक्स, हायर एजुकेशन, 68 (6) (दिसम्बर 2014): 977–1004 (ज्वाइंटली विद प्रशांत लॉयल्का, मार्टिन कॉरनॉय, इश्क फॉर्मिन, रफिक दोसनी एंड पोयंग), डीओआईः 10.1007/s107334-014-9755-8 http://download.springer.com/static/pdf/598/art%253A10.1007%252Fs10734-014-9755-8.pdf?auth66=142357078_a65091fd37a1152ace47d12f29e4e88d&ext=.pdf;

स्टेस्टिक्स आन एजुकेशन, सोशियल स्टेस्टिक्स डिवीजन, सेंट्रल स्टेस्टि ऑफिस, मिनिस्ट्री आफर स्टेस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लेमेंटेशन, गर्वमेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली, फरवरी 2014 (ज्वाइंटली विद पी.आर. पंचमुखी एंड के. बिस्वाल). http://mospi.nic.in/Mospi_new/upload/Them_Paper_Education.pdf साउथ–साउथ कूपरेशनः इंडिया प्रोग्राम आफ डवलपमेंट असिस्टेंस – नेचर, साइज एंड फंक्शनिंग, एशियन एजुकेशन एंड डवलपमेंट स्टडीज, 2014, 3(1): 58–75.

द कन्सैप्ट आफ पब्लिक गुड्स, द स्टेट, एंड हायर एजुकेशन फाइनेंसः ए व्यू फ्रॉम द ब्रिक्स, हायर एजुकेशन 68 (3) (सितम्बर 2014); 359–78 (ज्वाइंटली विद एम. कॉरनॉय, आइ. फ्रौमिन एंड पी. लॉयल्का). DOI10.1007/s10734-014-9717-1 http://wwwhse.ru/data/2014/03/05/1333111329/Carnoi_Froumin_Loyalka_Tilak_Public_Private%20Articale.pdf [also available at:SSRN Working Paper Series (June 2013) http://papers.ssrn.com/sol3/paper.cfm?abstract_id=2289126

''एडल्ट एजुकेशनः इंडियन परसैप्शन इन एन इवाल्यूशन पर्सपैक्टिव'', इन लिट्रेसी एंड एडल्ट एजुकेशनः स्लैक्ट रीडिंग्स (एडीटर ए. मैथ्यू एंड जांध्याला बी.जी. तिलक). नई दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन/न्यूपा, 2014, पीपी. 1–18 (ज्वाइंटली विद ए. मैथ्यू)।

ग्रोथ एंड रीजनल इनइक्वालिटी इन लिट्रेसी इन इंडिया'', इन लिट्रेसी एंड एडल्ट एजुकेशन स्लैक्ट रीडिंग्स (एडीटर ए मैथ्यू एंड जंध्याला बी.जी. तिलक), नई दिल्लीः शिप्रा प्रकाशन/न्यूपा, 2014, पीपी 113–25

पुस्तक/लेख समीक्षाः

इनोवेटिव एशियाः एडवांसिंग नौलेज–बेस्ड इकानमी (एशियन डवलपमेंट बैंक), जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 29(1) (जनवरी 2015): 91–92।

हायर एजुकेशन एंड द स्टेटः चेंजिंग रिलेशनशिप इन यूरोप एंड फास्ट एशिया (आर. गुडमैन. टी. करिया एंड जे. टेलर, एडीटर), जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 28(4) (अक्टूबर 2014): 433–37।

वर्ल्ड बैंक एंड एजुकेशन (एस.जे. क्लीज, जे. सेमॉफ एंड एन.पी. स्ट्रोमक्वेस्ट, एडीटर), जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 28(3) (जुलाई 2014): 311–14 (प्रेस में)

युनिवर्सिटी फार ए न्यू वर्ल्ड (डीएम स्क्रेडर), कन्टमप्रेरी एजुकेशन डायलॉग, 11(2) (जुलाई 2014) पृ. 235–41 http://ced.sagepub.com/content/11/235.full.pdf+html

द ग्रेट ब्रेन रेसः हाउ ग्लोबल युनिवर्सिटी आर रेस्पिंग द वर्ल्ड (बी. विल्डावस्की), जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 28 (2) (अप्रैल 2014): 200–03

l aks'Bh@ l Ee sy u e sa Hkkx hn kj h@ d k; Zkky k, a

राष्ट्रीयः

'भारतीय लोकतंत्र में दलितों के सतत विकास' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, में 28–29 अप्रैल, 2014

5वीं आईजीसी आईएसआई भारत विकास नीति सम्मेलन में एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर/भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली, 17–18 जुलाई, 2014।

'उच्च शिक्षा में सामाजिक समावेश' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में समापन भाषण। राजीव गांधी राष्ट्रीय

युवा विकास संस्थान और लोयला कॉलेज, चेन्नई, 29 अगस्त, 2014

दस वर्षीय समारोह सम्मेलन में असमानता पुनर्समीक्षा : साक्ष्य और नीति पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता, दिल्ली, 27–28 सितम्बर, 2014।

उच्च शिक्षा में नवाचार पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और एक विशेष व्याख्यान दिया। पी.बी. सिद्धार्थ कॉलेज, विजयवाड़ा और कृष्णा विश्वविद्यालय, 7–8 नवंबर, 2014।

नई दिल्ली में 16–18 नवम्बर, 2014 को भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी के वार्षिक सम्मेलन में विशेष सत्र की अध्यक्षता।

'भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के माहौल' पर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता और एक सत्र में पैनलकार। सामाजिक विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र, पांडिचेरी, 19–20 नवम्बर, 2014।

दिल्ली अर्थशास्त्र कॉन्क्लेव 2014 में भाग लिया, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 10–11 दिसम्बर, 2014, नई दिल्ली।

खंडित विश्व अर्थव्यवस्था में भारत विकास के पथ पर, भरत राम मेमोरियल संगोष्ठी, फिक्की, नई दिल्ली, 12, दिसंबर 2014 में भाग लिया ।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की दिशा पर आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय कुलपति सम्मेलन में पैनलकार, वी आई टी विश्वविद्यालय, वेल्लोर, 03–04 जनवरी, 2015

राष्ट्रीय सम्मेलन, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना : नयी ज़मीन की तलाश। भारतीय विश्वविद्यालय संघ और एसोचैम, नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015।

'विजन इंडिया' : आगे का रास्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में पैनलकार। सी.एल. वालिया वाणिज्य एवं कला कॉलेज, मुंबई, 27–28 जनवरी, 2015।

'विकास के लिए अभिशासन पर आयोजित सम्मेलन में पैनलकार। सीआईआई और तेलंगाना विकास मंच, हैदराबाद, 30 जनवरी 2015।

मुख्य वक्ता 'उभरती चुनौतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। जेएन व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, 14–15 फरवरी, 2015 जन भागीदारी और विकेन्द्रीकृत शैक्षिक शासन : नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण पर द्वितीय अनिल बोर्डिया मेमोरियल नीति संगोष्ठी में एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता। न्यूपा, नई दिल्ली, 16–17 फरवरी, 2015।

'उच्च शिक्षाः भारत और चीन का परिप्रेक्ष्य' पर संगोष्ठी में मुख्य भाषण। चीनी अध्ययन संस्थान, 27–28 फरवरी, 2015, नई दिल्ली।

अंतर्राष्ट्रीयः

'उच्च शिक्षा शिक्षण कर्मियों की शैक्षणिक संवर्धन' पर इरी–नेट विशेषज्ञ बैठक में आलेख प्रस्तुति, 20–21 मई, 2014 (यूनेस्को, बैंकॉक के सहयोग से) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान संस्थान, पेनांग, मलेशिया।

उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति, शिक्षा संकाय, हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग, 26–27 जून, 2014।

'उच्च शिक्षा सांख्यिकी' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पैनल सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय/योजना आयोग/यूनेस्को, नई दिल्ली, 03–04 जुलाई, 2014।

'विश्वविद्यालय अभिनव और आर्थिक विकास का एक स्रोत' पर पीकेयू–स्टैनफोर्ड फोरम में आलेख प्रस्तुति। पीकिंग विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड सेंटर, बीजिंग, 20–21 अक्टूबर, 2014।

'बड़े शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा का सार्वभौमीकरण पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में एक तकनीकी सत्र में परिचर्चाकार। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूपा, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014

आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तृतीयक शिक्षा के विस्तार। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एक उभरते अनुसंधान मुद्दे पर संगोष्ठी में भाग लिया। मेलबर्नः एलएच मार्टिन संस्थान (लैंगकॉवी 13–14 नवंबर, 2014 मलेशिया।

'उच्च शिक्षा में उर्ध्व सक्षमता और शिक्षण कर्मियों की

शैक्षणिक संवर्धन,' जेजियांग विश्वविद्यालय, हांग्जो, चीन पीपुल्स रिपब्लिक, पर यूनेस्को इरी–नेट की वार्षिक बैठक और अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लिया, 26–28 नवंबर, 2014।

'विकासशील देशों में विश्वविद्यालयों के कायाकल्प' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण। गीतम यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम और पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय 19–20 दिसंबर, 2014।

उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के अभिनव तरीके' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण। न्यूपा, नई दिल्ली, 23–25 फरवरी, 2015।

तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी के 59वें वार्षिक सम्मेलन में आलेख प्रस्तुति और एक तकनीकी सत्र का आयोजन एवं अध्यक्षता तथा विशेष सत्र का आमंत्रण। वाशिंगटन डीसी, 08–13 मार्च, 2015।

'सीमांतकों की शिक्षा' पर क्षेत्रीय कार्यशाला में तकनीकी सत्र की अध्यक्षता। एंट्रिप/न्यूपा, नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015

c ká O; k[; ku

2014, कृष्णा विश्वविद्यालय, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्याख्यान श्रृंखला, 18 अगस्त, 2014।

v U; 'kS{kd v kS O; kol kf; d ; ksx n ku

संपादक, जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (1990)

l koZ fud fud k; ka d ks i j ke 'kZv kS 'kS{kd l g k; r k

भारत में सरकार और अन्य निकायों (सरकारी समितियों में और सदस्यता) के लिए परामर्श सेवा

U; iwk d s c kg j ç[; kr fud k; ka d h l nL; r k

राष्ट्रीय :

सदस्य, शैक्षणिक समिति, शैक्षिक अध्ययन केंद्र, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे (2013–)

सदस्य, योजना बोर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, संचालन समिति नई दिल्ली (2013–)

अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा, वित्तीय आंकड़ा पर समिति : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (2013–)

सदस्य (विशिष्ट), शैक्षणिक सलाहकार समिति, सामाजिक विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पुडुचेरी संस्थान। (2014–)

सदस्य, शैक्षणिक कार्यक्रम समिति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (2014–)

सदस्य, मानक आधारित विश्वविद्यालय वित्तपोषण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (2014–)

सदस्य, सलाहकार बोर्ड, स्कूल शिक्षा, हैदराबाद विश्वविद्यालय (2014–)

l nL;] l ia kn d h; @l ia kn d h; l y kg d kj c kSMZ%

हायर एजुकेशन पालिसी

- कांटेमपोरैरी एजुकेशन डायलॉग (बैंगलोर)
- इंडियन जर्नल आफ ह्यूमन डवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फार ह्यूमन डवलपमेंट, नई दिल्ली।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान के लिए योगदानः आईएएसएसआई त्रैमासिक (नई दिल्ली)
- राजागिरि जर्नल आफ सोशल डवलपमेंट (केरल)

अंतर्राष्ट्रीयः

सदस्य, 2015 सी.आई.ई.एस. सम्मेलन सलाहकार समिति। तुलनात्मक और इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी अमरीका। (2014–15)

सदस्य, एशिया में उच्च शिक्षा पर पुस्तक श्रृंखला के सलाहकार बोर्ड (स्प्रिंगर)

शिक्षा और विकास अध्ययन पर इमराल्ड रिसर्च कंसोर्टियम (ताइवान/हांगकांग)

l ia kn d h; c kSMZ d s l nL;

- कम्पेयरः तुलनात्मक शिक्षा पर एक जर्नल (इंग्लैंड)
- शिक्षा की पीबॉडी जर्नल (वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका)
- विश्व शिक्षा फोरम (शिकागो, संयुक्त राज्य अमरीका)

- एशियाई प्रशांत शिक्षकों के जर्नल और शिक्षा (यूनीवर्सिटी सेन्स मलेशिया)
- शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अध्ययन के जर्नल (इलिनोइस विश्वविद्यालय)
- एशियाई शिक्षा और विकास अध्ययन (एमेराल्ड प्रकाशन/हांगकांग विश्वविद्यालय)
- शिक्षा के एशियाई–प्रशांत जर्नल (सिंगापुर)

; kt ky h t kt fQ u

अनुसंधान अध्ययन

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अध्ययन–डाईस डेटा विश्लेषण के तहत स्कूल अनुदान के उपयोग पर

çf' k{k.k l ke xh v k§ i kBî Øe d k fod kl , oaf' k{k.k k

उच्च शिक्षा पर 12वीं पंचवर्षीय योजना आवंटन, योजना और उच्च शिक्षा के प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पठन सामग्री और जेंडर बजट का महत्व।

शिक्षा का अधिकार–संकेतक प्रयोग के तहत स्कूल विकास पर पठन सामग्री का विकास।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्कूल वित्त की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए शिक्षा में लैंगिकीय बजट पर पठन सामग्री।

स्कूल शिक्षा में वित्तीय सुधार पर पठन सामग्री

स्कूल वित्त की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए शिक्षा में लैंगिक वित्त पर पठन सामग्री का विकास

l a ks'B h@l Ee sy u @d k; Zkky k e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय:

पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, नांनग्रीम हिल्स, शिलांग, मेघालय, में विद्यालय स्तर पर कार्य–निष्पादन में सुधार: नीति, योजना और कार्यान्वयन के मुद्दे पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्वोत्तर में निजी प्रारम्भिक विद्यालयों की वृद्धि और गुणवत्ता के सरोकार पर आलेख प्रस्तुति।

अंतर्राष्ट्रीय:

ओरेकल लैब (विभाग) यूनिवर्सिटी आफ री–यूनियन, सेंटडेविस (रीयूनियन–फ्रांस) महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं हिंसा पर आयोजित बहु–शास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय शिखर वार्ता में 'भारत में लैंगिक हिंसा–नये लैंगिक आतंकवाद के रूप में लड़कियों पर तेजाब हमला' पर आलेख प्रस्तुति। 13 नवम्बर, 2014

भारत में स्कूली शिक्षा स्तर पर कौशल विकास की नीतिगत चुनौतियां और भूमंडलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वाशिंगटन डीसी, 08–13 मार्च, 2015

'उच्च शिक्षा के वित्त पोषण की नवाचारी विधियों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचारी विधियां – वैश्विक रूझान पर आलेख प्रस्तुत, 23–25 मार्च 2015

l koZ fu d fu d k; ksa d ksi j ke ' kZ, o av d kn fe d l g k; r k

सीआईई, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध विद्यार्थियों को परामर्श।

सीआईई, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसआरएफ पी–एच. डी. से आरजीएनएफ में रूपांतरण साक्षात्कार आयोजित करने में बाहरी विशेषज्ञ

एम.फिल. शोध प्रबंध हेतु बाहरी परीक्षक, सीआईई, दिल्ली विश्वविद्यालय

समिति सदस्य, आईओएसी, यूनिवर्सिटी आफ ला रीयूनियन, ला द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, 05–06 नवम्बर, 2015।

एम.ए. शिक्षा की परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र निर्माता इग्नू।

इग्नू में एम.ए. शिक्षा का परीक्षक।

एमिटी विश्वविद्यालय के बी.एड. और एम.एड. छात्रों के लिए परीक्षक।

संपादकीय बोर्ड के सदस्य, होराइजन रिसर्च पब्लिशिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका।

U; wkd sckgj dhç[; kr fudk; ksad hl nL; rk

l nL;] efgykoy ZM dkax s

सदस्य, अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी

सदस्य, एडब्ल्यूआईडी

समिति के सदस्य, इंटरनेशनल सिम्पोजियम आन जेंडर, आईओएस आन जेंडर

i hxhr k jkuh

çdk'ku

पुस्तकें/अध्याय :

''चेंजिंग लैण्डस्केप आफ हायर एजुकेशन इन तमिल नाडु'', इन डवलपमेंट नेरेटिव्जः द पालिटिकल इकानमी आफ तमिलनाडु (एडीटर, वी.के. नटराज एंड ए. वैद्यनाथन), एकेडेमिक पब्लिकेशन, कोलकाता, 2014।

शोध पत्र/लेख/नोट्स :

''डिस्पार्टीज इन अर्निंग्स एंड एजुकेशन इन इंडिया'', ओएईएफ कोजेंट इकानमिक एंड फाइनेंस, टॉयलर एंड फ्रांसिस, 2014, 2:1, 941510।

''एजुकेशन लोन्स एंड फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडियाः एड्रेसिंग इक्विटी'', हायर एजुकेशन फार द फ्यूचर, सेज 2014, 1(2), पीपी 1–28।

''इक्विटी इन द डिस्ट्रिब्यूशन आफ इंडिया गर्वनमेंट सब्सिडीज ऑन एजुकेशन'', इंटरनेशनल जर्नल आफ एजुकेशन एंड इकानमिक डवलपमेंट, 2014, वॉल्यूम 5, पीपी. 1–39।

''एक्सप्लोरिंग अर्निंग एंड एजुकेशन डिस्पार्टीज एक्रॉस रीजन, कास्ट, रीलिजन एंड इंग्लिस लैंग्वेज एबिलिटी'', अर्थ विजनना, 2013, वॉल्यूम 55, नं. 4, पीपी. 402–420

''ए रिव्यू आफ फंडिंग एंड प्रोग्रेस आफ इलिमैंट्री एजुकेशन विद सर्व शिक्षा अभियान इन कर्नाटक'', मैन एंड डवलपमेंट, 2013, वॉल्यूम 35(2), पीपी. 99–120।

फंड फ्लो पैटर्न एंड फाइनेंसियल एफिसिएंसी आफ रिर्शोस यूटिलाइजेशन अन्डर सर्व शिक्षा अभियान इन गुजरात अर्थशास्त्र, इंडियन जर्नल आफ इकानमिक्स एंड रिसर्च, 2013, वॉल्यूम 2, पीपी. 12–23।

vuqlaèkku vè; ; u

पूर्ण :

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना से जारी रखने के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत)।

जारी :

शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन, लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल का एक विश्लेषण

l aks'Bh@l Eesyu@dk; Zkky kv ksaesaHkkx hnkjh

राष्ट्रीय :

शैक्षिक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने हेतु लिंग इक्विटी लेंस, मूल्यांकन पर कार्यशाला में, 'भारत में शिक्षा ऋण के मूल्यांकन' शीर्षक से अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किया न्यूपा, नई दिल्ली, मई 27,2014।

आईएचसी, नई दिल्ली में एनसीएईआर द्वारा आयोजित भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) उपयोगकर्ताओं के सम्मेलन में, 'भारत में क्षेत्र, जाति, धर्म और अंग्रेजी भाषा की क्षमता पर आय और शिक्षा असमानताओं की तलाश', शीर्षक से एक आलेख प्रस्तुत किया, 18–19 जुलाई, 2014

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, अर्थशास्त्र विभाग और आर्थिक परिवर्तन शोध केंद्र द्वारा आयोजित भारतीय अर्थमितीय सोसाइटी के 51वें वार्षिक सम्मेलन में, भाग

लिया और शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत भारत में छात्र ऋण के लिए मांग पैटर्न और निर्धारक, 12–14 दिसम्बर, 2014।

v U; 'kS{kd v kS O; kol kf; d ; kx n ku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकन:

आईडेपा प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन का मूल्यांकन किया।

पाठ्यक्रम समन्वय:

संयोजक (संयुक्त रूप से) शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन, डेपा के लिए 10 सत्र एकल क्रेडिट कोर्स और शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण और वित्तीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए।

शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय योजना और प्रबंधन पर दो क्रेडिट पाठ्यक्रम का संयोजक – आईडेपा के 20 सत्रों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण और वित्तीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान।

oS'V d g]h i h-, l - jkt w

çd k'ku

पुस्तकें/अध्याय:

चैप्टर आन ''एथिक्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशनः प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज'', इन बुक. ए डिस्कोर्स आन वैल्यू एजुकेशन (एडीटर अजीत मंडल एंड जयन्त मेटे) दिल्लीः कुनाल बुक्स (इन प्रैस)

रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट्स आन एजुकेशनल डवलपमेंट इन नार्थ इस्टर्न स्टेट आफ इंडिया (मोनोग्राफ बेस्ड आन डेपा डिजरटेशन)

रिसर्च अब्स्ट्रैक्ट्स आन एजुकेशनल फाइनेंस (मोनोग्राफ बेस्ड आन डेपा डिजरटेशन)

शोध पत्र/लेख/नोट्स:

टीचर मेंनेजमेंट इश्यूज एट एलीमेंट्री एजुकेशन इन सिक्किम. इन्टरनेशनल जर्नल ग्यान भव, जर्नल आफ टीचर एजूकेशन, 1(1) (2014 फरवरी): पीपी. 27–35

v uql 'akku v è; ; u

पूर्ण:

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना की केन्द्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना, भारत सरकार। भारत सरकार)

'राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना' की केन्द्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना, भारत सरकार)।

जारी:

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के – गैर नामांकन के कारण और ड्रॉप–आउटः एक तुलनात्मक अध्ययन

'जम्मू–कश्मीर के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना' का मध्यावधि मूल्यांकन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना, भारत सरकार)।

'कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन' (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना, भारत सरकार)।

l a kS'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky kv ka e sa Hkkx hn kjh

राष्ट्रीय:

पूर्वोत्तर परिषद और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी शिलांग, मेघालय, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मणिपुर के विशेष संदर्भ में उत्तर–पूर्व में माध्यमिक स्तर पर मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता पर एनएमएमएस योजना के कार्यान्वयन पर आलेख (एनईसी), शिलांग, मेघालय, 15–16 अक्टूबर, 2014

न्यूपा द्वारा आयोजित 'शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में भाग लिया, 28–29 नवम्बर, 2014।

न्यूपा द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया, न्यूपा, 9 जनवरी, 2015

असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्याह्न भोजन योजना में 'स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और सामुदायिक भागीदारी विषय पर प्रस्तुत 'जन भागीदारी और विकेंद्रीकृत शैक्षिक शासन– नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण' पर नीति संगोष्ठी, न्यूपा, नई दिल्ली 16–17 फरवरी, 2015।

लिंगाया ललिता देवी संस्थान द्वारा आयोजित प्रबंधन और विज्ञान मानवाधिकार जागरूकता बाल अधिकार पर फोकस, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, द्वारा प्रायोजित 7 फरवरी, 2015

अंतर्राष्ट्रीय:

संयुक्त रूप से, न्यूपा उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा, वृहद शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया 10–11 नवम्बर, 2014।

संयुक्त रूप से प्रस्तुति भारतीय तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी, गार्गी कॉलेज, गृह अर्थशास्त्र संस्थान और आरआरसीईई द्वारा आयोजित शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन पर 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आलेख प्रस्तुति, दिल्ली विश्वविद्यालय, 16–18 नवम्बर, 2014।

न्यूपा में संयुक्त रूप से एनसीएसएल–न्यूपा, नई दिल्ली और एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच में भाग लिया 12–13 फरवरी, 2015

59वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पत्र प्रस्तुत किया, तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सोसाइटी, हिल्टन वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, द्वारा आयोजित विश्व स्तर पर एक मानवतावादी शिक्षा की परिकल्पना– उबन्तू 08–13 मार्च, 2015

नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियां, उपेक्षित समूहों की शिक्षा पर एंट्रिप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया नई दिल्ली, आईआईईपी/यूनेस्को, पेरिस और न्यूपा द्वारा आयोजित, 25–27 मार्च, 2015।

dk;Zkkykvksa@lEesyuksa@çf'k{k.k dk;Øeksa dk vk;kstu

डीईओ और बीईओ के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर, भुवनेश्वर, ओडिशा में राज्य स्तरीय सम्मेलन (प्रो. प्रणति पांडा के साथ) 08–09 मई, 2014

न्यूपा, नई दिल्ली में 'स्कूल में वित्त की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम, 01–05 सितम्बर, 2014।

उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (प्रो वाई जोसफिन के साथ), न्यूपा, नई दिल्ली, 23–25 फरवरी, 2015

नई दिल्ली में आईआईईपी/यूनेस्को, पेरिस और न्यूपा द्वारा एंट्रिप क्षेत्रीय कार्यशाला उपेक्षित समूहों की शिक्षा नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियां (प्रो के. सुजाता के साथ) 25–27 मार्च, 2015

न्यूपा द्वारा आईएचसी में आयोजित 'स्कूल के मानकों और स्कूल सुधार के लिए मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परामर्शी बैठक' (प्रो. प्रणति पांडा के साथ), नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2014

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe dk fodkl vkSj f'k{k.k

स्कूल वित्त की योजना और प्रबंधन में ओरिएंटेशन कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन।

उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रूपरेखा और आयोजन में योगदान (प्रो. वाई. जोसफिन के साथ)।

स्कूल संसाधन प्रबंधन विषय पर शैक्षिक प्रशासन, न्यूपा विभाग द्वारा आयोजित सत्र।

एम.फिल./पी–एच.डी. पाठ्यचर्या (वैकल्पिक और कोर पाठ्यक्रम की संख्या) विकास समिति के सदस्य।

रूपरेखा और पाठ्यक्रम 213: शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में कंप्यूटर अनुप्रयोग आईडेपा कार्यक्रम का निरूपण और शिक्षण, न्यूपा, नई दिल्ली

डेपा और आईडेपा कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों और न्यूपा के अन्य कार्यक्रमों में शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन पर अनेक सत्रों में शिक्षण।

v U; 'kS{kd v kS Q; kol kf; d ; kxnku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकन:

श्री दीपेंद्र कुमार पाठक, न्यूपा की एम फिल शोध प्रबंध का मूल्यांकन

डेपा भागीदार का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा

डेपा प्रतिभागी के परियोजना शोध प्रबंध का मार्गदर्शन

v kbZMsi k çfrHkkxh d s i fj; kstuk 'kksèk çcaèk d k ekxZn'kZu

अन्य गतिविधियां:

सदस्य, एम.फिल./पी–एच.डी. की प्रवेश परीक्षा आयोजन समिति।

एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए निरीक्षक

सदस्य, न्यूपा की सभी खरीद के लिए निविदा खोलने वाली समिति

संकाय विकास (स्टाफ रिट्रीट) के लिए विभिन्न समितियों के सदस्य

न्यूपा संकाय विकास कार्यक्रम (स्टाफ रिट्रीट) में भाग लिया, 16–17 जनवरी, 2015

l koZ fud fud k; ksa d ks i jke'kZ v kS 'kS{kd l gk; r k

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दो केंद्र प्रायोजित योजना मूल्यांकन अध्ययन का संचालन।

पी.ए.बी. (2014–15) आरएमएसए डेस्क मूल्यांकन और बैठक (आंध्र प्रदेश), 1 मई, 2014

पीएबी (2014–15) आरएमएसए परियोजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एनआईओएस बैठक

जेएनयू के विद्यार्थी के एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन

U; wk d s cksgj ç[; kr fud k; ksa d h l nL; r k

राष्ट्रीय:

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय:

सदस्य, तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, संयुक्त राज्य अमरीका

पूर्व छात्र सदस्य, अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (आईआईईपी/यूनेस्को), पेरिस

शिक्षा नीति विभाग

v fouk'k d qekj fl g ¼fo Hkkx kè; {k½

ç d k' ku

पुस्तकें/अध्याय:

पुस्तक (एडीटेड वाल्यूम) 'एजुकेशन एंड इम्पावरमेंट इन इंडिया – पालिसीज एंड प्रैक्टिसेज'. रूटलेज इंडिया, टायलर एंड फ्रांसिस, नई दिल्ली (फोर्थकमिंग)

'द कमिंग क्राइसिस आफ सोशल साइंस एजुकेशन इन इंडिया', इन जी.जी. वॉनखेडे (एडीटर) मार्जिनालाइज्ड इन द इंडिया, हायर एजुकेशनः इन सर्च चह एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, सेज पब्लिकेशन लि.: नई दिल्ली (फोर्थकमिंग)

पुस्तक/लेख समीक्षाएँ:

रिव्यू आफ बुक सोशियोलॉजी आफ एजुकेशन इन इंडियाः चेंजिंग कन्टूर्स एंड इमरजिंग कर्न्सन' 2014 (गीता नामबिसन एंड एस. श्रीनिवास राव, एड.), सोशियोलॉजिकल बुलेटिन (जनवरी–अप्रैल), 63(1):153–55.

रिव्यू आफ बुक 'पीपीपी पाराडॉक्सेज : प्रॉमिजेज एंड पेरिल आफ पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन', 2013 (परीथा गोपालन), सोशियोलॉजिकल बुलेटिन (जनवरी–अप्रैल 2015), 64(1):122–23.

l a ks'Bh@l Ee sy u @d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय:

नेहू, शिलांग में 'योजना और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन' पर अभिविन्यास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व पर संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य, 16–20 जून, 2014

जेआईआईटी, नोएडा, में कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान पर उन्मुखीकरण कार्यशाला में शिक्षा और सामाजिक भाषा विज्ञान पर संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य, 15–16 नवम्बर, 2014

शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दों पर दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में राजनीति और सामाजिक परिवर्तन पर सीईएसआई सम्मेलन में सत्र की अध्यक्षता की, 16–18 दिसम्बर, 2014

वर्तमान स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्य प्रदेश) में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार, 13–14 दिसम्बर, 2014

वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थानों में गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने पर गोलमेज सम्मेलन में कौशल और ग्रामीण आजीविका पर प्रस्तुति, गांधीग्राम (तमिलनाडु), 23 जनवरी 2013

दीमापुर (नागालैंड) में, 02–6 फरवरी, 2015 को पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकारी और स्वायत्त परिषद के कामकाज पर उन्मुखीकरण कार्यशाला में स्थानीय प्राधिकरण और प्राथमिक शिक्षा पर संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य।

अभ्यास शिक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षणः प्रवृत्तियां और मुद्दे, पर आलेख प्रस्तुत किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज सेंटर, किशनगंज (बिहार), 26–27 फरवरी, 2015

अनुसंधान शिक्षा में क्रियाविधि, एससीईआरटी, पटना, पर उन्मुखीकरण कार्यशाला मेंь गुणात्मक अनुसंधान के तरीके और तकनीक पर पर संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य 11–13 मार्च, 2015

बाहर व्याख्यान:

स्वामी विवेकानंद, की जन्म वर्षगांठ पर शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर व्याख्यान, जेएनयू, नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

ç f' k{k.k k d k; Øe @l Ee sy u @d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

संगठित, परामर्शदात्री बैठक, आरटीई के तहत नीति प्रक्रिया न्यूपा, नई दिल्ली, 24–25 नवम्बर, 2014

द्वितीय अनिल बोर्डिया स्मारक नीति, संगोष्ठी, जन भागीदारी और विकेंद्रीत शैक्षिक अभिशासन : नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण का आयोजन न्यूपा, नई दिल्ली, 16–17 फरवरी, 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Zkkyk,a dk vk;kstu

आरटीई के तहत नीति प्रक्रिया पर परामर्शदात्री बैठक न्यूपा, नई दिल्ली, 24–25 नवम्बर, 2014।

जन भागीदारी विकेंद्रीकृत शैक्षिक अभिशासन : नीतिगत सुधार और कार्य व्यवहार पर द्वितीय अनिल बोर्डिया नीति स्मारक संगोष्ठी, न्यूपा, नई दिल्ली, 16–17 फरवरी, 2015

vU; 'kS{kd vkS Oko'kkf;d ;ksxnku

पर्यवेक्षण / मूल्यांकन:

श्री अजय कुमार चौबे, पी–एच.डी. विद्यार्थी (अंशकालिक), मार्गदर्शन शोध प्रबंध, स्कूल में बहिष्करण और समुदाय की गतिशीलता, न्यूपा।

सुश्री लाबोजी दास, पी–एच.डी. मार्गदर्शन विद्यार्थी (अंशकालिक), के शोध प्रबंध : वंचित समूहों की भागीदारी के संदर्भ में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और स्थानीय प्रशासन का मार्गदर्शन।

श्री सज्जाद अहमद, पी–एच.डी. शोधार्थी के शोध प्रबंध : शिक्षा, संस्कृति और आजीविका : जम्मू एवं कश्मीर में खानाबदोश बकरवालों का एक मार्गदर्शन।

डेपा प्रतिभागी, सुश्री सुषमा भट्ट को परियोजना प्रबंध : मध्य प्रदेश में मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार के अनुच्छेद 29 के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन।

कोर्स समन्वय:

एम.फिल. / पी–एच.डी. के पाठ्यक्रम गाइड (मुख्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम) के संशोधन का समन्वयन।

lkoZtfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkS 'kS{kd lgk;rk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित असम में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन, की संयुक्त समीक्षा मिशन के भारत सरकार के सदस्य के रूप में सदस्य 21–31 मार्च, 2015

ohjk xdqrk

çdk'ku

शोध पत्र / लेख / टिप्पणी:

पॉलिसी ऑन क्लासरूम अकॉसटिस इन इंडिया डीईटी–एफओइआरए (ए रिसर्च जर्नल इन एजुकेशन वार्षिक अंक 8, 31 जनवरी, 2015, आईएसएसएन नं. 0974–7966; दयाल बाग डीम्ड यूनिवर्सिटी।

द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज फार इन्क्लूजन आफ चिल्र्डन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी (स्पे. डी) इन इंडिया, बीईएसटी जर्नल, नवम्बर 2014 (वॉल्यूम. 2, इश्यू 11). बीईएसटी: आईएसएसएन (ऑनलाइन) 2348–0513।

प्रोफेशनल डवलपमेंट आफ टीचर एजुकेशन, जामिया जर्नल आफ एजूकेशन, नवम्बर 2014 आईएसएसएन 2348–3490।

''पालिसी विज़न एंड पालिसी इंप्लेमेंटेशन फार द गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स इन इंडिया'', रीजनल सेमीनार प्रोसीडिंग (अक्टूबर 2014), मैसूर: रीजनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, एनसीईआरटी।

laxksf"B;ksa@lEesyuksa@dk;Zkkykvksa esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय:

शिक्षा समाधान पर, नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2015 को आयोजित शिक्षा शिखर सम्मेलन में वक्ता।

समुदाय भागीदारी के माध्यम से शिक्षा में बदलाव पर आयोजित संगोष्ठी, न्यूपा, प्रज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए स्टैनफोर्ड सेंटर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, 22 जुलाई, 2014

स्कूल मानक पर कार्यशाला, न्यूपा, 25 जुलाई, 2014

स्कूल आधारित परामर्श और विशेष सेवाओं की जरूरत, राष्ट्रीय प्रगतिशील स्कूल सम्मेलन, सीबीएसई और एक्सप्रेसन इंडिया, 2 अगस्त 2014

प्रतिनिधि सीआईआई, एनएसडीए और हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ शिक्षा पर शिक्षा शिखर सम्मेलन, चंडीगढ़, 1 सितम्बर, 2014

बाल अधिकार, संरक्षण के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद पर नेशनल कन्वेंशन में समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक डेटा संग्रह और आंकलन के मुद्दे, 2014 सत्र में भाग लिया, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2014।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर में स्कूल मार्ग दर्शन कार्यक्रम में मौजूदा कार्य व्यवहार पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भारत में स्कूल मार्गदर्शन और परामर्श के लिए नीति और विजन का कार्यान्वयन पर आलेख प्रस्तुति, 9–10 अक्टूबर 2014

समेकन और विभाजन : लोकतंत्र और असमानताएं, पर मौलाना आजाद मेमोरियल व्याख्यान न्यूपा, 11 नवंबर, 2014

अगली पीढ़ी की शिक्षा प्रौद्योगिकी के आचरण पर एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया लर्निंग लिंक फाउंडेशन, नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2014 को आयोजित।

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर सम्मेलन और पुरस्कार प्रस्तुति, न्यूपा, 28–29 नवम्बर, 2014

एक खंडित विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की विकास दरः अवसर और चुनौतियां भरत राम मेमोरियल संगोष्ठी डॉ रघुराम राजन के साथ, सीआईआई, 12 दिसम्बर 2014

सेंटर फार सिविल सोसायटी और टीच फार इंडिया द्वारा शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार सुधार पैनल पर सम्मेलन के एक सत्र में वक्ता, 20 दिसंबर, 2014

स्कूल मानक पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक में भाग लिया न्यूपा, 10–11 फरवरी, 2015

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यक्रम पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता, शिक्षा कालेज चंडीगढ़ 21 फरवरी, 2015

अंतर्राष्ट्रीयः

शिक्षा एक झलक 2014 ओईसीडी संकेतक पर सेमीनार (मेजबानः एरिक मगुंसन, इवेन्ट संख्याः 951 865 836), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 10 सितंबर, 2014

विकलांगता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी फ्रीबर्ग (जर्मनी), डीडीएआई अमरीका, 25–29 अक्टूबर, 2014

वृहद शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में जन भागीदारी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, उच्च शिक्षा, नीति और शोध केंद्र, न्यूपा, 10–11 नवम्बर, 2014

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

सीडब्ल्यूएसएन के संबंध में स्कूल समावेशी बनाने पर कार्यशाला आयोजित 30 जून से 4 जुलाई, 2014

शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक नीति बनाने पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन, 17–22 नवम्बर, 2014

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe dk fodkl vkSj f'k{k.k

एम.फिल./पी–एच.डी. पाठ्यक्रम गाइड (मुख्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम) के संशोधन का समन्वय

बाहर के– स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के लिए मापदंड का विकास किया एनसीईआरटी कार्यशाला, 17–18 सितम्बर, 2014।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku i;Z{k.k@eY;kadu

मिड डे मील की नीति पर सुश्री संगीता डे की पीएचडी थीसिस का मार्गदर्शन

सुश्री के. चोंगथम की पीजीडेपा शोध परियोजना मणिपुर में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन का पर्यवेक्षण।

30वें आईडेपा कार्यक्रम में श्री राशिद बिन जमालुद्दीन द्वारा शोध प्रबंध चुने मलेशियाई स्कूलों में स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली की दिशा में अंग्रेजी शिक्षक उत्तम आचरण की एक जांच पर का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा के विशेष शिक्षा शोध पर सुश्री अर्चना वशिष्ठ की पीजीडीएसएलएम परियोजना के कार्य का पर्यवेक्षण।

31वें आईडेपा की श्रीमती वाई.वाई. थीन के परियोजना शोध प्रबंध : शिक्षा कॉलेज (मैंगवे शिक्षा कॉलेज, म्यांमार) में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में योग्य शिक्षकों का प्रभाव का पर्यवेक्षण

अन्य गतिविधियां:

लोकसभा के चैनल, 'इनसाइट' कार्यक्रम में शिक्षा नीति पर पैनल चर्चा में भाग लिया 5 दिसंबर, 2014

l koZ fud fud k; ksa dks i jke'kZ vk$ 'kS{kd l gk; rk

इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल एजुकेशन (आईएसएसएन 0972–5830), की आलेख समीक्षा पीएसएससीआईवीई, एनसीईआरटी, 14 अप्रैल, 2014।

रायत बहरा जर्नल आफ एजुकेशन, रायत और बहरा शिक्षा कालेज, सहौरन तहसील खरड़, जिला मोहाली (पंजाब) के लिए आलेख समीक्षा, 22 अप्रैल 2014

सदस्य, स्वायत्त स्थिति, प्रदान करने के लिए महाराजा कॉलेज के प्रदर्शन और शैक्षणिक योग्यता के आकलन के लिए वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति, 28 और 29 अप्रैल, 2014।

पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स और साइंस, कोयंबटूर, की यूजीसी–गठित शासी निकाय की बैठक में भाग लिया 2 मई, 2014।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य, सिम्बोसीस दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, पुणे, 24–25 जून, 2014।

सदस्य, एनसीईआरटी के कार्य और शिक्षा पर विशेषज्ञ पैनल, 26–27 जून, 2014

डॉ रेणुका सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर को यूजीसी पुराने नियमों की अनुसार प्रोफेसर बनाने के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति, यूजीसी ऑब्जर्वर, 13 अक्टूबर 2014

एड्स की महामारी को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के कार्यवाई योजना के कदम और रणनीति का सुझाव देने के लिए गठित समिति के सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 11 नवंबर, 2014

शिक्षा के अधिकार अधिनियम नजरिए से उत्तरी क्षेत्र (उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात) के महत्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों/मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता आकलन कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति, सीडब्ल्यूएसएन, एनसीईआरटी, 27 नवंबर, 2014

शिक्षक–मेंटर का प्रशिक्षण – लिंक फाउंडेशन, 6 दिसंबर, 2014

दूरस्थ शिक्षा, सिम्बायोसिस सैंटर फॉर आईटी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एससीडीएस), पुणे, की एसएलएम के मूल्यांकन के लिए यूजीसी की बैठक में भाग लिया विशेषज्ञ समिति 12 दिसंबर, 2014

शिक्षा के अधिकार अधिनियम नजरिए से उत्तरी क्षेत्र (उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात) के महत्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों/मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता आकलन कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति, सीडब्ल्यूएसएन, एनसीईआरटी, 16–18 दिसंबर, 2014

एनसीईआरटी, नई दिल्ली में 23 दिसम्बर 2014 को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत वी एस और एच एस ई के सीएसएस के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक में भाग लिया।

पीएसएससीआईवीई एनसीईआरटी के इंडियन जर्नल आफ वोकेशनल एजुकेशन के लिए लेख समीक्षा, 15 जनवरी, 2015।

27–28 जनवरी, 2015 के लिए एकल बालिका, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी फैलोशिप के पुरस्कार के चयन के लिए वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षक, 29 जनवरी से 6 फरवरी 2015।

परीक्षक के लिए संघ लोक सेवा आयोग, 12–19 फरवरी, 2015 की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा।

मिड डे मील पर पीएबी की बैठक में भाग लिया – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 13 फरवरी, 2015

बी.एड. कार्यक्रम, इग्नू की समावेशी शिक्षा पर निश्चित रूप से डिजाइन तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया 17–18 मार्च, 2015।

आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित

करने के लिए व्यावसायिक सहायता , असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

U; ivk d s c kgj ç[; kr fu d k; ksa d h l nL; r k

सदस्य, प्रबंधन बोर्ड, के.जे. सोमैया कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय

सदस्य, शासी निकाय, पीजी कॉलेज, तमिलनाडु

e u h'kk fi z e

प्रकाशन

पुस्तकें/अध्याय :

बुक कन्टेस्टेड पालिटिक्स आफ एजुकेशनल रिर्फोम्स इन इंडियाः अलाइनिंग अपरचुनिटीज विद इन्ट्रेस्ट. आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2015

''फ्रॉम क्लाइन्टस टू सिटीजनः लर्निंग फ्राम ब्राजील बोलसा फैमिलिया प्रोवाइड्स अपच्युनिटीज टू दिल्ली'', इन एन जयराम (एड.) सोशल डायनामिक्स आफ द अर्बन. स्प्रिंगर (फोर्थकमिंग)

''पॉलिसी रिफार्म एंड एजुकेशनल डवलपमेंट इन ए फेडरल कॉन्टेस्क्टः रिफ्लेक्शन आन द यूनेवेन प्रोसेस आफ चेंज इन बिहार'' इन ए.के. सिंह (एडी.).... रूटलेज (फोर्थकमिंग)

' kks/k i = @ y § k@ fVIi f. k; ka

'नई आर्थिक दिशा में देश'। दैनिक जागरण (हिन्दी न्यूजपेपर), 11 जुलाई 2014।

''विकल्प बनती दोस्ती'। अमर उजाला (हिन्दी न्यूजपेपर), 26 अगस्त 2014।

दैनिक जागरण (हिन्दी न्यूजपेपर), 27 अगस्त 2014)

अनालाजिंग द टेक्टोनिक शिफ्ट, मिन्ट (इंग्लिस न्यूजपेपर) 20 अक्टूबर, 2014। http://www.livemint.com/Opinion/Vbj11AtqJrGF0qWPABcqOL/Analysing-the-tectonic-shift.html.

'काबिलियत और निष्ठा को तरजीह'। अमर उजाला (हिन्दी न्यूजपेपर), 10 नवंबर 2014

'पाइप ड्रीम्स', सेमीनार, 663, नवंबर 2014

'द प्रॉब्लम', संगोष्ठी, 663, नवंबर 2014

'द युनिवर्सिटी एज एन आइडिया एंड एज ए प्रैक्टिसः रिफ्लेक्शन ऑन द क्वेस्ट फार ऑटोनॉमी इन इंडिया'', युनिवर्सिटी न्यूज, वॉल्यूम 53, नंबर 3 (19–25 जनवरी): 217–220

''इलेक्टिंग द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशनः वोटर डेलिब्रेसन फ्रॉम संगम विहार, दिल्ली, लोकसभा इलैक्शन 2014'', स्टडीज इन इंडिया पालिटिक्स, सेज, जुलाई (फोर्थकमिंग)।

i qLr d @ y § k l eh{kk, ;

जंध्याला बी.जी. तिलक (एडीटर) (2013) हायर एजुकेशन इन इंडियाः इन सर्च फार इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, रिव्यूड इन जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम XXVIII, नं. 2 (अप्रैल): पीपी. 193–96।

सुधा पई (एडीटर) (2013): हैण्डबुक आफ पालिटिक्स इन इंडिया स्टेट्सः रीजन्स, पार्टीज एंड इकोनमी रिर्फोम्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वाल्यूम 656 (अप्रैल) 73–76।

v u q la/kku v è; ; u

पूर्ण :

'बाधाओं के बावजूदरू दंतेवाड़ा में शैक्षिक पहल का केस अध्ययन' प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार (संजीव चोपड़ा और ओपी चौधरी के साथ) (Available at http://darpg.gov.in/darpgwebsite_cms/document/file/DANTEWADA_case.pdf).

l a k'Bh@ l Ee s y u@ d k; Z'kky kv ksa e sa Hkkx hn kjh

राष्ट्रीयः

उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, न्यूपा, 'शिक्षण और अधिगम, क्षमता विकास और प्रशिक्षण पर पटना में न्यूपा कार्यशाला (पोस्ट ग्रेजुएट प्रमुखों और डीन), में न्याय और विश्वविद्यालय के विचारः रोंल्स और सेन के सहसंबद्धता शीर्षक पत्र प्रस्तुत 08–10 दिसम्बर, 2014

सेंटर फार सिविल सोसायटी, नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा में स्वतंत्रता पर सरकार का परिप्रेक्ष्य, स्कूल चुनाव पर शीर्षक पत्र प्रस्तुत।

न्यूपा, नई दिल्ली में जन भागीदारी और विकेंद्रीकृत शैक्षिक अभिशासनः नीति सुधार और कार्यक्रम संप्रेक्ष्य पर आयोजित संगोष्ठी में मजबूत लोकतंत्र या संप्रभु वर्ग का नियंत्रणः शैक्षिक विकेंद्रीकरण पर सांस्थानिक डिजायन का प्रभाव पर आलेख प्रस्तुत किया, 16 फरवरी, 2015.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पटना में 11–12 मार्च, 2015 को गुणात्मक अनुसंधान के तरीके पर कार्यशाला, में बिहार में स्कूल विश्लेषण करने की स्थिति में गुणात्मक अनुसंधान के तरीके के उपयोग शीर्षक पर आलेख प्रस्तुत ।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में 20 मार्च, 2015 को आायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी शीर्षक पर आलेख प्रस्तुत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और शहरी गरीबों की शिक्षा विषय पर आयोजित सत्र में 'दिल्ली में शहरी उपेक्षित और स्कूल शिक्षा पर आलेख प्रस्तुति

अंतर्राष्ट्रीय :

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में योरोपीय सामाजिक शोध परिषद नेटवर्क अनुदान के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय भारत में बदलते निर्वाचन का स्पष्टीकरण पर आयोजित कार्यशाला में सत्ता दल और विपक्षी दल का निर्वाचन : नगरीय क्षेत्र के नागरिक जनमत पर आलेख प्रस्तुति, 19 अगस्त 2014

ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में 15–16 सितम्बर, 2014 को सामाजिक नीति और राजनीति सम्मेलन में 'एक भारतीय शहरी राज्य में सामाजिक नीतिः संघीय संस्थाओं, प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद, और उपेक्षित आमजन' पर आलेख प्रस्तुत।

योरोपीय सामाजिक शोध परिषद और जे.एन.यू., नई दिल्ली में निर्वाचन अध्ययन : नगरीय और ग्रामीण भारत में निर्वाचन विधियों का प्रतिबिंब और निर्वाचन में बदलाव की व्याख्या पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में 'भारत में निर्वाचन के स्वरूप को समझने में नृवंशविज्ञान के उपयोग पर आलेख प्रस्तुत, 9 जनवरी 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk,a laxfBr

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में फेलो के रूप में, भारतीय भाषाओं के राजनीतिक चिंतन : शोध विमर्श और बहस पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, 7–8 अगस्त, 2014

vU; 'kS{kd vkS O;kolkf;d ;ksxnku

शिक्षण :

एम.फिल. कार्यक्रम : सीसी4: शैक्षिक नीति

डिप्लोमा कार्यक्रमः स्कूल लीडरशिप–यूनिट 4 रूपांतरण की समझ।

अन्य गतिविधियां :

अल्फ्रेड हरहौरा सोसायटी, इंटरनेशनल फोरम आफ ड्यूश बैंक और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 10 जुलाई, 2014 को 'शहरों में जमीनी स्तर पर पहल की खोज पर पैनल चर्चा में प्रस्तुति

'भारतीय शहरों में नागरिकों की भागीदारी : वास्तविकता की जांच पर आयोजितः भारतीय शहरों में नागरिकों की भागीदारीः दिल्ली से विगनेट्स, पटना के बारे में चिंतन जनग्राहा पर आलेख प्रस्तुति ब्राउन, भारत पहल, बंगलौर नागरिकता सूचकांक पर पैनल चर्चा 16 दिसंबर 2014

'उच्च शिक्षा की नीति और शासन परिप्रेक्ष्यः नीति की रूपरेखा और संस्थागत संदर्भ' विषय पर पैनल चर्चा में विश्वविद्यालयों में विविधता और इक्विटी के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम में, समान, पहुँच और समतापूर्ण भागीदारी पर प्रस्तुति, न्यूपा, नई दिल्ली, 17 मार्च 2015

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षिक सहायता

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, में भा. प्र. से. के 2012 बैच के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय चरण) बाधाओं के विरूद्ध : दंतेवाड़ा में शैक्षिक पहल पर प्रस्तुति, 20 अगस्त, 2014

राजनीति विज्ञान के 42वें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, भारत में शिक्षा में सुधार की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति पर प्रस्तुति अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जेएनयू, 13 मार्च 2015

, l -d s efy d

çd k'ku

शोध पत्र/लेख/नोट्सः

'रोल आफ ईएफए एंड एमडीजी' 'ब्लॉक 3: इश्यू इन अल्टरनेटिव एजुकेशन', एमईएस 048, मॉड्यूल, इगनऊ, नई दिल्ली

l aks'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hnkjh

राष्ट्रीयः

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन में रिपोर्टकर्त्ता के रूप में भाग लिया , विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 28–29 नवम्बर, 2014

स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में भाग लिया (आई.एच.सी. सेंटर, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2015

लोगों की भागीदारी और विकेंद्रीकरण शासनः नीति, सुधार और कार्यक्रम आचरणः पर द्वितीय अनिल बोर्डिया स्मारक नीति संगोष्ठी में भाग लिया , नई दिल्ली, 16–17 फरवरी, 2015

अंतर्राष्ट्रीयः

संयुक्त रूप से न्यूपा की उच्च शिक्षा में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और ब्रिटिश काउंसिल, वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भाग लिया, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014

हाशिए पर समूह की शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्यशाला – नीतियां कार्यक्रम और चुनौतियां पर भाग लिया नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015

çf'k{k.k d k; Øe@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

न्यूपा, नई दिल्ली में आरटीई अधिनियम के तहत वंचित बच्चों की शिक्षा पर संगठित उन्मुखीकरण कार्यशाला 25–29 अगस्त, 2014

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकारी और स्वायत्त परिषद के कामकाज पर संगठित उन्मुखीकरण कार्यशाला (होटल अकासिया, दीमापुरः 2015, 02–06 फरवरी)

çf'k{k.k k l ke xh v k$ i kBî Øe fod fl r v k$ fu 'i fkn r

परियोजना कार्य के लिए ग्रंथ सूची/संदर्भ तैयार करने के लिए?

v U; 'kS{kd v k$ O; kol kf; d ; ksxnku i ; Z{k.k@ e W; kdu %

उजबेकिस्तान में शिक्षा प्रणाली के सुधार में नागरिक समाज संस्थाओं की भूमिका विषय पर प्रतिभागी को मार्गदर्शन

सामुदायिक भागीदारी पर निर्देशित विषय भागीदार – असम के धेमाजी जिले के अंतर्गत मुरकोंगसेलेक ब्लॉक में एक केस स्टडी प्राथमिक विद्यालयों के कामकाज में एसएमसी की भूमिका के संदर्भ के साथ

शिक्षणः

एम.फिल./पी–एच.डी. में अध्यापन वैकल्पिक कोर्स (शिक्षा में स्थानीय प्रशासन और समुदाय की भागीदारी)

अन्य गतिविधियांः

संकाय विकास कार्यक्रम में भाग लिया, 16–17 जनवरी, 2015।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान समूह के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. के सदस्य, कोर्स

एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए संवीक्षा समिति के सदस्य प्रवेश

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के जर्नल के संपादकीय समर्थन (न्यूपा जर्नल)

u j ś k d q kj

ç d k' ku

शोध पत्र/लेख/नोट्स :

'बियोन्ड युनिवरसलाइजेशन आफ सेकेण्डरी एजुकेशनः इश्यू, कर्न्सन एंड चैलेंजेज', मैन एंड डवलपमेंट, XXXVI (4):21-30.

'सोशल कन्स्ट्रक्सन आफ एजुकेशनल वैल्यूज : ए केस आफ झीर यूथ इन जम्मू सिटी', सोशल एक्शन ए क्वार्टरली रिव्यू आफ सोशल ट्रेंड्स, 64(2): 192–205 (ISSN 0037-7627)।

'बियोन्ड युनिवरसलाइजेशन आफ सेकेण्डरी एजुकेशनः इश्यू, कर्न्सन एंड चैलेंजेज', (अब्स्ट्रैक्ट इन डवलपमेंट, डायवरसिटी एंड डेमोक्रेसी' पीपी. 135)। समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (29 नवम्बर – 1 दिसम्बर, 2014 से आयोजित)।

पुस्तक/लेख समीक्षाएँ

रिव्यू आफ बुक 'लो फी प्राइवेट स्कूलिंगः एग्रेवेटिंग इक्विटी चज मिटिगेटिंग डिस्ऐडवेंटेज' (प्राची श्रीवास्तव द्वारा) जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (2014) XXVIII (2): 191.203।

रिव्यू आफ बुक 'टेकिंग साईडः रिर्जवेसन कोटाज एंड मिनोरिटी राईट्स इन इंडिया' (रुडोल्फ सी हेरेडिया द्वारा) सोशियोलॉजिकल बुलेटिन (मई 20 अगस्त 14) 63(2): 323–25

l a ks'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय :

"माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के परेः मुद्दे, चिंताओं और चुनौतियों" शीर्षक पर आलेख प्रस्तुत, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, द्वारा आयोजित 40वीं अखिल भारतीय समाजशास्त्र सम्मेलन में 29 नवंबर – 01 दिसंबर, 2014 तक।

çf'k{k.k d k; Øe@l Ee sy u@d k; Zkky kv ksad k v k; ks u

प्रो. हेंज मेयर, के साथ प्रस्तुति, उद्यमिता स्वायत्तता और विघटनकारी अभिनवः उच्च शिक्षा के शासन में प्रमुख रुझान पर विचार मंच का आयोजन किया, 20 मई, 2014

शिक्षा में मूल्यांकन अध्ययन न्यूपा, नई दिल्ली, 27 मई, 2014 को एक एक दिन की संवर्धन बैठक व संगोष्ठी का आयोजन किया।

डॉ अमिता गुप्ता, न्यूपा, नई दिल्ली, के साथ 17 जुलाई, 2014 एशिया में पांच देशों से आवाजें और छवियाँ, विविध बचपन शिक्षा नीतियों और प्रथाओं पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

गुणात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में तरीके, न्यूपा, नई दिल्ली, 21 जुलाई से 8 अगस्त 2014, तीन सप्ताह की उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन।

संगठित, ज्ञान की कल्पनाः सपना लोकतंत्र का, पर प्रो शिव विश्वनाथन द्वारा दिया गया न्यूपा स्थापना दिवस व्याख्यान, आईआईसी, नई दिल्ली, 11 अगस्त 2014

प्रो एम.एन. पाणिनी, न्यूपा, नई दिल्ली, 1 सितंबर, 2014 की प्रस्तुति के साथ, ढांचे और प्रक्रियाः आर्थिक सुधार के बाद असमानता, पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

प्राथमिक के बाद का स्कूल स्तरः एक तुलनात्मक विश्लेषण असमानता, अलगाव और शिक्षार्थी उपलब्धि पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन, वाणी के. बरूआ, न्यूपा, नई दिल्ली, द्वारा प्रस्तुति 15 सितंबर, 2014

भारत में खतरे में बालिकाः पहले और जन्म के बाद पर एक संवर्धन बैठक संगठित, प्रो उषा नायर, न्यूपा, नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014 के साथ प्रस्तुति।

स्कूल भोजन और दिल्ली में छात्र परिणाम पर (प्रो. रोहिणी सोमनाथन), द्वारा प्रस्तुति, न्यूपा, नई दिल्ली, 5 नवंबर 2014 को एक संवर्धन बैठक का आयोजन।

सर्व शिक्षा अभियान के लैंगिक समानता के परिणाम, न्यूपा, नई दिल्ली, 13 नवंबर 2014 (प्रो. रत्ना सुदर्शन) द्वारा एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 दिसम्बर, 2014: 'नीतिगत मुद्दों और कार्यक्रम हस्तक्षेप माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर सामाजिक रूप से वंचित की शिक्षा' पर एक सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन किया।

'शिक्षा, स्थिरता और 2015 के बाद विकास के एजेंडे पर

एक संवर्धन बैठक का का आयोजन न्यूपा, नई दिल्ली, 11 दिसंबर 2014 (डॉ राधिका आयंगर, निदेशक, शिक्षा क्षेत्र, वैश्वीकरण और के लिए केन्द्र और सतत विकास पृथ्वी संस्थान, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क)।

एक संवर्धन बैठक आयोजित 'अम्बेडकरः एक वैश्विक नागरिक' न्यूपा, नई दिल्ली, 12 जनवरी 2015 (डॉ. लुइस कारबेरा, सरकार और अंतरराष्ट्रीय संबंध स्कूल, ग्रिफिथ बिजनेस स्कूल, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तुति)।

न्यूपा, नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2015 (प्रो. जेम्स अरवानीताकीस पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, के साथ अनुसंधान अध्ययन पर छात्र संवाद पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

न्यूपा, नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2015 (प्रो. आरोन बोनावोट, निदेशक, ईएफए , ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट टीम, यूनेस्को द्वारा प्रस्तुति) 'प्राथमिकताएं, नीतियां, और राजनीतिः 2015 के बाद वैश्विक शिक्षा के लक्ष्यों पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन।

विकासशील देशों से साक्ष्यः स्कूल गुणवत्ता मायने रखता है' पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन (प्रोफेसर एंजेला डब्ल्यू लिटिल प्रो. एमिरत, शिक्षा संस्थान लंदन विश्वविद्यालय), न्यूपा, नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2015।

12 फरवरी, 2015 (डॉ. सोमेन चट्टोपाध्याय और दीपेंद्र नाथ दास, जे.एन.यू., नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुति) उच्च शिक्षा में सीधे सुधारः अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई)' पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

(डॉ राहुल चोड्डा न्यूयॉर्क द्वारा प्रस्तुति, विश्व शिक्षा सेवा), न्यूपा, नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015 'भारत के लिए अमेरिकी उच्च शिक्षा और इसके निहितार्थ का अंतर्राष्ट्रीयकरण' पर एक संवर्धन बैठक का आयोजन किया।

एक संवर्धन बैठक आयोजित 'मलेशिया की सार्वजनिक–निजी उच्च शिक्षा प्रणालीः यह 2020 तक उच्च आय वाले राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए एक समावेशी उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा का निर्माण कर सकती है (वक्ताः प्रो सेल्वा रत्नम, मलाया विश्वविद्यालय), न्यूपा, नई दिल्ली, 19 मार्च 2015

çf'k{k.k lkexzh rFkk ikB;Øe fodflr vkSj fu'ikfnr

न्यूपा के एम.फिल. और पीएच.डी. प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम विकसित कियेः

सीसी 03ः अनुसंधान क्रियाविधि–1

सीसी 05ः शैक्षिक अनुसंधान के तरीके और तकनीक

ओसी 09ः शिक्षा, लिंग और विकास

ओसी 14ः विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा में समावेशन

ओसी 07ः इक्विटी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

पर्यवेक्षण/मूल्यांकन :

श्री गैरसॉन तवया आशी के आईडेपा शोध – 'उत्तरी नगर पालिका, घाना अकुआपेम सीनियर हाई स्कूल के छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पर एकल अभिभावक के प्रभाव का पर्यवेक्षण

श्री भरत पाल सिंह रावत के डेपा शोध द्वारा 'उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय–साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति की परीक्षा में छात्रों की भागीदारी पर एक अध्ययन' का पर्यवेक्षण

शिक्षण :

शिक्षण 'अनुसंधान विधि– द्वितीय' न्यूपा में एम.फिल/पीएचडी छात्रों के लिए (कुल सत्रः 12)

आईडेपा प्रतिभागियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः शैक्षिक विकास पर अध्यापन।

अन्य गतिविधियांः

'प्रवेश समिति के सदस्य– एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रम के लिए, 22 मई, 2014 को कुलसचिव द्वारा गठित'

22 सितम्बर 2014 को न्यूपा के विजन दस्तावेज पर संकाय की बैठक के रिपोर्टकार

''आरटीईः मुद्दे और चुनौतियां'', 24–25 नवम्बर, 2014 (बैठक पर रिपोर्ट तैयार की), राष्ट्रीय चर्चा बैठक में रिपोर्टकार

मसौदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिसंबर 2014 में कुलपति द्वारा गठित 'शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति की दिशाः लोगों की आवाज सुनना' पर समिति के सदस्यः नई शिक्षा नीति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाना है

समिति सदस्य 'न्यूपा रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशन श्रृंखला' न्यूपा अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए जांच और संपादन हेतु 23 दिसंबर, 2014 को कुलसचिव द्वारा गठित

'शिक्षण और प्रशिक्षण दस्तावेजः न्यूपा के लिए एक विजन दस्तावेज' संकाय के लिए सूरजकुंड बैठक, 16–17 जनवरी, 2015, के लिये समूह रिपोर्ट तैयार की

परियोजना कनिष्ठ सलाहकार के पद के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए फरवरी 2015 में कुलपति द्वारा गठित समिति के सदस्य

l koZ fud fud k; ka d ks i j ke'kZ v kS 'kS{kd l gk; rk

डाइट, रायपुर, छत्तीसगढ़, 09–12 मार्च, 2015 तक 'डाईट के संकाय के लिए योजना और पुनर्निर्माण अनुसंधान परियोजनाओं' पर उन्मुखीकरण कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भागीदारी

Ld wy , oa v ukS p kfj d f' k{kk fo Hkkx

u fy u h t q s k ¼fo Hkkx kè; {k½

ç d k' ku

शोध पत्र/लेख/नोट्सः

'इंडियाज़ न्यू मंडेट अगेंस्ट इकोनोमिक अपार्थेड इन स्कूल्स' जर्नल आफ इंटरनेशनल कोपरेशन इन एजुकेशन (स्पेशल इश्यू ऑन राइट टू एजुकेशन), वाल्यूम 16, नं. 2 अप्रैल 2014: 55–70

'करैक्टिंग ए हिस्टोरिकल इनजस्टिस'. द हिन्दू, ओपिनियन, मई 15, 2014

l a k'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky k, a e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीयः

एम.वी. फाउंडेशन, हैदराबाद द्वारा आयोजित, 'मौजूदा प्रथाओं में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता' राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, सितंबर 1–2, 2015

आलेख प्रस्तुत ''75वें भारतीय इतिहास कांग्रेस, नई दिल्ली, 27–28 दिसम्बर, 2014 में ''अनुच्छेद 45 भारत के संविधान में सार्जेंट योजना लागू करने के लिए प्रयास है?

आलेख प्रस्तुत ''केंद्र राज्य गतिशीलता और भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक दर्जा'' लोगों की भागीदारी और विकेंद्रीकृत शैक्षिक शासनः नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण पर द्वितीय अनिल बोर्डिया मेमोरियल पॉलिसी संगोष्ठी, नई दिल्ली, 16–17 फरवरी 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

- शिक्षा के अधिकार पर अभिविन्यास कार्यक्रम, सितंबर 15–19,2014
- शिक्षा के अधिकार पर अभिविन्यास कार्यक्रम, अक्टूबर 13–17, 2014

lkoZtfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj vdknfed lgk;rk

vfrfFk laiknd % जर्नल आफ इंटरनेशनल कोपरेशन इन एजुकेशन, वाल्यूम 16, नंबर 2 अप्रैल 2014 के जर्नल (शिक्षा का अधिकार पर विशेषांक)

uhye lwn

laxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk esa Hkkxhnkjh

राष्ट्रीय:

गुजरात बोर्ड द्वारा आयोजित भारत में स्कूली शिक्षा बोर्ड की परिषद का 43वॉ वार्षिक सम्मेलन , गांधीनगर, 7–9 नवम्बर, 2014

'महाराष्ट्र राज्य के लिए बचपन विकास नीति', पर कार्यशाला, महाराष्ट्र सरकार और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, मुंबई, 29 जनवरी, 2015

द्वितीय राष्ट्रीय समीक्षा और स्कूल नेतृत्व विकास पर योजना कार्यशाला, इंडिया हैबिटेट सेंटर , नई दिल्ली, 17 मार्च 2015

अंतर्राष्ट्रीय:

अध्यक्षता बचपन विकास एवं अनुसंधान, जामिया मिलिया इस्लामिया और 'सेव द चिल्ड्रन' द्वारा आयोजित 'बचपन विकास के लिए उत्तर–अनुशासनात्मक दृष्टिकोण' शीर्षक से बचपन विकास पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''बचपन के विकास में अभिनव प्रथाओं'' पर सत्र की अध्यक्षता, भारत, 2 अप्रैल, 2014

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एन.सी.एस.एल. न्यूपा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित, 'नीति, अभ्यास और अनुसंधानः स्कूल नेतृत्व' नवंबर 17–18, 2014

एन.सी.एस.एल. द्वारा आयोजित 'शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन', न्यूपा, नई दिल्ली, 12–13 फरवरी, 2015

इंडिया हैबिटेट सेंटर में 10–11 फरवरी, 2015 को स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक और 30–31 अक्टूबर, 2014 न्यूपा में कार्यशाला

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu

''शिक्षकों के लिए संभावनाएँ और चुनौतियांः समावेशी शिक्षा'' विषय पर शिक्षकों–शिक्षकों का अभिविन्यास कार्यक्रम, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद, 28 अप्रैल, 2014 को आयोजित

संगठित, राज्य परामर्श और नियोजन कार्यशाला/बैठक, ब्रिटेन के प्रशिक्षण और नेतृत्व कॉलेज के साथ यूकेआईईआरआई के तहत एक सहयोगी परियोजना के लिए न्यूपा से नेतृत्व के रूप में केरल और महाराष्ट्र में स्कूल नेतृत्व में विकास (17 सितंबर 2014), (10 नवंबर, 2014)

राजस्थान, 09–10 अक्टूबर, 2014, स्कूल नेतृत्व विकास पर ट्यूटर फैसिलिटेटर के लिए दूसरा चरण क्षमता निर्माण कार्यक्रम

केरल (भाग–1), 13–15 अक्टूबर, 2014, ट्यूटर फैसिलिटेटर के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर तीन दिवसीय कार्यशाला।

महाराष्ट्र में ट्यूटर फैसिलिटेटर (भाग–1) का निर्माण क्षमता, 11 नवंबर 2014

''कार्यशाला का आयोजनः अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जम्मू, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में 'अच्छा प्रशासक और नेतृत्व के रूप में कॉलेज प्राचार्य', 4 दिसंबर, 2014

राज्य संसाधन समूह के साथ माध्यमिक विद्यालय नेतृत्व विकास पर परामर्श, पुडुचेरी, और स्कूलों का दौरा/स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के साथ चर्चा, 11–12 दिसम्बर, 2014

महाराष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद, के साथ 'ईसीसीई और स्कूल शिक्षा के बीच संबंध''

विषय पर पांच दिवसीय कार्यशाला, 29 दिसंबर, 2014 से 2 जनवरी, 2015

महाराष्ट्र के ट्यूटर फैसिलिटेटर के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर चार दिवसीय कार्यशाला (भाग–1 जारी) 06–09 जनवरी, 2015, महाराष्ट्र

स्कूल नेतृत्व विकास पर ट्यूटर फैसिलिटेटर के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, द्वितीय चरण 20–21 जनवरी, 2015, पुडुचेरी

महाराष्ट्र में ट्यूटर फैसिलिटेटर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (भाग द्वितीय), 02–03 फरवरी, 2015

महाराष्ट्र में स्कूल नेतृत्व विकास पर ट्यूटर फैसिलिटेटर के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तीसरा चरण (23–25 मार्च, 2015) और ट्यूटर फैसिलिटेटर कार्यक्रम का मूल्यांकन (भाग III) कोहलापुर और सतारा जिलों में स्कूल प्रमुखों के लिए वितरण, 26–27 मार्च, 2015)

çf'k{k.k lkexzh] ikBîØe fodflr vkS fu'ikfnr

प्रशिक्षण सामग्री ईसीसीई पर क्षेत्र आधारित कार्यशाला के लिए तैयार

पुनर्गठित एम.फिल. पर कार्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम 06 और 13 बचपन की देखभाल और शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पोषण और स्कूली शिक्षा

सदस्य, राज्य स्तर के अनुकूलन और चार राज्यों में स्कूल नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण सामग्री संदर्भीकरण

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkS 'kS{kd lgk;rk

एस.ओ.सी.ई. इग्नू में परामर्शः परिवार थेरेपी में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन , 23 अप्रैल 2014

विषय विशेषज्ञ के रूप में, प्री–डॉक्टरेट कार्य पर संगोष्ठी का आयोजन और सतत् शिक्षा, इग्नू के विद्यालय हेतु डॉक्टरेट प्रस्तावों की समीक्षा की, 25 अप्रैल, 2014

बचपन विकास (चतुर्थ सेमेस्टर), जामिया मिलिया इस्लामिया में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की परीक्षा के लिए परीक्षक 2 मई, 2014

लैंगिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में पुनर्गठन और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पर परामर्श, 7 मई 2014

''मुकाबला रणनीतियों का आकलन'' शीर्षक से आलेख का मूल्यांकन, 3 जून, 2014 को प्रस्तुति के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजा गया

दक्षिण एशिया में महिलाओं, के खिलाफ हिंसा पर काबू पाने पर विश्व बैंक के क्षेत्रीय रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया और सुझाव, 23 जुलाई, 2014

अनुसंधान प्रस्तावों और पीएच.डी. में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु समीक्षा बचपन विकास एवं अनुसंधान केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, 12 सितंबर, 2014 को अध्ययन समिति के भाग के रूप में बाल विकास

एक सदस्य, के रूप में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया, 9 नवंबर, 2014 अहमदाबाद, भारत

बाल विकास अनुसंधान परियोजनाओं, इग्नू में डॉक्टरेट की समीक्षा, 28 नवंबर 2014

फुलब्राइट–नेहरू शैक्षिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता फैलोशिप (शिक्षा) के लिए आवेदनों की यू.एस.आई.ई.एफ. 2015–16 समीक्षा प्रक्रिया का समर्थन और एक सदस्य के रूप में वरिष्ठ विद्वान कार्यक्रम, के लिए चयन समिति के पैनल सदस्य 16 दिसंबर, 2014।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, विज्ञान भवन में सामान्य निकाय की बैठक में भाग लिया, 27 फरवरी, 2015।

इग्नू के सतत् शिक्षा स्कूल के स्कूल बोर्ड की 51वीं बैठक में भाग लिया, 30 मार्च, 2015।

vU; 'kS{kf.kd vkS iš'ksoj ;ksxnku

पर्यवेक्षण / मूल्यांकनः

दिल्ली विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा में छात्रों की भागीदारी एक लिंग–आधारित विश्लेषण (शोध कार्य)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आरंभिक हस्तक्षेपः सेवा प्रदाताओं की भूमिका (शोध कार्य)

डाईट कुरुक्षेत्र में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का एक अध्ययन (पीजी डेपा के लिए अनुसंधान परियोजना कार्य)

ग्राईप से ग्रिप तकः स्वःसशक्तीकरण और दल निर्माण दिशा में एक यात्रा (स्कूल नेतृत्व में पीजी डिप्लोमा के लिए अनुसंधान परियोजना कार्य)

कोर्स समन्वय (एम.फिल / पीएच.डी.) :

अनुसंधान कार्यप्रणाली और सांख्यिकी पर कोर पाठ्यक्रम 03 और 05

वैकल्पिक पाठ्यक्रम 09 : लैंगिक, शिक्षा और विकास

f' k{k.k k %

दल शिक्षण और मूल्यांकन कार्य से संबंधित –

कोर पाठ्यक्रम सीसी03ः शोध पद्धति और सांख्यिकी एम.फिल. / पीएच.डी. कार्यक्रम

कोर्स नंबर 905 परियोजना कार्य और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर पीजी डिप्लोमा में लेखन (पीजी डेपा)

स्कूलों के प्राचार्यों के लिए स्कूल नेतृत्व पर पीजी डिप्लोमा में स्व विकास पर पाठ्यक्रम संख्या–103

v U; x fr fo fèk; k a%

सदस्य, एम.फिल. / पीएच.डी. में प्रवेश के लिए न्यूपा साक्षात्कार बोर्ड, 23–24 जून, 2014

27–30 जनवरी, 2015 के दौरान निरंतर के सहयोग से न्यूपा द्वारा प्रस्तुत ''लिंग और शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मुसलमानों का संदर्भीकरण और शिक्षा के मुद्दे'' (27 जनवरी, 2015) को सत्र की अध्यक्षता

चार राज्यों में 2014–15 के दौरान शुरू एन.सी.एस.एल., न्यूपा और नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ब्रिटेन के बीच सहयोग के माध्यम से यूकेआईईआरआई के तहत स्कूल नेतृत्व विकास परियोजना (द्वितीय चरण) के आचरण को सुविधाजनक बनाने और साझेदारी की योजना – राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी।

U; ivk d s c kg j ç[; kr fud k; ksa d h l nL; r k

सदस्य, स्कूल बोर्ड, सतत् शिक्षा स्कूल, इग्नू

सदस्य, जर्नल ''रिसेन्ट एजुकेशनल एंड साइकलाजिकल रिसर्च'', संपादकीय बोर्ड

सदस्य, कोबसे की कार्यकारी परिषद (भारत में स्कूली शिक्षा बोर्ड की परिषद)

सदस्य, डॉक्टरल अनुसंधान समिति, बाल विकास, इग्नू

सदस्य, लैंगिक अध्ययन पर सलाहकार बोर्ड, सामाजिक विज्ञान संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय

e èkfje r k c a ksi kè; k;

ç d k' ku

i qLr d sa@ v è; k; %

अध्याय, ''इंप्लेमेंटेशन ऑफ राईट टू एजुकेशन एक्ट, 2009ः एन एसैसमेंट'' इन बुक डेमोक्रेसी एंड गुड गर्वनेंसः रेंनवेंटिंग पब्लिक सर्विस डेलीवरी सिस्टम इन इंडिया (एड. रम्की बसु) नई दिल्लीःब्लूमबर्सी इंडिया फार डिपार्टमेंट आफ पॉलिटिकल साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया, 2015, पृ. 131–146

' kksèk i = @ y s[k@ u ksV+ %

''भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और बनाए रखने के लिए शैक्षिक पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण'' जर्नल ऑफ डवलपमेंट मैंनेजमेंट एंड कम्यूनिकेशन (अक्टूबर–दिसंबर 2014), विकास प्रबंधन संस्थान, जयपुर, वॉल्यूम–1 (4), पृ.सं. 396–404

''शिक्षा, गरीबी और बहिष्करण'' (न्यूपा समसामयिक आलेख सं. 45), 2014

l a ks'Bh@ l Ee sy u @ d k; Zkky k v ksa e sa Hkkx hn kj h

राष्ट्रीय :

'समुदाय के माध्यम से शिक्षा में बदलाव', और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए स्टैनफोर्ड सेंटर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (यूएसए), न्यूपा, प्रजयत्न, कर्नाटक द्वारा आयोजित नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014

आलेख प्रस्तुत ''विकेंद्रीकरण के माध्यम से बहिष्करण के साथ संबंधः भारत में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भागीदारी पर विशेष फोकस'', 'लोगों की भागीदारी और विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रशासनः नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण'', पर द्वितीय अनिल बोर्डिया पॉलिसी संगोष्ठी 16—17 फरवरी, 2015

l koZ fud fud k; ksa d ks i jke'kZ vk§ 'kS{kd l gk; r k

एमसीडी स्कूल के अभिभावक बैठक में बच्चों की शिक्षा 'में' माता—पिता की भूमिका पर इंटरेक्टिव सेशन के लिए संसाधन व्यक्ति, अस्पायर भारत, दिल्ली द्वारा आयोजित

न्यूपा के एक सदस्य के रूप में इक्विटी स्टडीज केंद्र, नई दिल्ली के लिए भारत से बाहर की रिपोर्ट के विकास के लिए बैठकों में भागीदारी और रिपोर्ट के लिए ''स्कूल शिक्षा और बहिष्करण'' पर एक अध्याय के लिए ''शिक्षा, गरीबी और बहिष्करण'' पर एक पृष्ठभूमि आलेख का योगदान (http://www.indianet.nl/pdf/indiaExclusion).

अर्थ संस्थान, कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग में अवंती अध्येताओं, नई दिल्ली में 'भारतीय शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देने के साथ, उभरते अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रुझान' — पायलट अधिगम कार्यक्रम कोर्स 'भारत में प्राथमिक स्तर पर हाशिए पर बच्चों की शिक्षा' विषय पर एक प्रस्तुति

भारत के योजना आयोग और यूएनडीपी के साथ संकेत, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित बुंदेलखंड क्षेत्र की मानव विकास रिपोर्ट के विकास के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया जो ''मानव विकासः अग्रसर समानता की ओर अग्रसर' परियोजना लागू कर रहे हैं

एनसीईआरटी में ''पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिएः प्रणालीगत सुधार विषय पर एनसीईआरटी की स्थिति पत्र में संशोधन के लिए टीम सदस्य

çf'k{k.k l kexzh vk§ i kBî Øe fod fl r vk§ fu'i kfnr

'भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार' पर कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री, अगस्त 4—8, 2014, न्यूपा

'भारत के दक्षिणी राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार' पर कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री, 06—10 सितम्बर, 2014, न्यूपा

'प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार के लिए भागीदारी कार्य परियोजना' पर प्रथम अनुवर्ती कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री, 10—14 नवम्बर, 2014, न्यूपा

प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की सार्वभौम भागीदारी की दिशा में भागीदारी परियोजना, 'प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार' पर अनुवर्ती कार्यशाला, 10—14 नवम्बर, 2014, नई दिल्ली

साक्षरता और स्कूल शिक्षा की वर्तमान स्थितिः कोर्स की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम के लिए एक अवलोकन पी.जी.डी.ई.पी.ए. एक परिप्रेक्ष्यः भारतीय शिक्षा 2014—15

U; wk d s c kg j ç[; kr fu d k; ka d h l nL; r k

सदस्य, भारत तुलनात्मक एजुकेशनल सोसायटी

सदस्य, अस्पायर इंडिया (दिल्ली—गैर सरकारी संगठन के आधार पर)

mPp , oa Q; kokl kf; d f'k{kk foHkkx

l èkkk'a kq HkV'kk. k ¼foHkkx kè; {k½

ç d k' ku

i qLr d s@v è; k; %

अध्याय ''एमजीडी पोस्ट 2015: एक्सैस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग'', पुस्तक हुमन डवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ (एड. तनुका एंडो, सुमित मजूमदार, मीतू सेनगुप्ता), इंस्टीट्यूट फार हुमन डवलपमेंट

क्वालिटी डिस्कोर्सेस इन द कान्टेक्स्ट आफ रेगुलेटर्स' पर्सपेक्टिव, मार्केट फोर्सेस, टीचर्स' वॉइसेज एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, कॉलेज पोस्ट, सीड.

हायर एजुकेशन: स्टोरी आफ द पास्ट एंड रिकंस्टीट्यूटिंग नया अध्याय इंडियन एजुकेशन: ए डवलपमेंटल डिस्कोर्स पुस्तक में (एडीटर एम. मुखोपाध्याय, एम. परहार), शिप्रा, 2015

स्टेट ऑटोनामी इन पॉलिसी फार्मुलेशन, युनिवर्सिटी न्यूज (जनवरी 19–25, 2015), वाल्यूम 53(3).

l ak'Bh@l Ee sy u @d k; Zkky kv ka e sa Hkkx hn kj h

मुख्य व्याख्यान एफ.एक्स. इंजीनियरिंग कॉलेज, वनारपेटायी, तिरुनेलवेली, 'एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन: रूसा' पर कार्यशाला 13 अप्रैल, 2014

अर्थशास्त्र विभाग, नौगाँव कॉलेज, नगांव (असम), 10 मई, 2014 को रूसा, पर कार्यशाला में महत्वपूर्ण व्याख्यान

पीजी और रिसर्च, वाणिज्य विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, कांची ममुनिवार केन्द्र, में आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित एक अनुसंधान क्रियाविधि पाठ्यक्रम में मुख्य व्याख्यान, 11 जुलाई, 2014

कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, इलाहाबाद, में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान, 13 मार्च, 2015

केन्द्रीय विश्वविद्यालय: कश्मीर – 'एनईपी–2015 के प्रस्तावों के विशेष संदर्भ में प्राथमिकताओं को बदलने के संदर्भ में मूल्यांकन सुधार परीक्षा' पर एक कार्यशाला में 'उच्च शिक्षा में मूल्यांकन' पर आलेख प्रस्तुत, 31 मार्च, 2015

v a j kZVªh; %

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के निमंत्रण पर, 02–04 अप्रैल, 2014 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन और अध्यापन के कार्यालय में कार्यशाला में भाग लिया

आईएचडी, नई दिल्ली, अप्रैल 28–29, 2014 द्वारा आयोजित ''दक्षिण एशिया में मानव विकास'' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयोग' पर विषयगत सत्र में संचालक,

वी आई टी वेल्लोर, 23 फरवरी, 2015 'प्रबंधन शिक्षा के विशेष संदर्भ में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ''शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारत की नीतियों'' पर व्याख्यान

v U; 'kS{kd v kS Q; kol kf; d ; kxn ku

यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित समर स्कूल, पंजाब विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण, 10 जून, 2014

l koZ fud fud k; ka d ks i j ke'kZv kS 'kS{kd l gk; rk

''प्रशासन और उच्च शिक्षा और अनुसंधान अनुदान पर नई योजनाएं'' यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कालेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, 3–5 फरवरी, 2015 में प्रमुखों और संकायों के डीन के लिए व्याख्यान

एससीईआरटी पटना, 10–11 मार्च, 2015 तक आयोजित, शोध पद्धति पाठ्यक्रम में अनुसंधान डिजाइन पर प्रस्तुति

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद

कार्य समूह के सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित शिक्षकों और शिक्षण योजना पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (योजना को अंतिम रूप देने के लिए)

सदस्य, आईसीएसएसआर अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला, भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित

v kj r h J h o kLr o

ç d k' ku

अतिथि संपादक, स्वायत्तता पर 19वें से 15वां विशेषांक, युनिवर्सिटीज् न्यूज, जनवरी, 2015

l a ks'Bh@ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k"Vªh; %

नेत्रहीन छात्रों को अर्थशास्त्र शिक्षण पर पांच दिवसीय कार्यशाला, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

भारतीय उच्च शिक्षा पर एक दिवसीय परामर्श बैठक, न्यूपा, नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2014

उच्च शिक्षाः विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापनाः नए कीर्तिमान पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015 को आयोजित

जी.ई.डी.: महिलाएँ और नेतृत्व, ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित 'अनुपस्थित' क्रांति, 10–11 फरवरी, 2015

उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित, एएससी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

रूसा पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में उच्च शिक्षा में शिक्षण पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित

उच्च शिक्षा की परिकल्पना– शिलांग में विभागीय कार्यक्रम

बीएचयू का शानदार इतिहास। पटना में विभागीय कार्यक्रम

उच्चतर शिक्षा में 'शिक्षा और शिक्षण', पटना में विभागीय कार्यक्रम

शिक्षा का वित्तपोषण, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

v a rjk"Vªh; %

सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ओ.एल.टी. कार्यशाला अप्रैल, 2014

''अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठीः उच्च शिक्षा और लोक सूचना प्रणाली'', यूनेस्को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग, 03–04 जुलाई, 2014

'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा का सार्वजनिकरण' पर संगोष्ठी, सी.पी.आर.एच.ई., 10–11 नवम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठीः 'उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में नए तरीके' 23–25 फरवरी, 2015, न्यूपा, नई दिल्ली

भारत और जापान में लिंग और शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, मार्च 2015

ç f' k{k.k k d k; Øe@ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम, राष्ट्रीय कार्यशाला, 12–14 जनवरी, 2015।

उच्च शिक्षा पर बाजार के साथ संबंधों पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 12–14 मार्च।

v U; ' kS{k.kd v kS j O; kol kf; d ; ksx n ku

i ; Zo s{k.k k@ e kV; kd u %

सुश्री अपरजिता गंतायेत की एम.फिल संबंधित काम का पर्यवेक्षण

पीएच.डी. का पर्यवेक्षण, सुश्री अनुनीता मित्रा के संबंधित कार्य

डेपा/आईडेपा कार्यक्रमों से संबंधित पर्यवेक्षण

(एम.फिल./पी–एच.डी) शिक्षणः

पाठ्यक्रम सीसी2 और ओसी 1

v U; x fr fo fèk; ka %

सदस्य, प्रवेश परीक्षा समिति एम.फिल./पीएच.डी., न्यूपा

सदस्य, एम.फिल./पीएच.डी. के लिए परीक्षा मूल्यांकन समिति, न्यूपा

सदस्य, विद्यार्थी सहायता समिति, न्यूपा

l koZ fud fud k; ka d ks i jke'kZ v kS ' kS{ kd l gk; rk

एम.फिल., जेएनयू के लिए परीक्षक

पीएच.डी., जेएनयू के लिए परीक्षक

सदस्य, एडसिल में चयन समिति

U; wk d s c kgj ç[; kr fud k; ka d h l nL; r k

आजीवन सदस्यः

प्रौढ़ शिक्षा संघ, आईटीओ, नई दिल्ली (1999)

भारतीय ज्ञानपीठ परिवार, नई दिल्ली (1999)

भारतीय आर्थिक संघ (2004)

इंडियन सोसायटी फार लेबर इकानमिक्स (1998)

नेशनल बुक ट्रस्ट (1998)

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड (2003)

थियोसोफिकल सोसायटी, वाराणसी (2004)

सी.ई.एस.आई., नई दिल्ली (2010)

अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (2009)

u hr Lu g h

ç d k' ku

i q Lr d s@ v è; k; %

मॉड्यूल पाठ्यक्रम एमईएस 048–अल्टरनेटिव एजुकेशन, पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मेंनेजमेंट एंड एडमिनिस्टेशन (पीजीडीईएमए), इग्नू, 'ट्रेंड इन अल्टरनेटिव एजुकेशनः मैंनेजेरियल पर्सपैक्टिव'

' kks/k i = @ y s[k@ u ksV ~ %

उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण अधिगम में सुधार – विषय आधारित नेटवर्क, प्रबंधन और परिवर्तन, वॉल्यूम 18(2), 2014

अकादमिक स्वतंत्रता और भारत में विश्वविद्यालय स्वायत्तता, विश्वविद्यालय समाचार (विशेषांक), वॉल्यूम 53(3), 19–25 जनवरी, 2015

l a ks'B h@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

'भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट', एक–दिवसीय परामर्श बैठक, 29 सितंबर, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली

'उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और शासन' पर कार्यशाला में 'उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और शासन' विषय पर एक आलेख प्रस्तुत किया। 19–21 दिसम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

एआईयू, नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015 को आयोजित 'विश्वविद्यालयों में स्थापित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्रः उच्चतर शिक्षा–नए कीर्तिमान' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

v a r j kZ"Vªh; %

'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 10–11 नवम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

सी.ई.एस.आई. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 'नीतियों और सुधारों का प्रभावः भारतीय उच्च शिक्षा में शैक्षणिक स्टाफ/संकाय का अभिशासन' पर एक आलेख प्रस्तुत 16–18 नवम्बर, 2014 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

जी.ई.डी. में भाग लियाः 'महिलाएँ और नेतृत्व' 'अनुपस्थित' क्रांति, ब्रिटिश काउंसिल, 10–11 फरवरी, 2015 नई दिल्ली

'उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में रिपोर्ट, 23–25 फरवरी, 2015 न्यूपा, नई दिल्ली

çf' k{k.k dk; Øe@l Eesyu@dk; Zkkyk vk ksa dk vk; kstu

उच्च शिक्षा के निजीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। 15–18 दिसम्बर, 2014 न्यूपा नई दिल्ली

समन्वयक, 'राष्ट्रीय अभिशासन पर कार्यशाला और स्वायत्तता', 19–21 दिसम्बर, 2014 न्यूपा नई दिल्ली

'उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम', राष्ट्रीय कार्यशाला 12–14 जनवरी, 2014 न्यूपा नई दिल्ली, में भाग लिया

i kBî Øe esa Hkkx hn kj h

यूनेस्को / आई.आई.ई.पी. विशेष पाठ्यक्रम कार्यक्रम शिक्षा योजना और प्रबंधन (ई.पी.एम.), आई.आई.ई.पी. पेरिस, 7 अप्रैल – 30 मई, 2014 में भाग लिया ..

l ko Z fu d fu d k; ksa d ks i j ke ' kZ v kSj ' kS{kd l gk; r k

समन्वित 'यूनिवर्सिटी न्यूज' में ''उच्च शिक्षा में स्वायत्तता'' पर विशेषांक के लिए योगदान (19–15 जनवरी 2015 के अंक में, भारतीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित)

d kS j fo t kj r

ç d k' ku

' kks/k i = @ y { k@ u kV~ l %

ऑटोनॉमी ऑफ अंडरग्रेजुएट कॉलेज विश्वविद्यालय समाचार (विशेषांक), वॉल्यूम–53(3), 19–25 जनवरी, 2015

l a kfs'B h@ l Ee sy u@ d k; Zkky k vk ksa e sa Hkkx hn kj h

j k"Vª h; %

भारतीय उच्च शिक्षा, 29 सितंबर, 2015 को एक–दिवसीय परामर्श बैठक

v a r j kZ "Vª h; %

'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सी.पी.आर.एच.ई. 10–11 नवम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

मीडिया विविधता की अवधारणा विश्लेषण, नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 25–26 नवम्बर, 2014

जी.ई.डी. ब्रिटिश काउंसिल, 10–11 फरवरी, 2015 तक आयोजित महिला एवं नेतृत्व, 'अनुपस्थित' क्रांति,

çf' k{k.k dk; Øe@l Ee sy u@ d k; Zkky k vk ksa dk vk; kstu

जबलपुर, नवंबर, 17–21, 2014 में कॉलेज प्रिंसिपलों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

l a hr k v a k

ç d k' ku

' kks/k i = @ y { k@ u kV~ l %

''इंस्टीट्यूशनल ऑटोनामी इन इंडिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज'', यूनिवर्सिटी न्यूज (वीकली जर्नल आफ हायर एजुकेशन–स्पेशल इश्यू आन ऑटोनामी इन हायर एजुकेशन शिफ्टिंग पैराडिज्म), एशोसिएशन आफ इंडिया युनिवर्सिटी, वाल्यूम 53(3):290–295, जनवरी 19–25, 2015

''प्राइवेट हायर एजुकेशन इन इंडिया: स्टडी आफ टू प्राइवेट युनिवर्सिटीज़'', हायर एजुकेशन फार द फ्यूचर, वाल्यूम 2(1):92–111, सेज़ पब्लिकेशन, जनवरी 2015

''रोड टू एक्सेलेंस: केस आफ कॉलेज विद स्ट्टेस ऑफ पोटेंशियल फार एक्सेलेंस'', युनिवर्सिटी न्यूज (वीकली जर्नज आफ हायर एजुकेशन – स्पेशल इश्यू आन ऑटोनामी एंड एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन), वाल्यूम 53(7): 162–168.

l a kfs'B h@ l Ee sy u@ d k; Zkky k vk ksa e sa Hkkx hn kj h

j k"Vª h; %

न्यूपा, नेहू, 16–20 जून, 2014 के दौरान आयोजित, ''कॉलेज प्रधानाध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में वर्तमान स्थिति और पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य की चुनौतियों' पर एक आलेख प्रस्तुत

संसाधन व्यक्ति के रूप में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की बाधाओं और चुनौतियों में

उच्च शिक्षा संस्थानों पर एक आलेख प्रस्तुत, एनएएसी आयोजित कार्यशाला 'ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानः समस्याएं और उपचार', डूमडूमा कॉलेज, डूमडूमा, तिनसुकिया, असम, 05–06 सितम्बर, 2014

भारतीय उच्च शिक्षा, पर एक दिवसीय परामर्श बैठक, 29 सितंबर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

'निजी उच्च शिक्षा', पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 'उच्च शिक्षा के निजीकरण की संकल्पना' पर एक आलेख प्रस्तुत, 15–18 दिसम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

'उच्च शिक्षाः विश्वविद्यालयों में स्थापित अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र–नए कीर्तिमान' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र की रिपोर्टिंग और भागीदारी एआईयू, 9 जनवरी, 2015, नई दिल्ली, को आयोजित

इंडिया हैबिटेट सेंटर, में आयोजित ''स्कूल के मानकों और मूल्यांकन'', पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में भाग लिया 10–11 फरवरी, 2015 न्यूपा, नई दिल्ली,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित जामिया मिलिया इस्लामिया, 24 मार्च, 2015 नई दिल्ली, कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली और क्रेडिट फ्रेमवर्क' पर एक कार्यशाला में भाग लिया

v ar j kZVªh; %

''वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सी.बी.आर.एच.ई. 10–11 नवम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

सी.ई.एस.ई. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 16–18 नवम्बर, 2014 'स्थिति और अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों की चुनौतियांः पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा' विषय पर एक आलेख प्रस्तुत किया

जी.ई.डी. महिला एवं नेतृत्व, 'अनुपस्थित' क्रांति, ब्रिटिश काउंसिल, 10–11 फरवरी, 2015 में भाग लिया

''उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक सत्र की रिपोर्टिंग 23–25 फरवरी, 2015

''भारत में निजी विश्वविद्यालयः स्थिति, चुनौतियां और नीति दृष्टिकोण'' विषय पर एक शोध पत्र प्रस्तुत और वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, 08–13 मार्च, 2015 के दौरान 59वें तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय एजुकेशनल सोसायटी सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता की

'हाशिए समूहों की नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियां की शिक्षा' पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया 25–27 मार्च, 2015

d k; Øe@l Eesy u@d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

एनईएचयू, शिलांग, 16–20 जून, 2014 के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कॉलेज प्रिंसिपलों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम समन्वित

''उच्च शिक्षा के निजीकरण'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कार्यक्रम समन्वय 15–18 दिसम्बर, 2014 न्यूपा

''अभिशासन और स्वायत्तता'' राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया 19–21 दिसम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

''उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम', राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया 12–14 जनवरी, 2015 न्यूपा, नई दिल्ली

' kS{kd v kS O; kol kf; d l g; kx

i ; Z{k.k@ eW; kad u %

आईडेपा कार्यक्रम के लिए 'माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों के प्रदर्शन पर प्राचार्य के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर अध्ययन'' –एम जैरी, फिलीपींस के शोध–निबंध का पर्यवेक्षण

एम इंदिरा देवी के शोध प्रबंध कार्य का मूल्यांकन; पी. जी. डेपा कार्यक्रम के लिए; 'मणिपुर के डाईट संकायों के क्षमता निर्माण आकलन की आवश्यकता

d kS Zl e Ub; %

समन्वयक, कोर्स 201: आईडेपा के लिए विषयगत संगोष्ठी

f' k{k.k %

आईडेपा के लिए पाठ्यक्रम 212–अनुसंधान क्रियाविधि और सांख्यिकी का संचालन

पी.जी. डेपा के लिए भागीदार संगोष्ठीः पाठ्यक्रम 906 का संचालन

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (नवाचार–संगठनों का अधिगम केंद्र) कोर्स–106 का संचालन

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षिक सहायता

समन्वयन और (भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) 'विश्वविद्यालय न्यूज' के 'उच्च शिक्षा में स्वायत्तता' पर (19–25 जनवरी, 2015) के विशेष अंक में योगदान दिया

मणिपुर और उत्तराखंड की 2014–15 की आरएमएसए योजना का मूल्यांकन

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्य, नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिक्षा समिति, शिलांग

सदस्य, पूर्वोत्तर भारत ए शिक्षा समिति, शिलांग की कार्यकारी समिति

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक शिक्षा समिति

आजीवन सदस्य, तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय ए शिक्षा समिति

' kSf{kd Ácaáku lpyuk Á.kkyh foHkkx

ई.एम.आई.एस. विभाग, अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त प्रकाशनों को प्रकाशित करने के साथ–साथ कार्यक्रमों का आयोजन और विस्तृत रूप में अपनी वेबसाइटों को अद्यतन बनाए रखने में संलग्न रहा

çdk'ku

भारत में प्राथमिक शिक्षाः यूईई की दिशा में प्रगतिः डाईस फ्लैश सांख्यिकी (मुद्रित)

ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षाः विश्लेषणात्मक तालिकाएं

शहरी भारत में प्राथमिक शिक्षाः विश्लेषणात्मक तालिकाएं

भारत में प्राथमिक शिक्षाः हम कहाँ खड़े हैं? जिला रिपोर्ट कार्ड, जिल्द–1

भारत में प्राथमिक शिक्षाः हम कहाँ खड़े हैं? जिला रिपोर्ट कार्ड, जिल्द–2

भारत में प्राथमिक शिक्षाः हम कहाँ खड़े हैं? राज्य रिपोर्ट कार्ड

भारत में प्राथमिक शिक्षाः यूईई की दिशा में प्रगति, विश्लेषणात्मक तालिकाएं

भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रवृत्ति, यू–डाईसः 2005–2006 से 2013–14

डाईस आंकड़ों के आधार पर विषयगत नक्शेः भारत में प्राथमिक शिक्षा

भारत में प्राथमिक शिक्षाः एक ग्राफिक प्रस्तुति

भारत में माध्यमिक शिक्षाः एक ग्राफिक प्रस्तुति

भारत में माध्यमिक शिक्षाः यू–डाईस फ्लैश सांख्यिकीः यूईई की दिशा में प्रगति

भारत में माध्यमिक शिक्षाः हम कहाँ खड़े हैं? राज्य रिपोर्ट कार्ड

osc l kbVksa d k v è; ; u

x g d k; Z@ v | r u @ v i u s e kS wk osc l kbVksa d ks v | r u cu ku k

www.dise.in

www.schoolreportcards.in

www.semisonline.net

डाईस आंकड़ों के आधार पर प्रकाशनों के अलावा, विद्यालय विशिष्ट 2013–14 की जानकारी वेबसाइटों पर अपलोड की गई, दुनियाभर में उपयोगकर्ताओं के द्वारा इसका सालाना अध्ययन किया जा रहा है।

i k; kft r i fj ; kst u k

वर्ष 2002 के बाद से यूनिसेफ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित, दीर्घकालिक परियोजना ‘‘शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली प्रबंधन’’ (डाईस), वर्ष के दौरान यू–डाईस के तहत प्राप्त जानकारी को आधिकारिक सांख्यिकी का दर्जा प्राप्त हुआ

v # . k l h- e g r k ¼fo Hkkx kè; {k½

l a ks'Bh@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

‘प्रगतिशील संकेतकः मुद्दे, संभावनाएं तथा परिप्रेक्ष्य, शिक्षा में बदलाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषणः एसआरएम विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, 9 मई 2014

यू–डाईस, इंडिया हैबिटेट सेंटर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्यशाला में मुख्य भाषण, 30 जून, 2014 नई दिल्ली

डी.ई.ओ. व बी.ई.ओ. हरियाणा, कुरुक्षेत्र, के सम्मेलन में भाग लिया और शैक्षिक योजना, आंकड़ा और एमआईएस की भूमिका पर एक प्रस्तुति, 3 जनवरी, 2015

यू–डाईस डेटा विश्लेषण, मा.सं.वि. मंत्रालय– प्रायोजित कार्यशाला में भाषण, गुवाहाटी, 19–20 जनवरी, 2015

यू–डाईस डेटा विश्लेषण, मा.सं.वि. मंत्रालय– प्रायोजित कार्यशाला में भाषण, भुवनेश्वर, 23–24 जनवरी, 2015

उप–शिक्षा अधिकारी के पूर्व इंडक्शन कार्यक्रम में एमआईएस और डेटा विश्लेषण पर प्रस्तुती, सीमेट उत्तराखंड, देहरादून, 12–13 फरवरी, 2015

‘प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की शिक्षा’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र की अध्यक्षता की, सीमेट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, 18 फरवरी, 2015

c kg j h O; k[; ku

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, 20 मई, 2014 में पी.एस.एस.एल.एम. जिला परियोजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ई.एम.आई.एस., ई.डी.आई. और यू–डाईस पर व्याख्यान दिया

एमआईएस और यू–डाईस पर व्याख्यान, जिला एमआईएस और योजना कार्मिक, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, 18 जून, 2014 को राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

çf' k{k.k d k; ZØe @ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

शैक्षिक सूचकांक पर विशेषज्ञों की कार्यशाला (श्री ए.एन. रेड्डी के साथ) 30 जुलाई, 2014

यू–डाईस पर तकनीकी कार्यशाला, अगस्त 7 एवं 8, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली

गुजरात के जिला स्तर एमआईएस अधिकारियों के साथः ‘2014–15 यू–डाईस का शुभारंभ’ वीडियो सम्मेलन 30 अगस्त, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली

‘2014–15– प्रबंधन और तकनीकी मुद्दे यू–डीआईएसई’, यू–ट्यूब के माध्यम से सीधा कार्यक्रम आयोजित किया, 9 सितंबर, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली

माध्यमिक शिक्षा, पर पश्चिमी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (श्री ए.एन. रेड्डी के साथ) 15—19 दिसम्बर, 2014, गांधीनगर

2015 के बाद का शिक्षा एजेंडा, (श्री ए.एन. रेड्डी के साथ) पर एक—दिवसीय बैठक, 9 जनवरी, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBî Øe fodflr vkSj fu'ikfnr

शिक्षा में सार्वजनिक नीति में प्रशिक्षण कार्यक्रम: 'नीति निर्माण में डेटा के उपयोग के सबूतों के प्रकार' पर व्याख्यान दिया, 11 नवंबर, 2014, न्यूपा, नई दिल्ली

यू—डाईस का परिचय: मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु, 8 जनवरी 2015

आईडेपा, जनसंख्या के अनुमानों का परिचय, 20 मार्च, 2015, न्यूपा, नई दिल्ली

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

i;Zos{k.k@ekxZn'kZu %

जम्मू एवं कश्मीर, मई 2014, आईसीटी पर डेपा प्रतिभागी को मार्गदर्शन

f'k{k.k %

ईएमआईएस पर पाठ्यक्रम का आयोजन किया, न्यूपा, नई दिल्ली, आईडेपा और ईएमआईएस एवं संबंधित क्षेत्रों पर विभिन्न सत्र, मार्च 2015

vU; xfrfofèk;ka

माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 2013—14: फ्लैश सांख्यिकी के लोकार्पण हेतु समन्वयन, 17 जून, 2014

30 सितंबर, 2014 को एक महत्वपूर्ण पैमाने पर देशभर में यू—डाईस दिवस मनाने के लिए सुविधाकर्त्ता

विद्यालय मानक और मूल्यांकन, 10 जनवरी, 2015 को संसाधन बढ़ाने पर कार्य समूह, राष्ट्रीय सलाहकार बैठक की अध्यक्षता

आरएमएसए के संयुक्त समीक्षा मिशन में यू—डाईस का विवरण प्रस्तुत, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 27 जनवरी 2015

ई.एम.आई.एस. विभाग की, 13 मार्च, 2015 को विभागीय सलाहकार बोर्ड की वार्षिक बैठक बुलाई

वार्षिक संकाय निवर्तन में भाग लिया सूरजकुंड, हरियाणा, 16—17 मार्च, 2015

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यू—डाईस के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए भ्रमण: 2014—15

पुडुचेरी, 09—10 जून, 2014

चेन्नई (तमिलनाडु), 14—23 सितम्बर, 2014

गांधीनगर (गुजरात), 30 सितंबर व 1 अक्टूबर 2014

हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़, 09—10 अक्टूबर, 2014

अगरतला (त्रिपुरा), 26—28 अक्टूबर, 2014

उत्तर प्रदेश: नोएडा (3 नवंबर 2014) और गाजियाबाद (19 नवंबर 2014)

पटना (बिहार), 10—12 नवम्बर, 2014

भुवनेश्वर (ओडिशा), 26—28 नवम्बर, 2014

हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और तेलंगाना, 08—10 दिसम्बर, 2014

बंगलौर (कर्नाटक), 29—30 दिसम्बर, 2014

सिलवासा (दादरा और नगर हवेली) और दमन (दमन और दीव), 12—14 जनवरी, 2015

हरियाणा: सोहना (16—17 जनवरी, 2015), गुड़गांव (25 फरवरी, 2015) और फरीदाबाद, (1 दिसंबर, 2014)

आइजोल (मिजोरम), 09—11 मार्च, 2015

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kS{kd lgk;rk

खंड शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, 16—18 अक्टूबर, 2014 को चुनने के लिए सदस्यीय समिति ।

टाइम्स ऑफ इंडिया सामाजिक प्रभाव पुरस्कार 2014 में विशेषज्ञ

सक्रिय रूप से आरएमएसए तकनीकी सहयोग एजेंसी (डीएफआईडी, नई दिल्ली), एनसीईआरटी, नई दिल्ली के साथ संलग्नता

, -, u - j ṡ h

v u ḋq akku v è; ; u

i wkZv è; ; u

(प्रो. ए.सी. मेहता के साथ) प्राथमिक शिक्षा पर डाईस डेटा का उपयोग पर अनुसंधान कार्यक्रम समन्वित

t kj h

स्कूल शिक्षा के लिए स्थानिक सूचना प्रणाली– एक पायलट परियोजना विकसित

ç d k' ku

एजुकेशन सिचुएशन आफ एसटीज़ इन इंडिया (विद प्रो. विमला रामचन्द्रन, नेशनल ट्राइबल हूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी

सेकण्डरी एजुकेशन इन महाराष्ट्रः क्रिटिकल रिव्यू आफ स्टेटस एंड इमरजिंग इश्यू

एजुकेशन एंड स्किल इन रूरल इंडियाः स्टेटस एंड प्रासपैक्टस (मिमियो)

l a kś'B h@ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की एक क्षेत्रीय परामर्श बैठक में भाग लिया, 16–17 सितंबर, 2014, भुवनेश्वर

यूएनडीपी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय मानव विकास रिपोर्ट पर कई परामर्श बैठकों में भाग लिया।

ç f' k{k. k d k; Øe @ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

प्राथमिक शिक्षा पर डाईस डेटा का उपयोग अनुसंधान कार्यक्रम के लिए चयनित शोधकर्ताओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला (1 जुलाई, 2014)

शिक्षा विकास सूचकांक पर कार्यशाला, 30 जुलाई, 2014

स्कूल के बाहर के बच्चों पर तकनीकी परामर्श, यूनिसेफ के सहयोग से 29 अगस्त, 2014

माध्यमिक शिक्षा की निगरानी और योजना में संकेतकों के प्रयोग, गांधीनगर, गुजरात, में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15–19 दिसम्बर, 2014

पोस्ट–2015 शैक्षिक संकेतकों पर राष्ट्रीय परामर्श, 9 जनवरी 2015

v U; ' kSkf. kd v kS i śkoj ; ksx n ku

i ; Z{k. k@ e ¥; kad u %

आईडेपा भागीदार के शोध प्रबंध कार्य निर्देशित और मूल्यांकन

f' k{k. k %

एम.फिल./पीएच.डी. शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ओसी–5) पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम का संचालन

संयोजक, पाठ्यक्रम सं. 206ः आईडेपा के भाग के रूप में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग

v U; x fr fo fèk; ka %

यू–डाईस के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए की पीएबी की बैठक भाग लिया, 17 अप्रैल 2014

सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए के जे.आर.एम. के सम्मुख प्रस्तुति

आरएमएसए टीसीए से संबंधित कई बैठकों में भाग लिया

' kS{ kd Áf' k{k.k , oa{ ke r k fod kl fo Hkkx

u t e k v [r j ¼fo Hkkx kè; {k½

v u q èkku v è; ; u

अपने व्यवसाय पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विधि और सामुदायिक कालेजों के उत्तीर्ण छात्रों की सफलता का अध्ययन करने के लिए कैलिफोर्निया सामुदायिक कॉलेज विश्वविद्यालय (यूएसए) द्वारा आमंत्रित किया

l a k'Bh@l Ee sy u@d k; Z kky kv ka e sa Hkkx hn kj h

''उच्च शिक्षा और सतत विकास में लैंगिगः एक भारतीय अनुभव'' पर ई–प्रस्तुति के लिए स्वीकार, संयुक्त रूप से लोरनटियन विश्वविद्यालय, कानून में अंतःविषय अनुसंधान के लिए' इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रस्तुत सतत विकास पर 2014 (कनाडा) में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; सामाजिक न्याय और नीति में अनुसंधान लोरनटियन विश्वविद्यालय, कनाडा में ओंटारियो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और निष्पादित

नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के निदेशक के रूप में, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, 2014–15 में पृष्ठभूमि आलेख को अंतिम रूप दिया और लगातार हैंडबुक, पुस्तिका, पठन सामग्री आदि के विकास में ऑनलाइन सहायता प्रदान की

प्रशिक्षण रूपरेखा, मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रबंधित स्कूलों के प्रमुखों के लिए संस्था निर्माण के लिए पढ़ने हेतु सामग्री

सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में नेतृत्व पर दो प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण रूपरेखा और सामग्री

स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए अनुभव उपकरण साझा किए उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थागत प्रमुखों के लिए अनुभव प्रोफार्मा साझा किए

डीईओ और बीईओ के मूल्यांकन के लिये उपकरण प्रशिक्षण की आवश्यकता

v U; ' kS{ kd v kS Q ko l kf; d ; kx n ku

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में 30वां इंटरनेशनल डिप्लोमा कार्यक्रम, आईडेपा, 1 फरवरी – 30 अप्रैल, 2014

l koZ fu d fu d k; ka d ks i j ke' kZ v kS ' kS{ kd l g k; r k

शिक्षा का स्कूल विश्वविद्यालय, जी.जी.एस. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, के 18वें बीओएस बैठक में भाग लिया, 2 अप्रैल, 2014 नई दिल्ली

विशाखापत्तनम, 15–16 अप्रैल, 2014 को आंध्र विश्वविद्यालय के स्वायत्त कॉलेज की स्वायत्तता देने के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए यूजीसी संयुक्त विशेषज्ञ समिति में भाग लिया

आईसीएआर इंस्टीट्यूशन हैदराबाद, 24 अप्रैल, 2014 एनएएआरएम (कृषि अनुसंधान प्रबंधन की राष्ट्रीय अकादमी) की आरएसी बैठक में भाग लिया

शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, 8 मई, 2014 की संकाय समिति की बैठक में भाग लिया

एनडीएमए द्वारा विकसित शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर शैक्षिक मॉड्यूल के लिए योगदान दिया

राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की परामर्शदात्री बैठक में योगदान और भाग लिया

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

जेएसएस लॉ कॉलेज, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यूजीसी द्वारा नामांकित (मैसूर विश्वविद्यालय)

भारती विद्यापीठ, मानद विश्वविद्यालय, योजना एवं अनुश्रवण बोर्ड के लिए यूजीसी द्वारा नामित, पुणे

जामिया मिलिया इस्लामिया की कार्यकारी परिषद में आगंतुक नामिनी

सदस्य, शासी निकाय, वायु सेना केन्द्रीय विद्यालय

सदस्य, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति, एन.सी.ई.आर.टी.

स्वायत्त प्रबंधन कॉलेज—गीतम पर यूजीसी प्रतिनिधि (आंध्र प्रदेश)

सदस्य, कार्यकारी समिति, कोबसे

मानद सदस्य, अल्पसंख्यक बालिका शिक्षा के मुद्दों का समर्थन करने के लिए विशेष जनादेश के साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग

शिक्षा के संकाय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति पर आगंतुक नामिनी, दिल्ली विश्वविद्यालय (नॉर्थ कैंपस)

सदस्य, यूजीसी गठित विशेषज्ञ समिति महाराजा कॉलेज, विजयनगरम, आंध्र विश्वविद्यालय के लिए स्वायत्त स्थिति के विस्तार के लिए प्रदर्शन और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु

सदस्य, इंदौर विश्वविद्यालय, इंदौर के अकादमिक स्टाफ कॉलेज की सलाहकार समिति

सदस्य, अध्ययन बोर्ड, जी.जी.एस. इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

सदस्य, जी.आई.ई.टी. के लिए केवीएस सलाहकार समिति

सदस्य, संपादकीय बोर्ड, मैनपावर जर्नल वाल्यूम ग्प्टए ट८ अंक—3 एप्लाइड मैनपावर रिसर्च इंस्टीट्यूट

सदस्य, आदर्श आचार संहिता समिति

सदस्य, डीपीएस एजुकेशनल सोसायटी

सदस्य, यूजीसी गठित विशेषज्ञ समिति एमईएस ममपैड कॉलेज, मलप्पुरम, केरल को स्वायत्त स्थिति के विस्तार के लिए प्रदर्शन और शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए

सदस्य, डीपीएस सीतापुर, हाथरस, अलीगढ़, राजनगर गाजियाबाद आदि के प्रबंधन बोर्ड

सदस्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुड़गांव के वायएमसीए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद

l for k d kSky

ç d k'ku

i qLr d sa@ v è; k; %

''मेकिंग आरटीई इफैक्टिवः वे फारवर्ड थ्रू कॉमन स्कूल सिस्टम'' बुक टाइटल कॉमन स्कूल सिस्टम एंड राइट टू एजुकेशन, पटना विश्वविद्यालय, पेरियार प्रकाशन, ISBN 978—81—921872—9—7 द्वारा प्रकाशित

''राईट टू एजुकेशन एक्ट'' एंड ''कम्यूनिटी पार्टीसिपेन्ट'' सेल्फ इन्स्ट्रक्शनल मैनुअल आन ''स्कूल आर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फार स्कूल प्रिंसिपल्स', दो अध्याय, डाइट, कड़कड़डूमा, ॅैठछ 978—81—929615—1—4, 2014 द्वारा प्रकाशित

' kksèk i = @ y s[k@ u kSV~ %

आलेख शीर्षक ''केस स्टडी ऑफ मिरामबिकाः ए चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच टू प्री—स्कूल एजुकेशन'', द प्राइमरी टीचर, जुलाई—अक्टूबर 2012 वाल्यूम XXXIX, अंक—1 और 2 (जनवरी और अप्रैल 2014), ISBN 0970—9282

''विद्यालय नेतृत्व क्षमता का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव'', परिप्रेक्ष्य 2013। वर्ष 20, वाल्यूम 3 (दिसंबर 2013), न्यूपा

शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारीः नीति के परिप्रेक्ष्य और प्रावधान, जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन, नवंबर 2014

''आईआईटी नर्सरी स्कूल, दिल्ली की केस स्टडीः प्री—स्कूली शिक्षा के लिए एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में'' राष्ट्रीय शैक्षिक सेमीनार, डाइट, भागलपुर, द्वारा प्रकाशित, मार्च 2015

l a ks'Bh@ l Ee sy u@ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), द्वारा आयोजित ''बचपन की देखभाल और शिक्षा, द्वि—वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम'', पर अध्याय लेखकों की अभिविन्यास कार्यशाला में 23 मई 2014 को आयोजित

''बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए जागरूकता सृजन'' एनसीईआरटी, द्वारा आयोजित कार्यशाला में 13 से 16 जून, 2014 को भाग लिया

समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में, ''बचपन की देखभाल और शिक्षा'' 18 अक्टूबर, 2014 को द्वि–वर्षीय कार्यक्रम के पाठों की समीक्षा करने के लिए एनआईओएस द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया

''प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार'' पर अनुवर्ती कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता की, 10–14 नवम्बर, 2014

शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में नवाचार के लिए पुरस्कार की राष्ट्रीय योजना के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और एक सत्र के लिए रिपोर्टर के रूप में काम किया, 28–29 नवम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

''स्कूल के मानकों और मूल्यांकन'' पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में भाग लिया और ''शिक्षार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास'', विषय पर समूह की सदस्या, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2015

''दिल्ली में शिक्षाः उपेक्षा, विविधता और स्कूलों'' पर सम्मेलन, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 18–20 मार्च, 2015 को आयोजित

न्यूपा, 25–27 मार्च, 2015 तक आयोजित ''वंचित वर्ग की शिक्षा'', पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला और 26 मार्च, 2015 को एक सत्र में रिपोर्टर के रूप में काम किया

varjkZVªh; %

''वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा का सार्वजनीकरण'', अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014 और एक सत्र में रिपोर्टर के रूप में काम

çf'k{k.k dk;ZØe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;ksftr dk vk;kstu

शैक्षिक योजना और प्रशासन में ररप्ट डिप्लोमा कार्यक्रम के तहत पूर्व परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्यशाला समन्वित (चरण–तृतीय), न्यूपा, 05–09 मई, 2014

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodfl r vkSj fu'ikfnr

समन्वयकों के रूप में और एम.फिल कार्यक्रम के विकास के लिए टीम के सदस्य के रूप में, दो वैकल्पिक पाठ्यक्रम 'स्वास्थ्य, पोषण और स्कूली शिक्षा ओ.सी.–13 कार्यक्रम' और 'बचपन की देखभाल और शिक्षा (ओ.सी.–6) पर पाठ्यक्रम

सदस्य, पी.जी.डी.ई.पी.ए. कार्यक्रम के विकास के लिए दल

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

i;Z{k.k@ekxZn'kZu %

पी–एच.डी. भागीदार के लिये मार्गदर्शन ''स्थिति, मुद्दे और सरोकार; असम में एससीईआरटी शीर्षक से शोध अध्ययन पर अजंता ब्रह्मा (असम), को मार्गदर्शन

'एससीईआरटी, कोहिमा, नागालैंड में 'सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन' शीर्षक से शोध अध्ययन पर पी.जी.डी.ई.पी.ए. भागीदार, थेवी यूसुफ (नागालैंड), के लिए मार्गदर्शन

''विज्ञान विषय में छात्रों की उपलब्धि पर बहु शिक्षण रणनीतियों के प्रभाव पर एक अध्ययन'' शीर्षक से शोध अध्ययन और स्कूल नेतृत्व में पीजी डिप्लोमा और प्रबंधन में भागीदार, श्री संदीप कुमार, को मार्गदर्शन

आईडेपा शोध प्रबंध के लिए मार्गदर्शन 'प्रशिक्षण की जरूरत और नोम पेन्ह कैपिटल, कंबोडिया में सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रशासकों की चुनौतियाँ (स्कूल प्रशासन) पर एक अध्ययन' शीर्षक से शोध अध्ययन पर, सुश्री सूक सोफ़ाल को मार्गदर्शन

ikB;Øe leUo; %

कार्यक्रम दल के सदस्यों के साथ–साथ, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, 2014–15 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में पृष्ठभूमि आलेख, पुस्तिका, ब्रोशर, पठन सामग्री और कार्यक्रम रिपोर्ट का समन्वय

सदस्य, सीसी2 पर एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य समूहः भारतीय शिक्षा को समझना

f' k{k.k %

संकाय सहयोगी और संसाधन व्यक्ति पीजीडेपा का कोर्स कोड 901 (शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में मूल बातें)

आयोजित किए, पीजीडेपा का कोर्स कोड 901 के सात सत्र (शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में मूल बातें)

पीजीडेपा का कोर्स कोड 905 (परियोजना का काम और लेखन) के लिए संयोजक और संकाय, पाठ्यक्रम के 13 सत्र आयोजित

संसाधन व्यकित, पीजीडेपा और पाठ्यक्रम के लिए तीन सत्रों का आयोजन किया, कोर्स कोड 902 के लिए (एक परिप्रेक्ष्य; भारतीय शिक्षा)

'सामग्री योगदान के अलावा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विषयों का विकासः स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर पीजी डिप्लोमा के लिए संसाधन व्यक्ति, पांच सत्रों का आयोजन किया

दो सत्रों में पीजीडेपा कोर्स कोड 902 –'बचपन की देखभाल और शिक्षा' एवं 'शिक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास' पर दूसरा सत्र

'आत्म विकास और संस्थागत परिवर्तन (कोर्स कोड 212) और 'प्रस्ताव लेखन' पर दूसरा सत्र, 3 मार्च, 2015

आईडेपा का अनुसंधान क्रियाविधि सत्र (कोर्स कोड 212), 23 मार्च 2015

v U; x fr fo fèk; ka %

सूरज कुंड, नई दिल्ली, 16–17 जनवरी, 2015 न्यूपा कर्मचारी निर्वतन में भाग लिया, और 'संकाय विकास' विषय पर रिपोर्टर के रूप में काम किया

l ko Z fu d fu d k; ka d ks i j ke ' kZ v k$ ' kS{ kd l g k; r k

बचपन की देखभाल और शिक्षा, पर व्यावहारिक मैनुअल के विकास के लिए बैठक में भाग लिया, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, 7 जुलाई, 2014 को दो वर्षीय कार्यक्रम के लिए

संसाधन व्यक्ति, डाइट, कड़कड़डूमा, 13 जनवरी, 2015 को ''उभरते हुए मुद्दों और आरटीई 2009 के संदर्भ में स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए चुनौतियों'' पर सत्र।

बीएड की शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ईएस361 में संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग, इग्नू, मार्च 3 और 4, 2015

सदस्य, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक अध्ययन के ग्रीनर जर्नल संपादकीय बोर्ड (http-gjournal-org) ISSN: 2354.225X.

e ku k l sn o ky

ç d k' ku

' kks/k i = @ y \$ k@ u kV\ %

''रोल ऑफ इंडियन थिएटर इन महाराष्ट्र फार रेजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनैस– केस स्टडी आफ टू प्लेज'', इनोवेटिव थॉट (इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल) वाल्यूम 1(5), (अप्रैल 2014): 5–13P ISSN 2321–5143 EISSN 2347–5722

''कैन कैपीसिटी बिल्डिंग इम्पावर द टीचर? एन इंट्रोस्पैक्शन'', एडुसर्च जर्नल आफ एजुकेशनल रिसर्च, वाल्यूम 5 (2) (अक्टूबर 2014): 7–14 ISSNL: 0976–1160

i qLr d @ y \$ k l e h{kk, ; %

रिव्यू आफ जगदीश लाल आजाद' बुक 'इवाल्यूशन आफ इंडियन एजुकेशन'' ग्यान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, जेपा में प्रकाशित, वाल्यूम XXIX, नंबर 1 (जनवरी 2015 पीपी 81–83)

l a k'Bh@l Ee sy u@d k; Z kky kv ka e s a Hkkx hn kj h

j k"Vh; %

न्यूपा, नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2014 ''डाईस आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान कार्यक्रम'' पर कार्यशाला में भाग लिया

''समुदाय सहयोग के माध्यम से शिक्षा में बदलाव'', न्यूपा, नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014 को संगोष्ठी में भाग लिया

''अनुसंधान शिक्षकों के काम की परिस्थितियों पर अध्ययन'', न्यूपा, नई दिल्ली, 01–03 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 30–31

अक्टूबर, 2014, के तत्वावधान में न्यूपा द्वारा आयोजित स्कूल के मानकों और मूल्यांकन, पर कार्यशाला में भाग लिया

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन, शैक्षिक प्रशासन विभाग (न्यूपा), विज्ञान भवन, 28–29 नवम्बर, 2014

समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भारतीय समाजशास्त्रीय सोसायटी एक्सएल (40वीं) विकास, विविधता और लोकतंत्र पर अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन में ''स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच भागीदारी का रुझान'' शीर्षक आलेख प्रस्तुत 29 नवंबर – 1 दिसंबर 2014

स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के तत्वावधान में न्यूपा द्वारा 10–11 फरवरी, 2015 इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित

नीतिगत सुधार और व्यवहार आचरण, लोगों की भागीदारी और विकेन्द्रीकृत शैक्षिक पर प्रशासन पर दूसरा अनिल बोर्डिया पॉलिसी संगोष्ठी, 16–17 फरवरी, 2015: न्यूपा, नई दिल्ली, में भाग लिया

उपेक्षा, विविधता और स्कूल, एयूडी सभागार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली 18–20 मार्च, 2015, दिल्ली में शिक्षा पर सम्मेलन में भाग लिया

v a j kZVªh; %

दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, द्वारा आयोजित, 16–18 नवम्बर, 2014 के भारत की तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, – ''एक समीक्षा; स्कूल शिक्षा में अनुसूचित जाति के बच्चों और शिक्षकों की भागीदारी'' पर शीर्षक से आलेख

होटल जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014 के दौरान ब्रिटिश काउंसिल, के सहयोग से उच्च शिक्षा में प्रगति अनसंधान केन्द्र (न्यूपा) द्वारा आयोजित 'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया

'नीति, अभ्यास और अनुसंधान; विद्यालय नेतृत्व' राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र (न्यूपा), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया

एन.सी.एस.एल. (न्यूपा) और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम, न्यूपा, नई दिल्ली, 12–13 फरवरी, 2015 तक संयुक्त रूप से आयोजित स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व' पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, में भाग लिया

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए, न्यूपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''नीतियां कार्यक्रम और चुनौतियां; वंचित समूह की शिक्षा'' पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला। 25–27 मार्च, 2015 में भाग लिया

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu dk vk;kstu

समन्वयक, 30वें अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमा (न्यूपा), नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय में फरवरी–अप्रैल, 2014 (17 देशों से 27 प्रतिभागियों के साथ)

कार्यक्रम समन्वयक, इंडोनेशिया, के शिक्षकों को शिक्षा के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन, 14–25 नवम्बर, 2014

प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए कार्यक्रम समन्वयक, 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और महाराष्ट्र में अंग्रेजी माध्यम आवासीय स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए स्कूल विकास योजना' नासिक, महाराष्ट्र, 22–27 सितम्बर, 2014

हरियाणा के जिला एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए कार्यक्रम समन्वयक; डॉ एस राधाकृष्णन सदन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, 03–04 जनवरी, 2015

एससीईआरटी, गुवाहाटी, असम, 06–11 जनवरी, 2015 के दौरान असम शिक्षा सेवा से नव नियुक्त अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशासन कार्यक्रम के लिए समन्वयक

गुवाहाटी, 21–22 जनवरी, 2015 के दौरान असम के जिला एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य सम्मेलन के लिए कार्यक्रम समन्वयक

पंजाब, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सभागार, मोहाली, पंजाब, 28–29 जनवरी, 2015 के दौरान जिला एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर राज्य सम्मेलन के लिए कार्यक्रम समन्वयक

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (आईडेपा), न्यूपा, नई दिल्ली, फरवरी में 31वें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के लिए कार्यक्रम समन्वयक फरवरी–अप्रैल, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

प्रशिक्षण मॉड्यूल 'आश्रम स्कूल प्रमुखों की भूमिका' प्रो बी.के. पांडा के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया अगस्त 2014

विभाग और संकाय सदस्यों के साथ शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (पीजीडेपा) में कार्यक्रम संचालन, संकल्पना और तैयारी, सितंबर, 2014

vU; 'kS{kf.kd vkSj iš'ksoj ;kxnku

सबके लिए शिक्षा समीक्षा रिपोर्ट पर (प्रो. के. रामचन्द्रन द्वारा समन्वित) राष्ट्रीय परामर्श बैठक, 20 जून, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

रूटलेज, एन इम्प्रिन्ट आफ टेलर एंड फ्रांसिस बुक्स, जनवरी 2015 पुस्तक का प्रस्ताव समीक्षित

भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों पर अध्ययन पर अंतर्दृष्टि साझा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 20 मार्च 2015 (अध्ययन विश्व बैंक के साथ शिक्षक प्रबंधन और विकास पर पीठ के तत्वावधान में राजीव गांधी फाउंडेशन की वित्तीय सहायता के साथ किया गया; एक तकनीकी भागीदार के रूप में इसके साथ जुड़े (नई दिल्ली)

भारतीय उच्च शिक्षा, सी.पी.आर.एच.ई. (न्यूपा), नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015 को शिक्षण और प्रशिक्षण पर एक परियोजना के लिए डेटा संग्रह के लिए उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक में भाग लिया

2015 के बाद का शिक्षा एजेंडा के लिए चुनौतियां और प्राथमिकताएं, न्यूपा और यूनेस्को द्वारा आयोजित भारत में सभी के लिए शिक्षा पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर) और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, 2015–शिक्षा का शुभारंभ

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kS{kd lgk;rk

समीक्षा, (टीओटी) मॉड्यूल एनआईडीएम (आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) की क्षमता निर्माण के अध्ययन के तहत तैयार ('ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति के निर्माण पर शिक्षकों के लिए टी.ओ.टी. मॉड्यूल' शीर्षक से), नई दिल्ली, अप्रैल, 2014।

शैक्षिक वीडियो व्याख्यान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अकादमिक जानकारी और सुझाव शैक्षिक संचार (सीईसी), नई दिल्ली 11 दिसंबर 2014, 23 फरवरी 2015 से 3 मार्च 2015 के दौरान कंसोर्टियम के लिए आयोजित पूर्वावलोकन बैठक।

आईटीआई प्रधानाध्यापकों के लिए छह दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शिक्षण विधियों पर कई सत्रों में भागीदारी आईआईएफटी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश, मई से जून 2014।

U;wkl scksMZ ds ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी, जेएनयू, नई दिल्ली।

आजीवन सदस्य, शैक्षिक अनुसंधान के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन, भुवनेश्वर।

आजीवन सदस्य, भारतीय सामाजिक सोसायटी (आईएसएस), नई दिल्ली।

jk"Vªh; fo|ky; usr`Ro dsUnz

jf'e nhoku ¼foHkkxkè;{k½

çdk'ku iqLrdsa@vè;k; %

''एडल्ट लिट्रेसी, एजुकेशन एंड लाईफलांग लर्निंग: टूवार्ड सस्टेन्ड् डवलपमेंट आफ ऑल'' इन ''एजुकेशन एज ए राईट एक्रास द लेवल: चैलेंज, अपरच्युनिटी एंड स्ट्रेटेजी', विभा बुक्स, 2014. पीपी 218–231

'kksèk i=@ys[k@uksV+ %

''स्माल स्कूल इन रूरल इंडिया: 'एक्सक्लूजन' एड 'इनइक्विटी' इन हिरारचिकल स्कूल सिस्टम'', पॉलिसी फ्यूचर इन एजुकेशन (स्पेशल इश्यू: इंडियन एजुकेशन एट द क्रासरोड आफ पोस्टकोलोनिलिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड द 21 सेंचुरी नॉलेज इकोनॉमी–पार्ट1), अतिथि संपादक मौसमी मुखर्जी, सेज जर्नल (फरवरी 2015), 13: 187–204, डीओई: 10.1177/1478210315579971

tkjh vuqlaèkku vè;;u %

स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियाँ और भूमिका: एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (संयुक्त रूप से डॉ कश्यपी अवस्थी के साथ)

çf'k{k.k dk;ZØe@lEesyu@dk;Z'kkyk,a

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन और समन्वयन; 'विद्यालय नेतृत्व: नीति, अभ्यास और अनुसंधान', आईएचसी, नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014

आलेख प्रस्तुत ''वयस्क साक्षरता, शिक्षा और आजीवन अधिगम निरंतर विकास की दिशा में सभी'', अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2014 (2014 आईईसी), जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 10–11 मार्च, 2014

f'k{k.k lkexzh vkSj ikB~;Øe fodflr vkSj fu"ikfnr

एन.सी.एस.एल. की टीम के भाग के रूप में, ''स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक माह के सर्टिफिकेट कोर्स'' का शुभारंभ किया और संकल्पना, 2014

एन.सी.एस.एल. की टीम के भाग के रूप में, ''स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा'' का शुभारंभ किया और संकल्पना, 2014

एन.सी.एस.एल. टीम द्वारा आयोजित सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में मार्गदर्शन, सहायता प्रदान की

''स्कूल नेतृत्व अवधारणा को समझना'' विद्यालय प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं में एक संसाधन के रूप में मॉड्यूल इस्तेमाल किया, न्यूपा

मॉड्यूल 'स्कूल विकास योजना की तैयारी के माध्यम से मार्गदर्शन: स्कूल प्रमुखों के लिए एक पुस्तिका (संयुक्त रूप से डा. बी.के. पांडा के साथ) स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया, न्यूपा

मॉड्यूल ''अधिगम बहु–ग्रेड स्कूल: मुख्य शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक गाइड'' विशिष्ट लक्ष्य समूह पर विशेष ध्यान देते हुए (संयुक्त रूप से डॉ मोना सेदवाल के साथ) स्कूल नेतृत्व विकास के भाग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूपा

पाठ्यचर्या की रूपरेखा और विद्यालय नेतृत्व विकास (2014) पर कार्यक्रम रूपरेखा, न्यूपा, नई दिल्ली (योगदानकर्ताओं में से एक)

विद्यालय नेतृत्व विकास (2014) पर एक पुस्तिका , न्यूपा, नई दिल्ली (योगदानकर्ताओं में से एक)

vU; 'kSf{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

i;Zos{k.k@eSaVfjax %

पर्यवेक्षण, सुश्री मीनू शर्मा को उनके अनुसंधान अध्ययन

''राजस्थान के अजमेर जिले में नव–साक्षरों के जीवन की गुणवत्ता के सुधार में प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका'' शीर्षक से।

पर्यवेक्षण, सुश्री रश्मि वाधवा को उनके अनुसंधान अध्ययन ''भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के निर्धारक''।

d ksZl eUo; %

कोर्स प्रभारी, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पर डेपा और आईडेपा कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम।

v U; x fr fo fèk; ka %

एन.सी.एस.एल. द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में मार्गदर्शन।

l koZ fu d fu d k; ka d ks i j ke' kZ v k\$ ' kS{ kd l gk; r k

विद्यालय नेतृत्व, विद्यालय विकास योजनाएं, संस्थागत योजना पर कई व्याख्यान सत्रों के लिए एससीईआरटी द्वारा संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित, एनसीईआरटी,

U; wk d s c kg j ç[; kr fu d k; ka d h l nL; r k

सदस्य, नेतृत्व कार्यक्रम और विद्यालय प्रबंधन पर परामर्शदात्री समिति, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली।

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

सदस्य, अनुसंधान सहायता समूह, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा गठित।

संस्थापक सदस्य डॉ एस राधाकृष्णन मॉडल स्कूल की स्थापना के लिए, स्कूल शिक्षा, हरियाणा बोर्ड द्वारा गठित, डॉ एस राधाकृष्णन शिक्षा समिति, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव रणनीतियों और तरीकों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला विद्यालय के रूप में काम करने हेतु।

आजीवन सदस्य, भारतीय शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक संघ, नई दिल्ली।

आजीवन सदस्य, राष्ट्रमंडल शैक्षणिक प्रशासक परिषद, नई दिल्ली।

l quhr k p qk

ç d k' ku

i qLr d s@ v è; k; %

''एलिमेंन्ट्री एजुकेशन इन इंडियाः प्रोग्रेस पर्सपैक्टिव'' पर अध्याय (सह लेखक) डा. मुखोपाध्याय और एम. पारहर (सं.) इंडियन एजुकेशनः ए डवलपमेंट डिस्कोर्स (जनवरी 2015), शिप्रा प्रकाशन।

यूनिट ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इंडिया, एनआईओएस मॉड्यूल नवम्बर 2014 करीकुलम फ्रेमवर्क एंड प्रोग्राम डिजाईन आन स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट (2014); न्यूपा, नई दिल्ली (एक योगदानकर्त्ता)।

हैण्ड बुक ऑन स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट (2014); न्यूपा, नई दिल्ली (एक योगदानकर्ता)।

' kksèk i = @ y \$ k@ u kS\/ %

सिविल स्ट्रिफ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रनः स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफैक्टेड बाई लैफ्ट विंग एक्स्ट्रेमाइज, जर्नल ऑफ इंडिनयन एजुकेशन, वॉल्यूम XXXX नं. 1 (मई 2014), एनसीईआरटी,

v u q aèkku v è; ; u

t kjh %

भारत में शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी पर महत्वपूर्ण मूल्यांकन का अध्ययन।

l a kS'B h@ l Ee y u @ d k; Z'kky kv ka e sa Hkkx hn kj h

j k"Vªh; %

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 09–10 जुलाई, 2014 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में योजना और व्यापक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन' परः ''विद्यालय नेतृत्वः एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य'' पर प्रस्तुति।

2014 पुडुचेरी 23 जुलाई, स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श बैठक में भाग लिया।

बिहार में स्कूल नेतृत्व विकास पर राज्य परामर्श बैठक में भाग लिया, पटना, 3 सितंबर, 2014

महाराष्ट्र राज्य में स्कूल नेतृत्व विकास, परामर्श बैठक में भाग लिया 2014, मुंबई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा आयोजित ''बाहर के स्कूली बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए यूडीसी सिटी आधार योजना'', पर एक सम्मेलन में ''बाहर के–स्कूली बच्चों की गुणवत्ता की शिक्षा के लिए रणनीतियाँ'' पर प्रस्तुति 28–29 अक्टूबर, 2014।

v a j kZVªh; %

''विद्यालय नेतृत्वः नीति, परिप्रेक्ष्य और अनुसंधान'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''शहरी गरीब क्षेत्रों में अग्रणी स्कूलों'' पर आलेख, 17–18 नवम्बर, 2014. ''शैक्षिक नेतृत्वः भारतीय परिप्रेक्ष्य 'विषय पर एक प्रस्तुति; स्कूल शिक्षा में महिला नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, 12–13 फरवरी, 2015

çf' k{k.k d k;Øe@l Eesy u@d k; Zkky kv ka d k v k; kst u

''भारत में शहरी मलिन बस्तियों में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी का महत्वपूर्ण मूल्यांकन'' विषय पर अध्ययन के लिए ''अनुसंधान रूपरेखा उपकरण'' पर कार्यशाला आयोजित, नई दिल्ली, 29–30 सितम्बर, 2014

पंजाब में राज्य संसाधन समूह के विद्यालय नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यशाला में मदद और समन्वयन, 27 अक्टूबर–4 नवंबर 2014, लुधियाना।

छत्तीसगढ़ में राज्य संसाधन समूह के विद्यालय नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यशाला में मदद और समन्वयन, रायपुर, 22–28 दिसम्बर, 2014।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विद्यालय नेतृत्व पर कार्यशाला समन्वित और व्याख्यान, 09–10 जनवरी, 2015 दिल्ली।

v U; ' kS{ kd v kS j Q;kol kf; d ; kxnku

d kS Zl e Ub ; %

कोर्स 101 (तैयारी अभ्यास) और पाठ्यक्रम 107 (नेतृत्वकारी भागीदारी) और स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, 2014–15, स्नातकोत्तर डिप्लोमा में कार्य रूपरेखा और पाठ्यक्रम मूल्यांकन के साथ सत्र में भागीदारी।

f' k{k.k %

महत्वपूर्ण क्षेत्र 6 का सत्र शिक्षणः मुख्य क्षेत्र 5 के दो सत्रों के साथ स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर एक महीने का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम (''अभिनव के माध्यम से स्कूल पुनर्गठन'' और ''मान्यता और पुरस्कार'') 02–27 जून, 2014

दो सत्र आयोजित ''ग्रामीण शहरी शिक्षा में असमानता'', 20 अक्टूबर, 2014 और ''स्लम क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ शहरी क्षेत्रों में शिक्षा'' 10 दिसंबर, 2014 को डेपा कार्यक्रम में।

v U; x fr fo f/k;k a %

लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास शिक्षा'' ओडिशाः एक विशेषज्ञ के रूप में अध्ययन, 08–10 नवम्बर, 2014

सदस्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा और पाठ्यचर्या की रूपरेखा और संपादन दल, अंग्रेजी और हिंदी में स्कूल नेतृत्व विकास पर हस्तपुस्तिका (2014 नवंबर), न्यूपा, नई दिल्ली।

l koZ fu d fu d k; ka d ks i j ke ' kZ v kS j ' kS{ kd l gk; r k

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और टीएसजी के साथ समन्वय और समय–समय पर एन.सी.एस.एल. में विकास पर प्रस्तुतीकरण किया।

पीएबी बैठकों 2014–15 के दौरान चुनिंदा राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास के लिए भाग लिया।

U;wik d s ckgj ç[;kr fud k;ksa d h lnL;rk

सदस्य, बाहर के स्कूल के बच्चों पर समिति, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

सदस्य, संघर्ष क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर संचालन समिति यूनिसेफ

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी

आजीवन सदस्य, अध्यापक शिक्षा अखिल भारतीय संघ

d ';i h v oLFkh

çd k'ku

iqLrd @v è; k; %

ट्रांसलेटेड एंड एडीटेड कलीकुलुम फ्रेमवर्क एंड हैंडबुक ऑन स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट फॉर स्कूल हैड इन गुजराती।

l a ks'Bh@l Ee sy u@d k; Zkky k, a

jk'Vªh; %

'संस्थागत नियोजन और मूल्यांकन' पर राष्ट्रीय कार्यशाला में ''डाईट और एस.सी.ई.आर.टी. के लिए संस्थागत योजना और मूल्यांकन'' पर तीन सत्रों में संसाधन व्यक्ति, अगस्त 2014, एनसीईआरटी।

पैनल चर्चाकार, कल के स्कूलों का सम्मेलन ''बेहतर का दुश्मन क्या बड़ा है – गुणवत्ता को बनाए रखते हुए निजी स्कूल विकास के लिए क्या मांग का संतुलन कर सकते हैं?'' जेडब्ल्यू मैरियट होटल, एरोसिटी, नई दिल्ली, 22 अगस्त 2014

भाग लिया, उच्च शिक्षा में बदलते शैक्षणिक परिदृश्य पर गोलमेज सम्मेलनः क्या अकादमिक अच्छा पेशेवरों को आकर्षित करने में सक्षम है? इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए पेशेवरों को क्या प्रेरित करता है? कैसे शिक्षा जगत बदलती जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया करता है? प्रबंधन अध्ययन विभाग, आईआईटी दिल्ली, फरवरी 2015

आरटीई और मिड डे मील कार्यक्रम का कार्यान्वयनः शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन और गुजरात में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थिति पर वादे और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में आलेख, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उज्जैन, मार्च 25–26, 2015

v ar jk"Vªh; %

''नीति अभ्यास और अनुसंधानः स्कूल लीडरशिप', आईआईसी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (रश्मि दीवान और एंथोनी यूसुफ के साथ सह लेखक): ''छह राज्यों के विश्लेषण भूमिकाओं और स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियों'' पर आलेख प्रस्तुत 17–18 नवंबर, 2014 नई दिल्ली।

''उच्च गरीबी संदर्भों में प्रमुख स्कूल – सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक झुकाव'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में (तमो चट्टोपाध्याय के सह–लेखन में) 'स्कूल लीडरशिपः नीति अभ्यास और रिसर्च' आईआईसी, नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014

'स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व', न्यूपा, 12–13 फरवरी, 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में भाग लिया।

U;wik l s ckgj fn, x, O;k[;ku %

''स्कूलों में सुधार : शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका'' पर भाईकाका स्मृति व्याख्यान दिया, सरदार वल्लभ पटेल विश्वविद्यालय, विद्यानगर, गुजरात, 19 दिसंबर, 2014, शिक्षा विभाग

çf'k{k.k d k;Øe@l Ee sy u@d k; Zkky kvksa d k v k;kst u

शिक्षा विभाग, एमएस विश्वविद्यालय, बडौदा, गुजरात, 19–23 मई, 2014 के दौरान गुजराती में हैंडबुक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुवाद के लिए पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, 14–24 जुलाई, 2014 के दौरान राज्य संसाधन समूह के लिए दस दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 15–16 सितम्बर, 2014 'स्कूल नेतृत्व विकास के लिए योजना' पर तीसरे चरण के राज्यों के लिए दो दिन की परामर्शकारी बैठक का आयोजन।

गुजराती में पुस्तिका के अनुवाद और पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए छह दिवसीय कार्यशाला 21–26 सितम्बर, 2014 न्यूपा, नई दिल्ली

'नीति, अभ्यास और अनुसंधानः स्कूल लीडरशिप', अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, नवंबर 17–18, 2014

त्रिपुरा, अगरतला, 24 नवम्बर – 4 दिसम्बर, 2014 के दौरान राज्य संसाधन समूह के लिए दस दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम

गुजरात में राज्य संसाधन समूह के लिए दस दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम, शिक्षा विभाग, वल्लभ विद्यानगर, आणंद, 08–19 दिसम्बर, 2014, एमबी पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन

28 जनवरी से 6 फरवरी, 2015 के दौरान मिजोरम, आइजोल, जनवरी में राज्य संसाधन समूह के लिए दस दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

मेघालय में राज्य संसाधन समूह के लिए 10 दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में छह दिनों के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, 28 मार्च 2015।

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

सदस्य, 'शैक्षिक प्रशासन' पर कोर्स टीम, और स्कूल लीडरशिप पर इकाई पर सत्र का आयोजन।

सदस्य, स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विकास के लिए दल।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

i;Zs{k.k@ekxZn'ku%

मार्गदर्शन प्रदानः ''जिला रियासी का एक केस अध्ययन जम्मू–कश्मीर में रेहबर–ए–तालीम योजना भारत में शिक्षकों की स्थिति'' पर शोध अध्ययन के लिए, डेपा भागीदार, सुश्री जसविंदर कौर (जम्मू) का शोध प्रबंधन।

मार्गदर्शन प्रदानः आईडेपा भागीदार, सुश्री हाजेर हांची (ट्यूनीशिया) के शोध प्रबंध साउसी, ट्यूनीशिया के क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति''।

मार्गदर्शन प्रदान; आईडेपा भागीदार, सुश्री चो विन (म्यांमार) के शोध प्रबंध यांगून क्षेत्र, म्यांमार में प्राइमरी स्कूल में छात्रों के अधिगम पर स्कूल नेतृत्व के प्रभाव का एक अध्ययन''।

f'k{k.k%

विद्यालय नेतृत्व परिप्रेक्ष्य पर कोर्स 102 के संयोजक और कार्य रूपरेखा और पाठ्यक्रम मूल्यांकन के साथ–साथ 29 सत्रों में भागीदारी।

vU; xfrfofèk;ka%

गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर विभिन्न रिपोर्ट तैयार की।

वार्षिक समीक्षा और योजना कार्यशाला और विद्यालय नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए रिपोर्ट।

सार्वजनिक निकायों को शैक्षिक सहायता और परामर्श

सलाहकार सदस्य, हिमगिरी शिक्षा समीक्षा (HER) ISSN 2321–6336 का संपादकीय बोर्ड

,u- eSFkyh

çdk'ku

iqLrd sa@vè;k; %

नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एंड करीकुलम फ्रेमवर्क आन स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट (2014)ः न्यूपा, नई दिल्ली (एक योगदानकर्त्ता के रूप में)

ए हैंडबुक आन स्कूल लीडरशिप डवलपमेंट (2014)ः न्यूपा, नई दिल्ली (एक योगदानकर्त्ता के रूप में)

i qLrd @ y s k l eh{kk, a %

पॉल मिलर (2013): स्कूल लीडरशिप इन कैरीबियन कंट्रीज, यू.के. सिम्पोजियम बुक्स, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, के जर्नल में समीक्षा, भारत (अक्टूबर, 2014)।

l a k s'B h@ l Ee s y u @ d k; Z k k y k v k s a e s a H k k x h n k j h

j k'V ªh; %

''प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्कूल में भागीदारी पर सुधार'' विषय पर कार्यशाला में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर एक सत्र की अध्यक्षता, न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 सितम्बर, 2014

''शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक नीति बनाने पर अभिविन्यास कार्यक्रम'' शीर्षक कार्यशाला में ''नीतिगत विकल्पों का चयन'' सत्र का आयोजन, न्यूपा, नई दिल्ली, 17–22 नवम्बर, 2014

v a r j k Z V ªh; %

''स्कूल के नेतृत्व में महिला: भारतीय संदर्भ में महिलाओं के प्रमुखों की केस स्टडी'' भारत का तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी, 16–18 नवम्बर, 2014 के दौरान आयोजित ''शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन'', पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत शोध पत्र।

अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ''भारत में स्कूल नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व'' स्कूल नेतृत्व नीति, अभ्यास और अनुसंधान संयुक्त रूप से न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, 12–13 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित स्कूल शिक्षा में महिला नेतृत्व पर न्यूपा, में नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन।

ç f' k{k. k d k; Ø e @ l Ee s y u @ d k; Z k k y k, a

हैदराबाद, 27 जनवरी – 9 फरवरी 2015 के दौरान आंध्र प्रदेश में राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) की क्षमता निर्माण।

03–12 फरवरी, 2015 के दौरान हैदराबाद में तेलंगाना में एसआरजी का क्षमता निर्माण

न्यूपा, भारत और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन के लिए समन्वयक (यूके), 12–13 फरवरी, 2015।

मेघालय, शिलांग, 31 मार्च, 2015 में राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण।

v U; ' k S{ k d v k S j O ; k o l k f; d ; k s x n k u

d k s Z l e U o ; %

स्कूल नेतृत्व विकास पर ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में 'अग्रणी नवाचार' पर महत्वपूर्ण क्षेत्र 5 हेतु समन्वयक एवं सत्र सुगमकर्त्ता।

समन्वयन और स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन के पीजी डिप्लोमा में 'अग्रणी नवाचार' पर पाठ पढ़ाया, 07–27 मार्च, 2015

समन्वयक, शैक्षणिक वर्ष 2014–15 के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

v U; x fr fo f/k; k a %

स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम फ्रेमवर्क और पाठ्यचर्या की रूपरेखा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिये तेलुगु भाषा में अनुवाद, समन्वयन एंव आयोजन तथा 12–18 अगस्त, 2014 और 18–22 अक्टूबर, 2014 को अंतिम रूप देने के लिए दो सदस्यों के समूह द्वारा संपादन, दिसंबर 2014।

न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हेतु कार्यक्रम समन्वित , नई दिल्ली, 20 फरवरी 2015।

l qjHkFkk t h-o h-

l a k s'B h@ l Ee s y u @ d k; Z k k y k, a %

j k'V ªh; %

एन.सी.एस.एल.–न्यूपा, नई दिल्ली द्वारा 09–10 जनवरी, 2015 के दौरान आयोजित, 'दिल्ली स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व पर दो दिवसीय कार्यशाला

v a j kZV ªh; %

प्रस्तुत शोध पत्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, 16—18 नवंबर, 2014 के दौरान तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''परिवर्तनकारी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन'' शीर्षक से आलेख

''विद्यालय नेतृत्वः नीति, व्यवहार और अनुसंधान, पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ओडिशा तथा कनार्टक में विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम, न्यूपा, नई दिल्ली, 17—18 नवंबर, 2014

न्यूपा—एन.सी.एस.एल. द्वारा आयोजित विद्यालयी शिक्षा में महिला स्कूल नेतृत्व' पर अन्तर्राष्ट्रीय विचारमंच में भागीदारी, 12—15 फरवरी, 2015।

अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया , न्यूपा, नई दिल्ली, 25—27 मार्च, 2015 'उपेक्षित समूहों—नीतियों, कार्यक्रमों और चुनौतियों की शिक्षा' पर कार्यशाला।

çf' k{k.k k d k; Øe @ l Ee sy u @ l a fBr

समन्वयन, न्यूपा, 2—27 जून, 2014 के दौरान ''स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन'' पर एक महीने का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम।

धारवाड़, कर्नाटक में अनुवाद कार्यशालाएं समन्वित, 05—07 अगस्त, 2014 और 02—04 सितम्बर, 2014, दो चरणों में।

समन्वित, ओडिशा, 27—28 अगस्त, 2014 के दौरान स्कूल नेतृत्व पर परामर्श।

समन्वित, ओडिशा, भुवनेश्वर, 20—29 नवंबर, 2014 के दौरान क्षमता निर्माण पर कार्यशाला।

समन्वित, धारवाड़, कर्नाटक, 15—24 दिसम्बर, 2014 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

v U; ' kS{kd v kS Q; ko l kf; d ; kx n ku

f' k{k.k k %

''शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बदलाव पर पाठ्यक्रम, डेपा कार्यक्रम में''

''शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बदलाव'' पर पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर जून 2014 में एक महीने का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम।

''शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बदलाव पर पाठ्यक्रम, कार्यक्रम के रूप में ''स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम, 2014—15 ''शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बदलाव'' पर एक सत्र का आयोजन।

, sFkksu h t kst Q +

i fj ; kst uk l y kg d kj & o fj 'B

l a ks'Bh@ l Ee sy u @ d k; Zkky k v ksa e sa Hkkx hn kj h

j k"'Vªh; %

ए और ए अर्थशास्त्र विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर, 22—23 अगस्त, 2014 द्वारा आयोजित ''संयुक्त कार्रवाई के विश्लेषण के लिए स्व—चेतन मन की एजेंसीः सामूहिक और व्यावसायिक जिम्मेदारी'', पर आलेख प्रस्तुत किया।

एन.सी.एस.एल. एवं न्यूपा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 14 सितंबर 2014 के तीसरे चरण के लिए 14 राज्यों के लिये स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय परामर्श।

स्कूल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, हेतु राष्ट्रीय संसाधन समूह कार्यशाला एन.सी.एस.एल., न्यूपा, दिल्ली।

न्यूपा, 28 फरवरी, 2015 — एन.सी.एस.एल. पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक।

एन.सी.एस.एल., न्यूपा, 16 और 17 मार्च, 2015 — स्कूल नेतृत्व विकास, पर राष्ट्रीय समीक्षा और योजना कार्यशाला।

मुख्य संस्थानों के साथ स्कूल नेतृत्व विकास के सहयोग के लिए परामर्शकारी बैठक छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, 30 मार्च, 2015

varjkZVªh; %

प्रस्तुत आलेख शीर्षक ''प्रतिबिंबित शिक्षाशास्त्रः सामाजिक न्याय के लिए व्यावसायिक ज्ञान, अभ्यास और संबंध की ओर'' 'शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन' पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2014 में, भारत का तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी (सेसी), सम्मेलन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, 16–18 नवम्बर, 2014

एन.सी.एस.एल., न्यूपा, दिल्ली, 12 और 13 फरवरी, 2015 'स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व', पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में भाग लिया।

''स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएंः छह राज्यों का एक विश्लेषण'', शीर्षक पर आलेख प्रस्तुत, एन.सी.एस.एल., न्यूपा, आईआईसी, नई दिल्ली, 17 और 18 नवंबर, 2014

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Zkkyk vk;kstu

संसाधन व्यक्ति, प्रशिक्षण, त्रिपुरा (अगरतला, 23 नवम्बर – 6 दिसम्बर, 2014), मणिपुर में राज्य संसाधन समूह के लिए ''स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम'' पर क्षमता निर्माण कार्यशाला में शैक्षणिक सहायता (इम्फाल, 18–27 दिसम्बर, 2014) और मिजोरम (आइजोल, 26 जनवरी – 8 फरवरी, 2015)।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

शिक्षणः

शैक्षणिक वर्ष 2014–15 के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य – कोर्स 102 के सह–सुविधाकर्त्ता ।

U;wik dsckgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी

th-,l- usxh

ifj;kstuk lykgdkj & ofj'B

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Zkkyk vk;kstu

2014–15 के दौरान ''स्कूल नेतृत्व विकास'' पर क्षमता निर्माण कार्यशाला, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और मणिपुर में राज्य संसाधन समूह के लिए राज्य परामर्श और आयोजित।

एस.एल.डी.पी. में एक महीने के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम और पीजी डिप्लोमा कोर्स।

डाइट पौड़ी जिला, उत्तराखंड के प्रधानाध्यापकों के लिए नवंबर 2014 में क्षमता निर्माण कार्यशाला

दिल्ली के स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए न्यूपा, नई दिल्ली, 09–10 जनवरी, 2015 के दौरान दो दिन की क्षमता निर्माण कार्यशाला

शीर्ष संस्थानों की बैठक के संचालन में डॉ. सुनिता चुग को सहायता प्रदान की।

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

महत्वपूर्ण क्षेत्र 4ःएसआरजी के लिए दलों का निर्माण और नेतृत्व पर सत्र के अनुसार विस्तृत मॉड्यूल तैयार किए।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

f'k{k.k %

एक महीने के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम (जून 2014) – और पी.जी.डी.एस.एल.एम. (दिसंबर 2014) और स्कूलों में टीमों के निर्माण प्रमुख नेतृत्व पर पाठ पढ़ाया।

vU; xfrfofèk;ka %

समन्वित पाठ्यचर्या रूपरेखा का अनुवादः बंगाली और मणिपुरी में।

चारु मलिक

परियोजना सलाहकार

प्रकाशन

पुस्तक/अध्याय

राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा और स्कूल नेतृत्व विकास पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2014) न्यूपा, नई दिल्ली (योगदानकर्ताओं में से एक)

स्कूल नेतृत्व विकास पर हस्तपुस्तिका (2014) न्यूपा, नई दिल्ली (योगदानकर्ताओं में से एक)

प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/कार्यशाला का आयोजन

हिमाचल प्रदेश, 14–23 जुलाई, 2014 के दौरान राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए समन्वयक।

क्षमता निर्माण पर मदद, उत्तर प्रदेश, 04–13 अगस्त, 2014 में राज्य संसाधन समूह के कार्यक्रम में समन्वयक।

समन्वयन और स्कूल लीडरशिप पर बिहार राज्य को परामर्श, 03–04 सितम्बर, 2014।

स्कूल नेतृत्व विकास, के लिए योजना पर तीसरे चरण के राज्यों के लिए राष्ट्रीय परामर्श हेतु समन्वयक, 15–16 सितम्बर, 2014

समन्वयन और बिहार में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मदद, 19–28 सितम्बर, 2014

राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मदद, उत्तराखंड, 09–12 अक्टूबर, 2014

समन्वित और हरियाणा में राज्य संसाधन समूह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मदद, 29 नवंबर से 8 दिसंबर, 2014

समन्वित द्वितीय राष्ट्रीय समीक्षा और स्कूल लीडरशिप पर योजना कार्यशाला, 16–17 मार्च, 2015

अन्य शैक्षिक और व्यावसायिक योगदान

कोर्स समन्वय

समन्वयन और महत्वपूर्ण क्षेत्र 2 का सत्र अध्यापन : स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, दिसंबर, 2014, एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में स्व–विकास।

शिक्षण

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, जून 2014,एक माह का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में शिक्षण अधिगम बदलावः मुख्य क्षेत्र 3 का सत्र अध्यापन।

अन्य गतिविधियां

संपादन दल, राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा और स्कूल नेतृत्व विकास पर पाठ्यक्रम ढांचा और हिंदी में स्कूल नेतृत्व विकास पर हैंडबुक (नवंबर 2014) न्यूपा, नई दिल्ली।

''उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में पहुंच और भागीदारी में क्षमता पर अध्ययन'' में पीएच.डी. सम्मान न्यूपा, (फरवरी) 2015

नम्रता

परियोजना सलाहकार

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला में भागीदारी

आईआईसी, नई दिल्ली, 17–18 नवम्बर, 2014, एन.सी.एस.एल., न्यूपा द्वारा आयोजितः ''नीति, अभ्यास और अनुसंधान स्कूल नेतृत्व'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मेंः विद्यालय प्रभावशीलता 'सामाजिक और भावनात्मक क्षमता बढ़ाना' पर एक आलेख प्रस्तुत किया।

'विकास की मानसिकता और शैक्षिक नेतृत्व विषय पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, सकारात्मक मनोविज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः सकारात्मक मनोविज्ञान इंडियन एसोसिएशन, मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, 27 फरवरी – 1 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित।

महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में भाग लिया, न्यूपा, नई दिल्ली, 12–13 फरवरी, 2015 में एन.सी.एस.एल., न्यूपा द्वारा आयोजित।

अन्य शैक्षिक और व्यावसायिक योगदान

dks Zl eUo; %

दिल्ली उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रमुखों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर एक वर्ष के कार्यक्रम हेतु सहायक समन्वयक 2014—15, न्यूपा, नई दिल्ली ।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रतिभागी संगोष्ठी का कोर्स संयोजक ।

f' k{k.k %

स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रम में पीजी डिप्लोमा के भाग के रूप में अनुसंधान विधि में केस अध्ययन पर सत्र।

v U; x fr fo fèk; ka %

एन.सी.एस.एल. पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हैंडबुक और संसाधन सामग्री का हिन्दी अनुवाद में योगदान दिया।

छत्तीसगढ़ में आयोजित राज्य संसाधन समूह एस.आर.जी., के क्षमता निर्माण पर आठ दिवसीय कार्यशाला के लिए शैक्षिक मदद की, 22—28 दिसम्बर, 2014

दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा और योजना कार्यशाला, आईएचसी, नई दिल्ली, 16—17 मार्च, 2015 के लिए शैक्षिक सहायता।

n j D' kka i j o hu

i fj ; kst uk l y kgd kj & d fu 'B

çf' k{k.k d k; Øe @l Eesy u@d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

समूह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए और उनके कार्यवृत की तैयारी के अलावा स्कूल लीडरशिप पर निम्नलिखित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन में शैक्षिक, प्रशासनिक और तार्किक समर्थन प्रदान किया।

स्कूल नेतृत्व विकास पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका पर हिंदी अनुवाद कार्यशाला, मई 2014

राज्य परामर्श, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व पर स्कूल प्रमुखों और राज्य संसाधन समूह का क्षमता निर्माण

स्कूल नेतृत्व विकास, ओडिशा राज्य को परामर्श, अगस्त 2014

14 राज्यों के लिए तीसरे चरण का स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय परामर्श, सितंबर 2014

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के साझेदारी के लिए एनआरजी कार्यशाला।

स्कूल नेतृत्व विकास, पर राज्य संसाधन समूह प्रशिक्षण, ओडिशा, 19—29 अगस्त, 2014

महिला नेतृत्व, पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, फरवरी 2015

राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक, फरवरी 2015

न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के फरवरी 2015 के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

22 राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर द्वितीय राष्ट्रीय समीक्षा योजना कार्यशाला, 16—17 मार्च, 2015

çf' k{k.k l kexzh v kSj i kBîØe fod fl r v kSj fu 'i kfn r

पाठ्यक्रम और सामग्री के विकास में निम्नलिखित सहायता प्रदान की :

शैक्षणिक स्कूल नेतृत्व पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा के विकास में आगत और इसे अधिक संक्षिप्त और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सुझाव।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रमुख क्षेत्रों और राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) के स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण

के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर हस्तपुस्तिका में सत्र निर्माण और दल का निर्माण और नेतृत्व, अग्रणी नवाचार और अग्रणी साझेदारी।

vU; 'kS{kd vkS Oj kol kf; d ;ksx nku

f'k{k.k %

स्कूल नेतृत्व विकास पर एक महीने के ग्रीष्मकाल कार्यक्रम में स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण के दौरान शिक्षण सत्र, जून 2014, न्यूपा, नई दिल्ली।

राज्य संसाधन समूह (एसआरजी), की क्षमता निर्माण के दौरान शिक्षण सत्र, 19–29 नवम्बर, 2014, भुवनेश्वर, ओडिशा।

vU; xfr fofèk; ka %

स्कूल नेतृत्व पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंश तैयार, जुलाई 2014

राष्ट्रीय सलाहकार समूह (एनएजी) की बैठक, एनसीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक और एन.सी.एस.एल. की विभिन्न बैठकों के लिए रिपोर्ट तैयार की।

राष्ट्रीय समीक्षा योजना कार्यशाला के लिए रिपोर्ट तैयार की, मार्च 2015

राज्य के अधिकारियों, राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी), राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) और स्कूल प्रमुखों के लिए ई–डेटाबेस तैयार किया।

एमएस एक्सेल में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति पत्र बनाने के लिए यू–डीआईएसई 2013–2014 से डाटा संग्रह, जुलाई, 2014

चार राज्यों (हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश) के लिए आईसीटी आंकड़ा विश्लेषण।

e kfu d k c t kt

i fj ; kst u k l y kg d kj & d fu 'B

çf' k{k.k d k; Øe @l Ee sy u @d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

समूह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए और उनके कार्यवृत्त की तैयारी के अतिरिक्त स्कूल नेतृत्व पर निम्नलिखित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन में शैक्षिक, प्रशासनिक मदद प्रदान की।

स्कूल नेतृत्व विकास पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पुस्तिका की हिंदी अनुवाद कार्यशाला, मई 2014

राज्य परामर्श, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड और हरियाणा के राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व पर स्कूल प्रमुखों का क्षमता निर्माण।

14 राज्यों के लिए तीसरे चरण का स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय परामर्श, सितंबर 2014

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के साझेदारी के लिए राष्ट्रीय संसाधन समूह कार्यशाला

स्कूल नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी, नवंबर 2014

स्कूल शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, फरवरी 2015

न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के फरवरी 2015 के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक, फरवरी 2015।

22 राज्यों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर द्वितीय राष्ट्रीय समीक्षा योजना कार्यशाला, मार्च 2015।

स्कूल नेतृत्व विकास पर मुख्य संस्थानों के साथ सहयोग के लिए सलाहकार बैठक, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, 30 मार्च, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBî Øe fodflr vkSj fu'ikfnr

पाठ्यक्रम और सामग्री के विकास में निम्नलिखित सहायता प्रदान कीः

शैक्षणिक स्कूल नेतृत्व पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय कार्यक्रम रूपरेखा के विकास में आगत और इसे अधिक संक्षिप्त और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सुझाव।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) और स्कूल प्रमुखों के क्षमता निर्माण के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर हस्तपुस्तिका में सत्र निर्माण; अग्रणी नवाचार और अग्रणी भागीदारी आदि।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;kxnku

vè;kiu

न्यूपा, जून 2014 में स्कूल नेतृत्व विकास पर एक माह के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण के दौरान शिक्षण सत्र में ले लिया।

न्यूपा, जनवरी 2014 में दिल्ली स्कूल प्रमुखों के दो दिनों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के दौरान शिक्षण सत्र।

स्कूल प्रमुखों के स्कूल नेतृत्व विकास पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 27 जनवरी – 25 फरवरी, 2015 दौरान शिक्षण सत्र, न्यूपा, दिल्ली।

लखनऊ में राज्य संसाधन समूह (एसआरजी), उत्तर प्रदेश, क्षमता निर्माण के दौरान शिक्षण सत्र 04–14 अगस्त, 2014।

vU; xfrfofèk;ka%

जुलाई 2014 में स्कूल नेतृत्व पर 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार अंश

राष्ट्रीय सलाहकार समूह (एनएजी) एनसीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य गैर सरकारी संगठनों, एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ एन.सी.एस.एल. की विभिन्न बैठकों के लिए तैयार रिपोर्ट तैयार की।

उत्तर प्रदेश, अगस्त 2014 में स्कूल नेतृत्व पर एसआरजी के 10 दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम की रिपोर्ट।

स्कूल नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी, की मसौदा रिपोर्ट तैयार की 17–18 नवम्बर, 2014।

न्यूपा पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक का कार्यवृत्त संपादित (28 फरवरी, 2015)।

राष्ट्रीय समीक्षा योजना कार्यशाला (मार्च 2015) के लिए रिपोर्ट तैयार।

राज्य के अधिकारियों, राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी), राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) और स्कूल प्रमुख के लिए ई–डेटाबेस।

यू–डाईस से इकट्ठे हुए स्कूल आंकड़ा एमएस एक्सेल में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति रिपोर्ट बनाने के लिए 2013–2014। (जुलाई, 2014)।

चार राज्यों के लिए आईसीटी डेटा विश्लेषण (हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश)

mPp f' k{kk u hfr v u q akku d sUnz

, u -o h- o x hZ ¼fu n s' kd ½

ç d k' ku

i qLr d s@ v è; k; %

डायवर्सीफिकेशन आफ पोस्ट–सेकेण्डरी एजुकेशन, पेरिसः आईआईईएफ/यूनेस्को (2014).

गर्वनेंस रिफार्म इन हायर एजुकेशनः ए स्टडी आफ इंस्टीट्यूटशनल ऑटोनॉमी इन एशियन कन्ट्रीज (विद माइकल मार्टिन), पेरिसः आईआईईएफ/यूनेस्को (2014).

फ्रॉम स्कूलिंग टू लर्निंग (आईडब्ल्यूजीई रिपोर्ट), पेरिसः एचईपी/यूनेस्को 2014).

हायर एजुकेशन इन एशियाः एक्सपैंडिंग अप – द राइज आफ ग्रेजुएट एजुकेशन एंड युनिवर्सिटी रिसर्च (सह संपादन), मानट्रिलः यूनेस्को इंस्टीट्यूट आफ स्टेटिक्स (2014)

' kksèk i = @ y s[k@ u ksV ¬ %

''ग्लोबल ट्रैण्ड्स इन प्राइवेट हायर एजुकेशन'' एडुटैक (मई–जून 2014): 6–7, नई दिल्ली

''एमओओसी एंड हायर एजुकेशन इन डवलपिंग कंट्रीज'' आईएयू हॉरीजन, (2014), 20 (1–2); 37–38। पेरिस। (2014)

''डेमोक्रेटाईजिंग लर्निंग गेन्सः लैसन फ्राम द जीएमआर 2013/2014.'' नॉराग न्यूज, नं.50: 39–41. जेनेवा 2014

''ट्रेण्ड्ज इन क्रॉस–बार्डर माबिलिटी इन हायर–एड'' एडुटैक (मार्च–अप्रैल 2014): 10–11, नई दिल्ली 2014.

''इस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया'' (गरिमा मलिक के साथ सह–संपादन). युनिवर्सिटी न्यूज, 53(3): 115–122, नई दिल्ली–2014.

''फ्रॉम राईट टू एजुकेशन (आर.टी.ई.) टू राइट टू लर्निंग''. नॉराग न्यूज, नं.51: 51:68–69. जेनेवा 2014

''चैलेंजेज आफ मैसिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया''. पेपर प्रजेंटेड एट द सेमीनार ऑन 'मैसिफिकेशन आफ हायर एजुकेशन इन लार्ज सिस्टम कन्ट्रीज', ज्वाइंटली आग्रेनाइज्ड बाई द सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई), न्यूपा एंड ब्रिटिश काउंसिल–इंडिया इन नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014

''ब्रिक्स एंड इंटरनेशनल कोलाबोरेशन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया.'' फ्रंटियर्स आफ एजुकेशन इन चाइना (2015), 10(1): 26–65

l aks'Bh@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

''उच्च शिक्षा आंकड़ा'' पर कार्यशाला में भाग लिया, योजना आयोग, 4 अप्रैल 2014

संगोष्ठी प्रस्तुति ''वैश्विक अधिगम संकट और बढ़ता अधिगम ह्रास'' बलवंत राय मेहता विद्या भवन और एएसएम अकादमी, नई दिल्ली, मई 9, 2014

''विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय'' पर संगोष्ठी पीडीपी विश्वविद्यालय, गुजरात, 14 मई, 2014

''अभिशासन सुधार'' एस.एच.ई.एस. तिरुवनंतपुरम, द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया और प्रस्तुति 29–30 मई, 2014

फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में एक सत्र संचालित और भागीदारी, नई दिल्ली, 13–14 नवम्बर, 2014।

तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी सम्मेलन में ''उच्च शिक्षा सुधारों की राजनीति'' पर एक सत्र की अध्यक्षता की नई दिल्ली, 16 नवंबर 2014

v arjkZVªh; %

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत 'MOCCs4D: पिरामिड के तल पर संभावनाएं' फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 09–11 अप्रैल, 2014

''वैश्वीकरण के दौरे : अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी'' मियामी, 01–02 मई, 2014

पेपरडीन विश्वविद्यालय अमरीका से प्रतिनिधियों के लिए ''शैक्षिक योजना'', पर संगोष्ठी प्रस्तुति, योजना आयोग, 6 मई, 2014

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा सांख्यिकी'' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। नई दिल्ली, 03–04 जुलाई, 2014

मुख्य वक्ता, दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की भूमिका आईआईसी, नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2014

वृहद शैक्षिक प्रणाली के सार्वजनीकरण और प्रबंधन पर ''अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और प्रस्तुति, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014

आईएयू द्वारा आयोजित सभी के लिए शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, अंकारा, तुर्की, 18–19 नवम्बर, 2014

''उच्च शिक्षा में महिला एवं नेतृत्व'' पर संगोष्ठी में पैनल चर्चा में भाग लिया, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, नई दिल्ली, 11–12 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित किया।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk,a dk vk;kstu

'प्रथम सहकर्मी समीक्षा लेखक' की बैठक आयोजित, भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (आई.एच.ई.आर. 2015), सी.पी.आर.एच.ई., न्यूपा, नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014 (गरिमा मलिक के साथ)।

'दूसरी सहकर्मी समीक्षा लेखक' बैठक आयोजित, भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (आई.एच.ई.आर. 2015), सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2014 (गरिमा मलिक के साथ)।

'विविधता और उच्च शिक्षा में भेदभाव' पर अनुसंधान परियोजना (निधि एस. सब्बरवाल और सी.एम. मनीष के साथ) पहली सलाहकार समिति की बैठक, सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2014

भारत के तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी सम्मेलन में 'उच्च शिक्षा नीति और सुधारों की राजनीति' पर एक पैनल चर्चा (अनुपम पचौरी के साथ) नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2014

'उच्च शिक्षा में शिक्षण और सीखने' पर सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2014 अनुसंधान परियोजना (तमो चट्टोपाध्याय) के साथ पहली विशेषज्ञ समिति की बैठक।

'उच्च शिक्षा, प्रशासन और प्रबंधन' पर शोध परियोजना की पहली विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित, सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014 (गरिमा मलिक के साथ)।

'उच्च शिक्षा के वित्त पोषण' पर अनुसंधान परियोजना की पहली विशेषज्ञ समिति की बैठक, सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 7 जनवरी 2015 (जिनुशा पाणिग्रही के साथ) ।

'भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता : संस्थागत स्तर पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के एक अध्ययन' पर शोध परियोजना की पहली विशेषज्ञ समिति की बैठक सी.पी.आर.एच.ई.,–न्यूपा, नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2015 (अनुपम पचौरी के साथ) ।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पर आईसीएसएसआर–आईडीआरसी बैठक में भाग लिया, बैंकॉक, 19–20 सितम्बर, 2014

e kuu k [kj s

ç d k' ku

i qLr d sa@ v è; k; %

एजुकेशन ऐड एंड इंटरनेशनल कोपरेशन इन इंडियाः शिप्टिंग डायनामिक्स, इंक्रीजिंग कोलाबोरेशन। ह्वेन चेंग, शेंग–जू चान (संपादक) इंटरनेशनल एजुकेशनल एड इन डवलपिंग एशिया – पॉलिसी एंड प्रैक्टिस स्प्रिंगर साइंस बिजनेस मीडिया सिंगापुर प्रा. लिमिटेड (अन्डर प्रिंट)।

''संचार कौशल – एक कला, एक विभा'', व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम – दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी'' मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (प्रकाशनाधीन)।

' kks èk i = @ y s[k@ u ksV ł %

''आइडोलॉजीकल शिफ्ट इन इंडियन हायर एजुकेशन इंटरनेशनलाइजेशन,'' इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, नंबर 78 (विशेषांक), बोस्टन कॉलेज सेंटर फार इंटरनेशनल हायर एजुकेशन।

''इंप्लायमेंट, इंप्लायबलिटी एंड हायर एजुकेशन इन इंडियाः द मिसिंग लिंक्स,' हायर एजुकेशन फार द फ्यूचर, केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद, सेज पब्लिकेशन्स 1(1), 39–62 (अगस्त 2014), लॉस एंजिल्स, लंदन, नई दिल्ली सिंगापुर, वाशिंगटन डीसी।

v u ql ak/ku v è; ; u

t kj h %

'भारत में तुलनात्मक शैक्षिक लाभ की स्थानिक गतिशीलता'।

l a ks'B h@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

सत्र की अध्यक्षा/आमंत्रित वक्ता, एमजी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में 'उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व', पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 23–24 जुलाई, 2014

कार्यशाला विविधता और भेदभाव, सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा के अनुसंधान परियोजना के बारे में जानकारी संग्रह के लिए अनुसंधान उपकरणों पर चर्चा, 12 जनवरी 2015

सी.पी.आर.एच.ई., न्यूपा की विविधता और भेदभाव, पर अनुसंधान परियोजना पर अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला, 09–10 फरवरी, 2015

आर्थिक परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय असमानता, उच्च शिक्षा के संस्थानों में पहुंच और भागीदारी; विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समता और विविधता के प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यशाला में चर्चाकार, 16–20 मार्च, 2015, न्यूपा।

भारत में शासन और उच्च शिक्षा के प्रबंधन पर परियोजना कार्यशाला के लिए शोध के साधन पर चर्चा, सी.पी.आर. एच.ई.–न्यूपा, 18 मार्च, 2015

सत्र अध्यक्ष/आमंत्रित वक्ता ' मानव संसाधन विकास के लिए उच्च शिक्षा में पुर्ननिवेश – 'ज्ञान या सूचना' काशी विद्यापीठ, वाराणसी में 'मानव संसाधन विकास में चुनौतियां' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 28 मार्च 2015।

विशेषज्ञ समवर्ती सत्र/जूरी/ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की 9वीं राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन (एनआरसी)/अध्यक्षता 'भारत में प्रबंधन शिक्षा का भविष्य', आईआईसी, नई दिल्ली, 31 मार्च – 1 अप्रैल 2015

v a j kZVªh; %

''उच्च शिक्षा में महिला नेतृत्व'' पर वैश्वीकरण शिक्षा संवाद–दक्षिण एशिया सीरीज 2015 में भाग लिया, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2015।

ç f' k{k.k d k; Øe @ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa d k v k; kst u

स्कूल में धन के प्रबंधन और योजना में अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति, सितंबर 1–5, 2014: (अन्तर–राज्यीय बदलाव सार्वजनिक–निजी भागीदारी; स्कूल शिक्षा में (पीपीपी) और भारत में प्राथमिक शिक्षा के वित्त पोषण पर सत्र) ।

संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम 'शिक्षा में मात्रात्मक अनुसंधान के तरीके', 05–15 जनवरी, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

''शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए वैकल्पिक तरीके'' शीर्षक से अनुसंधान मोनोग्राफ का प्रथम मसौदा, प्रगति के तहत सामग्री और अंतिम संशोधन और संपादन; अधिगम के रूप में तैयार किया गया है।

तीन मसौदों का पहला भाग 'शैक्षिक अनुसंधान के लिए सांख्यिकीय तरीके' पर मॉड्यूल, प्रो सुधांशु भूषण और डॉ सुमन नेगी के साथ पठन सामग्री के रूप में (श्री शशिरंजन झा के साथ सहयोजित), पी.एच–डी. विद्वान,

vU; 'kSf{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

i;Zos{k.k@eSaVj;kdu %

Mkslky ?kq'kkèk çcaèk dk i;Zos{k.k

निम्नलिखित एम.फिल./पी.एच–डी. की का पर्यवेक्षण। पी.एच–डी. कार्य –

''रिसर्च स्कॉलर, श्री शौविक मुखर्जी: एक बहुस्तरीय विश्लेषण: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में माध्यमिक स्तर विद्यालयी शिक्षा पर छाया शिक्षा''।

''भारत में उच्च शिक्षा के लिए ज्ञान आधारित उद्योगों और प्रवासन के स्थानिक वितरण के बीच अंतर–संबंध'' रिसर्च स्कॉलर, श्री सुमित कुमार।

f'k{k.k %

निम्नलिखित पाठ्यक्रम में शिक्षण में शामिल:

एम.फिल./पीएच–डी सीसी3, सीसी5 और ओसी 11।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा)

vU; xfr fofèk;ka %

सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, 25 जुलाई, 2014 को आयोजित आई.एच.ई.आर. 2014 को सहकर्मी लेखक समीक्षा बैठक।

न्यूपा वेब पोर्टल के समन्वयक, रखरखाव और प्रबंधन

सदस्य, पर्यवेक्षकों के आवंटन के लिए समिति

सदस्य, एम.फिल. और पी.एच–डी. प्रवेश समिति

सदस्य, एम.फिल./पी.एच–डी. के लिए प्रश्न की स्थापना के लिए समिति। पी.एच–डी. प्रवेश परीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग, डी.ए.सी.

शैक्षिक वित्त विभाग, डी.ए.सी.

शैक्षिक योजना विभाग, डी.ए.सी.

सदस्य – एम.फिल पाठ्यक्रम संशोधन और पुनर्गठन समिति।

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kSf{kd lg;rk

एनसीईआरटी में संसाधन व्यक्ति, परियोजना योजना, अनुश्रवण और मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 26–27 फरवरी, 2015 भोपाल, आर.आई.ई.।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से थीसिस का पीएच–डी मूल्यांकन

U;wk dscgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

सदस्य, शिक्षा क्षेत्र में सेवा उत्पादन सूचकांक पर उप–समिति, सांख्यिकी मंत्रालय तथा पीआई, सीएसओ

सदस्य, स्थायी उप–अनुसंधान सलाहकार समिति की समिति (आरएसी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नोएडा)।

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, योजना एवं अनुश्रवण विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

विशेषज्ञ, एस.एल.एम. के लिए मूल्यांकन, जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के डी.ई. कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो,

सह–संपादक, भारतीय आर्थिक जर्नल, भारतीय आर्थिक संघ,

समीक्षक स्प्रिंगर, सिंगापुर के पुस्तक प्रस्ताव हेतु।

संपादकीय सलाहकार बोर्डः हिमगिरी शिक्षा समीक्षा आई. एस.एस.एन. 2321–6336.

fu fèk l Ûc j o ky

ç d k' ku

i qLr d s@ v è; k; %

''ब्रीजिंग द सोशल गैपः पर्सपैक्टिव आन दलित इम्पावरमेंट'' (एस.के. थोराट) के साथ संपादन, 2014, नई दिल्लीः सेज

' kks/k i = @ y s[k@ u ksV ~ l %

''एजुकेशन फार सिविक लर्निंग – ब्रिगिंग इट एट कोर आफ लर्निंग'' शीर्षक लेख (सुखदेव थोराट के साथ), विश्वविद्यालय समाचार (उच्च शिक्षा में स्वायत्तता पर विशेषांकः मानदंड स्थानांतरण), 53 (03), 19–25 जनवरी, 2015, पृ. 61–66।

''लुकिंग एट दलित वूमन'', इन देवकी जैन एंड सी. पी. सुजाय (सं.) इंडियन वूमन रिवाइज्ड, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2015, पीपी. 61–90।

''कास्ट एंड सोशल एक्सक्लूजनः कान्सैप्ट, इंडिकेटरर्स एंड मेजनमेंट'' (एस.के. थोराट के साथ), ए.के. शिव कुमार, पी. रूस्तगी और पी. सुब्रामणियम (सं.) इंडियाज चिल्ड्रेन, नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015, पीपी. 374–392।

इश्यू आफ अंडर–रिप्रजेंटेशनः मैपिंग वूमन इन इंडिया पॉलिटिक्स (डेविड लाल और अभिरुचि ओझा के साथ) जर्नल आफ साउथ एशियन स्टडीज, 2014, वॉल्यूम 3(1): 93–102।

स्वलोविंग द हुमिलिएशनः द मिड–डे मील एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप (डी. दिवाकर, ए.के. नाइक और एस. शर्मा के साथ) जर्नल अफ इन्क्लूजन स्टडीज, वॉल्यूम 1, जुलाई–दिसंबर, 2014, पीपी 169–182।

कास्ट इनक्वालिटी एंड पावर्टी इन इंडियाः ए रिएसैसमेंट (वी.के. बरूआ, डी.दिवाकर, वी.के. मिश्रा और ए.के. नाइक के साथ) डेवलपमेंट स्टडीज रिसर्च, 1:1, अक्टूबर 2014, 279–294, डीओआईः 10,1080/21665095.2014. 967877

इवाल्युएटिंग द सोशल ओरिएन्टेशन आफ द इंटेग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम (वी.के. बरूआ और डी. दिवाकर के साथ), इकॉनमिक एंड पालिटिकल वीकली, वॉल्यूम 59, सं. 12, 2014, पृ. 52–62

''स्ट्रैन्थनिंग सोशल जस्टिस टू एड्रेश इंटरसैक्टिंग इक्वालिटीज पोस्ट–2015', रिपोर्ट के लेखकों में से एक योगदान ओवरसीज डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जुलाई–सितंबर, 2014 लंदनः ब्रिटेन।

v uq èkku v è; ; u

t kjh %

विविधता और भेदभावः (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश के साथ) नागरिक अधिगम और लोकतान्त्रिक सम्बन्ध के लिए उच्च शिक्षा। परियोजना सहयोग और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद द्वारा वित्त पोषित।

l a ks'B h@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

संसाधन व्यक्ति, 'अनुसूचित जातियों, जनजातियों बच्चों की समस्याओं पर राष्ट्रीय स्थिति आलेख को अंतिम रूप देने के लिए', कार्यशाला की समीक्षा विशेष जरूरतों के साथ समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 7–08 जुलाई, 2014 द्वारा आयोजित।

संसाधन व्यक्ति ''एक समावेशी नजरिए से पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण के विकास के लिए दो दिवसीय कार्यशाला'' विशेष जरूरतों के साथ समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 5–6 अगस्त, 2014

फिक्की में रैपोर्टियर, उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, नवंबर 13–14, 2014

संसाधन व्यक्ति, न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 दिसम्बर,: 'नीतिगत मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेपः माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के स्तर पर सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा' पर कार्यशाला 2014

संसाधन व्यक्ति, कार्यशाला को अंतिम रूप देने और उपकरणों को मान्यता देने हेतु और समावेशी शिक्षा के नजरिए से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री का विश्लेषण, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, 13–15 जनवरी, 2015

'समावेशी शिक्षाः चुनौतियां के परे, शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान (सीआईई), दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, 24 फरवरी 2015

''शिक्षा में अनुसूचित जाति समूह के लिए सरकारी सुविधाएँ'' 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति, प्राप्ति और चुनौतियां', राष्ट्रीय संगोष्ठी में सत्र के दौरान चर्चाकार आईसीएसएसआर, 24–25 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित।

''शैक्षिक संस्थानों – निजी, सरकारी और वंचित समूह पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति, प्राप्ति और चुनौतियां, पर सत्र के दौरान चर्चाकार आईसीएसएसआर, 26–27 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित।

आलेख प्रस्तुत ''व्यवहार बाधाओं पर काबू पानाः उच्च शिक्षा की भूमिकाः लोकतांत्रिक क्रिया और भेदभाव रहित उपयोग को बढ़ावा देने में'' (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश के साथ) ''उच्च शिक्षा तक पहुंच'' अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विकलांग छात्रों द्वारा चुनौतियों का सामना, समान अवसर कार्यालय, जेएनयू, नई दिल्ली, 9 मार्च, 2015 को आयोजित।

आलेख प्रस्तुत, पूर्वोत्तर भारत की समझः शैक्षिक मुद्दों और चुनौतियों पर वार्ता पर संगोष्ठी में पाठ्यक्रम के माध्यम से कक्षा संपर्क में विविधता को संबोधित करने का महत्व शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षा संस्थान (सीआईई), दिल्ली, मार्च विश्वविद्यालय 13–14, 2015

v a j kZVªh;

कोरिया विकास संस्थान और एशिया फाउंडेशन, कोलंबो, श्रीलंका की ओर से आयोजित सम्मेलन ''अनुभव, सबक और सहयोग के लिए अवसर; सामाजिक गतिशीलता के लिए एशियाई दृष्टिकोण'' पर ''बहिष्कृत समूहों के सामाजिक गतिशीलता के लिए भारत का रुख'' शीर्षक से आलेख प्रस्तुत, अगस्त 21– 22, 2014

''भारत में दलित महिलाओंः लिंग और जाति का पैमाना पर वैश्विक तिमिर सम्मेलन, ड्यूक विश्वविद्यालय, उत्तरी कैरोलिना (यूएसए), 06–08 नवम्बर, 2014

सी.पी.आर.एच.ई, न्यूपा, 10–11 नवम्बर, 2014 तक आयोजित, ''वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा का सार्वजनीकरण' अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय, 16–18 नवम्बर, 2014, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश के साथ) ''नागरिक अधिगम, लोकतांत्रिक बंधन और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा'' से आलेख प्रस्तुत।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में चर्चाकारः स्कूल नेतृत्वः, सत्र में नीति, अभ्यास और अनुसंधान' विविधता, समता और नीतिगत मुद्दे''', राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र द्वारा आयोजित न्यूपा, 17–18 नवम्बर, 2014

çf' k{k.k dk; Øe@l Ee sy u@dk; Zkky kv ka dk vk; kst u

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति, शिक्षा और लिंग, न्यूपा, नई दिल्ली, 20–30 जनवरी, 2015।

विविधता और भेदभाव, पर परियोजना के तहत राज्य शोध टीमों के लिए एक अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला आयोजित , 09–10 फरवरी, 2015 (संयुक्त रूप से सी. एम. मलिश के साथ) न्यूपा।

संसाधन व्यक्ति के रूप में, प्रस्तुति, शैक्षिक प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित ''विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और क्षमता का प्रबंधन'' पर अभिविन्यास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा के संस्थानों में सकारात्मक कार्रवाई और समावेशन 16–20 मार्च, 2015, न्यूपा, नई दिल्ली।

çf'k{k.k lkexzh vkSj iBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

''विविधता और भेदभाव'' पर अनुसंधान शुरू करने के लिए ''मात्रात्मक तरीके और गुणात्मक विधियों'' पर (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश) के साथ सामग्री तैयार ।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

अनुसंधान परियोजना पर प्रस्तुतिः नागरिक अधिगम और लोकतांत्रिक बंधन के लिए उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव; उच्च शिक्षा संस्थानों का एक अध्ययन परियोजना सलाहकार समिति की बैठक, (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश के साथ) सी.पी.आर.एच.ई., न्यूपा, 25 सितम्बर 2014

अनुसंधान उपकरण पर एक विशेषज्ञ समिति आयोजित ''विविधता और भेदभाव'' पर परियोजना के लिए (संयुक्त रूप से सी.एम. मलिश के साथ), न्यूपा, 12 जनवरी 2015

''उच्च शिक्षा की भूमिका नागरिक अधिगम और लोकतांत्रिक बंधन में शीर्षक से प्रस्तुति, गार्गी कॉलेज, नई दिल्ली, 4 मार्च, 2015 को आयोजित, सकारात्मक भेदभाव, पर यूजीसी प्रायोजित कोर्स।

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kS{kd lgk;rk

आईसीएसएसआर अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन

कोलकाता में वर्तमान में महिलाओं के बीच पारंपरिक गर्भनिरोधक के विकल्प अल्ट्रा–आधुनिकता या बेटे को प्राथमिकता, 2014

तमिलनाडु, 2014 में मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी के उपयोग में लिंग भेद।

दलित महिलाओं की शिक्षा पर पीएच–डी कार्य हेतु सलाहकार, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

संसाधन व्यक्ति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित ''श्रम अध्ययन में अनुसंधान के तरीके'' पर पाठ्यक्रम में एक सत्र का आयोजन किया, दिसंबर 5,2014

विशेष आवश्यकता समूह के शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नजरिए से शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर उत्तरी क्षेत्र (उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात) से महत्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों/मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति, 16–18,2014

एम.फिल निबंध थीसिस के लिए बाहरी परीक्षक – भारत में बच्चों का पोषण स्तरः जेएनयू के लिए तमिलनाडु और बिहार के विश्लेषण द्वारा (मौखिक 24 मार्च 2015 को आयोजित)

सदस्य, परियोजना पुणे विश्वविद्यालय के 'समावेशी' विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति।

लिंग संवेदीकरण पर सदस्य, जेएनयू विविधता कोर्स के लिए आमंत्रित किया।

U;wkdscgkj ç[;kr fudk;ksad hlnL;rk

तुलनात्मक शिक्षा समितियों के वर्ल्ड कांग्रेस से संबद्ध भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी की वार्षिक सदस्य।

vuqie ipkSh

vuqàkku vè;;u

iwkZ%

''प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के काम करने की स्थिति'' पंजाब राज्य अध्ययन प्रधान अन्वेषक, एससीईआरटी–पंजाब और डॉ एम.एस. सरकारिया के साथ; शिक्षक प्रबंधन और विकास की अंतिम रिपोर्ट पर न्यूपा के आर.जी.एफ. चेयर प्रो. विमला रामचंद्रन के तत्वावधान में भारत में शिक्षकों की काम की परिस्थितियों पर नौ राज्यों के अध्ययन की रिपोर्ट प्रधान अन्वेषक को प्रस्तुत की।

t kjh %

अनुसंधान अध्ययन परियोजना शीर्षक, 'भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ताः संस्थागत स्तर पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन' के एक अध्ययन में बाहरी गुणवत्ता आश्वासन और आंतरिक संरचना और क्रियाओं को समझने के लिए एक बहु राज्यीय अध्ययन के रूप में प्रस्तावित (क्वालिटी एश्योरेंस, उनके अंतर–संबंध और संस्थागत स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन पर प्रतिभागियों की भागीदारी)।

l ak f"B; ka l Ee sy u ka d k; Z kky k v ka e sa Hkkx hnkjh

jk"Vªh; %

''कार्यक्रम मूल्यांकन संगोष्ठी', न्यूपा, नई दिल्ली, 27 मई, 2014: बहु हितधारक भागीदारी पर एक अध्ययन से सबक एक मूल्यांकन ढांचे के विकास के लिए विचार' पर आलेख प्रस्तुत।

अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की, भारत, न्यूपा, नई दिल्ली, 1–03 सितम्बर, 2014 को शिक्षकों की काम करने की स्थिति पर शोध अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 'पंजाब में मानचित्रण नीति और व्यवहार'।

फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्रः 'उच्च शिक्षा विजन 2030: इसे बनाना है, फिक्की, नई दिल्ली, 12–13 नवम्बर, 2014

फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2014, फिक्की, नई दिल्ली, 13–14 नवम्बर, 2014

शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली, 16–18 नवंबर, 2014 – भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी सम्मेलन 2014

भारत में उच्च शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन पर परियोजना के लिए शोध के साधन पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला, सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, 18 मार्च, 2015

''आलेख प्रस्तुत, आरटीई अधिनियम अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है; क्यों? शिक्षा (आरटीई) फोरम, संवैधानिक क्लब, नई दिल्ली, 25 मार्च, 2015 को राइट द्वारा आयोजित आरटीई पर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय निर्दिष्टकालिक कन्वेंशन, पंजाब में मुद्दे, गुणवत्ता और शिक्षकों के लिए चुनौतियां।

v ar jkZ"Vªh; %

आलेख प्रस्तुत, राजस्थान में बहु हितधारक भागीदारी के अभिशासन में अस्थायी शक्तियां और भावनाएँ अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा 'शक्ति, राजनीति और तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्राथमिकताएं' पर 2014 का सम्मेलन, ब्रिटिश एसोसिएशन, बाथ, विश्वविद्याल, ब्रिटेन, 9 सितंबर, 2014

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संयुक्त रूप से, 'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण पर उच्च शिक्षा में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, न्यूपा और ब्रिटिश काउंसिल–भारत द्वारा आयोजित, गुणवत्ता आश्वासन'' पर विषयगत सत्र में रिपोर्टर के रूप में भाग लिया, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014

शैक्षिक वित्त विभाग, द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, न्यूपा, 23–25 फरवरी, 2015

युवा जिन्दगी–अंतरराष्ट्रीय अनुदैर्ध्य शैशवकालीन दरिद्रता शोध अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय दौर 4 का प्रारंभ : ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, भारत, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2014 द्वारा आयोजित।

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk,a dk vk;kstu

समन्वित, संयुक्त रूप से सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा और सी.ई.एस.आई., नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2014 को आयोजित शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन, भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी सम्मेलन 2014 में ''उच्च शिक्षा नीति और सुधारों की राजनीति'' शीर्षक पर पैनल चर्चाकार।

आईसीएसएसआर और सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा अनुसंधान परियोजना के लिए शोध के साधन पर चर्चा करने के लिए 'विविधता और भेदभाव' पर कार्यशाला जनवरी 12,2015

आईसीएसएसआर और सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा अनुसंधान परियोजना पर अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला 'विविधता और भेदभाव', 09–10 फरवरी, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj i kBî Øe fodflr

अनुसंधान परियोजना पर शोध पद्धति कार्यशाला सामग्रीः संस्थागत स्तर पर आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता आश्वासन के एक अध्ययन में भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। 10 संस्थानों से शोध टीमों के लिए सामग्री विकसित, संस्थागत प्रोफाइल, शिक्षकों और छात्रों के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली, संस्थागत नेताओं के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम को विकसित करने के लिए प्रारूप भी शामिल है।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;kxnku

एक दिन की चर्चा बैठक में रिपोर्टियर, उच्च शिक्षा नीति अनुसधान केन्द्र (सी.पी.आर.एच.ई.), न्यूपा, नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014 को आयोजित भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (आई.एच.ई.आर.) 2014

भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (आई.एच.ई.आर.) 2014, सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2014, द्वितीय सहकर्मी लेखक, एक दिवसीय बैठक में भाग लिया,

न्यूपा एम.फिल/पीएच–डी कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2014–15 में निरीक्षक।

lkoZfud fudk;ksa dks ijke'kZ vkSj 'kS{kd lgk;rk

परीक्षा और एम.फिल वाईवा–वोस शोध प्रबंध ''ग्रामीण झारखंड में शैक्षिक संबंध का अनुभव; विकास और भागीदारी''। दिल्लीः डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 24 अक्टूबर 2014

U;wvk dscksgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन (बी.ए.आई.सी.ई.), ब्रिटेन के सदस्य।

xfjek efyd

vuqlaèkku vè;;u

tkjh %

''भारत में उच्च शिक्षा का प्रबंधन और अभिशासन'' कैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के कार्यों का प्रबंधन और अभिशासन कार्य करता है और साथ ही साथ कैसे उच्च शिक्षा संस्थान कैसे शासित अ ौर प्रबंधित होते हैं। प्रधान अन्वेषक, अनुसंधान अध्ययन परियोजना।

çdk'ku

vuqlaèkku i=@y{k@uksV‐ %

''भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत स्वायत्तता'', (एन.वी. वर्गीज़ के साथ) विश्वविद्यालय समाचार, 53(3): 115–122 (जनवरी 19–25, 2015)।

laxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk,a

jk"Vªh; %

फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2014, नई दिल्ली, नवंबर 13–14,2014 में ''शासन और विनियामक ढांचे'' पर सत्र में रिर्पोटियर के रूप में भाग लिया।

(सी.ई.एस.आई.) सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2014 भारत तुलनात्मक एजुकेशनल सोसायटी में 'उच्च शिक्षा नीति और सुधारों की राजनीति' विषय पर पैनल सत्र में भाग लिया।

varjkZ"Vªh; %

सी.पी.आर.एच.ई. और ब्रिटिश काउंसिल–भारत, नई दिल्ली, नवंबर 10–11,2014 द्वारा आयोजित 'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, 'वृहद व्यवस्था का प्रशासन और प्रबंधन' विषय पर सत्र में रिपोर्टियर के रूप में भाग लिया।

शैक्षिक वित्त, न्यूपा, नई दिल्ली, 23–25 फरवरी, 2015 के विभाग द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के अभिनव तरीके'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सत्र में रैपोर्टियर के रूप में भाग लिया।

çf'k{k.k dk;ZØe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;ksftr dk vk;kstu

अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला विविधता और भेदभाव, 09–10 फरवरी, 2015 को आईसीएसएसआर और सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा अनुसंधान परियोजना पर।

''शासन और भारत में उच्च शिक्षा का प्रबंधन'', न्यूपा, नई

दिल्ली, मार्च 18,2015 पर परियोजना के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों पर कार्यशाला।

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBî Øe fodflr vkSj fu'ikfnr

हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों से ''भारत में उच्च शिक्षा का प्रबंधन और शासन'' 14 अनुसंधान दल के सदस्यों के लिए कार्यशाला हेतु तैयार किया। संस्था की सामग्री में प्रोफाइल, साक्षात्कार और फोकस समूह चर्चा के लिए शिक्षकों और छात्रों के कार्यक्रम के लिए प्रश्नावली।

मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों आधारित अनुसंधान उपकरणों अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला के लिए सामग्री विकसित।

vU; 'kSf{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

प्रथम सहकर्मी समीक्षा लेखक बैठक 'भारत में उच्च शिक्षा की रिपोर्ट (2015 आई.एच.ई.आर.),' सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2014 (प्रोफेसर वर्गीज़) के साथ आयोजित।

द्वितीय सहकर्मी समीक्षा लेखक बैठक भारत में उच्च शिक्षा की रिपोर्ट (2015 आई.एच.ई.आर.),' सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, नई दिल्ली, अक्टूबर 29, 2014 (प्रोफेसर वर्गीज़) के साथ आयोजित।

ft uqkk i kf.kxzgh

çdk'ku

iqLrd sa@ vè;k; %

समरी रिपोर्ट आफ द इंटरनेशनल सेमीनार ऑन ''मैसिफिकेशन आफ हायर एजुकेशन इन लार्ज एकेडेमिक सिस्टम'' (10–11 नवम्बर, 2014), प्रोफेसर एन.वी. वर्गीज, ऐवरिट रिचर्ड एंड एल. हैसलॉप, ब्रिटिश काउंसिल–इंडिया द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, जनवरी 2015

फाईनल रिपोर्ट आन द ''मैसिफिकेशन आफ हायर एजुकेशनः अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर एक रिपोर्ट, प्रोफेसर एन.वी. वर्गीज, ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली, भारत, 2015 द्वारा प्रकाशक

vuqlaèkku i=@ ys[k@ uksV~l %

''गोइंग ग्लोबल 2015ः चैलेंजेज फेसिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम'' (प्रो. एन.वी. वर्गीज़ एंड एल. हैसलोप के साथ सह–लेखक), विश्वविद्यालय विश्व समाचार (इंटरनेशनल जर्नल), 20 फरवरी 2015, अंक 355, आईएसएसएन 1756–29ग। इसके अलावा बांग्लादेश ऑब्जर्वर में मुद्रित, 4 मार्च 2015, पृ.10

शीर्षक ''ग्रोविंग प्राइवेट प्रोवाइडर्स एंड कन्स्ट्रेन्ट इन द च्वाइस आफ हायर एजुकेशन इंस्टीटयूटशनः इम्पैक्ट ऑन एक्सेस टू हायर एजुकेशन'', इकॉनमिक अफेयर्स, फरवरी 2015, वॉल्यूम 60(1)ः 41–47

द इंटरनेशनल सेमीनार आन ''मैसिफिकेशन आफ हायर एजुकेशन इन लार्ज एकेडेमिक सिस्टम'' 10–11 नवम्बर, 2014, कैम्पस न्यूज सैक्शन ऑफ द युनिवर्सिटी न्यूज, एसोसिएशन आफ इंडियन युनिवर्सिटीज, वॉल्यूम 53, सं. 1, 05–11 जनवरी 2015

vuqlaèkku vè;;u

tkjh %

प्रधान अन्वेषक, (यूजीसी द्वारा प्रायोजित) सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा प्रमुख अनुसंधान परियोजना का संचालन, ''भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त पोषणः धन के प्रवाह और उनके उपयोग का एक अध्ययन व्याप्ति अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान के साधन के साथ–साथ गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, परियोजना के लिए विकसित किया गया है, एक पायलट अध्ययन किया गया और शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक विशेषज्ञ समिति की बैठक जनवरी 2015 में आयोजित की गई।

laxks'Bh@lEesyu@dk;Zkkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk'Vªh; %

फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2014, फिक्की, नई दिल्ली, 12–14 नवम्बर, 2014ः ''नए मानदंड उच्चतर

शिक्षा का वित्त पोषण'' पर एक सत्र में रैपोर्टियर के रूप में भाग लिया।

''देश में शोध का परिदृश्यः एक जायजा'' पर एक सत्र में रैपोर्टियर के रूप में भाग लियाः संयुक्त रूप से भारतीय विश्वविद्यालय संघ और एसोचौम, होटल हयात रिजेंसी द्वारा आयोजित ''विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापनाः नये आधार– उच्च शिक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 9 जनवरी 2015।

'विविधता और भेदभाव' पर आईसीएसएसआर और सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा अनुसंधान परियोजना पर अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला में भाग लिया, न्यूपा, 09–10 फरवरी, 2015

भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन, न्यूपा, 18 मार्च, 2015, सी.पी.आर.एच.ई./न्यूपा अनुसंधान परियोजना के अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला में भाग लिया।

v a j kZVªh; %

संयुक्त रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स और क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, नवंबर 16–18 ,2014 द्वारा आयोजित 'शिक्षा, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन' पर 5वीं सी.ई.एस.आई. वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

'विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व' पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में भाग लिया, संयुक्त रूप से न्यूपा, नई दिल्ली, 12–13 फरवरी, 2015 के दौरान विद्यालय नेतृत्व केन्द्र, न्यूपा और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आयोजित।

वित्त विभाग, न्यूपा, नई दिल्ली, 23–25 फरवरी, 2015 द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के नए तरीके'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'उच्च शिक्षा के वित्त पोषण' पर एक सत्र में रैपोर्टियर के रूप में भाग लिया।

उपेक्षित समूहों की शिक्षा नीतियाँ कार्यक्रम और चुनौतियां पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लियाः संयुक्त रूप से आईसीएसएसआर, शैक्षिक प्रशासन विभाग, न्यूपा और आई.आई.ई.पी., पेरिस द्वारा आयोजित नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;kstu dk vk;kstu

ब्रिटिश परिषद–भारत के सहयोग से, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल, नई दिल्ली, 10–11 नवम्बर, 2014 को सी.पी.आर.एच.ई., न्यूपा द्वारा आयोजित 'वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, (प्रो. एन.वी. वर्गीज़) के साथ समन्वयन।

''धन के प्रवाह और उनकी उपयोगिता का एक अध्ययन भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण'' पर अनुसंधान परियोजना के लिए अनुसंधान साधन को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला।

''धन के प्रवाह और उनकी उपयोगिता का एक अध्ययनः भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषण'' पर अनुसंधान परियोजना के लिए अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला।

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBîØe fodflr vkSj fu'ikfnr

''धन के प्रवाह का अध्ययन और उनकी उपयोगिताः भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण'' पर परियोजना के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान उपकरण विकसित।

अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला परियोजना के लिए मॉड्यूल विकसित।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

न्यूपा, नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014 – सी.पी.आर.एच.ई. द्वारा आयोजित भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (2015 आई.एच.ई.आर.) की प्रथम सहकर्मी समीक्षा लेखक बैठक में भाग लिया।

न्यूपा, नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2014 – सी.पी.आर.एच.ई. द्वारा आयोजित भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (2015 आई.एच.ई.आर.) की द्वितीय सहकर्मी समीक्षा लेखक बैठक में भाग लिया।

U;wwk d s c kgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

आजीवन सदस्य, तुलनात्मक शिक्षा समितियों के वर्ल्ड कांग्रेस से संबद्ध भारत तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सी.ई.एस.आई.)।

आजीवन सदस्य, भारतीय आर्थिक संघ।

efy'kk lh-, e-

vuqla/kku vè;;u

tkjh %

सह–प्रमुख अन्वेषक के रूप में आयोजन (संयुक्त रूप से निधि एस सब्बरवाल के साथ) अनुसंधान परियोजना ''विविधता और भेदभावः नागरिक अधिगम और लोकतांत्रिक बंधन के लिए उच्च शिक्षा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित। अनुसंधान के उद्देश्य युवाओं के बीच लोकतांत्रिक बंधन और नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए नीति और प्रथाओं को विकसित करना, कॉलेज परिसरों में विविधता और भेदभाव के मुद्दों को समझना है।

laxks'Bh@lEesyu@dk;Zkkyk,a

jk'Vªh; %

2014, फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और ''पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीतियों'' पर एक पैनल चर्चा में रैपोर्टियर के रूप में काम किया, नई दिल्ली, 12–14 नवम्बर, 2014

''उच्च शिक्षा तक पहुंचः'' अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ओबीसी और विकलांग छात्रों से संबंधित छात्रों द्वारा चुनौतियों पर काबू पाना, पर राष्ट्रीय सम्मेलन में (संयुक्त रूप से निधि एस सब्बरवाल के साथ): ''उच्च शिक्षा की भूमिका लोकतांत्रिक क्रियाओं और गैर भेदभावपूर्ण उपयोग पहुंच को बढ़ावा देने में; व्यवहार बाधाओं पर काबू पानाः शीर्षक पत्र प्रस्तुत, समान अवसर कार्यालय, जेएनयू, नई दिल्ली, 09–10 मार्च, 2015

भारत में उच्च शिक्षा, सी.पी.आर.एच.ई.–न्यूपा, 18 मार्च, 2015, प्रशासन और प्रबंधन पर परियोजना के लिए शोध के साधन पर चर्चा के लिए कार्यशाला में भाग लिया।

varjkZ"Vªh; %

संयुक्त रूप से सी.पी.आर.एच.ई. और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित, ''वृहद शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, और ''उच्च शिक्षा के सार्वजनीकरण के निहितार्थ एक सत्र में रैपोर्टियर के रूप में काम किया, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल, नई दिल्ली, 10–11 नवंबर, 2014

भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में (संयुक्त रूप से निधि एस सब्बरवाल के साथ) ''नागरिक अधिगम लोकतांत्रिक बंधन और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा शीर्षक से आलेख प्रस्तुत नई दिल्ली, 16–18 नवम्बर, 2014

संयुक्त रूप से आईसीएसएसआर, नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015 के दौरान न्यूपा और आई.आई.ई.पी. पेरिस द्वारा आयोजितः 'नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियांः उपेक्षित समूहों की शिक्षा' पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

çf'k{k.k dk;ØZe@lEesyu @dk;Zkkyk,sa dk vk;kstu

विविधता और भेदभाव पर परियोजना के तहत अनुसंधान उपकरण पर एक विशेषज्ञ समिति (संयुक्त रूप से निधि एस सब्बरवाल के साथ) आयोजित, न्यूपा, 12 जनवरी 2015

विविधता और भेदभाव पर परियोजना के तहत राज्य शोध टीमों के लिए एक अनुसंधान क्रियाविधि कार्यशाला (संयुक्त रूप से निधि एस सब्बरवाल के साथ) आयोजित, न्यूपा, 09–10 फरवरी, 2015

çf'k{k.k lkexzh vkSj ikBî Øe@dk;Zfodkl r

विविधता और भेदभाव पर अनुसंधान शुरू करने के लिए मात्रात्मक तरीकों और गुणात्मक विधियों पर सामग्री (निधि एस. सब्बरवाल के साथ) तैयार। विकसित सामग्री में प्रकोष्ठों/समितियों के प्रभारी के साथ साक्षात्कार प्रश्नावली, संकाय विशेषताओं और छात्रों के लिए प्रपत्र, छात्र सर्वेक्षण प्रश्नावली, छात्रों के साथ फोकस समूह हेतु सारणी, संस्थागत नेताओं तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय सवा योजना के प्रभारी, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय मैनुअल।

vU; 'kS{kd vkSj O;kolkf;d ;ksxnku

सी.पी.आर.एच.ई., न्यूपा, 25 जुलाई, 2014 को आयोजित भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट (आई.एच.ई.आर.) 2014, पर एक दिन की चर्चा बैठक में भाग लिया।

अभिविन्यास कार्यक्रम; विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विविधता और इक्विटी का प्रबंधन, न्यूपा, नई दिल्ली में: 'नीति की रूपरेखा और संस्थागत संदर्भ: समान उपयोग और भागीदारी' विषय पर एक पैनल चर्चा में ''संस्थागत संस्कृति और संस्थागत व्यवहार परिप्रेक्ष्य'' विषय पर एक भाषण दिया, 16–20 मार्च, 2015।

U;wikk dsckgj ç[;kr fudk;ksa dh lnL;rk

वार्षिक सदस्य, तुलनात्मक शिक्षा समितियों के वर्ल्ड कांग्रेस से संबद्ध भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी (सी.ई.एस.आई.)।

l ;kr u e aMy

çdk'ku

i qLrd sa@v è;k;

नोडल पायनियर आफ मास एजुकेशन–सत्येन मैत्रा (बंगाली में) कोलकाता: सत्येन मैत्रा जनशिक्षा समिति 2014। आईएसबीएन: 978–81–925972–2–5

'kksèk i=@y s[k@uksV~l %

'आईसीटी एंड इकॉनोमी आन द चेजिंग डायमेंशन आफ एजुकेशन एंड लर्निंग इन इंडिया – डबल–एज स्वोर्ड'' वी. मोहनकुमार, लाईफलॉग लर्निंग स्लैक्टेड आर्टिकल्स, नई दिल्ली: भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन 2014

vuqlaèkku vè;;u

tkjh %

परियोजना समन्वयक, 31 मार्च 2015 तक कार्यान्वित किये जाने वाली अनुसंधान परियोजना 'भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम', सी.पी.आर.एच.ई./न्यूपा अनुसंधान परियोजना, अनुसंधान प्रस्ताव का विकास, अनुसंधान उपकरणों के विकास, राज्य शोध टीमों के साथ समन्वयन इत्यादि, साधन बैठक में विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श परियोजना की योजना बनाने हेतु कार्यप्रणाली कार्यशाला का नियोजन आदि, 31 मार्च, 2015 से पहले किया गया।

l aks'Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk vk;ksftr@Hkkxhnkjh

jk"Vªh; %

सत्र समन्वयक, प्रौढ़, सतत् शिक्षा और विस्तार विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 20–21 अक्टूबर, 2014 द्वारा आयोजित आजीवन अधिगम और विस्तार की संभावनाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला।

çf'k{k.k dk;ØZe@lEesyu@dk;Z'kkyk dk vk;kstu

कार्यशाला, सी.पी.आर.एच.ई./न्यूपा, नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015 'भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम' पर सी.पी.आर.एच.ई./न्यूपा परियोजना के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण पर चर्चा करने हेतु।

न्यूपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्य, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ (आईएईए), नई दिल्ली।

आजीवन सदस्य, भारतीय पाउलो फ्रेरे संस्थान (आई.पी.एफ.आई.), कोलकाता।

fo|ky; eku d vkSj ewY;kadu ,d d

ç.kfr i kaMk ¼foHkkxkè;{k½

çdk'ku

iqLrdsa@vè;k; %

अन्डरस्टैण्ड द एजुकेशनल चेंज प्रोसेस एंड टीचर्स' वर्क. इन ट्रांसफोर्मिंग टीचर्स' वर्क ग्लोबली: इन सर्च आफ ए बैटर वे फार स्कूल्स एंड देअर कम्यूनिटीज', सेंस पब्लिशर्स, 2013. आईएसबीएनः 978–94–6209–468–0 (पेपरबैक), आईएसबीएनः 978–94–6209–469–7, (हार्डबैक) नीदरलैंड, पीपी 339–345 (लिंडा एम. हग्रीव्स, कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय ब्रिटेन द्वारा समीक्षा, 2014)

मैपिंग स्कूल इवाल्यूशन प्रैक्टिसेज इन इंडिया (2014), सहोदया, ए स्पेशल वाल्यूम ऑन स्कूल सैल्फ इवल्यूशन, कोबसे, नई दिल्ली।

स्कूल इवाल्यूशन इन इंडिया–डू दीज प्रैक्टिसेज इम्प्रूव स्कूल? (2015), 28 इंटरनेशनल कांग्रेस फार स्कूल इफैक्टिवनैस एंड इम्प्रूवमेंट, कान्फ्रेंस प्रोसीडिंग, http://www.icsei.net/fileadmin/2015/Program.pdf) (इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशन)

vuqla/kku vè;;u

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्कूल मूल्यांकन आचरण के महत्वपूर्ण विश्लेषणः स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम से सीख, न्यूपा, नई दिल्ली।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का एक अध्ययन, न्यूपा, नई दिल्ली (भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पर नीति विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)।

laxks'Bh@lEesyu@dk;Z'kkykvksa esa Hkkxhnkjh

jk'Vªh; %

शैक्षिक प्रशासन पर जेपी स्कूल, न्यूपा, नई दिल्ली, 09–13 जून, 2014 को प्रधानाध्यापकों के लिए अभिविन्यास–सह–कार्यशाला में स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर चर्चा पर आलेख प्रस्तुत किया।

'स्कूल शिक्षक के लिए आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षणः दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के अनुभव' आलेख प्रस्तुत किया, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर परामर्श बैठक के दौरान, नई दिल्ली, 20 अगस्त 2014

न्यूपा, नई दिल्ली, 08–12 सितम्बर, 2014 'दक्षिणी राज्यों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल भागीदारी में सुधार' विषय पर कार्यशाला मेंः 'शिक्षकों और स्कूल नेतृत्व की भूमिका बच्चों की सार्थक भागीदारी' पर प्रस्तुति।

प्रस्तुति एनएएसी प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी : ''अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, गुणवत्ता मानकों को दोहराना शिक्षा उन्नत संस्थान, 20 और 21 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित एक–दिन संगोष्ठी में भाग लिया, ''आपदा न्यूनीकरण दिवस'', विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2014

भागीदारी और आलेख प्रस्तुत ''भारत में स्कूल मानचित्रण आचरण मूल्यांकनः आत्ममूल्यांकन पर महत्वपूर्ण प्रतिबिंब कोबसे का 43वां वार्षिक सम्मेलन, अहमदाबाद, 07–09 नवम्बर, 2014

दो दिन के सम्मेलन में मुख्य वक्ता ''कॉर्पोरेट अभिशासन और अध्यापक शिक्षा के अलगाव को कम करने में इसकी भूमिका'', में मुख्य वक्ता आईपी यूनिवर्सिटी, एमिटी कैम्पस, नई दिल्ली, 12–13 नवंबर, 2014

''भविष्य के लिए स्कूल'',पर गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चाकार, ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014

राष्ट्रीय संगोष्ठी में अतिथि वक्ता 'अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में नीति में परिवर्तनः पूर्ण दृष्टिकोण', एमिटी शिक्षा संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, 3 मार्च, 2015

एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता,एक दिवसीय कार्यशाला, भारतीय शिक्षा प्रणाली में 'शिक्षक, नौ राज्यों के अध्ययन का संश्लेषण, राज्य रिपोर्ट का राष्ट्रीय संश्लेषण, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

v a j kZV ªh; %

संयुक्त रूप से एन.सी.एस.एल.–न्यूपा, नई दिल्ली और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय (ब्रिटेन), नई दिल्ली, 12–13 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित 'स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व', पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में भाग लिया।

'हाशिए पर समूह की शिक्षाः नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनौतियां' विषय पर अंतरीप क्षेत्रीय कार्यशाला पर एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता और भागीदारी, नई दिल्ली, 25–27 मार्च, 2015

c kg j fn; s x; s O; k[; ku %

''उच्च शिक्षा में प्रभावी शिक्षण और अधिगम'', विषय पर व्याख्यान दिया। संकाय विकास कार्यक्रम, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश), 29 जुलाई, 2014

''शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण घटक'', विषय पर व्याख्यान उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ, 30 सितम्बर, 2014 को एक व्याख्यान दिया।

ç f' k{k.k dk; Ø e@l Ee sy u@dk; Z'kky kv ka dk vk; kst u

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, भुवनेश्वर, जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक प्रशासकों के लिए राज्य सम्मेलन (ओडिशा), 08–09 मई, 2014

राष्ट्रीय तकनीकी समूह (एन.टी.पी.) की बैठक, न्यूपा, नई दिल्ली, अगस्त 16,2014

स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर कार्यशाला (एसएसई फ्रेमवर्क पर असहमति और राज्य विशेष स्कूल मूल्यांकन प्रथाओं के लिए, न्यूपा, नई दिल्ली, 30–31, अक्टूबर 2014

स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (प्रत्येक मुख्य क्षेत्र और बुनियादी मानकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए), न्यूपा, नई दिल्ली, 27–28 जनवरी, 2015

राष्ट्रीय स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पर परामर्शदाता बैठक, न्यूपा, नई दिल्ली, 10–11 फरवरी, 2015 (एन.पी.एस.एस.ई. और एस.एस.ई. रूपरेखा पर विचार–विमर्श करने के लिए)।

दस छोटे समूह (1–6 दिनों की अवधि) की कार्यशालाएं, मुख्य क्षेत्र और बुनियादी मानकों पर सुधार पर विचार–विमर्श और सुझाव हेतु आयोजित।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और निष्पादित

एम.फिल. और पीएच–डी कार्यक्रम के लिए भारत में कोर कोर्स–2 शिक्षा पर पाठ्यक्रम विकसित और संपादित।

स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई.), न्यूपा पर परिचालन दस्तावेज विकसित।

स्कूल मानकों और मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित, स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई.), न्यूपा।

v U; 'kS{kd vkS O; kol kf; d ; kxnku

i ; Z s{k.k@e kxZn'k u

चार पीएच–डी. अनुसंधान पर्यवेक्षण विद्वानों और समावेशी शिक्षा के लिए एक एम.फिल. विद्वान को स्कूल नेतृत्व, शासन और अध्यापक शिक्षा, शिक्षक पहचान और मूल्यांकन के प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

f' k{k.k %

एम.फिल. और पीएच–डी कार्यक्रम के लिए ''भारत में शिक्षा'' पर कोर पाठ्यक्रम का शिक्षण।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शैक्षिक प्रशासन कोर्स (904)।

शैक्षिक नेतृत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए स्कूल नेतृत्व में शिक्षण परिप्रेक्ष्य (कोर्स 102)।

v U; x fr fo fèk; ka %

प्रस्तुति, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा स्कूल मानकों और मूल्यांकन कार्यक्रम फ्रेमवर्क, न्यूपा, नई दिल्ली, 5 मई, 2014

ब्रिटिश परिषद विद्यालय कार्यक्रम, कक्षाओं को जोड़ना, विद्यालयों में वैश्विक नागरिकता और इसके महत्व पर प्रस्तुतिकरण और प्रमख साक्षात्कारकर्त्ता के रूप में साक्षात्कार, 21 अगस्त 2014, नई दिल्ली।

संक्षिप्त दस्तावेज साझा और राज्य शिक्षा सचिवों और आरएमएसए राज्य परियोजना निदेशक, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014 की एक बैठक में एन.पी.एस.एस.ई. पर प्रस्तुति दी।

''अध्यापक शिक्षा में सुधार'', विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2014 को विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य शिक्षा सचिवों की बैठक में भाग लिया।

प्रस्तुति, स्कूल के मानकों और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई.), सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2014

l koZ fu d fu d k; ka d ks i j ke 'kZ v k$ 'kS{ kd l gk; r k

एनसीटीई के लिए शैक्षिक समर्थन विस्तारित, एनसीटीई के अध्यापक शिक्षा से संबंधित पुनश्चर्या और अनुसंधान समिति के सदस्य के रूप में।

एनसीटीई के जर्नल समिति के सदस्य के रूप में, शिक्षक समर्थन पर जर्नल के विविध पहलुओं के लिए विस्तारित अकादमिक सहायता।

शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एम.एड. स्तर) (एनसीटीई और यूजीसी) के लिए दिशा निर्देशों पर एनसीटीई को शैक्षिक समर्थन दिया।

अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए ओडिशा और एससीईआरटी, ओडिशा सरकार को शैक्षिक समर्थन दिया।

एल.डी.यू.13 पर टेस, भारत, ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय मॉड्यूल की समीक्षाः अपने स्कूल में बेहतर समर्थन अधिगम और समानता को बढ़ावा देना, विविधता और समेकन हेतु स्कूल संस्कृति का विकास ।

बाहरी समीक्षक के रूप में, कोरियाई शैक्षिक नीति जर्नल के पांच शोध लेख की समीक्षा की।

छह पीएच–डी और एक एम.फिल. के लिए बाहरी विश्लेषक और परीक्षक। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय के शोध।

विभिन्न राज्यों के लिए विस्तारित अध्यापक शिक्षा, अकादमिक सहायता, अध्यापक शिक्षा केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन बोर्ड के सदस्य के रूप में।

U; wk d s c kg j ç [; kr fu d k; ka d h l nL; r k

आगन्तुक नामिनी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय

सदस्य, जर्नल सलाहकार बोर्ड, एनसीटीई

सदस्य, एससीईआरटी, नई दिल्ली कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड

सदस्य, अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, आरएमएसए (टीसीए)

कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, शिक्षक शिक्षा में सुधार, यूनिसेफ और एससीईआरटी, पुणे

शिक्षा नीति पर के.ई.डी.ई. जर्नल, अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड के सदस्य (के.जे.ई.पी.)

जर्नल आफ एजुकेशनल पालिसी

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सदस्य, अनुसंधान समिति, स्ट्राइड इग्नू।

सदस्य, स्कूल प्रभावशीलता और सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस

सदस्य, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ

संस्थापक सदस्य, शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय फोरम (आई.आर.ओ.आर.ई.)

सदस्य, छात्र संघ, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ

l pwukrd uhd h fo Hkkx

çks d s J hfu o kl

l ax kš'Bh@ l Ee sy u @ d k; Zkky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k'Vªh; %

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया – 8 अक्टूबर, 2014 'व्यावसायिक विकास और शिक्षकों को शिक्षा देने की क्षमता निर्माण पर कार्यशाला' आई.ए.एस.ई. प्रायोजित।

अनुसंधान प्रणाली में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए 'ई–लर्निंग और एमओओसी' (सामाजिक विज्ञान) पर एक दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला, आयोजन किया, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद विश्वविद्यालय, 3 दिसंबर, 2014

इंजीनियरिंग कॉलेज संकाय, (आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित) मदनापल्ली, आंध्र प्रदेश, 19–20 दिसम्बर, 2014 के दौरान दो दिवसीय कौशल उन्मुख व्यावसायिक विकास कार्यशाला 'पाठ्यक्रम मूडल एम.ओ.ओ.सी. मंच का उपयोग करते हुए आनलाईन पाठ्यक्रम का शिक्षण और शुभारम्भ।

U; wk l s c kgj O; k[; ku

यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, के लिए विशेषज्ञ संकाय 'शिक्षण और प्रशिक्षण उपकरण', के उभरते मुद्दों पर व्याख्यान दिया 1–2 जून, 2014

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ संकाय, कॉलेज लेक्चरर और आईसीटी तकनीकों पर यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, द्वारा सभी विषयों के लिए सह–प्रोफेसरों के लिए 86वें अभिविन्यास कार्यक्रम में, ''नवीन शिक्षण, प्रशिक्षण आचरण एवं प्रबंध समय, के लिए ई–संसाधनों के दत्तक ग्रहण'' पर व्याख्यान दिया, विषयों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओरिएंटेशन कोर्स और आईसीटी तकनीक के साथ लागत और संसाधन 3–4 अक्टूबर, 2014

व्याख्यान दिया कॉलेजों में आई.टी. व्यवहार और शिक्षण और सीखने के लिए ई–संसाधन का उपयोग'' ''महिला कॉलेज प्रधानाध्यापक कार्यक्रम, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जबलपुर, 17–21 नवंबर, 2014

''ई–संसाधन और शिक्षण पर व्याख्यान दिया, वरिष्ठ अकादमिक सदस्यों के लिए पांचवें साप्ताहिक व्यावसायिक विकास कर्यक्रम, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2014

v U; 'kS{kd v kS j O; kol kf; d ; kxn ku

f' k{k.k %

बीए अर्थशास्त्र छठे सत्र के लिए एक 4 क्रेडिट विशेष रुचि कोर्स पढ़ाया, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।

आकलन, मूल्यांकन और अनुसंधान (सी.ए.ई.आर), 30 अप्रैल, 2014 के लिए केंद्र की ओर से आयोजित शिक्षा में प्रौद्योगिकी वृहद आकलन, पर गोलमेज में भाग लिया।

l koZ fu d fu d k; ksa d ks i j ke 'kZ v kS 'kS{kd l gk; rk

मूल्यांकन पीएच–डी. थीसिस शीर्षक 'डेटा वर्गीकरण तकनीकों का उपयोग सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता के अनुमान'एम.वी.पी. चंद्रशेखर राव, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के संकाय, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।

पीएच–डी. मूल्यांकन और वायवा–वोस परीक्षा, सुश्री कल्पना कंप्यूटर विज्ञान संकाय, जामिया मिलिया

इस्लामिया, नई दिल्ली ''एन्हांसिंग आन्टोलॉजी अलाईनमेंट विद मशीन लर्निंग फार बेटर इंटिरियोपेराबिलिटी ऑफ सिमेन्टिक वेब'' शीर्षक थीसिस।

मूल्यांकन, पीएच–डी. थीसिस श्री मकाला रमेश, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, आंध्र प्रदेश विभाग के थीसिस मैमोग्राम एमेज एनहान्समेंट यूजिंग सब–बैंड इमेज आफ डि–कम्पोसिज़शन एंड मल्टी–वेबलेट ट्रांसफार्म विद मल्टी रिसाल्यूशन अनालिसिस''।

e kS kuk v c gq d y ke v kt kn i hB

, l bj Q ku g c hc

ç d k' ku

i qLr d @ y { k l e h{ kk%

मौलाना आजाद, इस्लाम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (सईदा हमीद द्वारा), सेमीनार, अक्टूबर 2014

सऊदी वहाबिज़्म के कट्टरपंथी चेहरे, 19 नवंबर 2014, हिंदू।

समाधान के रूप में विज्ञान। फ्रंटलाईन, 12 दिसंबर 2014

परमाणु राज्य बीसवीं सदी के भारत में वृहद विज्ञान (जाह्नवी फालके द्वारा), आइसिस में, इंटरनेशनल जर्नल आफ हिस्ट्री आफ साइंस, 105:4 (2014)।

v U; ' kS{ kd v kS O; k[;ku l s l hf[kk ;ksx n ku

''अंतर को पाटना: लोकतंत्र और असमानताओं'' पर प्रो. जोया हसन द्वारा दिए गए पांचवें मौलाना आजाद मेमोरियल व्याख्यान को आयोजित किया, 11 नवंबर, 2014 मौलाना आजाद पर गुब्बर–ए–ख़ातिर नाटक में दिग्गज अभिनेता टॉम ऑल्टर आजाद के रूप में।

Ác áku v kS fo d kl i j j kt ho x kák h LFkki u k i hB

fo e y k j ke p æu

ç d k' ku

i qLr d sa@ v è; k; %

''जैंडर्ड इनएक्वालिटीज इन एजुकेशन'', इन देवकी जैन और सी.पी. सुजाया (सं.) इंडियन वूमन रिविजिटेड, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग। 2014 (आईएसबीएन–978–81–230–1799–0)

''इक्विटी, क्वान्टिटी एंड क्वालिटी: द प्रेकारियस वैलेंसिंग एक्ट इन इंडियन स्कूल्स'', इन नूट एक्सल जैकबसन (एड.) रूटलेज हैंडबुक आफ कन्टमप्रेरी इंडिया, नार्वे, (आईएसबीएन:978–0–415–73865–1)

' kksèk i = @ y { k@ u kSV ł %

इवाल्यूशन आफ जैंडर एंड इक्विटी इश्यूज अन्डर सर्व शिक्षा अभियान (प्रेरणा गोयल चटर्जी के साथ) इंडियन जर्नल आफ जैंडर स्टडीज़, 21(2): 157–178

l ax ks'B h@ l Ee sy u @ d k; Z'kky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

j k"Vªh; %

चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं, यूजीसी द्वारा आयोजित ''भारत के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति'' शीर्षक (आदिवासी मामलों और यूएनडीपी के मंत्रालय के लिए डॉ. ए.एन. रेड्डी के साथ संयुक्त रूप से तैयार) मसौदा पृष्ठभूमि पत्र प्रस्तुत रायपुर (17–18 अक्टूबर, 2014),

गुवाहाटी (14–15 नवम्बर, 2014) और पुडुचेरी (3–5 फरवरी, 2015) (24 जून, 2014, दिल्ली)।

बोर्डिया मेमोरियल संगोष्ठी, नई दिल्ली, फरवरी 16–17,2015 न्यूपा में विकेंद्रीकरण पर आलेख।

प्रस्तुत आलेख ''भारत में अधिगम संकट – क्यों हम इस स्थिति में हैं'' सार्वजनिक व्याख्यान ए.एस.ई.आर. केंद्र, गुवाहाटी, 2 मार्च, 2015 द्वारा आयोजित।

''भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के काम की परिस्थितियों पर अध्ययन'' राष्ट्रीय प्रचार–प्रसार की बैठक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 20 मार्च 2015।

v ar jkZVªh; %

स्कूल शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन में चर्चाकार, न्यूपा, 12–13 फरवरी, 2015

çf'k{k.k dk;Øe@lEesyu@dk;Z'kkyk,

शैक्षिक नवाचार, पर प्रज्यतना कार्यशाला, 22 जुलाई, 2014 को न्यूपा में चर्चाकार।

शिक्षकों के काम की परिस्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला (9 राज्य रिपोर्टों को राय देने और राष्ट्रीय संश्लेषण के लिए मुख्य अंतर्दृष्टि को चुनना), 1–3 सितम्बर, 2014।

लिंग और शिक्षा, (संयुक्त रूप से रत्ना सुदर्शन, राष्ट्रीय अध्येता, न्यूपा) के साथ 20–30 जनवरी, 2015 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में।

jk'Vªh; v/;sk

,- eSF;w

çdk'ku

iqLrd esa@v è;k; %

चैप्टर आन ''कमीशन एंड कमीटी आन हायर एजुकेशन इन इंडिया: पर्सपैक्टिव्स, स्ट्रेटेजी एंड रिकमैन्डेशन आन मेजर इश्यू'' इन इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट, सैंटर फार पॉलिसी इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, न्यूपा (आगामी)

'kks/k i=@y{k@uksV~ %

''इंडियाज न्यू पर्सपैक्टिव्स आन एडल्ट एजुकेशन'', इन एनएलएमए (2014), कम्पेंडियम आन लिट्रेसी एंड इंक्लूसिव डवलपमेंट, नई दिल्ली, पृ. 29–32।

इंटरनेशनल बैंचमार्क्स एंड इवाल्यूटिंग पर्सपैक्टिव्स इन इंडियन एडल्ट एजुकेशन'', इन मोहन कुमार (सं.) (2014) एडल्ट एंड लाइफलांग लर्निंग, स्लैक्टेड आर्टिकल्स, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली, पीपी 9–35।

laxks"Bh@lEesyu@dk;Z'kkyk vkSj eaMkx hnkjh

jk'Vªh; %

न्यूपा, नई दिल्ली, 27 मई, 2014 शैक्षिक कार्यक्रमों और समता एवं लैंगिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आलेख, 'साक्षरता अभियान का मूल्यांकन से सबक' शीर्षक से आलेख प्रस्तुत किया।

भारत तुलनात्मक एजुकेशन सोसाइटी सम्मेलन–2014, दिल्ली विश्वविद्यालय, 16 नवंबर, 2014: अप्राप्त लक्ष्य की गाथा, झूठे वादे: भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण'' पर आलेख प्रस्तुत किया।

आलेख प्रस्तुत ''साक्षरता आंदोलन और विकेंद्रीकरण: विकेंद्रीकृत शासन के रूप में संपूर्ण साक्षरता अभियान'' लोगों की भागीदारी और विकेन्द्रीकृत शैक्षिक शासन: नीतिगत सुधार और कार्यक्रम आचरण पर द्वितीय अनिल बोर्डिया मेमोरियल पॉलिसी संगोष्ठी, न्यूपा, नई दिल्ली, फरवरी 16–17, 2015।

भारत में उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी: हाशिये से केन्द्र और नीति में प्रभुत्वता विषय पर शोध आलेख प्रस्तुत, ग्ग्टप्प भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, 29 मार्च से 1 अप्रैल, 2015

v U; 'kS{kd vkS Oj kol kf; d ;ksx nku

आजादी के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सभी नीतिगत दस्तावेजों को दुनिया भर में आन–लाईन उपयोग हेतु 2012 में स्थापित न्यूपा डिजिटल अभिलेखागार के शिक्षा दस्तावेजों को 24ग7 और 365 दिन उपलब्ध कराया गया। डिजिटल अभिलेखागार केन्द्र की पंचवर्षीय योजनाओं और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई की वार्षिक रिपोर्ट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्य घटकों की तरह सभी नीतिगत दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री के लिए आसान पहुँच प्रदान करता है। न्यूपा के डिजिटल अभिलेखागार में 8000 से अधिक पूर्ण पाठ दस्तावेज है और लगातार बढ़ रहे हैं। प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए, दस्तावेजों को 18 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे अधिनियम, विधेयक, अदालत के आदेश, शैक्षिक योजनाएं, आरटीई, योजनाएं, आयोग और समिति की रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्ट, इन श्रेणियों में से प्रत्येक को आगे के रूप में उप–वर्गीकृत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के दस्तावेजों, के अनुसार किया गया है। दस्तावेज क्षेत्रीय भाषाओं में होने पर कई मामलों में, शीर्षक और बुनियादी सामग्री का अनुवाद प्रदान किया गया है।

U; wk d s ckgj ç[;kr fud k; ksa d h l nL; r k

सदस्य, भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी

सदस्य, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

j Ru k , e- l q 'kZ

çd k' ku

' kksèk i =@y s[k@u ksV l %

''एजुकेशन एंड सोशल ट्रांसफोरमेशन इन इंडियाः रोल फार एक्शन–बेस्ड रिसर्च एंड इवाल्यूएशन?' एजुकेशनल एसेसमेंट इवाल्यूऐशन एंड अकाउन्टाबिलिटी (2015), वॉल्यूम। 27(1): 85–92.

'इनेबलिंग वूमन वर्क (अक्टूबर 2014), आईएलओ एशिया–पैसिफिक वर्किंग पेपर सिरीज, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_324624.pdf

'अकाउंटिंग फार वूमन इम्पावरमेंटः मेटा इवाल्यूशन फ्राम ए जैंडर एंड इक्विटी लैंस' (रंजनी के. मूर्ति, श्रद्धा चिगातेरी के साथ) नवम्बर 2014, इवाल्यूशन कनैक्शन अवेलेवल एट http://www.europeanevaluation.org/resources/connections

l a ks'Bh@l Ee sy u @d k; Z kky kv ksa e sa Hkkx hn kj h

v a j kZV ªh; %

ससेक्स विश्वविद्यालयः 29–31 मई, 2014 के दौरान आयोजित, ''बियान्ड 2015:पाथवेज़ टू ए जेंडर जस्ट वर्ल्ड' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पैनल अध्यक्ष।

ग्यारहवीं यूरोपीय मूल्यांकन सोसायटी, द्विवार्षिक सम्मेलन, डबलिन, 29 सितम्बर – 3 अक्टूबर, 2014 (अध्यक्ष/पैनलिस्ट)।

''भारतीय अनुभव पर विचार आयोजन, लिंग और एकजुटताः भारतीय अनुभव पर विचार'' शीर्षक से आलेख प्रस्तुत क्या एकजुट अर्थव्यवस्था नारीवादी हो सकती है?' ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिनेवा, 16–17 अक्टूबर, 2014 के दौरान आयोजित।

çf' k{k.k d k; ZØe@l Ee sy u @d k; Z kky kv ksa d k v k; kst u

'विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और लिंग और समता लेंस को शामिल करने के साथ मूल्यांकन, पर संवर्धन बैठक, न्यूपा, (ए मैथ्यू और विमला रामचंद्रन के साथ) 27 मई 2014

'लिंग और शिक्षा' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, न्यूपा, 20–30 जनवरी, 2015 (विमला रामचंद्रन और निरंतर के साथ) 14 अगस्त 2015

i fj f' k"V

i fj f' k'V I

U; wk i fj "kn~ d s l n L;

¼31 ekp Z 2015 d s v u q l kj ½

अध्यक्ष

1. श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी
   माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री
   भारत सरकार,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

उपाध्यक्ष

2. प्रो. आर गोविंदा
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन
   विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली –110016

पदेन सदस्य

3. सचिव
   भारत सरकार
   उच्च शिक्षा विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   नई दिंल्ली–110001

4. सचिव
   भारत सरकार
   स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   नई दिल्ली–110001

5. अध्यक्ष
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   नई दिल्ली–110002

6. निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
   नई दिल्ली–110016

7. वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   भारत सरकार
   नई दिल्ली–110001

¼U; wk i fj "kn d s v /; {k } kj k i fj Øe okj j kT; i zfr fu f/k e u ksu hr] i kp {ks=kal s, d &, d l n L; ½

8. सचिव, (विद्यालय शिक्षा)
   तमिलनाडु सरकार
   सचिवालय
   फोर्ट स्टेफन जॉर्ज, गिन्डी
   चेन्नई–600009

9. सचिव (उच्च शिक्षा)
   गुजरात सरकार
   ब्लॉक नं. 5, सातवीं मंजिल
   न्यू सचिवालय कॉम्प्लेक्स
   गांधीनगर–382010 (गुजरात)

10. सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा)
दिल्ली सरकार
मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा
दिल्ली–110034

11. आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)
नागालैंड सरकार
सिविल सचिवालय, कोहिमा–797001
नागालैंड

12 सचिव (स्कूल शिक्षा)
छत्तीसगढ़ सरकार
डीकेएस भवन, मंत्रालय
रायपुर–469001
छत्तीसगढ़

प्रख्यात शिक्षाविद्

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

13. श्री राजेन्द्र एस. पवार
निदेशक, एनआईआईटी लि.
सैक्टर 32, प्लाट नं. 85
गुड़गांव (हरियाणा)

14. प्रो. दीपक नैयर
पूर्व कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय
एफ–5, फ्रैण्ड्स कॉलोनी (पश्चिम)
नई दिल्ली–110065

15. प्रो. पंकज चन्द्रा
निदेशक
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर
बनेरघाटा रोड
बंगलौर–560076

न्यूपा संकाय

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

16. प्रो. जंध्याला बी.जी. तिलक
अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त विभाग
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

17. श्री बसवराज स्वामी सचिव
कुलसचिव
न्यूपा, नई दिल्ली–110016

i fj f'k"V II

izca/ku cksMZ ds lnL;

¼31 ekpZ 2015 ds vuqlkj½

1. प्रो. आर. गोविंदा, अध्यक्ष
   कुलपति
   न्यूपा, नई दिल्ली – 110016

सदस्य

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

2. प्रो. फरीदा अब्दुल्ला खान, सदस्य
   राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
   लोक नायक भवन, पांचवा तल
   खान मार्केट, नई दिल्ली–110 003

3. प्रो. एम. आनन्दकृष्णन
   अध्यक्ष, आईआईटी कानपुर
   नं. 8/15, पांचवा मेन रोड,
   मदन अपार्टमेंट,
   कस्तूरीबाई नगर, अडयर चेन्नई–600 020

4. प्रो. पीटर रोनॉल्ड डिसूजा
   प्रोफसर
   अन्तर्राष्ट्रीय मानव विकास केन्द्र
   29, राजपुर रोड,
   दिल्ली–110092

अन्य सदस्य

5. श्री राकेश रंजन, आईएएस
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001

6. प्रो. जंध्याला बी.जी. तिलक, अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

7. प्रो. के. सुजाता
   तुलनात्मक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

8 प्रो. वाई. जोसेफिन
   प्रोफेसर
   शैक्षिक प्रशासनिक विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

9. श्री बसवराज स्वामी, सचिव
   कुलसचिव
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110016

i fj f' k'V III

foÙk lfefr dslnL;

¼31 ekpZ 2015 dsvuqlkj½

---

1. प्रो. आर. गोविंदा, *अध्यक्ष*
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली – 110016

अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित सदस्य

2. डा. बी.के. महापात्रा
   कुलसचिव
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
   नई महरौली रोड
   नई दिल्ली–110 067

3. प्रो. एन. यू. सिदि्दकी
   वित्त अधिकारी
   जामिया मिल्लिया इस्लामिया
   नई दिल्ली–110025

मा.सं.वि. मंत्रालय के प्रतिनिधि
(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

4. वित्तीय सलाहकार
   मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001

अन्य सदस्य

5. प्रो. एन.डी. माथुर,
   अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
   सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान
   किशनगढ़, अजमेर
   राजस्थान

6. श्री बसवराज स्वामी, विशेष आमंत्रिती
   कुलसचिव
   न्यूपा
   नई दिल्ली – 110016

7. श्रीमती उषा त्यागराजन, वित्त अधिकारी
   सचिव
   न्यूपा
   नई दिल्ली–110 016

i fj f' k'V IV

v d kn fe d i fj "kn d s l n L;

¼31 ekp Z 2015 d s v uq kj½

1. प्रो. आर. गोविंदा *अध्यक्ष*
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली – 110016

विभागाध्यक्ष, न्यूपा

2. प्रो. जंध्याला बी.जी. तिलक
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110016

3. प्रो. के. सुजाता
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशासन विभाग
   न्यूपा, नई दिल्ली–110 016

4. प्रो. (श्रीमती) नजमा अख्तर
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

5. प्रो. सुधांशु भूषण
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली – 110 016

6. प्रो. अरुण. सी. मेहता
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली – 110 016

7. प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली – 110 016

8. प्रो. ए.के. सिंह
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शिक्षा–आधार विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

9. प्रो. नलिनी जुनेजा
प्रोफेसर और अध्यक्ष
विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग
न्यूपा, नई दिल्ली–110 016

विख्यात शिक्षाविद्

(अध्यक्ष, न्यूपा परिषद द्वारा नामित)

10. प्रो. एन. जयराम
सेंटर फार रिसर्च मैथोडोलॉजी
टाटा इस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज
वी.एन. पूरव मार्ग, द्योनार, मुंबई–400088

11. प्रो. एन.जे. कुरियन
आगन्तुक प्रोफेसर
समाज विकास परिषद विभाग,
741, सैक्टर–21, निकट पालम विहार
गुड़गाँव–122017

12. प्रो. गीता सेन
भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर
बनेरघाटा रोड,
बंगलौर–560076

न्यूपा संकाय

(कुलपति, न्यूपा द्वारा नामित)

13. प्रो. सतीश देशपाण्डे
समाजशास्त्र विभाग
दिल्ली स्कूल आफ इकानमिक्स
दिल्ली विश्वविद्यालय

14. प्रो. एच रामचन्द्रन
आई.सी.एस.एस.आर., राष्ट्रीय अध्येता
ई–1675, पालम विहार
गुड़गाँव–122017

15. प्रो. पी. बालकृष्णन, निदेशक
विकास अध्ययन केन्द्र
प्रशान्त नगर के पास,
उल्लूर, त्रिवेन्द्रम–695011

न्यूपा संकाय

16. डा. रश्मि दीवान
सह–प्रोफेसर
न्यूपा,
नई दिल्ली–110016

17. डा. आर.एस. त्यागी
सहायक–प्रोफेसर
न्यूपा,
नई दिल्ली–110016

17. श्री बसवराज स्वामी *सचिव*
कुलसचिव
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

ifjf'k"V V

v/;;u cksMZ ds lnL;

¼31 ekpZ 2015 ds vuqlkj½

1. प्रो. आर. गोविंदा, *अध्यक्ष*
   कुलपति
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली–110 016

2. डीन
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

विभागाध्यक्ष, न्यूपा

3. प्रो. जंध्याला बी.जी. तिलक
   शैक्षिक वित्त विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

4. प्रो. के. सुजाता
   शैक्षिक प्रशासन विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

5. प्रो. (श्रीमती) नजमा अख्तर
   प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110016

6. प्रो. सुधांशु भूषण
   उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

7. प्रो. अरुण सी. मेहता
   शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

8. प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी
   शैक्षिक योजना विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

9. प्रो. नलिनी जुनेजा
   विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग
   न्यूपा,
   नई दिल्ली–110 016

10. प्रो. ए.के. सिंह
    शैक्षिक योजना विभाग
    न्यूपा,
    नई दिल्ली–110 016

अन्य न्यूपा संकाय
(कुलपति, न्यूपा द्वारा नामित)

11. प्रो. एन.वी. वर्गीज़
निदेशक, सीपीआरएचई
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

12. प्रो. रश्मि दिवान
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

13. प्रो. के. बिस्वाल
परियोजना प्रबंधन ईकाई विभाग
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

14. डा. (श्रीमती) वीरा गुप्ता
शैक्षिक नीति विभाग
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

15. डा. नीरू स्नेही
उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

16. प्रो. वीणा आर. मिस्त्री
बी–5, सी.एस. पटेल एन्क्लेव
3, प्रताप गंज, बड़ोदरा–390 002

17. प्रो. एस. होम चौधरी
ए–47/9, अपर रिपब्लिक
आईजोल–796001

18. प्रो. वसंत भट्ट
डीन – प्रोफेसर
श्रीजनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन
मैसूर

19. श्री बसवराज स्वामी *सचिव*
कुलसचिव
न्यूपा,
नई दिल्ली–110 016

i fj f' k'V VI

l adk; vkS i z'kkl fud LVkQ

¼31 ekp Z 2015 d s vu q kj½

कुलपति

प्रो. आर. गोविंदा

शैक्षिक योजना विभाग

एस.एम.आई.ए. जैदी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मोना खरे, प्रोफेसर
के. बिस्वाल, प्रोफेसर
एन.के. मोहंती, सहायक प्रोफेसर
सुमन नेगी, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रशासन विभाग

के. सुजाता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
कुमार सुरेश, प्रोफेसर
विनीता सिरोही, सह–प्रोफेसर
आर.एस. त्यागी, सह–प्रोफेसर
मंजू नरूला, सहायक प्रोफेसर
वी. सुचरिता, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक वित्त विभाग

जंध्याला बी.जी. तिलक, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वाई. जोसेफिन, प्रोफेसर
पी. गीता रानी, सह–प्रोफेसर
वेटुकुरी पी.एस. राजू, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक नीति विभाग

अविनाश के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, सह–प्रोफेसर
मनीषा प्रियम, सह–प्रोफेसर
एस.के. मलिक, सहायक प्रोफेसर
नरेश कुमार, सहायक प्रोफेसर

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग

नलिनी जुनेजा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
नीलम सूद, प्रोफेसर
प्रणति पांडा, प्रोफेसर
रश्मि दिवान, प्रोफेसर
मधुमिता बंद्योपाध्याय, सह–प्रोफेसर
सुनीता चुघ, सह–प्रोफेसर
कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग

सुधांशु भूषण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
आरती श्रीवास्तव, सह–प्रोफेसर
नीरू स्नेही, सहायक प्रोफेसर
कौसर विजारत, सहायक प्रोफेसर
संगीता अंगोम, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

अरुण सी. मेहता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
ए.एन. रेड्डी, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

नज़मा अख्तर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
बी.के. पांडा, प्रोफेसर
सविता कौशल, सहायक प्रोफेसर
मोना सेदवाल, सहायक प्रोफेसर

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

रश्मि दीवान, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष
सुनीता चुग, सह–प्रोफेसर
एन. मैथिली, सहायक प्रोफेसर
सुविथा जी.वी., सहायक प्रोफेसर

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

एन.वी. वर्गीज, प्रोफेसर और निदेशक
निधि सदाना सभरवाल, सह–प्रोफेसर
अनुपम पचौरी, सहायक प्रोफेसर
गरिमा मलिक, सहायक प्रोफेसर
जिनुशा पाणिग्रही, सहायक प्रोफेसर
मलिश सी.एम., सहायक प्रोफेसर
सायंतन मंडल, सहायक प्रोफेसर

विद्यालय मानक और मुल्यांकन एकक

प्रणति पांडा, प्रोफेसर और अध्यक्ष

परियोजना प्रबंधन एकक

के. बिस्वाल, प्रोफेसर और अध्यक्ष

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ

एस. इरफान हबीब, प्रोफेसर

अध्यापक प्रबंधन और विकास पर राजीव गाधी स्थापना पीठ

विमला रामचन्द्रन, प्रोफेसर

राष्ट्रीय अध्येता

ए. मैथ्यू, प्रोफेसर
रत्ना मंगला सुदर्शन, प्रोफेसर

सलाहाकार (आई.ए.आई.ई.पी.ए. परियोजना)

के. रामचन्द्रन, प्रोफेसर

प्रशासनिक और अकादमिक सहयोग

कुलसचिव
बसवराज स्वामी

सामान्य और कार्मिक प्रशासन
जी. वीराबाहु, प्रशासनिक अधिकारी
जय प्रकाश धामी, अनुभाग अधिकारी
बी.आर. पाहवा, अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)

अकादमिक प्रशासन
पी.पी. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी

वित्त और लेखा
उषा त्यागराजन, वित्त अधिकारी
चंद्र प्रकाश, अनुभाग अधिकारी

प्रशिक्षण कक्ष
पी.एन. त्यागी, प्रशिक्षण अधिकारी
(31.1.2015 को सेवा निवृत्ति)
जय प्रकाश धामी, अनुभाग अधिकरी (प्रभारी)

प्रकाशन एकक
प्रमोद रावत, उप प्रकाशन अधिकारी

हिंदी कक्ष
डा. सुभाष सी. शर्मा, हिंदी संपादक और सहायक हॉस्टल वार्डन

छात्रावास
कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर और सहायक हॉस्टल वार्डन

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र
पूजा सिंह, पुस्तकालयाध्यक्षा
डी.एस. ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी

कंप्यूटर केंद्र
के. श्रीनिवास, प्रोफेसर और अध्यक्ष, आई.सी.टी.
श्री नवीन भाटिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर

VII

वार्षिक लेखा

2014-15

r gyu i=

31 ekpZ2015 rd

राशि ₹ में

fuf/k dslzksr@nsrk,a	vuqlwph	pkyw o"kZ	foxr o"kZ
पूंजीकृत निधि	1	-	19,87,90,194
मौजूदा देनदारियां एवं प्रावधान	2	47,30,83,480	8,87,34,531
; ksx		47,30,83,480	28,75,24,725
आस्तियों का आवेदन/परिसम्पत्तियां	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियां	3	19,07,87,120	17,81,88,975
चालू परिसंपत्तियां	4	10,32,14,778	6,19,44,020
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशियां	5	5,26,33,882	4,73,91,730
पूंजी निधि	-	12,64,47,700	-
; ksx		47,30,83,480	28,75,24,725
लेखा की महत्वपूर्ण नीतियां	15		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां	16		

ह./–
¼m'kk R;kxjktu½
वित्त अधिकारी

ह./–
¼cl ojkt Lokeh½
कुलसचिव

ह./–
¼v kj- xksfoanjk½
कुलपति

v k; v k$S O; ; y $kk

31 e kp Z2015 r d

राशि ₹ में

fo oj.k	v uql p h	p ky wo"kZ	fox r o"kZ
v - v k;			
शैक्षणिक प्राप्तियां	6	1,19,76,379	73,86,269
अनुदान/सब्सिडी	7	25,70,61,459	20,81,16,353
अर्जित ब्याज	8	12,80,743	34,06,179
अन्य आय	9	25,72,366	41,00,795
योग (अ)		27,28,90,947	22,30,09,597
c - O; ;			
कर्मचारियों के भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	10	15,21,09,200	¼
अकादमिक व्यय	11	6,29,19,877	5,91,89,423
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	12	3,38,60,997	2,21,62,938
मरम्मत एवं रखरखाव	13	1,54,29,035	84,54,786
मूल्यह्रास	3	1,39,00,644	94,98,201
पूर्वावधि के व्यय	14	34,64,07,878	-
; kx ¼c ½		**62,46,27,631**	**24,22,44,361**
i w h fu f/k e sa g ks j g s v f/k' ks"k@ ¼?kkVk½		**(35,17,36,684)**	**(1,92,34,764)**

ह./—
¼m'kk R; kx j kt u½
वित्त अधिकारी

ह./—
¼cl o j kt Lo ke h½
कुलसचिव

ह./—
¼v kj - x kfo an k½
कुलपति

vuqlwph 1 ls 5
31 ekpZ 2015 dks lekIr foÙkh; o"kZ dk rqyu i=

vuqlwph 1

dks"k@iwath fuf/k

राशि ₹ में

fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
वर्ष के प्रारंभ में शेष	19,87,90,194	16,56,76,185
जमाः राशि/पूंजी निधि में योगदान	2,58,55,485	5,18,83,647
जमाः उपहार/दान में प्राप्त आस्तियां	5,272	84,016
जमाः अन्य परिवर्धन (पिछले वर्ष में उपहार में प्राप्त पुस्तकें)	-	3,81,110
जमाः प्रयोजित परियोजना निधि से खरीदी गई आस्तियां	6,38,033	-
जमाः व्यय खाते में स्थानांतरित व्यय पर आय से अधिक आय	-	-
;ksx	**22,52,88,984**	**21,80,24,958**
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित घाटाा	35,17,36,684	1,92,34,764
o"kZ ds var esa 'ks"k	**(12,64,47,700)**	**19,87,90,194**

vuqlwph 2

ekS wk nsunkfj;ka vkSj izko/kku

राशि ₹ में

fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
अ. वर्तमान देनदारियां		
प्रतिभूति राशि	5,29,858	4,91,883
पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	1,16,062	1,49,846
बकाया देयता	15,973	15,973
प्रायोजित परियोजना की प्राप्तियां कुल व्यय)	7,24,70,847	2,90,76,829
अग्रिम में प्राप्त आय (वर्ष 2014–15 की अप्रयुक्त अनुदान)	4,77,63,185	-
;ksx ¼v½	**12,08,95,925**	**2,97,34,531**
Ck- izko/kku		
पेंशन	30,42,03,067	4,50,00,000
उपदान	3,10,59,535	90,00,000
अवकाश नकदीकरण	1,69,24,953	50,00,000
;ksx ¼c½	**35,21,87,555**	**5,90,00,000**
;ksx ¼v +c½	**47,30,83,480**	**8,87,34,531**

vuqlwph 2 ¼v½

izk;ksftr ifj;kstuk

राशि ₹ में

Ø- l a	Ikfj;kstuk dk uke	izkjfEHkd tek		o"kZ d s nkSjku izkfIr;ka@ olwyh	dqy	o"kZ d s nkSjku O;;	tek 'ks"k	
		nsSu Ø;	tek 'ks"k				ukes	tek
1	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2010 (प्रो. बी.के. पांडा)	(22,74,786)	-	39,20,974	16,46,188		(26,43,096)	-
2	डाईस की स्थापना और संचालन (यूनीसेफ़) डा. ए.सी. मेहता	-	14,80,239	55,31,540	70,11,779		-	21,62,063
3	सर्वशिक्षा अभियान पर परियोजना (मा.सं.वि. मंत्रालय) (प्रो. ए.सी. मेहता)	-	45,011	6,50,606	6,95,617	4,73,447	-	2,22,170
4	ससेक्स विश्वविद्यालय के सहयोगात्मक परियोजना के संदर्भ में भारत में प्राथमिक शिक्षा (क्रिएट) डा. आर. गोविंदा)	-	2,025	-	2,025	-	-	2,025
5	स्कूल प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2006 (डा. आर.एस. त्यागी)	-	20,37,727	-	20,37,727	-	-	20,37,727
6	14 राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में ग्रा.शि.स./ डी.टी.ए./एस.एम. डी.सी./नगरीय निकायों की भूमिका का अध्ययन, एडसिल (प्रो. ए.के. सिंह)	-	10,64,860	-	10,64,860	2,03,393	-	8,61,467
7	माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रणाली प्रबंधन (सेमिस) मा.सं.वि. मंत्रालय (प्रो. ए.सी. मेहता)	-	31,74,681	-	31,74,681	6,05,724	-	25,68,957
8	यूनेस्को संविदा सं. 4500084591: माध्यमिक शिक्षक नीति तथा प्रबंधन (डा. प्रणति पांडा)	-	1,58,411	-	1,58,411	-	-	1,58,411

9	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का मुद्दे (यू.जी.सी. सहयोग) (डा. सुधांशु भूषण)	-	53,250	-	53,250	-	-	53,250
10	बुरूण्डी में भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (दक्षिण अफ्रीका)	-	25,64,658	-	25,64,658	2,09,843	-	23,54,815
11	एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के चुनिंदा विकासशील देशों में विद्यालय कार्य सूचना आधार (डा. विनीता सिरोही)	-	69,995	-	69,995	-	-	69,995
12	विश्व के वृहद विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा के त्वरित विस्तार का संभावित आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव (डा. जे.बी.जी. तिलक)	-	5,15,281	-	5,15,281	-	-	5,15,281
13	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (एडसिल) डॉ. के. सुजाता	-	2,16,440	-	2,16,440	8,10,000	(5,93,560)	-
14	शिक्षा–दक्षिण एशिया (डा. मोहन्ती/डा. जैदी)	-	28,881	-	28,881	-	-	28,881
15	महात्मा गांधी शान्ति शिक्षा संस्थान (एम.जी. आई.ई.पी.)	-	7,96,458	-	7,96,458	8,000	-	7,88,458
16	नेतृत्व कार्यक्रम (मा.सं. वि. मंत्रालय) डा. रश्मि दीवान	-	50,36,264	91,77,800			(12,44,025)	-
17	भारत में आर.एम. तथा सैनिक स्कूल (डा. प्रमिला मेनन)	-	4,02,189	-	4,02,189	-	-	4,02,189
18	आई.एस.एस.टी. परियोजना – डा. वी. रामचंद्रन	-	45,300	-	45,300	-	-	45,300
19	दक्षिण एशिया 4 देश – भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान (यूनिसेफ)	-	4,78,168	-	4,78,168	-	-	4,78,168

20	अध्यापक विकास और प्रबंधन राजीव गांधी स्थापना पीठ (प्रो. वी. रामचन्द्रन)	-	3,16,389	56,83,611	60,00,000	56,58,118	-	3,41,882
21	डीईओ– भूटान किंगडम परियोजना (प्रो. बी.के. पांडा)	-	26,50,039	-	26,50,039	-	-	26,50,039
22	नीति अनुसंधान केन्द्र (यूजीसी) (प्रो. एन.वी. वर्गीज)	-	23,50,049	457,17,000	480,67,049	148,70,974		331,96,075
23	राष्ट्रीय अध्येयता (आईसीएसएसआर) प्रो. एहसानुल हक	-	70,000	2,88,000	3,58,000	7,20,000	(3,62,000)	-
24	इंडोनेशिया कार्यक्रम (प्रो. बी.के. पांडा)	-	6,34,917	8,64,362	14,99,279	2,93,987	-	12,05,292
25	प्रशासनिक उपरिव्यय प्रभार/बचत खाता पर ब्याज	-	48,85,597	5,94,734	54,80,331	8,36,480	-	46,43,851
26	विविधता भेदभाव और असमानता के साथ लेनदेन (डा. निधि सदाना – सीपीआरएचई)	-	-	18,00,000	18,00,000	17,40,412	-	59,588
27	जेपी समूह स्कूलों के प्रधानाचार्यों की 5 दिवसीय कार्यशाला (प्रो. के. सुजाता)	-	-	3,60,000	3,60,000	75,653	-	2,84,347
28	केन्द्रीय योजना कार्यक्रम विद्यालय मानक और मूल्यांकन शिक्षा (प्रो. प्रणति पांडा)		-	2,42,06,000	2,42,06,000	68,65,384		1,73,40,616
	; kx	**(22,74,786)**	**2 ,90,76,829**	**9,87,94,626**	**12,55,96,669**	**5,79,68,504**	**(48,42,681)**	**7,24,70,847**

vuqlwph 2 ¼j½

ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ls izkIr vuiz;qDr vuqnku

राशि ₹ में

fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
अ. योजना अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
शेष राशि अग्रानीत	4,76,53,129	-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	12,06,97,000	11,85,00,000
;ksx ¼v½	**16,83,50,129**	**11,85,00,000**
घटाकर: राजस्व व्यय के लिए उपयोग	9,54,79,646	7,29,31,710
घटाकर: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	2,51,07,298	4,55,68,290
;ksx ¼c½	**12,05,86,944**	**11,85,00,000**
vuiz;qDr vxzkuhr ¼v&c½	**4,77,63,185**	-
c- vuqnku ;kstusrj ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;		
शेष राशि अग्रानीत	1,11,70,481	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	15,11,59,519	14,15,00,000
;ksx ¼l½	**16,23,30,000**	**14,15,00,000**
घटाकर: राजस्व व्यय के लिए उपयोग	16,15,81,813	14,12,34,250
घटाकर: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	7,48,187	2,65,750
;ksx ¼n½	**16,23,30,000**	**14,15,00,000**
vuiz;qDr vxzkuhr ¼l&n½	-	-
egk;ksx ¼v+c½	**4,77,63,185**	-

vuqlwph 3

vpy laifÙk;ka

राशि ₹ में

Ø- la	vkfLr ;ka'kh kZ	e w; âkl dh nj	Lkd y Cy kW v Fk ' kk	i fj o/kZu ; kss u k	i fj o/kZu ; kss us j	v U;	Tke k ' kk (4+5+6-7)	o"kZd s fy , e w; âkl v Fk ' kk	o"kZd s fy , e w; âkl i fj o/kZ i j o"kZd s n kSj ku e w; âkl	o"kZd s fy , e w; âkl d VkS h@ l e k; kst u	d qy e w; âkl (9+10-11)	fu o y Cy kW 31.03.15 (8-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भूमि	0%	23,07,892	-	-	-	23,07,892	-	-	-	-	23,07,892
2	भवन	2%	12,64,97,120	-	-	-	12,64,97,120	25,29,942	-	-	25,29,942	12,39,67,178
3	कार्यालय उपकरण	7.50%	1,13,73,656	7,16,279	-	-	1,20,89,935	8,53,024	53,721	-	9,06,745	1,11,83,190
4	कम्प्यूटर और उपकरण	20%	36,35,038	29,70,228	-	-	66,05,266	7,27,008	2,22,767	-	9,49,775	56,55,491
5	फर्नीचर फिक्सर और फिटिंग	**7.50%**	**61,18,936**	**1,30,879**	-	-	**62,49,815**	**4,58,920**	**9,816**	-	**4,68,736**	**57,81,079**
6	वाहन	10%	11,03,834	-	7,48,187	-	18,52,021	1,10,383	74,819	-	1,85,202	16,66,819
7	पुस्तकालय पुस्तकें	10%	54,14,722	25,48,114	-	-	79,62,836	5,41,472	1,91,109	-	7,32,581	72,30,255
8	जर्नल	10%	1,91,27,856	75,55,462	-	-	2,66,83,318	19,12,786	5,66,660	-	24,79,445	2,42,03,873
	; kx ¼v½		**17,55,79,054**	**1,39,20,962**	**7,48,187**	-	**19,02,48,203**	**71,33,536**	**11,18,891**	-	**82,52,426**	**18,19,95,777**
9	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	3,81,221	98,51,952	-	-	1,02,33,173	1,52,488	39,40,781	-	40,93,269	61,39,904
10	ई–जर्नल	40%	22,28,700	13,39,656	-	-	35,68,356	8,91,480	5,35,862	-	14,27,342	21,41,013
	; kx ¼c½		26,09,921	1,11,91,608	-	-	1,38,01,529	10,43,968	44,76,643	-	55,20,611	82,80,917
11	अन्य (प्रायोजित)	20%	-	-	-	6,38,033	6,38,033	-	1,27,607	-	1,27,607	5,10,426
	; kx ¼l½	-	-	-	-	**6,38,033**	**6,38,033**	-	**1,27,607**	-	**1,27,607**	**5,10,426**
	e gk; kx ¼v+c+l½	-	**17,81,88,975**	**2,51,12,570**	**7,48,187**	**6,38,033**	**20,46,87,765**	**81,77,504**	**57,23,140**	-	**1,39,00,644**	**19,07,87,120**

vuqlwph 4

pky wi fjl Ei fÙk; ka

राशि ₹ में

Ø-la	fooj.k	pky wo"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
	1- LVkWd		
1	प्रकाशनार्थ	2,97,804	2,97,305
2	इन्वैंटरी	5,80,316	-
	2- udnh ,oa cSad cpr		
1	भारतीय स्टेट बैंक (34778757702) (चालू खाता)	12,082	-
2	बैंक बचत (बचत खाता)	10,22,83,089	6,15,98,006
3	डाक टिकट स्टॉक	**41,487**	**48,709**
	;ksx	**10,32,14,778**	**6,19,44,020**

vuqlwph 5

ऋण, अग्रिम और जमा

राशि ₹ में

Øe-la	fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
	1- deZpkfj;ksa dks vfxze ¼xSj&C;kt½		
1	त्यौहार अग्रिम	1,18,800	1,10,625
2	अन्य (जीएसएलआईसी)	800	2,280
	2- deZpkfj;ksa dks nh?kkZof/k dsfy, vfxze ¼C;kt½		
1	मोटर कार	84,000	1,20,000
2	स्कूटर अग्रिम	4,000	19,965
3	गृह निर्माण अग्रिम	-	64,950
4	कम्प्यूटर अग्रिम	72,700	34,500
	3- vfxze vkSj udn eW; ;k oLrqdsa: i esaolwyh ;kX; vU; jkf'k;ka		
1	पूंजी लेखा	4,69,30,876	4,45,73,558
	4- iwoZHkqxrku O; ;		
1	chek	38,616	-
2	vU; O; ;	3,81,950	-
	5- tek		
1	,y-ih-xSl	77,348	77,348
2	Tky ehVj	1,650	1,650
3	fo|qr	17,500	17,500
4	vU;	1,800	1,800
	6- iksaHkwr vk;		
1	ऋण एवं अग्रिम	61,161	92,768
	7- vU; & ;wthlh@ikz;kftr ifj;kstukvksalsikIr; orZeku ifjlaifÙk;ka		
1	प्रायोजित परियोजनाएं में शेष ऋण	48,42,681	22,74,786
	;ksx	**5,26,33,882**	**4,73,91,730**

vuqlwph 6

'k$kf.kd izkfIr;ka

राशि ₹ में

Ø-la	fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
	Nk=ksa ls 'kqYd		
	'k$kf.kd		
1	छात्र शुल्क	4,51,714	2,09,000
	;ksx ¼v½	4,51,714	2,09,000
	fcØh		
1	प्रकाशन बिक्री	2,67,328	2,09,670
2	अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	14,519	-
3	प्रास्पैक्टस की बिक्री	9,300	66,100
	;ksx ¼c½	2,91,147	2,75,770
vU; vkdfLed izkfIr;ka			
1	रॉयल्टी	26,393	29,183
2	विविध प्राप्तियां	91,840	2,78,259
3	स्टाफ कार का प्रयोग	6,830	2,696
4	विविध परियोजनाओं से प्राप्त संस्थागत प्रभार	89,79,179	45,69,152
5	अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान	21,29,276	20,22,209
	;ksx ¼l½	1,12,33,518	69,01,499
	egk;ksx ¼v+c+l½	1,19,76,379	73,86,269

vuqlwph 7

vuqnku@lfClMh ¼izkIr v'kks/; vuqnku½

राशि ₹ में

fooj.k	;kstuk	;kstusrj	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
	Ekk-l afo-ea=ky; Hkkjr ljdkj	Ekk-l afo-ea=ky; Hkkjr ljdkj	dqy	dqy
शेष अग्रानीत	4,76,53,129	1,11,70,481	5,88,23,610	-
जोड़करः वर्ष के दौरान प्राप्तियां	12,06,97,000	15,11,59,519	27,18,56,519	26,00,00,000
;ksx	**16,83,50,129**	**16,23,30,000**	**33,06,80,129**	**26,00,00,000**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर व्यय (अ)	2,51,07,298	7,48,187	2,58,55,485	5,18,83,647
'ks"k	**14,32,42,831**	**16,15,81,813**	**30,48,24,644**	**20,81,16,353**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर मुद्रा व्यय (ब)	9,54,79,646	16,15,81,813	25,70,61,459	-
'ks"k lh@,Q ¼4½	**4,77,63,185**	-	**4,77,63,185**	**20,81,16,353**

v uq lwph 8

v ftZ C;kt

राशि ₹ में

Ø-l a	fooj.k	pky w o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
1.	v uq lwfpr cSadks esa cpr [kkrksa ij		
	अ) योजनेतर	6,48,197	5,97,003
	ब) योजना	3,50,092	23,00,806
	स) dsujk cSad	-	4,85,920
	द) ओवरहेड प्रशासनिक निधि खाता	70,634	-
	य) छात्रावास खाता	12,788	12,291
2.	_.kksa ij		
	अ. कर्मचारी/स्टाफ (अग्रिमों पर ब्याज)	1,99,032	10,159
	;ksx	**12,80,743**	**34,06,179**

vuqlwph 9

vU; vk;

राशि ₹ में

Ø-la	fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
v- Hkwfe ,oa Hkouksa ls vk;			
1	छात्रावास किराया	18,38,180	30,47,880
2	लाईसेंस शुल्क	1,91,593	1,85,594
3	जल प्रभार की वसूली	6,293	6,096
	;ksx	**20,36,066**	**32,39,570**
c- vU;			
1	निविदा फार्म की बिक्री	7,000	36,100
2	पेंशनरों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रवेश शुल्क	1,20,300	5,92,800
3	चिकित्सा योजना के लिए योगदान	4,09,000	2,32,325
	;ksx	**5,36,300**	**8,61,225**
	egk;ksx ¼v+c½	**25,72,366**	**41,00,795**

अनुसूची 10

कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ (प्रशासन व्यय)

राशि ₹ में

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष (2014-15)			विगत वर्ष (2013-14)		
		योजनेतर	योजना	योग	योजनेतर	योजना	योग
1	वेतन और मजदूरी	4,16,40,113	22,15,861	4,38,55,974	4,19,94,616	20,97,210	4,40,91,826
2	बोनस और भत्ते तथा समयोपरि भत्ता	6,00,14,483	30,62,598	6,30,77,081	5,14,49,174	21,73,883	5,36,23,057
3	नई पेंशन योजना में योगदान	13,64,055	-	13,64,055	11,58,586	-	11,58,586
4	कर्मचारी कल्याण व्यय (वर्दी)	21,390	-	21,390	42,040	87,427	1,29,467
5	अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	26,30,346	-	26,30,346	13,72,038	-	13,72,038
6	चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति	50,80,959	-	50,80,959	37,87,276	--	37,87,276
7	शिक्षा प्रभार	7,43,658	-	7,43,658	8,00,498	-	8,00,498
8	यात्रा भत्ता	1,23,970	-	1,23,970	75,482	-	75,482
9	अन्य (सरकारी अंशदान–सीपीएफ)	63,799	-	63,799	3,47,626	-	3,47,626
10	सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ						
अ)	पेंशन	2,65,77,864	-	2,65,77,864	2,92,13,686	-	2,92,13,686
ब)	ग्रेज्युटी	51,97,528	-	51,97,528	48,21,025	-	48,21,025
स)	अवकाश नकदीकरण	33,72,576	-	33,72,576	35,18,446	-	35,18,446
	योग	**14,68,30,741**	**52,78,459**	**15,21,09,200**	**13,85,80,493**	**43,58,520**	**14,29,39,013**

अनुसूची 10 अ

कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ

राशि ₹ में

क्र.सं.	विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	योग
	01–04–2014 को अथ शेष राशि (ए)	30,05,91,909	2,93,93,712	1,65,98,647	34,65,84,268
	घटाकरः वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	2,29,66,706	35,31,705	30,46,270	2,95,44,681
	31–03–2015 को उपलब्ध बचत राशि (अ–ब)	27,76,25,203	2,58,62,007	1,35,52,377	31,70,39,587
	वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31–03–2015 को आवश्यक प्रावधान (डी)	30,42,03,067	3,10,59,535	1,69,24,953	35,21,87,555
अ.	चालू वर्ष में किये जाने वाले प्रावधान (डी–सी)	**2,65,77,864**	**51,97,528**	**33,72,576**	**3,51,47,968**

vuqlwph 11

शैक्षणिक व्यय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित)

राशि ₹ में

Ø- la	fooj.k	p ky w o"kZ (2014-15)			foxr o"kZ (2013-14)		
		; kstusrj	; kstuk	; kx	; kstusrj	; kstuk	; kx
1	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (संकाय के लिए यात्रा भत्ता)	-	45,69,380	45,69,380	-	47,95,519	47,95,519
2	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (भागीदार के लिए यात्रा भत्ता)	-	90,69,048	90,69,048	-	88,20,207	88,20,207
3	संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय पर व्यय (प्रशासनिक कार्यक्रमों में व्यय)	-	54,87,815	54,87,815	-	42,41,720	42,41,720
4	संकाय के भ्रमण के लिए भुगतान (संसाधन/व्यक्ति को मानदेय	-	16,09,987	16,09,987	-	6,48,987	6,48,987
5	विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन	-	1,66,95,391	1,66,95,391	-	1,86,41,133	1,86,41,133
6	छात्रों को छात्रवृत्ति (एम.फिल. और पी–एच.डी.)	-	84,98,965	84,98,965	-	59,43,204	59,43,204
7	छात्रवृत्ति/पुस्तकें व परियोजना अनुदान	-	3,53,439	3,53,439	-	2,86,678	2,86,678
8	प्रकाशन व्यय (मुद्रण से प्राप्त)	-	21,94,068		-	15,34,132	-
	1) जोड़कर: पिछले वर्ष का स्टाक	-	2,97,305	21,93,569	-	2,66,393	15,03,220
	2) घटाकर: प्रकाशनार्थ का स्टॉक	-	(2,97,804)		-	(2,97,305)	-
9	सदस्यों के लिए शुल्क	-	1,10,695	1,10,695	-	-	-
10	अन्य (फोटोकॉपी प्रभार)	-	4,47,046	4,47,046	-	5,22,015	5,22,015
11	गैर–सरकारी संगठन को अनुदान	-	71,07,885	71,07,885	-	53,19,967	53,19,967
12	एनईआर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित)	-	67,76,657	67,76,657	-	84,66,773	84,66,773
	; kx	-	**6,29,19,877**	**6,29,19,877**	-	**5,91,89,423**	**5,91,89,423**

अनुसूची 12

प्रशासनिक और सामान्य व्यय

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2014-15) योजनेतर	योजना	योग	विगत वर्ष (2013-14) योजनेतर	योजना	योग
अ	आधार संरचना						
1	विद्युत प्रभार	64,68,823	-	64,68,823	88,01,509	31,920	88,33,429
2	जल प्रभार	1,31,15,286	29,87,380	1,61,02,666	-	-	-
3	(संपत्ति कर सहित किराया, दरें और कर)	3,97,070	-	3,97,070	3,69,819	-	3,69,819
4	सुरक्षा प्रभार	-	2,11,933	2,11,933	24,115	4,90,803	5,14,918
5	वैधानिक व्यय	7,000	12,800	19,800	72,800	32,800	1,05,600
ब	संचार						
1	डाक तथा तार	-	4,39,112	4,39,112	-	4,86,526	4,86,526
2	टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार	8,43,849	2,74,771	11,18,620	8,83,556	89,767	9,73,323
स	अन्य						
1	विज्ञापन प्रभार	-	8,62,726	8,62,726	-	19,65,503	19,65,503
2	पोषाहार व्यय	-	29,71,474	29,71,474	-	37,65,462	37,65,462
3	पेट्रोल/तेल/ल्यूब्रीकैन्ट प्रभार	6,08,505	-	6,08,505	5,74,989	-	5,74,989
4	बीमा	5,993	-	5,993	18,565	32,395	50,960
5	किराए पर टैक्सी	-	5,11,688	5,11,688	-	2,49,951	2,49,951
6	लेखा परीक्षा शुल्क	81,047	-	81,047	33,350	-	33,350
7	मजदूरी प्रभार	-	10,61,237	10,61,237	-	10,02,182	10,02,182
8	विज्ञापन प्रभार	-	16,94,733	16,94,733	-	22,61,842	22,61,842
9	अखबार प्रभार	1,38,955	10,440	1,49,395	1,25,018	15,228	1,40,246
10	अन्य पाठ्यक्रम शुल्क/प्रशिक्षण	-	4,64,216	4,64,216	-	1,70,750	1,70,750
11	विविध व्यय	68,333	6,22,806	6,91,139	2,53,167	4,10,921	6,64,088
12	बैंक प्रभार (अन्य खाते)	-	-	821	-	-	-
	योग	**2,17,34,861**	**1,21,25,315**	**3,38,60,997**	**1,11,56,888**	**1,10,06,050**	**2,21,62,938**

vuqlwph 13

ejEer ,oa j[kj[kko

राशि ₹ में

Ø- la	fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)			fox r o"kZ (2013-14)		
		;kstusrj	;kstuk	;ksx	;kstusrj	;kstuk	;ksx
1	भवन का रख–रखाव	-	11,25,999		-	6,40,130	6,40,130
2	संपदा रखरखाव इलेक्ट्रिकल (एआरएमओ)	-	58,18,801	69,44,800	-	3,10,834	3,10,834
3	फर्नीचर तथा फिक्सर का रख–रखाव	-	17,247	17,247	-	11,58,217	11,58,217
4	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	-	34,81,691	34,81,691	-	33,14,493	33,14,493
5	वाहनों के रख–रखाव (स्टाफ कार)	2,73,040	-	2,73,040	2,04,913	-	2,04,913
6	हाऊस कीपिंग प्रभार	-	45,54,166	45,54,166	9,78,260	17,64,945	27,43,205
7	बागवानी	-	1,58,091	1,58,091	-	82,994	82,994
	;ksx	**2,73,040**	**1,51,55,995**	**1,54,29,035**	**11,83,173**	**72,71,613**	**84,54,786**

vuqlwph 14

iwokZof/k O;;

राशि ₹ में

Ø- la	fooj.k	pkyw o"kZ (2014-15)			fox r o"kZ (2013-14)		
		;kstusrj	;kstuk	;ksx	;kstusrj	;kstuk	;ksx
1	अप्रयुक्त अनुदान अग्रानीत	1,11,70,481	4,76,53,129	5,88,23,610	-	-	-
2	स्थापना व्यय (वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ)	28,75,84,268	-	28,75,84,268	-	-	-
	;ksx	**29,87,54,749**	**4,76,53,129**	**34,64,07,878**	-	-	-

vuqlwph 15

egRoiw.kZ ys[kkadu uhfr;ka

1- Yks[kk fu ekZ.k d s v kèkkj

1.1 जब तक कि विधि का उल्लेख न किया जाए और सामान्यतया आमतौर पर कहा गया है कि लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभूत विधि पर तैयार किए जाते हैं।

2- jkt Lo eku;r k

2.1 विद्यार्थियों से शुल्क, निविदा प्रपत्र, बचत बैंक खाते पर प्रवेश, रूपों, रॉयल्टी और ब्याज की बिक्री की नकदी आधार पर लेखांकन किए जाते हैं।

2.2 छात्रावास किराया से आय नकदी आधार पर लेखांकन किया जाता है।

2.3 हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन की पूरी अदायगी के बाद शुरू होता है, गृह निर्माण पेशगी, वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम की वसूली प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।

3- vpy i fj l aifÙk;ka v kS eY; ã kl

3.1 अचल संपत्ति भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण स्थापना और परिचालन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च आवक सहित अधिग्रहण की लागत से निर्धारित किया जाता है।

3.2 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों पर मुद्रित बिक्री मूल्य को मूल्यवान माना जाता है। उपहार में प्राप्त जिन पुस्तकों मे मूल्य पुस्तक में मुद्रित नहीं होते, उनका मूल्यांकन के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उन्हें पूंजी कोष में जमा करके संस्था की अचल संपत्ति के साथ विलय कर लिया जाता है। मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्तियों की लागू दरों पर निर्धारित किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्ति का मूल्य मूल्यह्रास में घटाकर निकाला जाता है। अचल परिसंपत्तियों का अवमूल्यन निम्नलिखित दरों के अनुसार सीधे तौर पर किया जाता है।

1	भवन	2%
2	कार्यालय उपकरण	7.5%
3	कंप्यूटर और अन्य सहायक सामग्री	20%
4	फर्नीचर फिक्चर और फिटिंग्स	7.5%
5	वाहन	10%
6	पुस्तकालय में पुस्तकें	10%
7	जर्नल्स	10%
8	ई–जर्नल	40%
9	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%

3.5 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

3.6 एक परिसंपत्ति जिसका पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका हो इसे तुलन पत्र में रु. 1 की एक अवशिष्ट मूल्य पर अंकन किया जाएगा और आगे उसका पुनः मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, मूल्यह्रास के परिवर्धन पर लागू मूल्यह्रास की दर से गणना की गई।

3.7 इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं (ई–जर्नल्स) पर व्यय की अधिकता को देखते हुए लाइब्रेरी में इसे पुस्तकों से अलग किया गया है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए 10 प्रतिशत के अवमूल्यन के सापेक्ष 40 प्रतिशत की एक उच्च दर पर ई–जर्नल्स के संबंध में मूल्यह्रास प्रदान किया गया।

3.8 कंप्यूटर और सहायक सामग्री को अर्जित सॉफ्टवेयर के व्यय से अलग किया गया है क्योंकि यह कोई ठोस वस्तु नहीं होती और इसकी लुप्तशीलता

की दन अपेक्षाकृत उच्च होती है। उच्च स्तर के साफफ्टवेयर का अवमूल्यन दर 40 प्रतिशत है जबकि कंप्यूटर और सहायक सामग्री का अवमूल्यन दर 20 प्रतिशत है।

5- LVkWd

5.1 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के आधार पर स्टॉक की मूल्य सूची के अनुसार स्टेशनरी, प्रकाशन और अन्य स्टॉक की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि वस्तु सूची के अनुसार राजस्व व्यय को कम करके शेष स्टॉक का मूल्य अंकन किया जाता है।

6- l sokfuo Ùk y kHk

6.1 सेवानिवृत्त यानी, पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ और अवकाश नकदीकरण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी अन्य नियोक्ता संस्थानों से आये हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया है, उनके नियोक्ता संस्थानों से प्राप्त पेंशन और ग्रेच्यूटी लाभ पूंजीकृत मूल्य के रूप में पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट कर रहे हैं। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् नई पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति पर गृह नगर के लिए यात्रा बिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जमा लिंक्ड इंश्योरेंस अंशदान (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान सह बकाया बिल) वास्तविक रूप में लेखांकित किया गया है।

7- l jd kjh v kS ;w h-l h- v uqnku

7.1 सरकारी अनुदान और यू.जी.सी. अनुदान प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

7.2 पूंजीगत व्यय की दिशा में प्रयुक्त सरकारी अनुदान पूंजीगत निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

7.3 राजस्व व्यय (वास्तविक आधार पर) को पूरा करने के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को प्रयुक्त मानकर उसे उस वर्ष की आय के रूप में लिया गया है जिसमें वह प्राप्त हुआ है।

7.4 अनुप्रयुक्त अनुदान (इस तरह के अनुदान का भुगतान अग्रिमों सहित) को आगामी वर्ष में लिया गया है और उसे तुलनपत्र में देयताएं के रूप में प्रस्तुत किया गया।

8- i k; kst r i fj ; kst uk, a

8.1 पहले से जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि ''चल रही परियोजनाओं की मौजूदा देनदारियों और प्रावधान–मौजूदा देनदारियों–अन्य देयताएं–पाप्तियां'' के रूप में जमा किया गया है। और ऐसी परियोजनाओं के भुगतान हेतु व्यय/अग्रिम है, या संबंधित परियोजना खाते के लिए आवंटित भूमि के ऊपर आरोपों/प्रशासनिक शुल्क के साथ डेबिट किया जाता है। जब देनदार खाता से डेबिट किया जाता है। परियोजनाओं से बरामद ओवरहेड प्रशासनिक प्रभार ओवरहेड प्रशासनिक फंड ए/सी 913920001108 में जमा कर रहे हैं।

9- i h&, p -Mh- v kS , e -fQ y - d s Nk= ksa d s fy , Nk= o fÙk

9.1 पी–एच.डी. और एम.फिल. के छात्रों को छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा प्रदान किए गए योजना अनुदान से भुगतान की जा रही हैं और इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखांकित किया जाता है।

10- fp fd Rl k v à kn ku

10.1 चिकित्सा अंशदान न्यूपा की चिकित्सा योजना के अनुसार योजनेतर खाते में जमा किया जाता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति गैर–योजना खाते से भुगतान किया जाता है।

11- x S l jd kjh l aBu ksa d ks v uqnku

11.1 समान उद्देश्य वाले गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान योजना के खाते के अंतर्गत व्यय के रूप में लेखांकित की जा रही है।

vuqlwph 16

[kkrksa esa vkdfLed nsrk,a vkSj fVIif.k;ka

1- vpy laifÙk;ka

1.1 अचल संपत्तियां केवल योजना अनुदान से खरीदी गई है, जबकि वाहन गैर–योजना अनुदान से लिए गए हैं। अनुसूची 3 में वर्ष के दौरान संबंधित अचल संपत्तियों में योजना निधि (₹ 2,51,12,570), गैर–योजना निधि से (₹ 7,48,187), खरीदी गई और लाइब्रेरी में किताबें और विश्वविद्यालय को तोहफे के मूल्य (₹ 5,272), की अन्य सपत्ति शामिल की गई हैं। आस्तियां कैपिटल फंड में जमा करके स्थापित की गई हैं।

1.2 31.03.2015 के तुलन पत्र और पहले के वर्षों के तुलनपत्र में साफ तौर पर योजना के धन से बनाई गई अचल आस्तियों और योजना निधि तथा अन्य निधि से बनाई गई अचल आस्तियों को अलग–अलग प्रदर्शित नहीं किया गया है। योजना और गैर–योजना निधि से वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक सवंर्धित और उन परिवर्धनों पर संबंधित अवमूल्यन को अलग रूप में प्रदर्शित किया गया है (अनुसूची–3)।

1.3 अनुसूची–3 में अचल संपत्ति के रूप में उच्च शिक्षा नीति शोध केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के धन से खरीदी गई संपत्ति शामिल हैं। ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों की राशि ₹ 6,38,033 है।

2- ekStwnk nsunkfj;ka vkSj izkoèkku

2.1 आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने की स्थिति में, आय कर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

2.2 क्रेडिट पर जमा हुए अवकाश के नकदीकरण के एवज में एकमुश्त भुगतान के प्रति दायित्व और कर्मचारियों और की सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों प्रति देयता के लिए प्रावधान पिछले साल के अनुमान के आधार पर निर्धारित थे। इस साल, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन किया गया था और पहले किए गए प्रावधानों में पिछले सालों को कवर करने के लिए, पूर्व की अवधि 2014–15 के व्यय को भुगतान किया गया था। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2015 पर और मौजूदा खाते में 2014–15 में किए गए भुगतान और शुद्ध प्रावधानों को आगे 2014–15 के प्रावधानों लिए आय भुगतान और व्यय खाता द्वारा वर्ष 2014–15 के खातों में भुगतान किए गए थे।

3- ekStwnk ifjlaifÙk;ksa] _.k] vfxze vkSj tek

3.1 विश्वविद्यालय की राय में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम और जमाओं पर आमतौर पर कम से कम तुलन पत्र में दिखाया गया कुल राशि के बराबर मूल्य है।

4- Hkfo"; fufèk [kkrk

4.1 सरकार से संबंधित निर्देश के अनुसार भविष्य निधि खाते के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा उन निधियों को सदस्यों के स्वामित्व में प्रस्तुत किया गया हैं, विश्वविद्यालय के खाते से भविष्य निधि खाते को अलग किया जाता है। हालांकि प्राप्ति और भुगतान खाता (उपचय के आधार पर) आय और व्यय खाता और भविष्य निधि खाते का तुलन पत्र विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा में संलग्न है।

5- U;w isa'ku ;kstuk [kkrk

5.1 नई पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को पीआरए सं. प्राप्त है। नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लि. (एनएसडीएल) में संेट्रल रिकॉडिकीपिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा

नियमित रूप से स्थानान्तरण कर रहे हैं। उनमें से संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी योगदान की स्थानांतरित होने की कोई राशि बकाया नहीं है।

6- l sokfu o`Ùk y kHk

6.1 सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पिछले नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के कैपिटल के मूल्य, संबंधित प्रावधान खातों में जमा किया गया है।

7- vuqnku

7.1 योजना अनुदान लेखा और अग्रिम की बैंक बैंलेस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के आधार पर अनुदान कोष और बकाया समायोजन के बाहर का भुगतान किया है, हालांकि पिछले वर्षों में योजना अनुदान सीमा को छोड़कर आय के रूप में प्राप्त किया गया, वे पूंजीगत व्यय के लिये उपयोग किया गया था। तुलन पत्र की आस्तियों पक्ष पर अंकित किया गया है। अनुप्रयुक्त अनुदान पूर्व अवधि के खर्च के लिए डेबिट करके 2014–15 के लिए खातों में स्थापित किए गए हैं। 31.03.2015 के रूप में अप्रयुक्त अनुदान आगे बढ़ाया और तुलन पत्र में एक दायित्व के रूप में प्रदर्शि किया गया है।

8- बचत बैंक खातों में शेष के विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची अ में संलग्न हैं।

9- पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार फिर से वर्गीकृत किया गया है।

10- अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में अंकित किया गया हैं।

11- अनुसूची 1 से 14 को संलग्न किया गया है और यह 31 मार्च 2015 के तुलन पत्र और इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय लेखा हो अभिन्न भाग होता है।

rqyu i=

31 ekp Z 2015 dks lekIr foÙkh; o"kZ ds vuqlkj

राशि ₹ में

31 ekp Z 2014	nsrk,a foo j.k		31 ekp Z 2015	31 ekp Z 2014	ifjlaifÙk;ka foo j.k	31 ekp Z 2015
10,54,73,629	अथशेष		11,90,01,273		fuos'k	
				11,08,10,209	जीपीएफ/सीपीएफ निवेश	11,48,05,724
	thih,Q					
1,81,22,630	वर्ष में अंशदान	2,03,30,369		37,46,694	31 मार्च, 2015 को अर्जित ब्याज	14,05,487
87,96,521	ब्याज जमा	97,78,903				
(1,47,60,809)	घटायाः निकासी	(1,92,26,411)	1,08,82,861			
	lhih,Q				cSad esa udnh	
66,000	वर्ष के दौरान अंशदान	66,000		44,44,370	एसबीआई खाता नं. 10137881013	1,73,07,848
25,001	ब्याज जमा	32,918	98,918			
	fo'ofo|ky; va'knku ¼lhih,Q½					
23,766	ब्याज जमा		31,236			
62,088	मार्च 2015 के लिए अंशदान		63,799			
	C;kt fjtoZ					
11,92,447	व्यय पर आय से अधिक		34,40,972			
11,90,01,273			**13,35,19,059**	**11,90,01,273**		**13,35,19,059**

g-@&
¼m"kk R;kxjkt u½
foÙk vf/kdkjh

g-@&
¼cl ojkt Lokeh½
dqylfpo

g-@&
¼vkj- xksfoan k½
dqyifr

v k; v kS O; y s[kk

31 e kp Z2015 d ks l e kIr fo Ùkh; o"kZd s v u dq kj

राशि ₹ में

	O;			v k;		
31 e kp Z 2014	fooj.k	31 e kp Z 2015	31 e kp Z 2014	fooj.k		31 e kp Z 2015
	ब्याज श्रेय:					
87,96,521	t hih,Q [kkr s	97,78,903	71,04,092	निवेश/बचत खाते पर अर्जित ब्याज	1,56,25,236	
25,001	सीपीएफ खाते	32,918	87,87,527	जोड़ें: मार्च 2015 को अर्जित ब्याज	64,46,320	
			(61,39,422)	घटाया: मार्च 2014 के लिए उपार्जित ब्याज	(87,87,527)	1,32,84,029
23,766	विश्वविद्यालय के अंशदान पर ब्याज (सीपीएफ)	31,236	3,47,626	प्राप्त विश्वविद्यालय अंशदान (सीपीएफ)		63,799
62,088	fo'ofo|ky; vàknku ¼ihih,Q½	63,799				
11,92,447	ब्याज पर आय से अधिक	34,40,972				
1,00,99,823		**1,33,47,828**	**1,00,99,823**			**1,33,47,828**

g-@&
¼m"kk R;kxjkt u½
foÙk vf/kdkjh

g-@&
¼cl ojkt Lokeh½
dqy lfpo

g-@&
¼v kj- x ksfoan k½
dqyifr

i kfIr vkS Hkqxrku ys[kk

31 ekpZ 2015 dks lekIr fo Ùkh; o"kZ ds vuqlkj

राशि ₹ में

i kfIr ;ka	pkyw o"kZ 2014-15	foxr o"kZ 2013-14	Hkqxrku	pkyw o"kZ 2014-15	foxr o"kZ 2013-14
प्रारंभिक जमा	44,44,370	22,56,312	tho h, Q	1,92,26,411	1,47,60,809
			vfxze@vkgj.k		
जीपीएफ अंशदान	2,03,30,369	1,81,22,630	सीपीएफ अग्रिम/ आहरण		
सीपीएफ अंशदान	66,000	66,000	वर्ष के दौरान निवेश	7,73,81,460	3,28,85,945
सीपीएफ विश्वविद्यालय अंशदान	63,799	3,47,626			
निवेश नकदीकरण	7,33,85,945	2,41,94,464			
ब्याज प्राप्ति	1,56,25,236	71,04,092	tek 'ks"k	1,73,07,848	44,44,370
	11,39,15,719	**5,20,91,123**		**11,39,15,719**	**5,20,91,123**

g-@&
¼m"kk R;kxjkt u½
foÙk vf/kdkjh

g-@&
¼cl ojkt Lokeh½
dqy lfpo

g-@&
¼vkj- xksfoan k½
dqyi fr

i kfIr vkS Hkqr ku y \$kk

31 e kp Z2015 d ks l e kIr fo Ùkh; o"kZd s v u q kj

राशि ₹ में

i kfIr ; ka	p ky wo"kZ 2014-15	fo x r o"kZ 2013-14	Hkq r ku	p ky wo"kZ 2014-15	fo x r o"kZ 2013-14
i kj afHkd t e k			O ;		
1 cpr cSd [kkr k	6,16,46,715	5,15,66,376	स्थापना व्यय	14,65,05,913	13,59,39,013
e k-l afo-e a l s i kIr			शैक्षणिक व्यय	5,44,21,411	5,32,77,131
v u qnku					
			प्रशासनिक व्यय	3,42,22,485	2,21,62,938
अ) योजनेतर	15,11,59,519	14,15,00,000	मरम्मत और रख–रखाव	1,02,48,807	81,43,952
ब) योजना	12,06,97,000	11,85,00,000			
' kS{kf. kd i kfIr ; ka	29,63,416	73,81,556	फैलोशिप के संबंद्ध में भुगतान	84,98,965	59,43,204
i k; kst r					
i fj ; kt ukv ka@ ; kst ukv ksad s l ac a) e sai kfIr ; ka	9,87,94,626	4,14,99,960	प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के संबंद्ध में भुगतान	5,79,68,504	3,52,35,892
			l hi hMCY; Mh d s fy ,		
i kIr C; kt			v py l Ei fÙk v kS v fx e		
			i j O ;		
1. बैंक वचत खाता			अचल संपत्तियां		
अ) योजना	3,50,093	23,00,806	अ) योजना	2,51,07,298	2,17,62,444
ब) गैर–योजना	6,48,197	5,97,003	ब) गैर–योजना	7,48,187	-
स) केनरा बैंक	-	4,85,920	सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	81,76,119	2,40,39,027
द) ओवरहेड प्रशासनिक निधि	70,634		o SkkfU d Hkqr ku l fgr		
			v U; Hkqr ku		
ल) छात्रावास खाता	12,788	12,291	1. ओवरहेड प्रशासनिक निधि खाता	68	
2. ब्याज अग्रिमों पर ब्याज	2,30,639	82,731	2. प्रभार	135	
अन्य आय	25,72,366	41,16,768	3. विविध व्यय	618	
जमा और अग्रिम	4,21,240	3,72,655	t e k v kS v fx e	3,12,725	2,63,910
i sk. k	4,03,40,070	3,47,53,003	i sk. k	4,03,38,590	3,47,54,843
o SkkfU d i kfIr ; ka l fgr fo fo /k j l hn			' kSk l e ki u		
1. ओवरहैड प्रशासनिक निधि खाता 1108	89,79,179		cSd cSy sl		

i kfIr ; ka	p ky wo "kZ 2014-15	fo x r o "kZ 2013-14	Hkq r ku	p ky wo "kZ 2014-15	fo x r o "kZ 2013-14
			i) चालू खातों में (34778757702)	12,082	-
			ii) बचत खाते में		
			1. भारतीय स्टेट बैंक (10137881320)	48,19,755	1,11,70,481
			2. सिंडिकेट बैंक (91392010001112)	2,26,859	30,79,571
			3. सिंडिकेट बैंक (91392010001092)	6,76,28,166	2,68,02,044
			4. केनरा बैंक (25536)	10,832	2,02,29,377
			5. छात्रावास खाता (91392015365)	3,29,322	3,16,534
			6. हस्तगत डाक	41,487	48,709
			7. ओवरहैड प्रशासनिक निधि (91392010001108)	2,92,68,155	-
; ksx	**48,88,86,482**	**40,31,69,069**	; ksx	**48,88,86,482**	**40,31,69,069**

g -@ &
¼m"kk R; kx j kt u ½
fo Ùk v f/kd kj h

g -@ &
¼c l oj kt Lo ke h½
d q y l fp o

g -@ &
¼v kj - x ksfo an k½
d q y i fr

c Sd [kkrksa esa 'ks"k jkf'k

31 ekpZ 2015 dks lekIr foÙkh; o"kZ ds vuqd kj

राशि ₹ में

Øe la	cSad [kkrs	pkyw o"kZ (2014-15)	foxr o"kZ (2013-14)
1	भारतीय स्टेट बैंक (10137881320) योजनेतर	48,19,755	1,11,70,481
2	सिंडिकेट बैंक (91392010001112) योजना	2,26,859	30,79,571
3	सिंडिकेट बैंक (91392010001092) परियोजना	6,76,28,166	2,68,02,043
4	सिंडिकेट बैंक (91392010001108) ओवरहैड प्रशासनिक निधि	2,92,68,155	-
5	सिंडिकेट बैंक (91392015365) छात्रावास	3,29,322	3,16,534
6	सिंडिकेट बैंक खाता 25536	10,832	2,02,29,377
	;ksx	10,22,83,089	6,15,98,006

o"kZ 2014&15 ds fy,

xSj&ljdkjh laxBu dks vuqnku dh lwph

राशि ₹ में

Ø- la	,ut hvks d suke	tkjh jkf'k
1	सेंट एल्वायसस कॉलेज (ऑटोनोमस), मंगलौर	1,50,000.00
2	माधवी वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	1,35,000.00
3	अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण समिति, मुरैना (मध्य प्रदेश)	27,500.00
4	माइनोरिटी एजुकेशनल सोसायटी (महाराष्ट्र)	50,000.00
5	कु. गायत्री अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति, मुरैना (मध्य प्रदेश)	1,50,000.00
6	लिटिल फ्लावर एजुकेशनल सोसायटी, कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	1,02,500.00
7	सोसायटी फार सोशियल ट्रांसफोरेमेशन, कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	50,000.00
8	सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	1,24,350.00
9	कीर्ति हैल्थ एजुकेशनल एंड रूरल डवलपमेंट सोसायटी (खेर्द) कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	1,37,500.00
10	डवलपमेंट आफ इंटग्रेटेड नर्चुरिंग एसोसिएशन टू किंडल अवेकिंग फार रेनीशेंस (दिनकर), कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	1,37,500.00
11	कलाबन्धु कला परिषद, कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	1,37,500.00
12	श्रीमती पानकुंवर बाई शिक्षा समिति, देवास, (मध्य प्रदेश)	1,22,880.00
13	कुण्डू एरिया रूरल डवलपमेंट सोसायटी, कुरनुल (आन्ध्र प्रदेश)	1,25,000.00
14	अंत्यज सेवा समिति, बिहार	1,35,000.00
15	श्रीमती वैजयंती देवी शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना (मध्य प्रदेश)	79,100.00
16	श्री मधु मेहता वैलफेयर सोसायटी, खंडवा (मध्य प्रदेश)	1,31,290.00
17	कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एम. समिति, लोनावला	2,50,000.00
18	सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईएसआरडी)	99,000.00

Ø-la	,uthvksdsuke	tkjh jkf'k
19	शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, आईआईटी खड़गपुर	1,24,400.00
20	सोना एजुकेशनल सोसायटी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	1,40,000.00
21	कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान, जयपुर	2,44,200.00
22	माँ मंगला देवी पूनम अग्रवाल महिला मंडल, भिण्ड (मध्य प्रदेश)	1,50,000.00
23	ग्रामीण गरीब विकास सोसायटी (आरपीडीएस), कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	1,19,000.00
24	सर्व कल्याण महिला मंडल, भोपाल	1,50,000.00
25	सेंटर फार प्रोमोशन आफ एजुकेशनल एंड कल्चर एडवांसमेंट आफ मुस्लिम आफ इंडिया (सीईपीईएसएएमआई), अलीगढ़	1,50,000.00
26	डे पॉल एक्सटेंशन सर्विस (डीईएस), केरल	64,972.00
27	ग्राम पंचायत राज किनारू, मुज्जफरपुर, बिहार	1,27,500.00
28	विजय वर्धन संस्थान, ग्वालियर	1,30,815.00
29	डवलपमेंट इनोवेटर्स, ओडिशा	2,47,500.00
30	पीजी डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी आफ जम्मू, जम्मू (जे एंड के)	25,394.00
31	हैल्थ एजुकेशन एंड डवलपमेंट सोसायटी, तमिलनाडु	1,19,600.00
32	एस एंड टी एजुकेटर्स फोरम, नई दिल्ली	2,50,000.00
33	चांद माइनोरिटी वैलफेयर एसोसिएशन, (आन्ध्र प्रदेश)	1,50,000.00
34	इलाश्री सेवा संस्थान, बिहार	1,37,500.00
35	सोसायटी फार वूमन इम्पावरमेंट थ्रू डवलपमेंट एक्शन (एसडब्ल्युईटीडीए), ओडिशा	1,13,884.00
36	अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसायटी, अलीगढ़	1,46,500.00
37	नव जीवन ग्रामोद्योग समिति, आगरा (उत्तर प्रदेश)	1,50,000.00
38	सोसायटी फार एजुकेशनल एंड इकानमिक डवलपमेंट (सीड), नई दिल्ली	1,50,000.00
39	फतिमा मुस्लिम महिला मंडली (एफएमएमएम), कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	1,50,000.00

Ø- la	, ut hv ksd s u ke	t kjh jkf'k
40	अलीगढ़ हिस्टोरियंस सोसायटी, अलीगढ़	1,50,000.00
41	ग्लोरियस वूमन इम्पावरमेंट, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	1,50,000.00
42	साई एजुकेशनल रूरल एंड अर्बन डवलपमेंट सोसायटी (सेरूड्स), कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश	1,50,000.00
43	समाधान, बिहार	1,50,000.00
44	नवज्योति यूथ एसोसिएशन, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	1,50,000.00
45	संघर्षोत्थान, हाथरस, (उ.प्र.)	1,50,000.00
46	चण्डीगढ़ कॉलेज आफ एजुकेशन, मोहाली, पंजाब	1,22,500.00
47	इंडियन एकेडमी आफ सोशल साइंसेज	3,00,000.00
48	महिला एवं ग्रामीण विकास एसोसिएशन (एडब्ल्यूएआरई)	1,50,000.00
49	अभ्युदय संस्थान, (उत्तर प्रदेश)	1,50,000.00
50	फतिमा मुस्लिम महिला मंडली	1,50,000.00
51	नवज्योति यूथ एसोसिएशन, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	1,50,000.00
	; ksx	**71,07,885.00**

01-04-2014 से 31-03-2015 तक की अवधि के लिए

निवेश का विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	एफडीआर सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि	ब्याज की दर (%)	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	सिंडिकेट बैंक	970000	20.05.2014	20.05.2015	70,00,000.00	9.05	76,55,325.52	5,27,917
2	सिंडिकेट बैंक	197809	13.06.2014	31.08.2015	21,00,000.00	9.15	23,44,370.83	1,44,113
3	सिंडिकेट बैंक	197811	20.06.2014	07.09.2015	40,00,000.00	9.15	44,65,468.25	2,74,500
4	सिंडिकेट बैंक	197812	20.06.2014	07.09.2015	30,00,000.00	9.15	33,49,101.19	2,05,875
5	सिंडिकेट बैंक	197821	30.06.2014	17.09.2015	50,00,000.00	9.15	55,81,835.31	3,43,125
6	सिंडिकेट बैंक	197828	08.07.2014	25.09.2015	70,00,000.00	9.15	78,14,569.44	4,27,000
7	सिंडिकेट बैंक	969781	04.10.2014	04.10.2015	35,00,000.00	9.05	38,27,662.76	1,58,375
8	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143	18.09.2014	22.10.2015	1,37,81,460.00	9.00	1,51,90,576.00	6,20,166
9	सिंडिकेट बैंक	197860	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56	4,80,375
10	सिंडिकेट बैंक	197861	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56	4,80,375
11	सिंडिकेट बैंक	197862	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56	4,80,375
12	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/1066	15.12.2012	31.12.2015	70,00,000.00	9.00	91,78,418.00	6,30,000
13	सिंडिकेट बैंक	197895	18.10.2014	05.01.2016	65,00,000.00	9.00	72,43,443.89	2,43,750
14	सिंडिकेट बैंक	407156/969620	8.11.2014	26.01.2016	35,00,000.00	9.00	39,00,315.94	1,31,250
15	सिंडिकेट बैंक	969825	10.11.2014	28.01.2016	50,00,000.00	9.00	55,71,879.91	1,87,500
16	सिंडिकेट बैंक	197964	18.11.2014	05.02.2016	20,00,000.00	9.00	22,28,751.97	60,000
17	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/1543	31.01.2013	16.02.2016	1,00,00,000.00	9.00	1,31,12,026.00	9,00,000
18	केनरा बैंक	032137	04.03.2015	21.05.2016	70,00,000.00	8.85	7786708.00	51,625
19	एसबीआई एसपीएल जमा	812	27.06.1981	-	14,24,264.00		14,24,264.00	100000
				योग	11,48,05,724.00		13,08,16,627.69	64,46,319.87

uxnhdj.k 2014&15

Ø-la	cSad dk uke	,QMh la	tkjh djus dh frfFk	ifjiDork frfFk	dqy jkf'k	C;kt dh nj ¼%½	ifjiDork ewY;
1	सिंडिकेट बैंक	969566	20.05.2012	20.05.2014	76,89,067.96	9	84,04,791.92
2	सिंडिकेट बैंक	501436	13.06.2012	13.06.2014	21,96,876.55	9	24,01,369.11
3	सिंडिकेट बैंक	501438	20.06.2012	20.06.2014	40,00,000.00	9	43,72,333.28
4	सिंडिकेट बैंक	501439	20.06.2012	20.06.2014	30,00,000.00	9	32,79,249.96
5	सिंडिकेट बैंक	501938	08.07.2012	08.07.2014	70,00,000.00	9	82,05,809.66
6	भारतीय स्टेट बैंक	31867492916	03.08.2011	03.08.2014	80,00,000.00	9.25	1,02,79,406.00
7	भारतीय स्टेट बैंक	31867493090	03.08.2011	03.08.2014	80,00,000.00	9.25	1,02,79,406.00
8	भारतीय स्टेट बैंक	31867493352	03.08.2011	03.08.2014	60,00,000.00	9.25	77,09,553.00
9	सिंडिकेट बैंक	969793	14.09.2013	18.10.2014	65,00,000.00	9.3	71,87,642.47
10	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900	14.08.2013	18.09.2014	1,25,00,000.00	9.00	1,37,81,460.00
11	सिंडिकेट बैंक	969843	18.11.2013	18.11.2014	20,00,000.00	9.1	21,81,351.52
12	केनरा बैंक	440191	19.02.2013	17.02.2015	65,00,000.00	9.05	77,71,645.00
					7,33,85,944.51		

वर्ष 2014-15 के दौरान किये गये एफडी (सावधि जमा)

क्र.सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि	ब्याज की दर (%)	परिपक्वता मूल्य
1.	सिंडिकेट बैंक	970000	20.05.2014	20.05.2015	70,00,000.00	9.05	76,55,325.52
2.	सिंडिकेट बैंक	197809	13.06.2014	31.08.2015	21,00,000.00	9.15	23,44,370.83
3.	सिंडिकेट बैंक	197811	20.06.2014	07.09.2015	40,00,000.00	9.15	44,65,468.25
4.	सिंडिकेट बैंक	197812	20.06.2014	07.09.2015	30,00,000.00	9.15	33,49,101.19
5.	सिंडिकेट बैंक	197821	30.06.2014	17.09.2015	50,00,000.00	9.15	55,81,835.31
6.	सिंडिकेट बैंक	197828	08.07.2014	25.09.2015	70,00,000.00	9.15	78,14,569.44
7.	सिंडिकेट बैंक	197860	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56
8.	सिंडिकेट बैंक	197861	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56
9.	सिंडिकेट बैंक	197862	12.08.2014	30.10.2015	90,00,000.00	9.15	1,00,47,303.56
10.	सिंडिकेट बैंक	197895	18.10.2014	05.01.2016	65,00,000.00	9.00	72,43,443.89
11.	पंजाब नेशनल बैंक	CBU022534/ 139900/23143	18.09.2014	22.10.2015	1,37,81,460.00	9.00	1,51,90, 576.00
12.	सिंडिकेट बैंक	197964	18.11.2014	05.02.2016	20,00,000.00	9.00	22,28,751.97
		योग			7,73,81,460.00		8,60,15,353.08

o"kZ 2014&15 ds fuos'k fooj.k

अथ शेष	11,08,10,208.51
वर्ष के दौरान किये गये निवेश	7,73,81,460.00
dqy fuos'k	**18,81,91,668.51**
वर्ष के दौरान किये गये नकदीकरण	7,33,85,944.51
'kq) fuos'k ¼var 'ks"k½	**11,48,05,724.00**

' ks'k i j h{k.k

1 vi Sy 2014 l s 31 ekpZ 2015 rd

fooj.k	vFk' ks'k	gLrkUrj.k		va' ks'k
		fu dklh	tek	
i wathxr y s[kk	**21,80,24,958.49 Cr**	**1,96,99,890.34**	**2,69,63,916.34**	**22,52,88,984.49 Cr**
जोड़कर/अधिक आय/व्यय	1,92,34,764.00 Cr	1,92,34,764.00		
पूंजीगत निधि	19,83,25,068.15 Cr		2,69,63,916.34	22,52,88,984.49 Cr
परिसंपत्ति निधि दान	4,65,126.34 Cr	4,65,126.34		
pkyw ns;rk,a	**8,64,57,465.52 Cr**	**57,36,05,524.77**	**95,53,88,058.42**	**46,82,39,999.17 Cr**
राशि लेनदार	15,973.00 Cr			15,973.00 Cr
राशि लेनदान – सी.पी.एफ.	15,973.00 Cr			15,973.00 Cr
बिलों से कटौती		7,24,257.00	7,24,257.00	
ठेकेदार से आयकर – योजना		5,76,369.00	5,76,369.00	
ठेकेदार से आयकर – परियोजना		1,44,170.00	1,44,170.00	
ठेकेदार से आयकर – योजनेतर		3,718.00	3,718.00	
वेतन से कटौती	2,280.00 Dr	3,96,14,333.00	3,96,15,813.00	800.00 Dr
जी.पी.एफ. अंशदान (प्रतिनियोक्ता)		1,92,77,104.00	1,92,77,104.00	
सामूहिक बीमा योजना	2,280.00 Dr	94,280.00	95,760.00	800.00 Dr
आयकर (वेतन) – योजनेतर		1,29,50,757.00	1,29,50,757.00	
आयकर (वेतन) – योजना		13,72,742.00	13,72,742.00	
आयकर (वेतन) – परियोजना		15,28,398.00	15,28,398.00	
एल.आई.सी.		2,72,405.00	2,72,405.00	
नई पेंशन स्कीम से वसूली		14,14,617.00	14,14,617.00	
सोसायटी वसूली		27,04,030.00	27,04,030.00	
fof'k"V i fj;kstuk	**2,68,02,043.52 Cr**	**7,51,01,835.77**	**11,59,27,958.42**	**6,76,28,166.17 Cr**
प्रावधान	5,90,00,000.00 Cr		29,31,87,555.00	35,21,87,555.00 Cr
प्रावधान – ग्रेच्युटी	90,00,000.00 Cr		2,20,59,535.00	3,10,59,535.00 Cr
प्रावधान – अवकाश वेतन	50,00,000.00 Cr		1,19,24,953.00	1,69,24,953.00 Cr
प्रावधान – पेंशन	4,50,00,000.00 Cr		25,92,03,067.00	30,42,03,067.00 Cr
भुगतान के बदले में	4,91,883.00 Cr	64,525.00	1,02,500.00	5,29,858.00 Cr
जर्नल की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	1,49,846.00 Cr	1,83,630.00	1,49,846.00	1,16,062.00 Cr
निधि हस्तांतरण – योजना		5,00,00,000.00	5,00,00,000.00	
निधि हस्तांतरण – केनरा बैंक		4,00,00,000.00	4,00,00,000.00	
निधि हस्तांतरण – योजनेतर		4,25,00,000.00	4,25,00,000.00	
निधि हस्तांतरण – ओवरहैड एडमिन. खाता 1108		5,00,000.00	5,00,000.00 Cr	
परियोजना खाते से हस्तांतरण अनुदान		4,20,00,000.00	4,20,00,000.00	

fooj.k	vFk' ks"k	gLr kUrj.k		v a ' ks"k
		fudklh	tek	
अनुप्रयुक्त अनुदान – योजना		12,05,86,944.00	16,83,50,129.00	4,77,63,185.00 Cr
अनुप्रयुक्त अनुदान – योजनेतर		16,23,30,000.00	16,23,30,000.00	
v p y l a fÙk; ka	**17,81,88,975.53 Dr**	**2,73,70,003.53**	**1,47,71,858.00**	**19,07,87,121.06 Dr**
1027 – जर्नल की खरीद	36,15,306.00 Dr			36,15,306.00 Dr
2025 – फर्नीचर और साजो–सामान	61,18,936.34 Dr	1,30,879.00	4,68,736.00	57,81,079.34 Dr
2026 – अन्य कार्यालय उपकरण	1,13,73,655.82 Dr	7,16,279.00	9,06,745.00	1,11,83,189.82 Dr
2027 – पुस्तकालयों की पुस्तकें	54,14,721.95 Dr	25,48,114.00	7,32,581.00	72,30,254.95 Dr
2028 – कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री	36,35,037.90 Dr	36,08,261.00	15,87,808.00	56,55,490.90 Dr
2029 – जर्नल की खरीद	1,55,12,550.95 Dr	75,55,462.00	24,79,445.00	2,05,88,567.95 Dr
2030 – ई–जर्नल की खरीद	22,28,699.62 Dr	13,39,655.53	14,27,342.00	21,41,013.15 Dr
2055 – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3,81,221.00 Dr	1,00,85,133.00	43,26,450.00	61,39,904.00 Dr
अचल परिसंपत्ति – स्पॉनसर्ड		6,38,033.00	1,27,607.00	5,10,426.00 Dr
भूमि	23,07,892.03 Dr			23,07,892.03 Dr
कार्यालय भवन	12,64,97,119.99 Dr		25,29,942.00	12,39,67,177.99 Dr
स्टाफ कार की खरीद	11,03,833.93 Dr	7,48,187.00	1,85,202.00	16,66,818.93 Dr
or Zku i fj l a fÙk; ka	**10,70,58,684.32 Dr**	**73,93,35,258.40**	**69,53,88,764.07**	**15,10,05,178.65 Dr**
स्टाफ को अग्रिम		3,30,83,844.00	3,30,83,844.00	
2033 – विविध अग्रिम		3,26,68,365.00	3,26,68,365.00	
अग्रदाय – योजना		10,000.00	10,000.00	
चिकित्सा अग्रिम		4,05,479.00	4,05,479.00	
v k; i ksn Hkw	92,768.00 Dr	61,161.00	92,768.00	61,161.00 Dr
ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज प्रोद्भूत	92,768.00 Dr	61,161.00	92,768.00	61,161.00 Dr
b a o sVj h		5,80,316.00		5,80,316.00 Dr
इंवेंटरी – स्टेशनरी		5,80,316.00		5,80,316.00 Dr
i wZi znÙk O; ;		**4,20,566.00**		**4,20,566.00 Dr**
प्रीपेड – बीमा		38,616.00		38,616.00 Dr
प्रीपेड – अन्य		3,81,950.00		3,81,950.00 Dr
वसूली योग्य – स्टाफ	3,50,040.00 Dr	2,48,200.00	3,18,740.00	2,79,500.00 Dr
कार अग्रिम	1,20,000.00 Dr		36,000.00	84,000.00 Dr
कंप्यूटर अग्रिम	34,500.00 Dr	59,200.00	21,000.00	72,700.00 Dr
त्योंहार अग्रिम	1,10,625.00 Dr	1,89,000.00	1,80,825.00	1,18,800.00 Dr
भवन निर्माण अग्रिम	64,950.00 Dr		64,950.00	
स्कूटर अग्रिम	19,965.00 Dr		15,965.00	4,000.00 Dr
t e k ¼i fj l a fÙk; k½	4,45,73,558.00 Dr	81,76,119.00	58,18,801.00	4,69,30,876.00 Dr
सी.पी.डब्ल्यू.डी. को जमा–सिविल / इलैक्ट्रिकल	4,45,73,558.00 Dr	81,76,119.00	58,18,801.00	4,69,30,876.00 Dr
विविध देनदार	98,298.00 Dr			98,298.00 Dr

fooj.k	vFk' ks'k	gLrkUrj.k		var ' ks'k
		fudklh	tek	
jksdM+ gkFk esa		3,71,10,023.00	3,71,10,023.00	
रोकड़ – योजनेतर		20,47,662.00	20,47,662.00	
रोकड़ – योजना		2,54,60,079.00	2,54,60,079.00	
रोकड़ – परियोजना		96,02,282.00	96,02,282.00	
बैंक	6,15,98,006.32 Dr	65,93,15,738.40	61,86,18,574.07	10,22,95,170.65 Dr
1000 – एस.बी.आई. – 10137881320 – योजनेतर	1,11,70,481.40 Dr	23,88,77,820.55	24,52,28,547.00	48,19,754.95 Dr
2000 – सिंडीकेट बैंक – 91.1112 – योजना	30,79,570.64 Dr	19,82,15,357.54	20,10,68,069.43	2,26,858.75 Dr
3000 – सिंडीकेट बैंक – 91.1092 – परियोजना	2,68,02,043.52 Dr	15,14,77,106.42	11,06,50,983.77	6,76,28,166.17 Dr
4000 – चालू खाता – 34778757702		12,700.00	618.00	12,082.00 Dr
6000 – हॉस्टल खाता	3,16,534.25 Dr	12,787.93		3,29,322.18 Dr
8000 – केनरा बैंक	2,02,29,376.51 Dr	4,09,51,743.46	6,11,70,287.87	10,832.10 Dr
9000 – प्रशासन निधि खाता 1108		2,97,68,222.50	5,00,068.00	2,92,68,154.50 Dr
हस्तगत डाक टिकट	48,709.00 Dr	41,487.00	48,709.00	41,487.00 Dr
हस्तगत प्रकाशन	2,97,305.00 Dr	2,97,804.00	2,97,305.00	2,97,804.00 Dr
vizR;{k vk;		12,45,935.62	27,41,36,882.57	27,28,90,946.95 Cr
pkyw [kkrk esa tek			11,000.00	11,000.00 Cr
4004 – न्यूपा से जमा			11,000.00	11,000.00 Cr
प्राप्तियां – केनरा बैंक		9,51,743.46	9,51,743.46	
8001 – प्रशासन निधि से प्राप्ति		9,51,743.46	9,51,743.46	
प्राप्तियां– चालू खाता			1,700.00	1,700.00 Cr
4001 – विवरणिका की बिक्री			1,700.00	1,700.00 Cr
प्राप्तियां – योजनेतर		2,94,192.16	16,82,80,099.55	16,79,85,907.39 Cr
पेंशन भोगी चिकित्सा दाखिला फीस			1,20,300.00	1,20,300.00 Cr
स्वास्थ्य योजना अंशदान (सीजीएचएस)			4,09,000.00	4,09,000.00 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से प्राप्त अनुदान – योजनेतर			16,15,81,813.00	16,15,81,813.00 Cr
छात्रावास किराया		2,660.00	18,40,840.00	18,38,180.00 Cr
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज		92,768.00	2,91,800.00	1,99,032.00 Cr
बचत खाता पर ब्याज			6,48,196.55	6,48,196.55 Cr
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान			21,29,276.00	21,29,276.00 Cr
विविध प्राप्तियां		3,228.16	84,068.00	80,839.84 Cr
लाइसेंस शुल्क की वसूली			1,91,593.00	1,91,593.00 Cr
जल प्रभार की वसूली			6,293.00	6,293.00 Cr
रॉयल्टी			26,393.00	26,393.00 Cr
बेकार वस्तुओं की बिक्री		10,000.00	24,519.00	14,519.00 Cr
विवरणिका की बिक्री		200.00	7,800.00	7,600.00 Cr

fooj.k	vFk' ks"k	gLrkUrj.k		var ' ks"k
		fudklh	tek	
प्रकाशन की बिक्री		1,52,936.00	4,20,264.00	2,67,328.00 Cr
टेंडर फार्म की बिक्री			7,000.00	7,000.00 Cr
छात्र शुल्क		32,400.00	4,84,114.00	4,51,714.00 Cr
स्टाफ़ कार का प्रयोग			6,830.00	6,830.00 Cr
प्राप्तियां – प्रशासन निधि खाता 1108			90,49,813.09	90,49,813.09 Cr
9001 – प्राप्तियां शीर्ष 1108			89,79,179.00	89,79,179.00 Cr
बचत पर ब्याज – प्रशासन शीर्ष खाता 1108			70,634.09	70,634.09 Cr
प्राप्तियां – योजना			9,58,29,738.54	9,58,29,738.54 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान – योजना			9,54,79,646.00	9,54,79,646.00 Cr
बचत खाता से ब्याज – योजना			3,50,092.54	3,50,092.54 Cr
प्राप्तियां – हॉस्टल टेलीफोन बूथ			12,787.93	12,787.93 Cr
vi R; {k O; ;		64,65,16,975.40	2,18,89,344.50	62,46,27,630.90 Dr
अवमूल्यन		1.39.00.644.00		1.39.00.644.00 Dr
अवमूल्यन – भवन		25,29,942.00		25,29,942.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर		9,49,775.00		9,49,775.00 Dr
अवमूल्यन – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		40,93,269.00		40,93,269.00 Dr
अवमूल्यन – ई–जर्नल		14,27,342.00		14,27,342.00 Dr
अवमूल्यन – फर्नीचर		4,68,736.00		4,68,736.00 Dr
अवमूल्यन – जर्नल		24,79,445.00		24,79,445.00 Dr
अवमूल्यन – पुस्तकालय पुस्तकें		7,32,581.00		7,32,581.00 Dr
अवमूल्यन – कार्यालय उपकरण		9,06,745.00		9,06,745.00 Dr
अवमूल्यन – अन्य (आयोजन)		1,27,607.00		1,27,607.00 Dr
अवमूल्यन – वाहन		1,85,202.00		1,85,202.00 Dr
व्यय – केनरा बैंक		135.00		135.00 Dr
8002 – विश्रित व्यय/प्रभार		135.00		135.00 Dr
व्यय – चालू खाता		618.00		618.00 Dr
4003 – मिश्रित व्यय		618.00		618.00 Dr
व्यय – प्रशासन शीर्ष निधि खाता 1108		68.00		68.00 Dr
9002 – व्यय – प्रशासन निधि खाता 1108		68.00		68.00 Dr
गैर–योजना – व्यय		17,15,59,856.00	27,21,214.00	16,88,38,642.00 Dr
LFkkiuk O; ; & x\$&;kstuk		14,72,52,181.00	4,21,440.00	14,68,30,741.00 Dr
1001 – अधिकारियों को वेतन		2,87,73,535.00	43,414.00	2,87,30,121.00 Dr
1002 – स्थापना को वेतन		1,29,09,992.00		1,29,09,992.00 Dr

fooj.k	vFk'ks'k	gLrkUrj.k		vUr'ks'k
		fudklh	tek	
1003 – वेतन – भत्ता		5,97,41,175.00	1,28,557.00	5,96,12,618.00 Dr
1004 – समयोपरि भत्ता		88,126.00		88,126.00 Dr
1005 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति		50,80,959.00		50,80,959.00 Dr
1006 – अवकाश यात्रा रियायत		26,80,049.00	49,703.00	26,30,346.00 Dr
1007 – बोनस		3,13,739.00		3,13,739.00 Dr
1008 – अंशदाता के पी.एफ. पर ब्याज		63,799.00		63,799.00 Dr
1009 – वर्दी		21,390.00		21,390.00 Dr
1010 – नई पेंशन योजना (सरकारी अंश)		14,70,387.00	1,06,332.00	13,64,055.00 Dr
1011 – ग्रेच्यूटी		51,97,528.00		51,97,528.00 Dr
1012 – पेंशन		2,66,67,298.00	89,434.00	2,65,77,864.00 Dr
1013 – अवकाश नकदीकरण		33,72,576.00		33,72,576.00 Dr
1014 – यात्रा भत्ता		1,27,970.00	4,000.00	1,23,970.00 Dr
1016 – ट्यूशन शुल्क		7,43,658.00		7,43,658.00 Dr
dk;kZy; O; & ;ks us j		**2,43,07,675.00**	**22,99,774.00**	**2,20,07,901.00 Dr**
1021 – लेखा शुल्क		81,047.00		81,047.00 Dr
1022 – कानूनी व्यय		7,000.00		7,000.00 Dr
1023 – बीमा		44,609.00	38,616.00	5,993.00 Dr
1024 – स्टाफ कार की मरम्मत		2,98,140.00	25,100.00	2,73,040.00 Dr
1025 – समाचार पत्र प्रभार		1,39,535.00	580.00	1,38,955.00 Dr
1026 – पेट्रोल ऑयल तथा ल्यूब्रीक. ट्स		6,08,505.00		6,08,505.00 Dr
1028 – दर/किराया तथा टैक्स		3,97,070.00		3,97,070.00 Dr
1029 – टेलीफोन प्रभार		8,47,993.00	4,144.00	8,43,849.00 Dr
1030 – जल प्रभार		1,31,15,286.00		1,31,15,286.00 Dr
1031 – विद्युत प्रभार		64,87,139.00	18,316.00	64,68,823.00 Dr
1032 – विविध आकस्मिकताएं		22,81,351.00	22,13,018.00	68,333.00 Dr
;ks uk & O; ;		**11,46,47,776.40**	**1,91,68,130.50**	**9,54,79,645.90 Dr**
1- LFkkiuk O; &; ks uk		**69,19,782.00**	**16,41,323.00**	**52,78,459.00 Dr**
2001 – अधिकारियों का वेतन		28,68,631.00	6,52,770.00	22,15,861.00 Dr
2003 – भत्ते तथा मानदेय		40,51,151.00	9,88,553.00	30,62,598.00 Dr
2- dk;kZy; O; & ;kst uk		**3,28,95,088.40**	**56,13,778.10**	**2,72,81,310.30 Dr**
2005 – विज्ञापन		16,94,733.00		16,94,733.00 Dr
2006 – पोषाहार प्रभार		29,71,474.00		29,71,474.00 Dr
2007 – मुद्रण प्रभार		4,80,599.00	41,487.00	4,39,112.00 Dr
2008 – पोस्टेज तथा टेलीग्राम		15,86,812.00	7,24,086.00	8,62,726.00 Dr
2011 – टेलीफोन / टेलीग्राम प्रभार		2,74,771.00		2,74,771.00 Dr
2016 – बागवानी		1,58,091.00		1,58,091.00 Dr

fooj.k	vFk'ks"k	gLrkUrj.k		var 'ks"k
		fudklh	tek	
2018 – कानूनी व्यय		12,800.00		12,800.00 Dr
2019 – उपकरणों का रख–रखाव		41,20,264.00	6,38,573.00	34,81,691.00 Dr
2020 – भवन का रख–रखाव / हॉस्टल		69,44,800.00		69,44,800.00 Dr
2021 – समाचार पत्र प्रभार		10,440.00		10,440.00 Dr
2022 – जल तथा विद्युत प्रभार		70,32,274.00	40,44,894.00	29,87,380.00 Dr
2024 – अन्य विविध प्रशासनिक व्यय		7,33,924.40	1,11,118.60	6,22,805.80 Dr
2031 – हाऊस कीपिंग सेवाएं		45,54,166.00		45,54,166.00 Dr
2035 – सुरक्षा व्यय		2,55,033.00	43,100.00	2,11,933.00 Dr
2037 – मजदूरी प्रभार		10,62,396.00	1,159.00	10,61,237.00 Dr
2038 – टैक्सी प्रभार		5,11,688.00		5,11,688.00 Dr
2040 – फर्नीचर तथा फिक्चर रख–रखाव		17,247.00		17,247.00 Dr
2054 – पाठ्क्रम शुल्क / प्रशिक्षण		4,73,576.00	9,360.50	4,64,215.50 Dr
3- vdknfed O;; & ;kstuk		**2,95,43,571.00**	**57,02,592.00**	**2,38,40,979.00 Dr**
2007 – मुद्रण प्रभार		24,91,373.00	2,97,804.00	21,93,569.00 Dr
2010 – छात्रवृत्ति, पुस्तकें तथा परियोजना (डेपा)		3,53,439.00		3,53,439.00 Dr
2012 – अकादमिक कार्यक्रम व्यय		66,43,856.00	11,56,041.00	54,87,815.00 Dr
2013 – संकाय को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता		62,27,379.00	16,57,999.00	45,69,380.00 Dr
2014 – भागीदारों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता		1,15,26,276.00	24,57,228.00	90,69,048.00 Dr
2015 – संसाधन व्यक्तियों को मानदेय		17,43,507.00	1,33,520.00	16,09,987.00 Dr
2036 फोटोकॉपी प्रभार		4,47,046.00		4,47,046.00 Dr
2039 – अकादमिक संस्थानों को सदस्यता		1,10,695.00		1,10,695.00 Dr
4- fo'ofo|ky; v/;;u@,u-th- vks & ;kstuk		**3,85,12,678.00**	**62,10,437.00**	**3,23,02,240.60 Dr**
2041 – एम.फिल. / पी.एच.डी. छात्रों को अध्येतावृत्ति		87,48,607.00	2,49,642.00	84,98,965.00 Dr
2051 – एन.जी.ओ. को अनुदान		72,30,765.00	1,22,880.00	71,07,885.00 Dr
2064 – स्कूल शिक्षा में पहुंच, भागीदा. री तथा अधिगम		15,355.00		15,355.00 Dr
2065 – मॉडल शिक्षा की तैयारी – कोड नियम		5,29,921.00		5,29,921.00 Dr
2070 – शिक्षा के सामाजिक आयाम का केस अध्ययन		47,000.00		47,000.00 Dr
2071 – अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण		1,35,500.00		1,35,500.00 Dr

fooj.k	vFk'k ks'k	gLrkUrj.k		vafre 'ks'k
		fudklh	tek	
2079 – स्कूल कौन जाता है? अनुभवाश्रित विश्लेषण		1,06,806.00	17,000.00	89,806.00 Dr
2080 – विद्यालय गुणवत्ता का पुनरीक्षण – डा. मधुमिता		1,12,319.00		1,12,319.00 Dr
2081 – अनुसंधान अध्ययन		18,00,196.00	3,032.00	17,97,164.00 Dr
2083 – डी.ई.ओ. तथा बी.ई.ओ. क्षमता निर्माण सम्मेलन		27,59,398.00	13,00,000.00	14,59,398.00 Dr
2084 – शैक्षिक दस्तावेजों का डिज़िटल भंडारण (डा. मैथ्यू)		18,90,023.00		18,90,023.00 Dr
2085 – प्रकाशन एकक की योजनाएं (पी. रावत)		4,93,340.00		4,93,340.00 Dr
2086 – राष्ट्रीय साधन – मेरिट छात्रवृत्ति		57,000.00		57,000.00 Dr
2087 – बच्चों की भागीदारी पर सुधार लाने पर कार्यशाला		1,20,257.00		1,20,257.00 Dr
2088 – विदेशी बोर्ड का अध्ययन – प्रणति पांडा		4,60,217.00	3,871.00	4,56,346.00 Dr
2090 – ऑटोनामी आफ इंडियन हायर स्कूल		4,78,710.00		4,78,710.00 Dr
2091 – शैक्षिक प्रशासन में राष्ट्रीय नवाचार		4,74,839.00		4,74,839.00 Dr
2092 – बच्चों के शिक्षा का महत्वपूर्ण मूल्यांकन		7,50,168.00		7,50,168.00 Dr
2093 – निजी फ्रेंचाइजी प्रदान करने से पूर्व स्कूल शिक्षा		2,92,387.00		2,92,387.00 Dr
2095 – तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण – आर.एस. त्यागी		17,36,128.00		17,36,128.00 Dr
2096 – लड़कियों की राष्ट्रीय योजना – डा. वी.पी.एस. राजू		6,31,865.00		6,31,865.00 Dr
2097 – शिक्षा ऋण का मूल्यांकन – डा. गीता रानी		2,84,741.00	19,354.00	2,65,387.00 Dr
2098 – डीडी सेकेण्डरी एजूकेशन रमसा – डा. जैदी		5,92,554.00		5,92,554.00 Dr
2099 – विद्यालय प्रमुख का कार्य – डा. रश्मि दीवान		5,60,479.00		5,60,479.00 Dr
2100 – बिहार और मध्य प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन – प्रो. कुमार		1,65,516.00	37,742.00	1,27,774.00 Dr
2101 – अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार – डा. मधुमिता		2,59,411.00	36,102.40	2,23,308.60 Dr
2102 – गैर नामांकित और शाली त्यागी बच्चे		6,26,698.00		6,26,698.00 Dr
2103 – उच्च शिक्षा के विशेष कारक		4,46,507.00		4,46,507.00 Dr

foo j . k	v Fk' ks"k	g Lr kUr j . k fu d kl h	t e k	v a r e ' ks"k
2104 – विकास हेतु पायलट परियोजना		1,85,264.00		1,85,264.00 Dr
2105 – शि.का.अ. में समता की समीक्षा – डा. नरेश कुमार		2,72,720.00		2,72,720.00 Dr
2106 – स्कूल सुधार हेतु उन्नत प्रशिक्षण – डा. मधुमिता		2,67,097.00		2,67,097.00 Dr
2107 – स्कूल मानक एवं मूल्यांकन – डा. प्रणति पांडा		44,00,814.00	44,00,814.00	
2108 – शिक्षा की वर्तमान स्थिति – डा. मधुमिता		83,355.00		83,355.00 Dr
2109 – परियोजना व्यवस्था एकक – डा. के. बिस्वाल		2,95,550.00		2,95,550.00 Dr
2110 – कार्यान्वयन पर अध्ययन 25%		2,29,377.00		2,29,377.00 Dr
2111 – लिंग और शिक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला		4,13,126.00	20,000.00	3,93,126.00 Dr
डेपा वेतन		5,58,668.00		5,58,668.00 Dr
5- mÙkj&iwohZ{ks=		**67,76,657.00**		**67,76,657.00 Dr**
2052 – उत्तर–पूर्वी क्षेत्र		67,76,657.00		67,76,657.00 Dr
पूर्व अवधि व्यय		34,64,07,878.00		34,64,07,878.00 Dr
पूर्व अवधि व्यय – गैर–योजना		29,87,54,749.00		29,87,54,749.00 Dr
पूर्व अवधि व्यय – योजना		4,76,53,129.00		4,76,53,129.00 Dr
आय और व्यय खाता			1,92,34,764.16	
लाभ और हानि खाता	1,92,34,764.16 Dr			
e g k; kx		2,00,77,73,588.06	2,00,77,73,588.06	

y$[kki jh{kk fjiksVZ

y $ kki j h{kk fj i kSVZ

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के 31 मार्च 2014 के तुलन–पत्र की एवं 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा कर ली है। हमें वर्ष 2015–16 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण के व्यवहार्य से एकरूपता, लेखाकरण के मानदंडों और पारदर्शिता के मानकों इत्यादि के संबंध में लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। पृथक निरीक्षण रिपोर्टों/नि.म.ले. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के द्वारा आवश्यकतानुसार विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियामक) के अनुपालन और वित्तीय संचालन और कार्य निष्पादन सहित कार्यदक्षता संबंधी पक्षों इत्यादि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती है।

3. हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के अधिक यथार्थ विवरणों से युक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण के सिद्धांतों, महत्वपूर्ण आकलनों की समीक्षा के साथ–साथ प्रस्तुत किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर प्रतिवेदन करते हैं कि–

(i) लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ii) तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे वित्त मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं. 29–4/2012 एफ.डी., दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सही प्रकार से तैयार किए गए हैं तथा लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(iii) हमारी राय के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय ने समुचित रूप से लेखा पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया है जो कि ऐसी पुस्तिकाओं की जांच–पड़ताल से पता चलता है।

(iv) हम पुनः प्रतिवेदन करते हैं कि :

v- rgu i=

v-1 ifjlaifÙk;ka

v-1-1 vpy ifjlaifÙk;ka ¼vuqlwph&3½ #- 19-08 djksM+

इसमें परियोजना निधि के अंतर्गत रु. 4.44 लाख की लागत से खरीदे गए। फर्नीचर और फिक्चर शामिल नहीं किया गया है। इस कारण अचल परिसंपत्ति में रु. 4.44 लाख कम दिखाया गया है।

c- Hkfo"; fuf/k y$kk dk rgu i=

c-1 ifjlaifÙk;ka

निवेश (सा.भ.नि.) –रु. 11.48 करोड़

न्यूपा के पास कर योग्य कोई आय नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष के दौरान परिपक्व तीन आवधिक जमा राशियों के ब्याज पर रु. 6.76 लाख कर के रूप में कटौती की है। इस राशि को लेखा वसूली योग्य राशि के रूप में अंकित नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप आवर्ती परिसंपत्ति और पूंजीकृत निधि में रु. 6.76 लाख का अव प्राक्कलन हुआ है।

l- lkekU;

l-1- न्यूपा ने वर्ष 2014–15 में मंत्रालय द्वारा एनईआर, जनजातीय उपयोजना, अ.ज.जा. के लिये विशेष घटक योजना के लिए जारी रु. 306.30 लाख का अलग लेखे नहीं तैयार किए जबकि स्वीकृत पत्र में इसके लिए विशेष उल्लेख किया गया था। अतः अलग लेखों के अभाव के कारण लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन प्रयोजनबद्ध निधियों के उपयोग को सत्यापित नहीं कर सकी।

l-2- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी लेखा प्रपत्र के अनुसार अचल संपत्तियां अनुसूची में प्रदर्शित परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करके योजना, गैर–योजना अमूर्त परिसंपत्ति, पेटेंट और कापीराईट आदि उप अनुसूचियों में प्रस्तुत करना था मगर न्यूपा द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

n- lgk;rk vuqnku

विश्वविद्यालय ने मार्च 2015 में रु. 2718.57 लाख (योजना में 1206.97 लाख, योजनेतर में रु. 1511.60 लाख) का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसमें से रु. 9.90 लाख (योजना) मार्च 2015 में प्राप्त हुआ। न्यूपा के पास कुल रु. 588.23 लाख की प्राप्तियां (योजना रु. 476.53 लाख और योजनेतर में रु. 111.70 लाख) अर्थ शेष था। विश्वविद्यालय ने कुल रु. 3306.80 लाख में से रु. 2829.17 लाख (योजना में रु. 1205.87 लाख, योजनेत्तर में रु 1623.30 लाख) का उपयोग किया। 31 मार्च 2015 को रु. 477.63 लाख (योजना) बचत शेष था।

विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान मा.सं.वि. मंत्रालय से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए रु. 340.34 लाख का अनुदान प्राप्त किया और इन परियोजनाओं में रु. 90.52 लाख अथ शेष था। कुल राशि रु. 430.87 लाख में से रु. 234.11 लाख रुपये वर्ष के दौरान व्यय किए गए और 31 मार्च, 2015 को रु. 196.76 लाख बचत शेष पाया गया।

;- izca/ku i= %लेखा से संबंधित जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें दूर करने हेतु पृथक रूप से प्रबंधन पत्र के द्वारा कुलपति, न्यूपा के संज्ञान में लाया गया है।

(v) आगे के अनुच्छेदों में टिप्पणी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखा रिपोर्ट में तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

(vi) हमारे विचार से और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित वित्तीय विवरण

जो लेखाकरण की नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां के अधीन माने गये हैं, उपर्युक्त महत्वपूर्ण विवरणों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नित भाग में प्रस्तुत अन्य दूसरी सामग्री आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं:

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च 2015 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के तुलन पत्र की स्थिति से संबंधित हैं।

(ब) जहाँ तक यह इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आय तथा व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक तथा महानिदेशक, लेखापरीक्षा की ओर से और कृते

g-@&

egkfuns'kd] ys{kkijh{kk dsUnzh; O;;

LFkku %ubZ fnYyh

fnukad %27-10-2015

y$kk ijh{kk dsfy;s vuqyXud

1- vkarfjd y$kk ijh{kk O;oLFkk dh i;kZIrrk

- न्यूपा में अलग से कोई लेखा परीक्षा विभाग नहीं है। आमतौर पर लेखा का भुगतान करने से पूर्व सभी बड़े भुगतानों की जाँच करता है।
- न्यूपा की आंतरिक लेखा परीक्षा पी.पी.ए. कार्यालय, मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।
- न्यूपा द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है।

2- vkarfjd fu;a=.k O;oLFkk dh i;kZIrrk

- 31 मार्च 2015 तक 2000–01 तथा 2011–12 की अवधि के दौरान 33 लेखा परीक्षा पैरा के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

3- laifÙk;ksa dk HkkSfrd fujh{k.k

- 31.03.2014 तक भूमि और भवनों एवं वाहनों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
- 31.03.2012 तक फर्नीचरों और फिक्सरों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
- कंप्यूटर और सहायक सामग्रियों का 31.03.2012 तक भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान कुछ सामान अप्राप्य मिले। उसकी पुनः जांच के लिए न्यूपा ने जनवरी 2013 में जांच और सत्यापन के लिए समिति का गठन किया था। समिति ने पुनः जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कोई सामान अप्राप्य नहीं पाया गया।
- पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक निरीक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है और जुलाई 2012 तक यह सत्यापन किया गया है। 45 पुस्तकें अप्राप्य पाई गईं जिनकी लागत रु. 1028+8 डालर है। इस संबंध में पिछली लेखा परीक्षा में अल्लेख किया था। मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4- bUoasUVjh dh HkkSfrd tkap

- स्टेशनरी, प्रकाशन तथा उपभोग वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मार्च 2012 तक कर लिया गया है। कोई कमी की रिपोर्ट नहीं की गई।

5- lkafofèkd Hkqxrku esa fu;ferrk

- लेखा के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2015 तक पिछले छः महीने से कोई भी सांविधिक देयता का भुगतान बाकी नहीं था।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

17-*बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली* -110016
फोन : 91-11-26544800, 26565600
फैक्स : 91-11-26853041, 26865180
ई–मेल : nuepa@nuepa.org *वेबसाईट* : www.nuepa.org